राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 160

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 18 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

बिल गेट्स बोले, भारत में तेज आर्थिक विकास की क्षमता

>> 12

पुनर्विचार याचिका के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष दोफाड़

बदला रुख ▶ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर, फिर से जाएंगे अदालत

पांच एकड़ भूमि लेने से भी इन्कार, कहा– 'शरीयत नहीं देता इजाजत'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष बंटा नजर आने लगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अनुचित बताते हुए नामंजूर कर दिया है। रविवार को बोर्ड की कार्यकारिणी ने अहम बैठक कर निर्णय लिया है कि कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। बोर्ड ने मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमि दूसरी जगह लेने से भी यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि यह शरीयत के खिलाफ है। हालांकि बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्णय से सहमत नहीं हैं। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी भी कह चुके हैं कि वह पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक रविवार को लखनऊ के नदवातुल उलमा में होनी थी लेकिन, प्रशासन से अनुमति न मिलने से डालीगंज स्थित मुमताज पीजी कॉलेज में हुई। बोर्ड में पचास सदस्य हैं जिसमें लगभग 35 सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित मुस्लिम नेता भी शामिल हुए।

करीब तीन घंटे तक चली बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तमाम बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता में बोर्ड के सचिव और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। यह महसूस किया गया है कि कोर्ट के निर्णय में कई बिंदुओं पर न केवल विरोधाभास है, बल्कि प्रथमदृष्टया अनुचित प्रतीत होता है। उनका दावा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए तीन पक्षकारों की सहमति मिल गई है। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैय्यद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने की। इसमें जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना वली रहमानी, जलालुद्दीन उमरी, सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, महिला सदस्य डॉ. आसमा जहरा, आमना रिजवाना, परवीन खान, ममदुहा माजिद आदि ने शिरकत की।

मस्जिद की जमीन के बदले कोई अन्य भूमि स्वीकार नहीं : जिलानी ने कहा, याचिका में इस तथ्य का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले मुस्लिम कोई अन्य भूमि स्वीकार नहीं कर सकते। मुसलमान किसी दूसरे स्थान पर अधिकार लेने के लिए कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की भूमि के लिए न्याय के लिए गए थे। उन्होंने कहा, अयोध्या में नई मस्जिद बनाने की हमें क्या जरूरत है। पहले से ही वहां तमाम मस्जिदें हैं। बोर्ड के सचिव मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने कहा, शरीयत के अनुसार, हम मस्जिद के एवज में कोई वस्तु या जमीन नहीं ले सकते। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सह संयोजक कासिम रसूल इलियास बोले, हम फैसले के 30 दिन के अंदर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर देंगे।

जिलानी ने कहा, दबाव में होंगे इकबाल अंसारी : पक्षकार इकबाल अंसारी के बारे में पूछने पर जिलानी का कहना था कि पुलिस प्रशासन किसी को फैसले के खिलाफ बोलने नहीं दे रहा। हो सकता है कि अंसारी दबाव में हों।

मदनी ने बीच में छोड़ी बैठक, कल्बे सादिक शामिल नहीं हुए : जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी बोर्ड बैठक बीच में ही छोड़ कर चले गए। दूसरी ओर बोर्ड के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना डॉ. कल्बे सादिक बैठक में शामिल नहीं हुए।

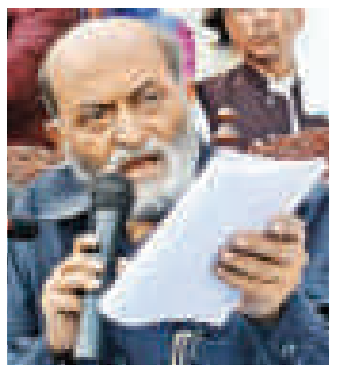

लखनऊ में रविवार को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद जानकारी देते जफरयाब जिलानी। जागरण

तीन पक्षकारों की मिली सहमति : जिलानी

मुस्लिम पर्सलन लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी का दावा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए तीन पक्षकारों की सहमति मिल गई है। पक्षकार जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की है। पक्षकार मौलाना महफुजर्रहमान, मो. उमर, मिसबाहुद्दीन ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

हमें नहीं चाहिए रिव्यू, जिसे कोर्ट जाना हो जाए : इकबाल

बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे मो. इकबाल अंसारी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए रिव्यू, जिसे कोर्ट जाना हो जाए। मैं कोर्ट का फैसला स्वीकार करने के अपने रुख पर पूरी तरह से कायम हूं। दोहराया कि अब हमें बाबरी मस्जिद को भूल कर आगे की ओर देखना होगा। इकबाल उन लोगों में रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुक्तकंठ से सराहना की है और विवाद से मुक्त होकर आपसी सहमति-सौहार्द के पर्याय बनकर सामने आए हैं। बाल को सौहार्द की यह शिक्षा अपने अब्बू व बाबरी मस्जिद के मुद्दई मो. हाशिम अंसारी से विरासत में मिला है। वह अपने अब्बू की ही तरह मस्जिद की पैरोकारी के बावजूद मुस्लिमों से अधिक हिंदुओं में लोकप्रिय हैं

मामले में अब हो रही सियासत : मौलाना रजवी

बरेली : तंजीम उलमा-ए- इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि अयोध्या मामले में अब राजनीति हो रही है। अयोध्या मुद्दा खत्म हो जाने के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड इसे जिंदा रखना चाहता है। जिससे राजनीतिक बिसात सजा कर हिंदू-मुसलमान के बीच भाईचारा और देश के अमन को नुकसान पहुंचा सकें। मौलाना ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड देश के महज 25 फीसद मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। 75 फीसद मुसलमान इसके खिलाफ हैं। बेहतर होगा कि अयोध्या मामला अब यहीं छोड़ दिया जाए और उससे आगे की बात हो।

पुनर्विचार की जरूरत नहीं

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी भी कह चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वह पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जमीन लेने या न लेने के मामले में कानूनी विमर्श कर रहे हैं।

अयोध्या पर विशेष पेज
श्रीराम >> पेज 7

सरोकार

इंदौर में पराली से तैयार किए डिस्पोजेबल बर्तन

रायपुर : इंदौर जिले के एक युवा दंपती ने पराली (धान के अवशेष) से डिस्पोजेबल बर्तन तैयार किया है। इससे न सिर्फ पराली का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि होगी और कुटीर उद्योग धंधे विकसित होंगे। (पेज-11)

जागरण विशेष

किराना स्टार्टअप ने चार साल में ली 225 गुना बढ़त

इंदौर : मप्र के इंदौर जिले से संचालित होने वाला शॉप किराना स्टार्टअप धूम मचा रहा है। इसकी शुरुआत तीन दोस्तों ने 2015 में की थी। इसकी सफलता को देखते हुए अमेरिका की बैटर कैपिटल, जापान की इन्क्यूबेट फंड और नौकरी डॉट कॉम ने 14 करोड़ की फंडिंग की है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

झारखंड में बागी हुए सरयू राय सीएम के खिलाफ ठाकेंगे ताल

जमशेदपुर : भाजपा की टिकटों की घोषणा में वेटिंग में रखे गए झारखंड के खाद्य व आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अब पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। रविवार को जहां उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। वहीं, मंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

श्रीनगर-बनिहाल के बीच तीन माह बाद रेल सेवा बहाल

जम्मू : कश्मीर में बनिहाल-श्रीनगर-बारामुला रेल खंड के बीच तीन माह बाद रेल सेवा बहाल हो गई। शनिवार व रविवार को सफल ट्रायल रन के बाद रेल सेवा शुरू हो गई। राज्य प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर तीन अगस्त को सेवा बंद कर दी थी। बारामुला-श्रीनगर के बीच यह सेवा मंगलवार से ही बहाल कर दी गई थी।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

बेहतर कारोबार में जीएसटी के नियम की दीवार

वाराणसी : वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के नियम 36(4) ने व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया है। व्यापारी इस नियम के कारण जीएसटीआर-2ए में दर्ज उस माह की संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के 20 फीसद से ज्यादा का लाभ नहीं ले पाएगा। व्यापारियों के लिए यह मुश्किल जीएसटीआर-वन भरने के समय निर्धारण में भिन्नता से है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

हांगकांग में विवि के भीतर से पुलिस पर बरसे तीर

हांगकांग : हांगकांग में रविवार को हिंसा फिर भड़क उठी। काऊलून प्रायद्वीप में अवरोधों से घिरे हांगकांग पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय से पुलिस पर तीरों और पेट्रोल बमों से हमला हुआ। विवि परिसर के बाहर बने मोर्चों की आड़ और भवन की छतों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागे व नीले रंग का तरल पदार्थ छोड़ा। हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर है।

संसद में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार : मोदी

सर्वदलीय बैठक

- प्रधानमंत्री ने पिछली बार की तरह ही यह सत्र भी सफल होने की जताई उम्मीद
- विपक्ष ने कहा, अब्दुल्ला और चिदंबरम को सत्र में भाग लेने की मिले अनुमति

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में हैं गृह मंत्री अमित शाह और अन्य दलों के नेता। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं बहस करना है। सरकार सदन के नियमों व प्रक्रियाओं के दायरे में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। रविवार को शीतकालीन सत्र की पूर्वसंध्या पर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को यह भरोसा दिलाया। वहीं विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कांफ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया और उन्हें सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दिए जाने की मांग की। बैठक में 27 दलों के नेताओं ने भाग लिया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के अनुसार, विपक्ष ने सत्र के दौरान आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की।

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इस सत्र के भी पिछले सत्र जितना ही फलदायी होने की उम्मीद जताई। पिछला सत्र लोकसभा के इतिहास में सबसे सफल सत्र रहा था। इस दौरान 35 विधेयक पारित हुए थे। राज्यसभा से 32 विधेयकों को स्वीकृति मिली थी। सर्वदलीय बैठक में मोदी ने कहा, संसद में रचनात्मक चर्चा नौकरशाही को भी सतर्क रखती है। विपक्षी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए पीएम ने कहा, प्रदूषण, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, किसान व कृषि समेत सभी मुद्दों पर सरकार सभी दलों के सकारात्मक सहयोग के साथ लंबित विधायी कार्यों और नीतिगत फैसलों पर काम करेगी। हालांकि विपक्ष पीएम के आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिखा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हकीकत यह है कि जब भी सदन में आर्थिक मंदी, किसानों की हालत और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, तो सरकार का रवैया बदल जाता है। विपक्ष की ओर से फारूक अब्दुल्ला को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

नेशनल कांफ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा, संसद सत्र में फारूक अब्दुल्ला की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा, 'किसी सांसद को अवैध रूप से हिरासत में कैसे लिया जा सकता है?' साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस के नेता पी. चिदंबरम को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत देने की मांग की। उनका कहना था कि पहले ऐसे मामलों में सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जा चुकी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सभी दलों की बैठक बुलाई थी और सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की थी।

सत्र हंगामेदार रहने के आसार : शीतकालीन सत्र में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, आर्थिक सुस्ती और कश्मीर जैसे मसलों पर हंगामे के आसार हैं। 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 47 बिल एवं प्रस्ताव संसद में रखे जाने हैं। सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, ई-सिगरेट पर पाबंदी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे।

शिवसेना को विपक्ष की सीट मिली : राजग से संबंध तोड़ने के बाद शिवसेना के सांसदों के बैठने का क्रम बदल गया है। मंत्री पद छोड़ने वाले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत अब लोस में पहली के बजाय तीसरी पंक्ति में बैठेंगे। बाकी 17 सांसद भी विपक्ष के खेमे में बैठेंगे।

आज दिल्ली में बिछेगी महाराष्ट्र सरकार की बिसात

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- सोनिया गांधी से मिलकर राज्य में सरकार बनाने पर चर्चा करेंगे पवार
- कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना के बीच अब तक की बातचीत की जानकारी देंगे

सोनिया गांधी

शरद पवार (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना सरकार बनने के मामले में गेंद अब केंद्रीय नेताओं के पाले में पहुंच गई है। माना जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर सरकार बनाने के बारे में चर्चा करेंगे।

रविवार को पुणे में राकांपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। पार्टी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राकांपा विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक के अनुसार बैठक में राज्य में चुनी हुई सरकार बनाने का निर्णय किया गया। चूंकि प्रदेश में राकांपा और कांग्रेस का चुनावपूर्व गठबंधन है, इसलिए शरद पवार सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। वे उन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना नेताओं के बीच हुई अब तक की चर्चा की जानकारी देंगे और आगे की योजना पर विचार करेंगे। उसके बाद मंगलवार को कांग्रेस-राकांपा के नेता साथ बैठकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।

महाराष्ट्र इस समय राष्ट्रपति शासन के दौर से गुजर रहा है। नौ नवंबर को पिछली विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने 105 सदस्यों वाले सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। भाजपा के असमर्थता जाहिर करने पर शिवसेना को 24 घंटे का समय दिया। शिवसेना प्रतिनिधि दी गई अवधि से 45 मिनट पहले ही राजभवन पहुंच गए थे लेकिन कांग्रेस, राकांपा के समर्थन का पत्र नहीं पहुंचने से मायूस लौटे। उसके बाद राकांपा को भी 24 घंटे का समय दिया गया, लेकिन राकांपा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। इसे सरकार बना पाने में राकांपा की असमर्थता मानते हुए राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।

शिवसेना को सीएम पद देने को तैयार प्रदेश स्तर के नेता : शिवसेना की कांग्रेस और राकांपा नेताओं से कई स्तर पर बातचीत हो चुकी है। स्वयं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे राकांपा अध्यक्ष शरद पवार एवं कांग्रेस नेता अहमद पटेल सहित प्रदेश स्तर के नेताओं से मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि तीनों दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस और राकांपा प्रदेश स्तर के नेता शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने को राजी दिख रहे हैं। बदले में कांग्रेस और राकांपा को पूरे पांच वर्ष के लिए उपमुख्यमंत्री पद के साथ कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकते हैं।

बाला साहब ठाकरे स्मृति स्थल पर फड़नवीस के खिलाफ नारेबाजी पेज>>4

जेएनयू में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में छात्रों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में तोड़फोड़ कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वसंत कुंज थाने की पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में लगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही अपशब्द भी लिखे थे। इस मामले में कार्रवाई के लिए शनिवार को पुलिस को दो शिकायतें मिली थीं। अधिकारियों के मुताबिक, एक शिकायत भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने दी थी, जबकि दूसरी शिकायत स्वामी विवेकानंद स्टेच्यू स्टॉलेशन कमेटी के अध्यक्ष बुद्ध सिंह ने दी थी। इसके आधार पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि कुछ छात्रों ने गत दिवस एक टीवी चैनल की पत्रकार के साथ भी बदसुलूकी की थी। (पेज-2 भी देखें)

चीन समर्थक गोतबाया राजपक्षे होंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति

- यूएनपी के सजित प्रेमदासा को 13 लाख से अधिक वोटों से हराया
- पीएम मोदी ने भी दी बधाई, राजपक्षे बोले-मिलने को उत्सुक हूं

गोतबाया राजपक्षे फाइल फोटो

कोलंबो, प्रेट्र : पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भाई गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। चीन समर्थक माने जाने वाले राजपक्षे ने यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के प्रत्याशी सजित प्रेमदासा को 13 लाख से अधिक वोटों से हराया। राजपक्षे ने चुनावी दौरे में कई बार कहा था कि अगर वह सत्ता में आते हैं, तो चीन से रिश्तों को मजबूत बनाया जाएगा। सनद रहे कि उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका सरकार ने चीन को खूब बढ़ावा दिया। उनकी सरकार ने चीन को हंबनटोटा बंदरगाह और एयरपोर्ट का ठेका दिया। भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ से घेरने की चीन की योजना में उक्त परियोजनाएं अहम हिस्सा हैं।

गोतबाया की इस जीत के साथ ही राजपक्षे परिवार की पांच साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है। इससे पहले महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजपक्षे को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी है। जवाब में राजपक्षे ने कहा कि वह निकट भविष्य में मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। चुनाव में जीत के बाद 70 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) गोतबाया ने समर्थकों से गरिमा व अनुशासन से जीत की खुशी मनाने का आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट में कहा, 'आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका नई यात्रा की शुरुआत कर चुका है। देश का हर व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा है।'

वहीं, चुनाव में हार के बाद प्रेमदासा ने ट्वीट किया 'लोगों के निर्णय का सम्मान करना और श्रीलंका के सातवें राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने के लिए गोतबाया को बधाई देना सौभाग्य की बात है।' माना जा रहा है कि इस चुनाव परिणाम के बाद यूएनपी के नेता और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पद छोड़ सकते हैं। गोतबाया अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को नया पीएम बनाएंगे।

सिंहली बहुल इलाकों में एकतरफा जीत पेज>>13

राजपक्षे की नीतियों पर होगी भारत की नजर

नई दिल्ली : श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे पर भारत की पैनी नजर रहेगी। आतंकी संगठन लिट्टे के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान वह रक्षा सचिव थे और उन पर निर्दोष तमिल आबादी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन के काफी आरोप लगे थे। नेपाल के बाद श्रीलंका इस क्षेत्र का दूसरा देश है, जहां हुए चुनाव में किसी ऐसे व्यक्ति या पार्टी की जीत हुई है, जिसकी छवि भारत समर्थक की नहीं रही है। (पेज-13)

इस बार चुनाव मैदान में थे कुल 35 उम्मीदवार

इस राष्ट्रपति चुनाव में कुल 35 उम्मीदवार मैदान में थे। राजपक्षे को जहां 52.25 फीसद (6,924,255) वोट मिले, वहीं प्रेमदासा 41.99 फीसद (5,564,239) मत प्राप्त करने में सफल रहे। अन्य उम्मीदवारों को 5.76 फीसद वोट मिले। देश के कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए 50 फीसद या उससे अधिक मत प्राप्त करने जरूरी हैं। शनिवार को हुए मतदान में 1.59 करोड़ मतदाताओं में से 80 फीसद से कुछ ज्यादा लोगों ने भाग लिया था, यह 2015 के चुनाव से थोड़ा कम था। उस चुनाव में मैत्रिपाल सिरिसेन ने महिंदा राजपक्षे को हराया था।

सुरक्षा की चिंता

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ कैंप के आसपास तीन बार उड़ते देखे गए ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, दिखते ही मार गिराने का आदेश, भारत-पाक सीमा पर हथियारों की तस्करी में हुआ था ड्रोन का इस्तेमाल

नक्सली भी कर रहे ड्रोन का इस्तेमाल

अनिल मिश्रा, जगदलपुर

पंजाब से सटे भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद धुर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन गया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों की टोह लेने के लिए नक्सली इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में तीन बार यहां सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) कैंपों के ऊपर और आस-पास ड्रोन मंडराते देखे गए हैं।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और डीआरजी (डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड) के जवान संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। सुकमा इलाके में सीआरपीएफ ज्यादा प्रभावी है और इसी कारण यह नक्सलियों के निशाने पर है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में दो बार सीआरपीएफ के किस्टारम और पालोडी कैंप के ऊपर ड्रोन देखा गया। जवानों के मुताबिक लाल और सफेद लाइट वाले इस ड्रोन को वे गिरा पाते कि वह गायब हो गया। एक और कैंप के पास भी ड्रोन देखे जाने की चर्चा है।

प्रतीकात्मक फोटो

मामला सामने आते ही बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों को एक नई चुनौती के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बस्तर के आइजी सुंदरराज पी ने कहा कि अब तक लैंड माइंस का ही खतरा था। अब ड्रोन पर भी निगरानी रखने की रणनीति बनाई गई है। समूचे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, हालांकि अभी यह नहीं पता चल पाया है कि ड्रोन का कंट्रोल कहां था? उन्होंने कहा कि इस इलाके में आदिवासियों के पास ड्रोन के लायक संसाधन नहीं हैं। इसलिए माना जा रहा है कि नक्सली नेता सुरक्षा बलों की गतिविधियों को जानने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नक्सलियों के गढ़ में बनाया पालोडी कैंप : सीआरपीएफ ने पिछले साल ही किस्टारम से 12 किमी अंदर नक्सली मांद में घुसकर पालोडी में भी कैंप बनाया था। इससे बौखलाए नक्सलियों ने 23 मार्च 2018 को किस्टारम से पालोडी जा रहे सीआरपीएफ के वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया था जिसमें नौ जवान शहीद हुए थे।

आइजी बोले, जांच की जा रही : राज्य पुलिस के आइजी सुंदरराज ने कहा कि कैंप के ऊपर कोई अवांछित चीज उड़ेगी तो उसे शूट करने का निर्णय जवान ले सकते हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। बीते दिनों मुंबई एयरपोर्ट पर बगैर कस्टम क्लियरेंस के सौ से ज्यादा ड्रोन ले जाते एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। हालांकि उसका यहां से कोई कनेक्शन है या नहीं यह पता नहीं लग पाया है।

एनआइए कर रही जांच : पंजाब से सटे भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीते महीनों हथियारों की तस्करी में ड्रोन के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआइए) इसकी जांच कर रही है।

बेमिसाल रहा जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल

नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई रविवार को ावानिवृत्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट में लगभग सात साल न्यायाधीश और उसमें से 13 महीने 14 दिन तक देश के प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाले जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल बेमिसाल रहा। अनुशासनप्रिय, सख्त और बेबाक व्यक्तित्व के धनी जस्टिस गोगोई ने कई ऐस फैसले दिए और काम किए जो उन्हें औरों से अलग और यादगार बनाते हैं। (पेज-3)

एलओसी के पास आईईडी धमाका, जवान शहीद

जम्मू : जम्मू जिले के सीमावर्ती अखनूर के प्लांवाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब रविवार दोपहर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) धमाके में सेना का एक जवान शहीद और दो अन्य घायल हो गए। विस्फोट उस समय हुआ जब सेना के कुछ जवान वाहन से अग्रिम चौकी की ओर बढ़ रहे थे कि जोरदा धमाका हुआ। अस्पताल में भर्ती एक जवान की हालत गंभीर बताई जाती है। (पेज-6)

सबरीमाला मंदिर को आंदोलन का अखाड़ा नहीं बनने देंगे : केरल

- एलडीएफ सरकार के मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वत: स्टे
- सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में सभी आयु की महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं, केरल की वाममोर्चा सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार वो सबरीमाला मंदिर को आंदोलन का अखाड़ा नहीं बनने देगी।

केरल के कानून मंत्री एके बालन ने पत्रकारों से कहा, संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार अदालत के आदेश के मुताबिक ही काम कर सकती है। इस मामले में सरकार के सामने नई समस्या पैदा हो गई है। अगर यह पूछा जाय कि शीर्ष अदालत का 14 नवंबर का फैसले पहले के आदेश पर रोक है तो कानूनन इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन शीर्ष अदालत के फैसले से 28 सितंबर 2018 के आदेश पर स्वतः स्टे की तरह रोक लग गई है। दरअसल, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 14 नवंबर को तीन-दो के बहुमत से मामले को सात सदस्यीय बड़ी पीठ के सामने भेजने का फैसला किया था।

बता दें कि गत वर्ष अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने 10 से 50 आयु वर्ग समेत सभी महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। इसे लेकर बहुत बवाल हुआ था। वाम मोर्चा सरकार ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिलाने के इंतजाम किए थे। धार्मिक रूप से प्रतिबंधित उम्र की दो महिलाओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन भी किए थ

6 लोगों पर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने खुलेआम पराली या कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाया है और इन्हें पर्यावरण शत्रु घोषित किया है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है जो घर का कूड़ा-कचरा कॉलोनी के किसी कोने-नुक्कड़ पर जला देते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 18 नवंबर 2019

दावा ▸ मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, प्रदूषण पर साफ नीयत से सबको मिलकर काम करने की जरूरत

'पराली जलनी बंद हुई तो साफ हो गई हवा'

दिल्ली की हवा में पराली से पांच फीसद प्रदूषण का दावा करने वालों पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक बार फिर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पराली जलने के कारण है। अब इसके लगभग खत्म होने पर वायु गुणवत्ता सुधर रही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलनी बंद हो गई तो दिल्ली की हवा भी साफ हो गई। कुछ लोग कह रहे थे दिल्ली की हवा में केवल पांच फीसद पराली का प्रदूषण है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केवल पांच फीसद प्रदूषण कम होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज्यादा होने के बाद घटकर 200 से कम हो गया? केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण पर राजनीति नहीं, साफ नीयत से सबको मिलकर काम करने की जरूरत है।

केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान पांच फीसद ही है। हालांकि दिल्ली में इस तरह को कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह साफ हो सके कि प्रदूषण में किस चीज का कितना योगदान है।

नासा की तस्वीरों से साफ है, पराली जलने से ही हुआ दिल्ली में प्रदूषण : सीएम ने कहा कि

अरविंद केजरीवाल। (फाइल)

उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली ने ही उत्तर भारत की हवा को प्रदूषित किया। नासा की तरफ से जारी तस्वीरों से इसकी पुष्टि होती है। इनमें साफ है कि जिस तरह पराली जलने की घटनाएं बढ़ीं, उसी लिहाज से उत्तर भारत की हवा भी प्रदूषित होती चली गई। नासा की तरफ से जारी ताजा तस्वीरों में पराली जलना कुछ कम हुआ है। इसी कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत की हवा में भी प्रदूषण कम हुआ। इसके बाद सीएम ने दिल्ली के साफ आसमान की फोटो ट्वीट कर लिखा कितना सुंदर शहर है हमारा। जरा सोचिए, अगर पराली जलनी बंद हो जाए तो पूरा साल ऐसा ही नीला आसमान नजर आएगा। हमारी सेहत भी सुधर जाएगी। दिल्ली के अपने प्रदूषण को भी हमें और कम करना है।

नौ अक्टूबर तक साफ थी दिल्ली की हवा : सीएम केजरीवाल ने कहा नौ अक्टूबर तक दिल्ली की एयर क्वालिटी संतोषजनक थी। अचानक 10 अक्टूबर से दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब, बेहद खराब और फिर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंडस्ट्री का भी प्रदूषण है, गाड़ियों का भी प्रदूषण है, धूल-मिट्टी का भी प्रदूषण है। इन सारी चीजों का प्रदूषण मिलाकर भी नौ अक्टूबर तक का डाटा दिखाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 से लेकर 130 था। नौ अक्टूबर तक दिल्ली की हवा संतोषजनक स्थिति में थी। अचानक 10 अक्टूबर से एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर पार कर गया। नासा की तस्वीरें दिखाती हैं कि 10 अक्टूबर से ही पराली जलने के लाल धब्बे तस्वीरों में आने शुरू हो गए। इससे साफ है कि वर्तमान प्रदूषण के लिए पराली जलना ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर पड़ोसी राज्य पराली जलाना बंद नहीं कर रहे तो दिल्ली के लोग आखिर क्यों तकलीफ झेलें और कब तक झेलें।

दिल्ली ने अपना प्रदूषण कम करने के लिए सब कुछ किया : सीएम ने कहा दिल्ली ने अपना प्रदूषण कम करने के लिए सब कुछ किया है। ऑड-इवेन स्कीम दिल्ली के लोकल प्रदूषण को कम करती है। दिल्ली में लगभग तीस लाख गाड़ियां प्रतिदिन सड़क पर उतरती हैं। ऑड-इवेन में 15 लाख गाड़ियां सड़क से हट गईं। इससे प्रदूषण में कमी आई।

प्लास्टिक कचरे का निस्तारण न करने पर लगेगा जुर्माना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सिंगल यूज प्लास्टिक और इसके कचरे का सही निपटान नहीं करने वाले संस्थानों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग ने मिलकर नई नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि इसमें अब आम लोगों पर भी जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई है। हालांकि उन पर जुर्माना एक हजार रुपये तक ही लगेगा। दिल्ली सरकार की मंजूरी मिलते ही इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। वहीं कूड़ा जलाते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में रोजाना 690 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसे अक्सर लोग इधर-उधर फेंक देते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत जुर्माने के प्रावधान को अधिसूचित किया जाएगा। अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक के कचरे का सही निस्तारण नहीं होने पर दिल्ली में जुर्माने का उचित प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अब प्लास्टिक कचरे का सही निपटान करना लोगों के लिए अनिवार्य होगा। इसके दायरे में सामाजिक फंक्शन (शादी समारोह व भंडारा आदि) के साथ होटल, रेस्त्रां व सभी व्यावसायिक संस्थान होंगे। इसके तहत अगर आम नागरिक भी प्लास्टिक कचरे के जरिये गंदगी फैलाएगा तो उसे न्यूनतम एक हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा।

भाजपा सरकार बनते ही एक साल में ही खत्म होगा प्रदूषण : गोयल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : ऑड-इवेन का विरोध करने वाले राज्यसभा सदस्य और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने रविवार को जंतर-मंतर पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एलान किया कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से ऑड-इवेन लागू किया तो जनता सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। उन्होंने प्रदूषण के दौरान मास्क बांटने के नाम पर घोटाले के आरोप लगाए और दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक साल के भीतर प्रदूषण को खत्म किया जाएगा। दिल्ली सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि ऑड-इवेन के उल्लंघन पर जुर्माना चार हजार से 500 रुपये करके दिखाएं। फिर पूरी दिल्ली सड़क पर होगी। चार हजार रुपये जुर्माना होने के बावजूद करीब पांच हजार लोगों ने इसका उल्लंघन करके जुर्माना भरा है। प्रदूषण से दिल्ली की जनता को बीमार करने वाले मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। वह तुरंत इस्तीफा दे। केजरीवाल सरकार ने पांच साल तक प्रदूषण के खिलाफ एक भी कार्य नहीं किया।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने ली खुलकर सांस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिवाली के बाद से लगातार हेल्थ इमरजेंसी झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने रविवार को खुलकर सांस ली। हवा ने रफ्तार पकड़ी तो गंभीर से आपातकालीन स्थिति में चल रहा वायु प्रदूषण भी खराब श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक रविवार की हवा पिछले पांच सालों के दौरान सबसे साफ दर्ज की गई। दिवाली के बाद छह नवंबर को ही हवा कुछ हद तक सांस लेने लायक थी। इस दिन एयर इंडेक्स 214 था। एक पखवाड़े से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, नाक और गले में खराश जैसी परेशानी हो रही थी। रविवार को भी दिल्ली का एयर इंडेक्स 215 दर्ज किया गया। शाम चार बजे हवा में पीएम 10 के कणों की संख्या 181 और पीएम 2.5 कणों की संख्या 95 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रही। एनसीआर के शहर भी काफी साफ नजर आए। गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 218, ग्रेटर नोएडा का 202, गुरुग्राम का 136 और नोएडा का 203 रहा।

दरअसल, पिछले दो दिनों से दिल्ली में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही हैं। इसलिए प्रदूषण से लोगों को काफी अधिक राहत मिली है। सफर और मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी तेज हवा चलेगी। इससे सामान्य या खराब स्थिति में ही प्रदूषण रहने के आसार हैं। सफर के अनुसार, इस समय जमीनी सतह पर हवा काफी तेज हैं, जिसकी गति धीरे-धीरे कम होगी। मंगलवार से प्रदूषण का स्तर फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। बुधवार से इसके और अधिक खराब हो जाने की आशंका है।

▸ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, रविवार की हवा पिछले पांच सालों के दौरान सबसे साफ दर्ज की गई

पिछले पांच साल के दौरान 17 नवंबर का एयर इंडेक्स

साल	एयर इंडेक्स
2015	263
2016	374
2017	310
2018	267
2019	215

सफर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पराली जलाने के 214 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि हवा की रफ्तार तेज होने से अभी दिल्ली-एनसीआर पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलबत्ता, सोमवार से पराली का धुआं दो फीसद से बढ़कर नौ फीसद तक हो जाएगा। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद कोयला आधारित उद्योगों के संचालन पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई है। सीपीसीबी की टास्क फोर्स ने पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और बहादुरगढ़ में चलने वाले कोयला आधारित उद्योगों और दिल्ली में चलने वाले वाले गैर पीएनजी उद्योगों को चलाने की अनुमति दे दी है।

जेएनयू शिक्षकों की अपील, आंदोलन खत्म करें छात्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ और कई छात्रों की तरफ से पिछले दो हफ्ते से छात्रावास की फीस बढ़ोतरी और इसके नए नियमों को लागू करने के मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को जेएनयू प्रशासन से जुड़े कुछ शिक्षकों ने प्रेसवार्ता करते हुए छात्रों से आंदोलन खत्म करने के लिए अपील की। छात्र कल्याण डीन प्रो. उमेश कदम ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रावास शुल्क के रूप में लागत खर्च ही लेता है। अभी यह शुल्क लागत के मुकाबले काफी कम था और इसी वजह से हमें शुल्क में वृद्धि करनी पड़ी है। संस्थान की ओर से गरीब तबके के छात्रों लिए राहत दे दी गई है। ऐसे में अब आंदोलनकारी छात्रों को आंदोलन समाप्त कर कक्षाओं में लौट आना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि जेएनयू के अधिकतर छात्रों को कोई न कोई छात्रवृत्ति मिल रही है। ऐसे में उन्हें बढ़ा हुआ शुल्क देने में क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि यह पूरा आंदोलन छात्र संघ को अधिसूचित कराने के लिए है, जो नियमानुसार अभी नहीं हुआ है। प्रोफेसर कदम ने बताया कि जेएनयू की कार्यकारी परिषद (ईसी) ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के छात्रों के लिए राहत की घोषणा की है। जब उनसे पूछा गया कि बीपीएल को किस तरह परिभाषित करेंगे तो उन्होंने कहा कि हर राज्य सरकार बीपीएल परिवारों को कोई न कोई दस्तावेज जारी करती है। हम उसी दस्तावेज को मान्य कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए शुल्क अगले सत्र से लागू होने हैं इसलिए इनमें बातचीत करके बदलाव भी संभव है। प्रेसवार्ता में मौजूद वंदना मिश्रा ने कहा कि मुझे छात्रों ने बंधक बनाया था। वह जबरन अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे। ऐसा करने वालों के खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई करेगा। प्रोफेसर कदम ने कहा कि परिसर में लगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर आपत्तिजनक शब्द लिखने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर सीपीआइ के नेता मुहम्मद सलीम और केके रगेश रविवार को जेएनयू पहुंचे और छात्रों की मांगों का समर्थन किया। केके रगेश केरल से राज्यसभा सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को ससंद में भी उठाया जाएगा।

'छात्रों ने अकादमिक नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने रविवार को कहा कि यदि छात्रों ने अकादमिक नियमों, मानदंडों का पालन नहीं किया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार प्रो. प्रमोद कुमार ने कहा कि छात्रों के एक समूह की ओर से जारी हड़ताल के कारण जेएनयू में अकादमिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने और विश्वविद्यालय में अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना बनाने वाले हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानदंडों और अकादमिक कैलेंडर का पालन करना छात्रों के हित में होगा। जिसके अनुसार, उन्हें 12 दिसंबर से शुरू होने वाली अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। एमफिल, पीएचडी कर रहे छात्रों को संबंधित कार्य, पत्र मूल्यांकन के लिए 31 दिसंबर तक हर हाल में विभागों में जमा करना होगा। इन तिथियों को अकादमिक परिषद (एसी) ने तय किया है। इसलिए इनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। अकादमिक अध्यादेश के क्लॉज-7 के मुताबिक हर एमफिल करने वाले छात्र को अपना 50 फीसद पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

प्रदूषण से निपटने को उत्तरी राज्यों के अधिकारी आज करेंगे मंथन

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली व इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय संबंधित राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक करेगा। पर्यावरण सचिव सीके मिश्रा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर विमर्श के साथ-साथ इस संबंध में पूर्व में उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे जो बेहतर यातायात प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण के लिए यातायात भी बड़ा कारक है। बैठक में दिल्ली के नगर निकायों के आयुक्त तथा फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सहभागिता करेंगे। उल्लेखनीय है कि संसदीय समिति की तरफ से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में शुक्रवार को पर्यावरण मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे थे।

आप ने केंद्रीय मंत्री पासवान पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ संजय सिंह ने कहा, दिल्ली के पानी पर केंद्र के ही दो मंत्रियों में विरोधाभास

▸ जलशक्ति मंत्री ने राजधानी के पानी को यूरोपियन स्टैंडर्ड से अच्छा बताया था

राजधानी के पेयजल पर आई केंद्र सरकार के संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर दूसरे दिन फिर करारा हमला बोला है। आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए दिल्ली के पानी पर केंद्र के ही दो मंत्रियों में विरोधाभास होने की बात कही है। इस बारे में उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्री कहते हैं कि दिल्ली में 20 जगह पानी का सैंपल लिया गया जो जांच में यूरोपियन स्टैंडर्ड से अच्छा पाया गया। उन्होंने टिप्पणी की कि पासवान जी जल वैज्ञानिक कब बने? झूठ क्यों बोल रहे हैं पता नहीं। मंत्री आपस में तय करें कि सच कौन बोल रहा?

इस ट्वीट के साथ संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उस खबर को भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दिल्ली के पानी को यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी अच्छा बताया था। सिंह ने कहा कि दिल्ली को बदनाम करने की मुहिम को कोई भी चला सकता है। लेकिन पानी के सैंपल पर केंद्र के दो कैबिनेट मंत्रियों के बयान

संजय सिंह। (फाइल)

विरोधाभासी होंगे तो इससे लोगों के मन में शंका पैदा होगी। उन्होंने कहा कि बीते दिनों गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि दिल्ली में 20 जगहों से पानी के सैंपल लिए गए, जो यूरोपीय मानकों पर खरे उतरे हैं। अब पहले दोनों मंत्रियों का बताना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। वैसे भी रामविलास पासवान को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने चुनौती दी कि भाजपा शासित राज्यों के शहरों के सैंपल व दिल्ली के पानी के सैंपल की किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवा लें। तब पता चल जाएगा कि किस शहर का पानी खराब है।

इस मसले पर आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने भी केंद्रीय मंत्री पासवान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब उन्हीं की सरकार में जल शक्ति मंत्री पासवान की बात को खारिज कर चुके हैं तो वह बार-बार इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। यह लोगों की समझ में आ रहा है कि पासवान जी इस पर केवल राजनीति कर रहे हैं।

पानी की गुणवत्ता मामले में हर्षवर्धन और केजरीवाल भी कूदे : भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड की जांच में दिल्ली जल बोर्ड के पानी के नमूनों के फेल होने की खबर को रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लिखा कि मुफ्त पानी के नाम पर दिल्ली की जनता को जहर पिला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देश के 20 शहरों के पानी पर हुए सर्वे में दिल्ली का पानी सबसे ज्यादा जहरीला पाया गया। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट कर लिखा कि सर, आप तो डॉक्टर हैं। आप जानते हैं कि यह रिपोर्ट झूठी है। राजनीति से प्रेरित है। आप जैसे व्यक्ति को ऐसी गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

मंदिर का डेढ़ किलो सोना और 50 किलो चांदी बैंक लॉकर से गायब

जासं, नई दिल्ली : सीआर पार्क स्थित काली मंदिर की सोसायटी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराधा शाखा (ईओडब्ल्यू) में मंदिर की नकदी और सोने व चांदी के आभूषणों के बैंक लॉकर से गायब होने की शिकायत दी है। शिकायत में 50 किलो चांदी और एक किलो 400 ग्राम सोने के गायब होने की बात कही गई है। एफआइआर दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मंदिर प्रशासन की तरफ से ईओडब्ल्यू को दी गई शिकायत में कहा गया है कि मंदिर समिति द्वारा की गई आंतरिक जांच में यह बात सामने आई है कि बैंक के लॉकर में सोने और चांदी के साथ रखी गई दान की राशि का एक बड़ा हिस्सा भी गायब है। यह भी कहा गया है कि वर्तमान कमेटी को एक ज्वेलर द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट के अनुसार, मंदिर को दान में मिले आभूषणों के 26 पैकेट और 16 सोने के सिक्कों को उनकी दुकान पर गलवाया गया था। मंदिर समिति ने जब इस सर्टिफिकेट की जांच कराई तो पता लगा कि ज्वेलर ने किसी भी प्रकार के आभूषणों को नहीं गलाया था और न ही कोई सर्टिफिकेट दिया था। ज्वेलर ने मंदिर समिति को यह भी बताया कि उसके पास कमेटी का एक सदस्य एक किलो 400 ग्राम की सोने की ईंट की जांच और वजन कराने के लिए आया था।

बूथ पर नहीं आधार, राजनीतिक दल बढ़ाने में लगे हैं जनाधार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ लोस चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी 13,819 में से 25 फीसद बूथों पर भी बीएलए नियुक्त नहीं कर पाई

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रमुख राजनीतिक दल इन दिनों अपना जनाधार बढ़ाने में लगे हैं और अपनी जीत को लेकर भी बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। जनता के बीच तो पता नहीं, लेकिन बूथों पर किसी दल का आधार 25 फीसद भी नहीं है यानी प्रत्येक राजनीतिक दल ने करीब 75 फीसद बूथों पर एक भी एजेंट नहीं बनाया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (सीईओ) दिल्ली के मुताबिक सभी राजनीतिक दल तीन स्तरों पर अपने प्रतिनिधि (एजेंट) नियुक्त करते हैं। कुछ प्रतिनिधि वे होते हैं, जो प्रदेश स्तर पर सीधे सीईओ कार्यालय से संपर्क में रहते हैं।कुछ जिला स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े रहते हैं। तीसरे स्तर पर वे प्रतिनिधि होते हैं, जो बूथ स्तर पर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें बीएलए कहा जाता है। लेकिन बूथ स्तर पर कमोबेश सभी राजनीतिक दलों की पकड़ बहुत ही कमजोर नजर आती है।

सीईओ कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मई 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कुल 13,819 बूथ बनाए गए थे। लेकिन दिल्ली का एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था, जो 25 फीसद बूथों पर भी अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर पाया हो।

विडंबना यह है कि सीईओ कार्यालय की ओर से सभी दलों को बार-बार रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन दलों की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई।

लोकसभा चुनाव में किस दल ने बनाए कितने बीएलए

दल	बीएलए
कांग्रेस	3,478
भाजपा	3,024
आप	1,881
बसपा	252
एनसीपी	01
सीपीआइ	00
सीपीएम	00
तृणमूल कांग्रेस	00

विधानसभा चुनाव के लिए 69 बूथ किए कम

फरवरी 2020 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीईओ कार्यालय ने लोकसभा चुनाव की तुलना में 69 बूथ कम कर दिए हैं। इस बार 13,819 पर नहीं, बल्कि 13,750 बूथों पर मतदान होगा। बताया जाता है कि सीईओ कार्यालय ने एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1400 से बढ़ाकर 1500 कर दी है। लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान केंद्र भी 189 घटा दिए गए हैं। तब दिल्ली में 2889 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए 2700 बनाए जा रहे हैं।

बीएलए नियुक्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बार-बार पत्र लिखा जाता है, लेकिन फिर भी वे सूची नहीं भेजते। जहां तक बूथ और मतदान केंद्र कम करने का सवाल है तो बहुत सी जगहों पर मतदाताओं की संख्या काफी कम थी, इसीलिए उन्हें अब दूसरे बूथों और मतदान केंद्रों में एडजस्ट कर दिया गया है।

-डा. रणबीर सिंह, सीईओ, दिल्ली

जमीन अधिग्रहण पर किसानों की सहमति नहीं लेगा प्रशासन

जासं, ग्रेटर नोएडा : जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभावित परिवारों का पुनर्वास जेवर बांगर गांव में होगा। जमीन अधिग्रहण पर इस बार किसानों की सहमति नहीं ली जाएगी। किसानों की आपत्ति दर्ज कर उसका निस्तारण होगा और जमीन अधिग्रहण का कार्य आगे बढ़ जाएगा। जमीन अधिग्रहण के लिए अभी इलाके के किसानों पर इसके प्रभाव के आकलन के लिए एसआइए रिपोर्ट तैयरा की जा रही है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए छह गांव दयानतपुर, रन्हेरा, किशोरपुर, रोही, पारोही व बनबारीवास की जमीन अधिगृहीत की गई है। इन गांवों के करीब 37 सौ परिवार ऐसे हैं, जिन्हें एयरपोर्ट के कारण दूसरी जगह बसाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने जेवर बांगर गांव के समीप जमीन चिह्नित की है। परिवारों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन जेवर बांगर गांव में करीब 46 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगा। फिलहाल इस जमीन के प्रभावित किसानों पर अधिग्रहण के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। गौतमबुद्ध विश्व विद्यालय सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट एसआइए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह रिपोर्ट दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद इस रिपोर्ट को शासन को भेजा जाएगा।

आप का चौथा जनसंपर्क अभियान आज से

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को चौथे जनसंपर्क अभियान को शुरू करने की घोषणा की। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आम आदमी पार्टी 18 नवंबर यानी सोमवार से दिल्ली में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। यह अभियान 24 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत दिल्ली में 14 हजार बूथों पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस अभियान में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। इसमें केवल विधायक भाग लेंगे।

गोपाल राय ने बताया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं हैं, वहां पर विधानसभा अध्यक्ष एवं संगठन मंत्री इस कार्य का निर्वहन करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में रोज चार से पांच बूथों पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा व कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुए कार्यों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा कराए गए कार्यों पर चर्चा की जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बूथ कमेटियों का भी गठन किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने 2700 मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की है। ये सभी मंडल प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में हर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे।

24 दिसंबर के बाद प्रत्याशियों पर फैसला लेगी आप : फरवरी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी 24 दिसंबर के बाद प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए आप अपने वर्तमान में विधायकों के कामकाज का आकलन करा रही है। सूत्रों की मानें तो विधायकों के कामकाज का एक सर्वे पूरा कराया जा चुका है। मगर अभी किसी भी सीट पर प्रत्याशी के चयन पर बात नहीं होगी। फरवरी 2015 में हुए चुनाव में आप ने 70 में से 67 सीटों जीती थीं। तीन सीटें भाजपा ने जीती थीं। इसके बाद दो सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें आप की एक सीट और कम हो गई। वहीं पांचवें साल में आप के पांच विधायक बागी हो गए। पार्टी ने कुछ माह पहले दिल्ली विधानसभा में शिकायत कर इनकी सदस्यता रद कराई है। इस लिहाज से अब आप के नौ सीटों पर विधायक नहीं हैं। इस समय आप के 61 विधायक हैं।

आयोजन

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में विदेशी मंडप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, बहरीन, ब्रिटेन आदि देशों के हैं स्टॉल

घर है सजाना तो विदेशी मंडप जरूर जाना

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

39वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में विदेशी मंडप भी दर्शकों की खास पसंद बना हुआ है। हॉल नंबर-10 में लगे इस मंडप में कई देशों के उत्पाद दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। इनमें तुर्की के झूमर और लाइटें तो ईरान का सूखा मेवा दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। थाइलैंड के फूल और कोरिया के स्वास्थ्य उत्पाद भी दर्शकों को भा रहे हैं।

विदेशी मंडप में अबकी बार 19 देशों ने हिस्सेदारी की है। हालांकि अभी मेला आम दर्शकों के लिए नहीं खुला है और केवल व्यापारी दर्शक ही आ रहे हैं। बावजूद इसके तुर्की के स्टॉल पर लाइटिंग एवं झूमर दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। यह झूमर दो हजार से लेकर 50,000 रुपये तक की कीमत में हैं।

इरान की स्टॉल पर आर्टीफिशियल ज्वेलरी महिलाओं और युवतियों को पसंद आ रही है। इनकी रेंज भी महज 500 से पांच हजार तक है। इनमें ईयर रिंग एवं फिंगर रिंग को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अफगान और इरान के सूखे मेवे दर्शक हाथोंहाथ ले रहे हैं। अंजीर के अलावा यहां के अखरोट, पिस्ता, फिग आइ, पिंड खजूर को भी लोग पसंद कर रहे हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए इनके एक किलोग्राम से लेकर 110 ग्राम तक के पैक बनाए गए हैं। बिना खरीदे भी दर्शक इनका स्वाद तो ले ही रहे हैं।

तुर्की की कलपक टोपी भी दर्शकों को खूब लुभा रही है। यह टोपी तुर्की की पहचान है। यहां के स्टाल पर काफी लोग इसे पहने नजर आते हैं। कलपक टोपी पुरुषों के लिए है और इसकी अनेक स्टाइल हैं। इसके अलावा वियतनाम के स्टाल में महिलाओं की लकड़ी से बनी टोपी भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। छतरीनुमा इस टोपी को 300 से 500 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा वियतनाम के स्टाल पर लकड़ी के बने अन्य आइटम भी पसंद किए जा रहे हैं।

चीन की स्टॉलों पर आम जनता के लिए नहीं कुछ खास

व्यापार मेले में दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहने वाले चीन के स्टॉल इस बार निराश कर रहे हैं। इन पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा जो किसी के मन को भा जाए। आलम यह है कि दर्शक इन स्टॉलों पर ज्यादा देर तक ठहर भी नहीं पा रहे। हालांकि चीन की करीब दर्जन भर कंपनियों ने मेले में भाग लिया है, लेकिन अधिक कंपनियां मशीनरी उद्योग से जुड़ी हैं। अगर उत्पादों की बात करें तो एक दो स्टॉल पर वाशिंग मशीन, एयर प्य

1952 से अब तक राज्यसभा की 5466 बैठकें हो चुकी हैं। इस दौरान 3817 बिल पारित किए गए। लोकसभा से पारित 120 विधेयकों में समुचित संशोधन कर वापस किए गए, जबकि पांच विधेयक रिजेक्ट हुए।

बेमिसाल रहा जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल

विदाई ▶ 13 महीने 14 दिन देश के प्रधान न्यायाधीश रहे गोगोई को अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसले के लिए हमेशा याद किया जाएगा

जस्टिस एसए बोबडे प्रधान न्यायाधीश के पद की आज लेंगे शपथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट में लगभग सात साल न्यायाधीश और उसमें से 13 महीने 14 दिन तक देश के प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाले जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल बेमिसाल रहा। अनुशासनप्रिय, सख्त और बेबाक व्यक्तित्व के धनी जस्टिस गोगोई ने कई ऐसे फैसले दिए और काम किए जो उन्हें औरों से अलग और यादगार बनाते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला देकर उन्होंने नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। इसके अलावा न्यायिक आदेश से उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति, असम में एनआरसी लागू करने, सुप्रीम कोर्ट के ही सेवानिवृत न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू को कोर्ट में बुलाने और फिर उन्हें अवमानना नोटिस जारी करने, प्रधान न्यायाधीश के दफ्तर को आरटीआइ के दायरे में लाने जैसे कुछ अहम फैसले भी उनके खाते में आते हैं, जो उन्हें बेमिसाल बनाते हैं।

इसके अलावा वरिष्ठताक्रम में अगले प्रधान न्यायाधीश बनने की पंक्ति में खड़े जस्टिस गोगोई का सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों की तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली ऐतिहासिक प्रेस कांफ्रेंस में शामिल होना भी उन्हें सामान्य से अलग बनाता है। जस्टिस गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद सोमवार को जस्टिस एसए बोबडे प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे।

जस्टिस गोगोई को आम से खास करती कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो पाते हैं कि 16 दिसंबर, 2015 का एक आदेश उन्हें इतिहास में कुछ खास मुकाम पर दर्ज कराता है। इस आदेश से देश में पहली बार किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा था कि सर्वोच्च अदालत के आदेश का पालन करने में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का नाकाम रहना बेहद अफसोसजनक और आश्चर्यचकित करने वाला है।

दूसरी घटना 11 दिसंबर 2016 की है। केरल के चर्चित सौम्या हत्याकांड के फैसले पर ब्लॉग के जरिए टिप्पणी करने पर जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू को तलब कर लिया था। जस्टिस काटजू से सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ बहस हुई थी, बल्कि पीठ ने उन्हें हाथों हाथ अवमानना का नोटिस भी थमा दिया था। इतिहास में यह भी पहली बार हुआ था कि कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हो और उसने बहस की हो।

असम में एनआरसी लागू करने का आदेश भी दूरगामी और ऐतिहासिक था। अयोध्या राम जन्मभूमि मुकदमें में संविधान पीठ की अगुवाई जस्टिस रंजन गोगोई ने ही की थी। इस मामले में पांचों न्यायाधीशों का सर्वसम्मति से फैसला आना किसी उपलब्धि से कम नहीं कहा जा सकता। सरकारी विज्ञापनों में नेताओं के फोटो छापने पर रोक और पवित्र धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण आदि के नाम पर सेवा या सामान के ट्रेडमार्क का दावा न किए जा सकने का चर्चित फैसला भी जस्टिस गोगोई की पीठ ने सुनाया था।

जस्टिस गोगोई ने प्रधान न्यायाधीश बनने के बाद व्यवस्था सुधारने के लिए भी काफी काम किए। मुकदमों को लिस्ट करने की एक व्यवस्था बनाई। सर्वोच्च अदालत देखने की उत्सुक आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के कुछ हिस्से घुमाने की योजना शुरू की।

कई उतार-चढ़ाव भी देखे : जस्टिस गोगोई ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। पूर्व कर्मचारी ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनी और कमेटी ने आरोपों को निराधार घोषित किया लेकिन जांच कमेटी की क्लीनचिट की रिपोर्ट आने तक वक्त जस्टिस गोगोई के लिए बेहद कठिन और चुनौती पूर्ण रहा। हालांकि उन्होंने अपना आत्मबल नहीं डिगने दिया और उसी तत्परता से जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे।

देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश होंगे जस्टिस बोबडे : जस्टिस एसए बोबडे सोमवार को प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। वह देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। वह 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने थे। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाए जाने के अलावा जस्टिस बोबडे ने अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इनमें निजता को मौलिक अधिकार घोषित करना, आधार नहीं होने पर किसी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं करने और प्रदूषण को काबू करने के लिए 2016 में दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाना शामिल है। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल 2021 तक इस पद पर रहेंगे।

सेवानिवृत्ति के दिन भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे

तिरुपति, प्रेट्र : प्रधानमंत्री न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपने सेवानिवृत्ति के दिन रविवार को प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। मंदिर के एक अधिकारी ने बताया कि जस्टिस गोगोई और उनकी पत्नी रूपांजलि गोगोई ने तड़के तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों का मुख्य पुजारी ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। तिरुपति मंदिर में पूजा के बाद जस्टिस गोगोई दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने शनिवार को भी यहां पूजा की थी। इससे पहले शनिवार को ही वह तिरुपति से कुछ दूर तिरुचनूर मार्ग पर स्थित देवी श्री पद्मावती मंदिर में पूजा की थी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट का दिन पूजा-पाठ में बिताया। रविवार को तिरुपति में उन्होंने पत्नी के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। प्रेट्र

निजी डाटा की सुरक्षा पर जल्द बन सकता है कानून

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश में निजी डाटा की सुरक्षा के लिए जल्द कानून बन सकता है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इससे संबंधित विधेयक लाने की तैयारी में है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने हाल में कहा था कि सरकार लोगों के परामर्श के बाद संसद में निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2018 पेश करेगी। सरकार ने पिछले साल विधेयक का मसौदा जारी किया था, जिसका कई वैश्विक कंपनियों ने विरोध किया था। कंपनियों का कहना था कि इससे उनका कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही परिचालन व्यय भी बढ़ेगा। विधेयक का मसौदा जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण द्वारा जुलाई, 2018 में सौंपी गई रिपोर्ट पर आधारित था। विधेयक के अंतिम मसौदे के बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मसौदा विधेयक में लोगों के डाटा का इस्तेमाल उनकी अनुमति से ही करने का प्रावधान किया गया था। साथ ही डाटा संग्रह के लिए देश में ही सरवर रूप स्थापित करने का नियम बनाया गया था।

प्रस्तावित बिल में डाटा सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन पर 15 करोड़ रुपये या कंपनी के कुल टर्नओवर के चार फीसद जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हाल के दिनों में वाट्सएप पर डाटा की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद सरकार और सतर्क हो गई है। इस मामले को लेकर बवाल मचा था। वाट्सएप मामले में रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार निजता को गंभीरता से लेती है और सूचना की गोपनीयता इसी का हिस्सा है।

राज्यसभा के 250वें सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सोमवार से शुरू हो रहा राज्यसभा का शीतकालीन अधिवेशन सदन का 250वां सत्र होगा। राज्यसभा ने इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रखी है। इसमें 250 रुपये का चांदी का सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा।

राज्यसभा सचिवालय की ओर से बताया गया कि 250वें सत्र को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की गई है। सत्र की इस बैठक में 'भारतीय राजनीति में राज्यसभा की भूमिका : सुधार की जरूरत' विषय पर विशेष चर्चा कराई जाएगी।

राज्यसभा के चेयरमैन एम. वेंकैया नायडू ने सदन के 250वें सत्र की शुरुआत की पूर्वसंध्या पर रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा का सफरनामा पुस्तिका का विमोचन किया। 118 पेजों के राज्यसभा का सफरनामा में कुल 29 चैप्टर हैं, जिनमें कई तरह की संसदीय घटनाओं के रोचक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। सामाजिक बदलाव, आर्थिक सुधार, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और 103 संवैधानिक सुधारों को इसमें शामिल किया गया है।

सदन की प्रमुख उपलब्धियों में बताया गया कि 1952 से अब तक राज्यसभा की कुल 5466 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 3817 विधेयक पारित किए गए। इनमें तीन तलाक तथा जीएसटी जैसे प्रमुख बिल भी शामिल हैं। राज्यसभा ने समय-समय पर अपनी ताकत का अहसास भी कराया। इस दौरान राज्यसभा ने लोकसभा से पारित 120 विधेयकों को समुचित संशोधन के लिए वापस किया, जबकि पांच विधेयकों को रिजेक्ट कर दिया। सदन में कुल 2282 सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचे, जिनमें 208 महिलाएं और 137 नामित होने वाले सदस्य भी शामिल हैं। संसद के इस उच्च सदन में 1952 में जहां 15 महिला सदस्य पहुंचीं, वहीं 2014 में यह संख्या बढ़कर 31 हो गई।

सबसे अधिक सात बार डॉ. महेंद्र प्रसाद पहुंचे सदन : राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इस सदन में सबसे अधिक सात बार डॉ. महेंद्र प्रसाद पहुंचे, जबकि डॉ. मनमोहन सिंह छह बार निर्वाचित होकर सदन में पहुंचे। डॉ. नजमा हेपतुल्ला और राम जेठमलानी समेत दो अन्य नेता छह बार पहुंचे। गुलाम नबी आजाद, एके एंटनी, अहमद पटेल व अंबिका सोनी पांच-पांच बार चुनकर सदन में पहुंचे। प्रणब मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, सीताराम केसरी, सरोज खापर्डे, बीवी अब्दुल्ला समेत कुल 11 सदस्यों को पांच बार सदन पहुंचने का मौका मिला। वर्तमान चेयरमैन वेंकैया नायडू समेत 45 सदस्यों को चार-चार बार सदन पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ।

जब पीठासीन अधिकारी ने विपक्ष के पक्ष में दिया वोट : राज्यसभा के 67 साल के इतिहास में अब तक एक ही मौका आया है जब सदन के पीठासीन अधिकारी को किसी प्रस्ताव पर मतदान करना पड़ा हो। यह वाकया पांच अगस्त 1991 का है, जब दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश को खारिज करने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर हुए मतदान में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बराबर वोट पड़ने के कारण राज्यसभा के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के रूप में एमए बेबी को मतदान करना पड़ा। प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के कारण सदन में विपक्ष की जीत हुई। पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्तापक्ष के विरोध में मत देने की भी यह पहली घटना है।

तीन सदस्यों के निष्कासन की अब तक की गई कार्रवाई : दिलचस्प है कि राज्यसभा के तीन सदस्यों के निष्कासन की अब तक कार्रवाई की गई। पहली बार उच्च सदन ने 1976 में सुब्रह्मण्यम स्वामी को सदन की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं करने के मामले में निष्कासित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसके बाद 2005 में डा. छत्रपाल सिंह को पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप में और 2006 में साक्षी महाराज को सांसद निधि योजना में अनियमितता के आरोप में निष्कासित किया गया था।

संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, मंत्री थावरचंद गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित अन्य नेता मौजूद रहे। संजय

सदस्यों की गैरहाजिरी पर नायडू ने जताई चिंता

सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक में राज्यसभा चेयरमैन एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि संसदीय समितियों की बैठक में सदन के सदस्यों की उपस्थिति से बेहतर नतीजे निकलते हैं। शहरी विकास मंत्रालय की 28 सदस्यीय स्थायी समिति की बैठक में मात्र चार सांसदों के मौजूद रहने से उठे विवाद के बाद नायडू ने यह टिप्पणी की। नायडू ने कहा, हमें अपने उच्च संसदीय मानकों को नीचे नहीं आने देना चाहिए। राज्यसभा के 67 सालों के लंबे सफर में सदन ने उच्च मानक बनाए हैं। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को संसद के सेंट्रल हाल में संविधान को अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है।

आंकड़े छिपाने के आरोपों पर चिदंबरम ने सरकार को घेरा

- कहा, यह सूचना का अधिकार है, जिसका सरकार पालन करती है
- चार दशक में पहली बार उपभोक्ता खर्च में गिरावट आने का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : उपभोक्ता खर्च पर आंकड़े दबाने के आरोपों के मद्देनजर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सूचना का अधिकार है, जिसका सरकार पालन करती है। भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामलों में जेल में बंद चिदंबरम ने हिंदी में ट्वीट किया, 'पिछले साल रोजगार पर आंकड़े छिपाए गए। अब उपभोक्ता खर्च पर आंकड़ों को दबाया जा रहा है। यह सूचना का अधिकार है जिसे सरकार निभाती है।'

चिदंबरम का यह बयान उस खबर के बाद आया है, जिसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि 2017-18 में चार दशक से अधिक समय में पहली बार उपभोक्ता खर्च में गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह ग्रामीण क्षेत्र में कम होती मांग है। खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट इस साल 19 जून को जारी करने के लिए स्वीकृति दी गई थी, लेकिन सरकारी एजेंसी ने प्रतिकूल आंकड़ों के कारण इसे रोक लिया।

आतिश तासीर और आकार पटेल के समर्थन में उतरे

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने एक अन्य ट्वीट में पत्रकार आतिश तासीर तथा एमनेस्टी इंडिया के प्रमुख आकार पटेल से लड़ाई से हाथ पीछे नहीं खींचने को भी कहा। चिदंबरम की ओर से उनके परिवार ने ट्वीट किया, 'आतिश तासीर और आकार पटेल निश्चिंत रहें। धमकाने में न आएं, लड़ाई नहीं छोड़ें।' गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ब्रिटिश लेखक तासीर का ओसीआइ कार्ड निरस्त करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने पिता के पाकिस्तानी होने के तथ्य को छिपाया। आलोचकों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि टाइम पत्रिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले लेख के लिए तासीर को निशाना बनाया जा रहा है। सीबीआइ ने शुक्रवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और उसके तीन सहयोगी संगठनों के खिलाफ 36 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे से संबंधित मामले में कानून के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया था।

चिदंबरम की जमानत पर फैसले में कोर्ट ने किया था दूसरे मामले का उल्लेख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और अपने एक अन्य फैसले का उल्लेख किया है, जिसका इस केस से कोई संबंध नहीं है। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने अपने फैसले में वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली निवासी अधिवक्ता रोहित टंडन की मनी लांड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने का भी जिक्र किया। फैसले में दिए गए एक उदाहरण में लिखा है कि यह आरोप लगाया गया है कि 15 से 19 नवंबर 2016 की अवधि के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक में आठ बैंक खातों में 31.75 करोड़ की बड़ी नकदी जमा की गई थी। पीठ ने इसके साथ ही रोहित टंडन के मनी लांड्रिंग मामले में वर्ष 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ही दिए गए पूर्व फैसले का हवाला दिया।

इसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि मनी लांड्रिंग के मामले में विशेष अदालतों द्वारा परीक्षण का प्रावधान है। मनी लांड्रिंग के तहत धारा-44 में संयुक्त परीक्षण की संभावना तभी होती है जब जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया जाए और मामला विशेष न्यायालय के लिए संबद्ध हो।

शिवसेना के अलगाव का असर, राजग में उठी संयोजक की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को राजग के घटक दलों की बैठक में शिवसेना के अलग होने का असर दिखा। लोजपा प्रमुख एवं सांसद चिराग पासवान समेत कुछ सहयोगी दलों ने गठबंधन में एक संयोजक की जरूरत जताई।

राजग की बैठक के बाद चिराग ने कहा, 'आज बैठक में मुझे व्यक्तिगत रूप से शिवसेना की कमी महसूस हुई। वह राजग के सबसे पुराने सहयोगी दलों में से थी। भाजपा-शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में जो हुआ, वह टाला जा सकता था।' चिराग ने कहा कि यह चिंता की बात है कि पहले तेलुगु देसम पार्टी अलग हुई, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अलग हो गई। सहयोगी दलों के बीच बेहतर समझ के लिए एक संयोजक होना चाहिए या समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए।

हालांकि चिराग ने आगामी संसद सत्र में राजग के सभी घटक दलों की ओर से मिलकर काम करने की बात कही। सूत्रों के अनुसार अपना दल, जदयू और पूर्वोत्तर के कुछ सहयोगी दलों ने भी राजग में संयोजक नियुक्त किए जाने का सुझाव दिया है।

छोटे मतभेदों से अशांत नहीं होना चाहिए : मोदी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग के घटक दलों की बैठक ली। उन्होंने सहयोगी दलों को परिवार की संज्ञा देते हुए छोटे-छोटे मतभेदों से प्रभावित नहीं होने को कहा। उन्होंने कहा, 'राजग सहयोगियों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक बड़ा परिवार हैं। छोटे मतभेदों से अशांत नहीं होना चाहिए।' बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट किया, 'राजग की बैठक बहुत अच्छी रही। हमारा गठबंधन भारत की विविधता और 130 करोड़ भारतीयों की अकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हम मिलकर अपने किसानों, युवाओं, नारी शक्ति एवं निर्धनतम व्यक्ति के जीवन में बदलाव की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।' बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया और शीतकालीन सत्र में बेहतर प्रबंधन व समन्वय की अपील की।

गृह मंत्री ने लद्दाख को दी विशेष विंटर ग्रेड डीजल की सौगात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- माइनस 33 डिग्री सेल्सियस पर भी लद्दाख में काम करेगा विशेष डीजल
- बर्फीले मौसम में दौड़ेंगी गाड़ियां, पर्यटन को बढ़ावा देने में बड़ा कदम

अब बर्फीले तूफानों के बीच भी लद्दाख क्षेत्र में डीजल की गाड़ियां दौड़ सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख क्षेत्र के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल उपलब्ध कराने की योजना को हरी झंडी दिखाई। इंडियन ऑयल की पानीपत की रिफाइनरी में तैयार यह डीजल माइनस 33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नहीं जमता है। दरअसल, लद्दाख में तापमान की गिरावट के साथ सर्दियों में सामान्य डीजल जम जाता है। इससे गाड़ियां चलाने में परेशानी होती है। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।

इस अवसर पर अमित शाह ने लद्दाख के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना लद्दाख के लिए सही कदम है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही लद्दाख के लोगों की सालों से लंबित मांग और आकांक्षाएं पूरी होने लगी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के समुचित विकास के लिए 50 हजार करोड़ की लागत से बिजली, सौर ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन की योजनाओं को पूरा कर रही है। इसके तहत लद्दाख में 7,500 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है और नौ मेगावाट की पनबिजली परियोजना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही बजट में लद्दाख के लिए निर्धारित बजट राशि को खर्च करने की अवधि की अनिवार्यता को भी समाप्त किया है।

वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल की मानवीय आवश्यकता और सेवा पर आधारित इस पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख में विंटर ग्रेड डीजल की निर्बाध आपूर्ति संभव होगी। परिवहन अगर बिना रुकावट सुचारु रूप से चलता रहेगा तो वहां लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

गौरतलब है कि विशेष विंटर ग्रेड डीजल में लगभग पांच प्रतिशत बायोडीजल का मिश्रण भी किया गया है। यह डीजल वाहन के लिए बेहतर रहेगा। साथ ही इसके जम जाने की समस्या से निजात मिलेगी। यह डीजल बीआइएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के मानकों पर भी खरा है।

गृहमंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए विशेष विंटरग्रेड डीजल लांच किया। साथ में हैं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बाएं)। जागरण

यूजीसी ने रैगिंग पर अंकुश के लिए राज्यों को भी दी जिम्मेदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मुख्य सचिवों, उच्च शिक्षा सचिवों को लिखी चिट्ठी, रैगिंग मुक्त राज्य बनाने का आह्वान
- रैगिंग की घटनाओं को थमता न देख उठाया कदम, इस वर्ष दर्ज हो चुके हैं 950 मामले

सख्ती के बावजूद रैगिंग की घटनाएं थमती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में यूजीसी ने रैगिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। पहली बार राज्यों के मुख्य सचिवों व उच्च शिक्षा सचिवों को चिट्ठी लिखकर यूजीसी ने प्रदेश को रैगिंग मुक्त बनाने और नियम तोड़ने वालों से सख्ती से पेश आने को कहा है। यूजीसी की यह मुहिम अब तक विश्वविद्यालयों और दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों तक ही सीमित थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राज्यों को पत्र यूं ही नहीं लिखा है, बल्कि रैगिंग की बढ़ती घटनाएं इसके पीछे बड़ी वजह हैं। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक रैगिंग के करीब 950 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि वर्ष 2018 में करीब 1010 मामले दर्ज हुए थे। जिस रफ्तार से रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं, आशंका है कि इस साल पिछले साल का आंकड़ा पार हो सकता है। स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि वर्ष 2016 से रैगिंग के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं। वर्ष 2016 में जहां रैगिंग के कुल 515 मामले सामने आए थे, वहीं वर्ष 2017 में ये बढ़कर 901 हो गए। ऐसी घटनाएं तब सामने आ रही हैं, जब रैगिंग को लेकर सख्त कानून मौजूद है। दोषी छात्रों को जेल और जुर्माने तक का प्रावधान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अब तक रैगिंग की घटनाओं को लेकर सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थानों पर ही जवाबदेही आती थी, लेकिन अब राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि कुछ राज्यों में यह बुराई ज्यादा व्यापक है।

उत्तर प्रदेश में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले रैगिंग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। वहां वर्ष 2018 में 180 मामले सामने आए। दूसरे स्थान पर बंगाल रहा, जहां रैगिंग की 119 शिकायतें दर्ज हुईं। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा, जहां 104 शिकायतें सामने आईं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

प्रस्ताव खारिज

आयुष्मान भारत में महंगा इलाज नहीं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) का प्रस्ताव ठुकराया स्वीकृति नहीं देने की वजह राष्ट्रीय आरोग्य निधि से अलग मापदंड

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'आयुष्मान भारत' के लाभार्थियों को महंगे इलाज वाली जानलेवा बीमारियों के लिए 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' के तहत इलाज कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि ऐसे गंभीर रोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की पांच लाख की सीमा को बढ़ाकर उन्हें इलाज की सुविधा देने पर विचार अवश्य किया जा सकता है।

एम्स और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने मंत्रालय से अपील की थी कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को ब्लड कैंसर और लीवर की गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती है। चूंकि इन बीमारियों को इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाइ) की सीईओ इंदु भूषण को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में एम्स और एनएचए के सुझावों को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, चूंकि इन दोनों योजनाओं का मापदंड अलग है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत वित्तीय सहायता का आधार राज्य में समय-समय पर निर्धारित गरीबी की रेखा है। जबकि पीएमजेएवाई के तहत इलाज की सुविधा उन्हीं लोगों को मिलती है जो एसईसीसी के डाटाबेस 2011 में वंचितों के आधार पर उपयुक्त हों। मंत्रालय ने कहा कि उनका ध्यान ऐसे मामलों की ओर आकृष्ट किया गया जिसमें पीएमजेएवाई के तहत ब्लड कैंसर और लीवर की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज करने से इन्कार कर दिया गया।

चूंकि इस योजना के तहत दिए जाने वाले 1350 मेडिकल पैकेज में इन बीमारियों का उल्लेख नहीं है। लेकिन यह मरीज आरएएन योजना के तहत भी इलाज का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि पीएमजेएवाई में फंडिंग का पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का है जबकि आरएएन योजना के तहत सौ फीसद धनराशि केंद्र सरकार ही देती है। आरएएन योजना एक आम स्वास्थ्य योजना नहीं है जो सभी मरीजों का इलाज कर सके। इस स्वास्थ्य योजना के तहत पांच लाख रुपये से अधिक के इलाज वाले मरीज ही आते हैं।

गरीबों को मुफ्त इलाज की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। फाइल फोटो

निर्भया के स्वजनों की याचिका पर 25 को सुनवाई

जासं, नई दिल्ली : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों को जल्दी फांसी देने के लिए मामला दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार कर ली है। इस पर सुनवाई 25 नवंबर को होगी। पीड़िता के माता-पिता ने अपनी याचिका में अदालत से दोषियों को फांसी देने के आदेश पर तिहाड़ जेल प्रशासन को अमल करने का निर्देश देने की मांग की है।

27 प्रतिशत आदिवासियों की आबादी है झारखंड में। भाजपा का दावा है कि उसने 521 आदिवासी सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की, 424 करोड़ रुपये की लागत से 11 हजार से अधिक टोलों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 18 नवंबर 2019

बागी हुए सरयू राय, सीएम के खिलाफ ठाकेंगे ताल

आमने-सामने ▸ जमशेदपुर पूर्वी सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं रघुवर दास

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

भाजपा ने राय की पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी से देवेंद्र सिंह को उतारा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर

सरयू राय फाइल फोटो

रघुवर दास फाइल फोटो

भाजपा की टिकटों की घोषणा में वेटिंग में रखे गए झारखंड के खाद्य व आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अब पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। रविवार को जहां उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने का एलान कर दिया, वहीं मंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया।

झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की चौथी सूची में भी अपना नाम नहीं रहने के बाद सरयू ने एक दिन पहले ही को दो टूक एलान कर दिया था कि अब उन्हें भाजपा का टिकट नहीं चाहिए। इसके बाद रविवार को बिष्टुपुर स्थित अपने आवास पर सरयू ने भाजपा कार्यकर्ताओं-समर्थकों के साथ विचार-विमर्श किया। इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों के समक्ष जमशेदपुर पूर्वी से भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। रविवार को पहले उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन देर शाम इसमें सुधार करते हुए केवल पूर्वी सीट से ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी।

हालांकि सरयू राय ने अभी तक भाजपा से इस्तीफा नहीं दिया है। उधर तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच भाजपा ने भी सरयू राय की पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिमी से देवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सोमवार को इस सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख है। सरयू ने यह भी कहा कि भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अभी भी भाजपा की नीतियों पर ही चल रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा, 'यह मेरा आखिरी चुनाव है, केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया था। अब भाजपा को निर्णय लेना है कि वह मुझे पार्टी में रखना चाहती है या नहीं।'

झारखंड में बिहार के चारा घोटाले से ज्यादा भ्रष्टाचार : सरयू राय ने कहा, 'भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना मेरे स्वभाव में है। मैं आजीवन प्रदूषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा।' उन्होंने आगे कहा कि यहां लालू यादव के चारा घोटाले से हजार गुना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तक उनके सामने झारखंड में भ्रष्टाचार के जो मामले आए हैं, उसमें पांच फीसद ही उजागर हुए हैं। 95 फीसद मामले आने बाकी हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने सरकार को कई बार चेताया कि ये रास्ते मधु कोड़ा के पास ले जाने वाले हैं, फिर भी कोई नहीं चेता। गलतियों को ढंकने-छिपाने से ही भ्रष्टाचार फलता-फूलता है।'

सोनिया ने मांगे संगठन के कार्यों में हिस्सा न लेने वाले नेताओं के नाम

कैलाश नाथ, चंडीगढ़ : केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पांच से 25 नवंबर तक देशभर में दिए जा रहे धरने को लेकर पार्टी सख्त हो गई है। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा शनिवार को दिल्ली में ली गई बैठक में यह बात सामने आई कि कई नेता संगठन या सरकार में पद तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाद में पार्टी के कार्यों में हिस्सा नहीं लेते। सोनिया ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे नेताओं की सूची बनाकर उन्हें भेजें। उनके सख्त रुख से पार्टी के अंदर खलबली पैदा हो गई है। इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि धरने से गायब रहे विधायकों की परेशानी बढ़ सकती है।

पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने 15 नवंबर को दिए गए धरने को लेकर जिला प्रधानों से रिपोर्ट मांगने की तैयारी कर ली है। जिला प्रधानों को अपनी रिपोर्ट में ये भी बताना पड़ेगा कि धरने में कितने नेता, कौन सा विधायक व वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। धरने की फोटो भी भेजनी होगी। प्रदेश कांग्रेस को यह रिपोर्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजनी है।

देश के ज्यादातर राज्यों में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हाथों लगातार मिल रही हार को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने संगठन पर जोर देना शुरू किया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के खिलाफ देशभर में दिए जा रहे धरने की गंभीरता से निगरानी की जा रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि धरनों की रिपोर्ट के साथ प्रमाणिकता साबित करने के लिए फोटो भी मांगी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने 30 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के धरने की घोषणा कर दी है। यह फैसला शनिवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

बालासाहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर फड़नवीस के विरुद्ध हुई नारेबाजी

राज्य ब्यूरो, मुंबई

▸ शिवसेना के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री

▸ शिवसैनिकों ने 'मी पुन्हा येईन' कहकर चिढ़ाने का प्रयास किया

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने रविवार को मुंबई में शिवसेना के संस्थापक बालासाहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेट्र

महाराष्ट्र में शिवसेना, भाजपा के बीच पैदा हुई कड़वाहट शिवसेना संस्थापक दिवंगत बालासाहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर भी दिखाई दी। ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को शिवसैनिकों की नारेबाजी का सामना करना पड़ा।

रविवार को बालासाहब ठाकरे की सातवीं पुण्यतिथि थी। देवेंद्र फड़नवीस मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित ठाकरे स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उन्होंने स्मृति स्थल के चबूतरे के पास पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और अपने वाहन की ओर बढ़ने लगे। तभी वहां बड़ी संख्या में मौजूद शिवसैनिकों ने 'मी पुन्हा येईन', 'मी पुन्हा येईन' के नारे लगाने शुरू कर दिए। बता दें कि देवेंद्र फड़नवीस ने चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाओं में कहा था कि मी पुन्हा येईन (मैं पुनः आऊंगा), लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वह अब तक अपनी सरकार नहीं बना सके हैं। शिवसैनिक उनकी उसी बात को दोहरा कर उन्हें चिढ़ाने का प्रयास करते दिखाई दिए, लेकिन फड़नवीस उन्हें कोई उत्तर दिए बगैर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। फड़नवीस ने आज सुबह ट्वीटर पर भी बालासाहब ठाकरे को याद करते हुए कहा था कि हमने स्वाभिमान और हिंदुत्व के प्रति सम्मान ठाकरे से सीखा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे आदि भाजपा नेता भी बालासाहब ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके स्मृति स्थल पर पहुंचे।

अन्य वर्षों के विपरीत इस बार बालासाहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने करीब-करीब सभी दलों के नेता पहुंचे। इसकी शुरुआत सुबह राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल एवं छगन भुजबल से हुई। ठाकरे को श्रद्धांजलि देते हुए भुजबल की आंखें नम हो गईं। भुजबल ने अपनी राजनीति की शुरुआत शिवसैनिक के रूप में ही की थी, लेकिन 1990 में पार्टी के 17 विधायक अपने साथ लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1999 में कांग्रेस का विभाजन होने के बाद से शरद पवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि, दोनों पुत्र आदित्य एवं तेजस ने भी स्मृति स्थल पहुंचकर शिवसेना संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही में भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना रविवार को ही ठाकरे स्मृति स्थल पर अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाकर बालासाहब ठाकरे का सपना पूरा करने की योजना बना रही थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस-राकांपा के साथ सरकार बनाने पर फैसला न हो पाने के कारण ऐसा नहीं हो सका।

बीरेंद्र सिंह का राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर, करेंगे प्रदेश की राजनीति

कर्मपाल गिल, जींद

पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उचाना से पत्नी प्रेमलता की करारी हार के बाद बीरेंद्र सिंह ने उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को इस्तीफा सौंपा था। हालांकि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भी बेटे को टिकट दिलाने के लिए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को अपना इस्तीफा सौंपा था। बता दें कि बीरेंद्र सिंह का पौने तीन साल का कार्यकाल बाकी था। उनके परिवार में अब सिर्फ उनका बेटा बृजेंद्र सिंह लोकसभा सदस्य रह गया है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी प्रेमलता को उचाना से दोबारा टिकट देने पर काफी बवाल हुआ था। तब कई सांसदों व अन्य नेताओं ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही परिवार से तीन सदस्य विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में कैसे हो सकते हैं। विरोध के बावजूद प्रेमलता को सीटिंग एमएलए होने के कारण टिकट दे दिया गया था, मगर उन्हें जजपा प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने 47,452 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा के बड़े जाट चेहरे कैप्टन अभिमन्यु, ओमप्रकाश धनखड़, सुभाष बराला को हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए बीरेंद्र सिंह राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे। रविवार को उचाना में कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए उन्होंने इसका एलान भी कर दिया।

कार्यकर्ता बोले, सीएम के बयान के कारण हारे

बीरेंद्र ने जब हार के कारणों के बारे में पूछा तो कार्यकर्ताओं ने सीएम मनोहर लाल द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा में बयान और यात्रा के दौरान गुटबाजी व मेरिट पर नौकरी लगने सहित कई कारण बताए। बीरेंद्र ने कहा कि चुनाव में भ्रामक प्रचार किया कि हमारे परिवार के तीन सदस्य राजनीति में हैं, लेकिन जो यहां से विधायक (दुष्यंत का नाम लिए बिना) चुना गया है, उनके परिवार के तो पांच लोग विधायक बने हैं।

बेटियों को घर से कॉलेज तक यातायात के साधन मुहैया कराएगी हरियाणा सरकार

कृष्ण वशिष्ठ, बहादुरगढ़

▸ उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के कॉलेजों और यातायात अधिकारियों को दिए रूट चार्ट बनाने के निर्देश

▸ प्रदेश के 155 सरकारी कॉलेजों में पढ़ती हैं 1 लाख 10 हजार 141 बेटियां

हरियाणा की बेटियां अब बीच में ही अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। वे 12वीं के बाद कॉलेजों में उच्च शिक्षा भी आसानी से हासिल कर सकेंगी। यातायात के साधनों की समस्या अब उनके रास्ते में आड़े नहीं आएगी। सरकार ने बेटियों को घर से कॉलेज लाने व छोड़ने के लिए यातायात के साधन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुहैया कराई जाएगी। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी कालेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर अपने जिलों के यातायात अधिकारियों के साथ मिलकर रूट चार्ट निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। रूट चार्ट निर्धारित होते ही सरकार की ओर से लड़कियों को कॉलेज तक के लिए यातायात के साधन मुहैया करा दिए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश के 173 रूटों पर 181 महिला बसें चलाई जा रही हैं।

प्रदेश में 155 सरकारी कॉलेज हैं। इन कालेजों में एक लाख 10 हजार 141 छात्राएं पढ़ती हैं। विभाग ने जिला वाइज, कॉलेज वाइज गांवों व कस्बों से सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वालीं छात्राओं की संख्या के अनुसार लिस्ट भेजकर रूट चार्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद यह है कि हर लड़की के लिए घर से कॉलेज तक का सफर पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा के अनुपात में सुधार लाया जा सके।

> विभाग का पत्र हमें मिल गया है। लड़कियों की संख्या व उनके गांवों के हिसाब से रूट चार्ट तैयार करवाया जा रहा है। जल्द ही इसे फाइनल करके सूची विभाग मुख्यालय में भेज दी जाएगी। यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है।
> **– जगपाल कौशिक, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बहादुरगढ़**

> सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को घर से कॉलेज लाने व छोड़ने के लिए यातायात के साधन मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में कॉलेज प्रबंधन व यातायात विभाग के अधिकारियों को रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रूट चार्ट बनते ही लड़कियों को यह सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल इन रूटों पर रोडवेज की बसें ही चलाने का निर्णय लिया गया है।
> **–हेमंत वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर कॉर्डिनेशन, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा**

पहली बार पार्टी में मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे पासवान

राज्य ब्यूरो, पटना

28 नवंबर को पटना में लोजपा के स्थापना दिवस पर होगी खास चर्चा

रामविलास पासवान फाइल

इस महीने की 28 तारीख को पटना के बापू सभागार में लोजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में रामविलास पासवान पहली बार मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। इस मौके पर लोजपा युवाओं को आकर्षित करने की रणनीति को विशेष अंदाज में सार्वजनिक करेगी।

यह पहला मौका होगा जब लोजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। वह कहते हैं कि पार्टी अब 19 वर्ष पुरानी हो गई है। कहिए तो युवा हो गई है। इसलिए जरूरी है कि पार्टी चलाने का जिम्मा युवाओं को दे दिया जाए। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यह पहला स्थापना दिवस समारोह होगा। इधर, लोजपा ने तय किया है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग के गठन के मसले को फिर से उभार देगी। वहीं, जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा का मसला भी युवाओं को ध्यान में रख पार्टी की स्थापना दिवस में फिर से उठाया जाएगा।

14 अप्रैल को गांधी मैदान में बड़ी रैली का हो सकता है एलान : पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के तुरंत बाद लोजपा बिहार में अगले वर्ष होने वाले चुनाव की तैयारियों पर फोकस करेगी। इस क्रम में स्थापना दिवस के दिन लोजपा पटना के गांधी मैदान में 14 अप्रैल को बड़ी रैली का भी एलान कर सकती है। स्थापना दिवस के अगले ही दिन से पार्टी अपना सदस्यता अभियान भी आरंभ करेगी। सदस्यता अभियान की सक्रियता को आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारी का आधार भी माना जाएगा।

उत्तराखंड में कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान योजना का हल जल्द

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को भी अटल आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के लिए उत्तराखंड सरकार अब कवायद तेज करने जा रही है। इस कड़ी में शासन अब एक बार फिर विभागीय अधिकारियों से मंथन करने के बाद कर्मचारी संगठनों से वार्ता करेगा। मकसद यह है कि सबकी सहमति से इस योजना को धरातल पर उतारा जा सके।

उत्तराखंड सरकार ने बीते वर्ष आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के उद्देश्य से अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया गया। सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए जो योजना प्रस्तावित की गई उसमें इलाज के खर्च को असीमित रखा गया। इसके लिए लाभ लेने वाले कार्मिक के पद के हिसाब से अंशदान लिए जाने का प्रावधान किया गया। प्रदेशवासियों के लिए योजना तो बीते वर्ष ही शुरू कर दी गई थी।

संजीव चतुर्वेदी ने लोकपाल में नियुक्ति का किया अनुरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई का हवाला देते हुए व्हिसलब्लोअर नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी ने खुद को लोकपाल में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने का अनुरोध किया है। दिल्ली स्थित एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी के तौर पर अपने कार्यकाल में खबरों में रहे संजीव ने लोकपाल को पत्र लिखकर उनकी जांच शाखा में सेवा के लिए नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। संजीव 2002 बैच के भारतीय वनसेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के मार्फत लिखे पत्र में कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मानित परिवार से आता हूं। मैंने कई तरह की परेशानियों के बावजूद पूरी प्रतिबद्धता से सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के ताकतवर एवं ऊंचे पदों पर आसीन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है।

संजीव इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन संरक्षक (अनुसंधान) के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए 2015 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संजीव ने अपने पत्र में उन कुछ मामलों का जिक्र किया है, जिनकी उन्होंने एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी और हरियाणा में तैनाती के दौरान जांच की थी। हरियाणा में उनके कार्यकाल के दौरान 2008 से 2014 के बीच उनके पक्ष में राष्ट्रपति के चार आदेश पारित किए गए थे। भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने के लिए उन्हें परेशान किया गया। इसके बाद अगस्त 2015 में उन्हें हरियाणा से उत्तराखंड कैडर में भेज दिया गया था। उन्होंने एम्स में भ्रष्टाचार के करीब 200 मामलों की जांच की थी।

संजीव चतुर्वेदी फाइल फोटो

जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद राजनीति से ले लूंगा संन्यास : गिरिराज

जेएनएन, पूर्णिया

▸ कहा, बिहार-बंगाल में भी एनआरसी की जरूरत, बड़ी संख्या में हुई है घुसपैठ

गिरिराज सिंह फाइल

भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना उनकी अंतिम राजनीतिक इच्छा है। यह कानून लागू होते ही वह राजनीति को अलविदा कह देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार और बंगाल में भी एनआरसी की जरूरत है। इन दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। गिरिराज सिंह कार्यक्रमों में शामिल होने पूर्णिया और कटिहार आए थे।

पत्रकारों से बातचीत में पूर्णिया में उन्होंने कहा कि पूरे देश में ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की जरूरत है। उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी वकालत की। कहा, पड़ोसी देश चीन जनसंख्या नियंत्रण कानून के कारण ही विकास की ऊंची दर प्राप्त कर सका है। भारत में जनसंख्या विस्तार के आंकड़े विस्फोटक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि 2050 तक जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि अन्न-जल संकट और अन्य परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर पर एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वह देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जबकि अयोध्या मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से वहां विकास का द्वार खुला है। गुलाम कश्मीर के बिना कश्मीर अधूरा है। जब गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा, तभी संपूर्ण भारत का सपना पूरा होगा। यद्यपि उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत विचार बताया।

राहुल को माफी मांगनी चाहिए : उन्होंने कहा कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है। राहुल को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। राम मंदिर, गोमाता के संरक्षण एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए वे राजनीति में आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना सरदार पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद से की। कहा, दोनों की जोड़ी ने वैश्विक पटल पर भारत को नई पहचान दी है।

बिहार में विपक्षी दलों को एकजुट रखना रालोसपा की नई चुनौती

एसए शाद, पटना : बिहार में विपक्षी दलों को एकजुट रखना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के लिए नई चुनौती बनती जा रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद महागठबंधन में शामिल दलों के कुछ नेताओं के व्यक्तिगत बयानों ने आपसी तालमेल को प्रभावित करना आरंभ कर दिया, मगर डॉ. लोहिया की पुण्यतिथि और फिर पिछले दिनों केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ संयुक्त आक्रोश मार्च में विपक्षी दलों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। इन दोनों ही कार्यक्रमों में रालोसपा ने समन्वयक की भूमिका निभाई।

सूत्रों ने बताया कि सितंबर माह में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रांची जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में ही लालू प्रसाद ने उन्हें डॉ. लोहिया की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में समन्वयक की भूमिका निभाने कहा था। डॉ. लोहिया के घोर कांग्रेस विरोधी रहने के बावजूद 12 अक्टूबर को बापू सभागार में आयोजित महागठबंधन के इस कार्यक्रम में कांग्रेस शामिल हुई। कार्यक्रम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अन्य दलों के नेताओं को साथ लेकर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन भी किया था। फिर 13 नवंबर को महागठबंधन ने केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी की असहमति, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नाराजगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुप्पी के बावजूद महागठबंधन के सभी दल आक्रोश मार्च में शरीक हुए। मांझी को मनाने खुद उपेंद्र कुशवाहा उनके आवास पर एक दिन पूर्व गए थे। मांझी अपने सहयोगियों के साथ आक्रोश मार्च में शामिल हुए थे। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में दो वाम दलों-भाकपा और माकपा, के नेताओं ने भी शिरकत की थी।

नया सफर

21 नवंबर को दिल्ली में होगी शादी, 23 और 25 को प्रीतिभोज, शादी समारोह में मौजूद रहेंगे केवल दोनों परिवारों के सदस्य

पंजाब के विधायक संग सात फेरे लेंगी अदिति सिंह

जागरण संवाददाता, रायबरेली

अंगद सिंह फाइल

अदिति सिंह फाइल

उत्तर प्रदेश की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह 21 नवंबर को पंजाब के एमएलए अंगद सिंह के साथ सात फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंध जाएंगी। दो वर्ष पहले ही 2017 में राजनीतिक पारी शुरू करने वाले दोनों ही अपने प्रांत के सर्वोच्च सदन में पहुंचे हैं।

रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांच बार विधायक और गांधी परिवार के करीबी रहे अखिलेश सिंह की बेटी अदिति ने बीते विधानसभा चुनाव से पहली बार राजनीति में कदम रखा और करीब 90 हजार वोटों से जीतीं। इसके बाद वह अपने परिवार की राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में सामने आईं। यह रिश्ता तय कर पूर्व विधायक अखिलेश सिंह ने एक रस्म भी निभाई थी। इस बीच अदिति सिंह पार्टी लाइन से हटकर कई बयानों को लेकर खासी चर्चित हुईं, जिसमें कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की बात या उप्र विधानसभा में पार्टी के बहिष्कार के बावजूद उपस्थित होना और बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात शामिल है।

पंजाब के नवांशहर विधायक अंगद सिंह को 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट मिला। पहले ही चुनाव में वह जीतकर विधानसभा पहुंचे। अंगद पंजाब के सबसे युवा विधायकों में से एक हैं।

अंगद के पिता प्रकाश सिंह के चाचा दिलबाग सिंह वर्ष 1962 में पहली बार नवांशहर विधायक बने थे। वह लगातार छह बार नवांशहर के विधायक रहे। उनके बाद वर्ष 1997 में दिलबाग सिंह के बेटे चरणजीत सिंह विधायक बने। वर्ष 2002 में अंगद के पिता प्रकाश सिंह नवांशहर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2012 में अंगद सिंह की माता गुरइकबाल कौर ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।

खास बात यह कि यह शादी दिल्ली में होगी और इसमें दोनों परिवारों के सदस्य ही शामिल होंगे। शादी के बाद 23 नवंबर को दिल्ली या चंडीगढ़ में प्रीतिभोज में बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। 25 नवंबर को स्थानीय नेताओं के लिए पार्टी रखी गई है, जिसमें हजारों लोगों को आमंत्रित हैं।

विधायक अंगद सिंह का परिवार भी राजनीति से लंबे समय से जुड़ा रहा है। इससे पहले 2008 में अंगद सिंह नवांशहर यूथ कांग्रेस के महासचिव चुने गए थे।

राज्यपाल के खिलाफ संसद में आवाज उठाएगी तृणमूल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▸ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले तृणमूल सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय

▸ राज्यपाल के रवैये पर जताई नाराजगी, राज्य में समानांतर प्रशासन चलाने का लगाया आरोप

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जारी टकराव की गूंज अब सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में भी सुनने को मिलेगा। इस बीच रविवार को तृणमूल सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें राज्यपाल के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप किए जाने की जानकारी दी। इस दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए तृणमूल सांसद ने कहा कि राज्यपाल राज्य में एक समानांतर प्रशासन चला रहे हैं। बिना राज्य सरकार को सूचित किए उन्होंने कई कदम उठाए हैं।

इससे पहले तृणमूल सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात कर उन्हें भी राज्यपाल के रवैये से अवगत कराते हुए उनके खिलाफ शिकायत की है। तृणमूल का आरोप है कि राज्यपाल राज्य में एक समानांतर प्रशासन चला रहे हैं। बिना राज्य सरकार को सूचित किए उन्होंने कई कदम उठाए हैं। ऐसे में उक्त मसले पर तृणमूल ने सदन में अन्य विपक्षी दलों से समर्थन की अपील की है। इधर, तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने आरोप लगाया कि राज्यपाल संवैधानिक एकाधिकार से बाहर काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा शासित अन्य राज्यों के राज्यपाल भी इस तरह का व्यवहार करते हैं? साथ ही उन्होंने संसद में उक्त मसले को उठाए जाने की भी बात कही। हालांकि, उक्त मसले पर राज्यपाल ने कहा कि अगर समानांतर सरकार चलता तो हेलीकॉप्टर से फरक्का जाता न की गाड़ी से।

20 हजार की आबादी हिमालय में 40 गांवों की मुश्किलों में घिर सकती है। आने वाले दिनों में इन गांवों को बर्फबारी के बीच पानी-बिजली ही नहीं, खाद्यान्न के संकट से भी जूझना पड़ सकता है। दरअसल, इन गांवों को मिलने वाला केरोसिन का कोटा पूरी तरह बंद हो चुका है।

उप्र के उन्नाव में दूसरे दिन भी सुलगी ट्रांस गंगा सिटी, लाखों का सामान जला

बढ़ा विवाद ▸ प्रशासन ने फोर्स के साथ गांवों में रूट मार्च किया, शुरू हुआ निर्माण

जागरण संवाददाता, उन्नाव

मुआवजे की मांग को लेकर उप्र के उन्नाव स्थित ट्रांस गंगा सिटी रविवार को भी सुलगती रही। किसानों ने इस बार प्रशासन से गुरिल्ला वार किया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अफसरों ने अधिगृहीत भूमि पर बोई फसल उखाड़ना शुरू किया तो किसानों ने यूपीसीडा के निर्माणाधीन दो सब स्टेशनों में आगजनी कर दी। वहां उपकरण और सामान फूंक दिए। इस घटना के बाद पुलिस-प्रशासन ने गांवों में रूट मार्च कर दबाव बनाया और सिटी परिसर में निर्माण कार्य शुरू कराया। आगजनी की घटना पर यूपीसीडा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गंगाघाट थाने में तहरीर दी है।

प्रशासन को पहले से ही आशंका थी कि रविवार को बवाल बढ़ सकता है। भारी पुलिस और पीएसी बल के साथ अफसरों ने सुबह ही ट्रांस गंगा सिटी परिसर में डेरा जमा लिया था। लगभग 10 बजे एसडीएम दिनेश सिंह और सीओ भीम कुमार गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी शुरू करा दी। यूपीसीडा के अधिकारियों ने भूमि पर कब्जा कर बोई गई फसल को जेसीबी से उखाड़ना शुरू किया तो किसानों ने कार्यालय से करीब दो किमी दूर यूपीसीडा के एक निर्माणाधीन सब स्टेशन में आग लगा दी। वहां जमा लाखों रुपये के प्लास्टिक पाइप जल गए। किसानों ने आग कब लगाई, प्रशासन व पुलिस को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। प्रशासन आग बुझवा रहा था, तभी दूसरे सब स्टेशन से धुआं और लपटें निकलने लगीं। सब स्टेशनों में लाखों रुपये का सामान व मिक्सर मशीन जल गई। दोनों स्थानों की आग बुझाने में तीन घंटे मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद गांवों में फोर्स के रूट मार्च के दौरान कुछ किसान नेताओं पर शिकंजा कसा गया और गांव वालों को हिदायत देते हुए सिटी परिसर में निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय, एडीएम राकेश सिंह, एसपी एमपी वर्मा, एएसपी विनोद कुमार पांडेय आदि अधिकारियों ने मौके पर मोर्चा संभाला।

उन्नाव में किसानों ने यूपीसीडा के सब स्टेशन ने लगाई आग, वहां रखे सामान से उठता धुआं। जागरण

घायल किसान पर लाठी बरसाती रही पुलिस

ट्रांस गंगा सिटी में शनिवार को पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठी भांजी थी। हद तो तब हो गई जब भगदड़ के दौरान एक किसान घायल होकर गिर पड़ा। उसे उठाना तो दूर, एक सिपाही उस पर लाठी बरसाता रहा। पुलिस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो महकमे में खलबली मच गई। एसपी ने मामले की जांच करा कार्रवाई की बात कही है। पुलिस का अमानवीय चेहरा उजागर करते इस वीडियो में दिख रहा है कि आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के दौरान एक किसान घायल होकर गिर पड़ा। वह इस कदर अधमरा होकर पड़ा था कि उठकर भाग भी नहीं सकता था। जमीन पर गिरा किसान मदद की गुहार लगा रहा था। इतने में एक सिपाही करीब आया और उठाने की जगह उस पर लाठी चलाने लगा।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में एक दशक बाद शामिल हुई महिला जज

नई दिल्ली, आइएएनएस

▸ आखिरी महिला सदस्य जस्टिस पाल वर्ष 2006 में हो गई थीं सेवानिवृत्त

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में एक दशक बाद रविवार को किसी महिला सदस्य को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रविवार को सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस आर. भानुमति को कोलेजियम में जगह मिली है।

जस्टिस भानुमति से पहले कोलेजियम में जस्टिस रूमा पाल सबसे ज्यादा तीन साल तक सदस्य रहीं। चार जून 2006 को जस्टिस पाल के सेवानिवृत्त होने के बाद कोलेजियम में कोई महिला सदस्य नहीं रहा था। वह 28 जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुई थीं।

तमिलनाडु की रहने वाली जस्टिस भानुमति शीर्ष अदालत के पांच वरिष्ठ जजों में से एक हैं, इसलिए नियमानुसार वह कोलेजियम की सदस्य बनीं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। अब जस्टिस भानुमति के साथ-साथ नामित चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस आरएफ नरीमन कोलेजियम के सदस्य हैं। जस्टिस भानुमति 19 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त होंगी और तब तक वह कोलेजियम की सदस्य रहेंगी। 20 जुलाई 1955 को जन्मी भानुमति का वर्ष 1988 में तमिलनाडु हायर जूडिशियल सर्विसेज में सीधा चयन हुआ। राज्य के कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करने के बाद तीन अप्रैल 2003 को उन्हें मद्रास हाई कोर्ट के जज के रूप में प्रोन्नति मिली।

जस्टिस आर. भानुमति फाइल

झारखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रहीं, कई उल्लेखनीय काम किए : जस्टिस भानुमति ने 16 नवंबर 2013 को झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था। वहां उन्होंने न सिर्फ जिला अदालतों के आधारभूत ढांचे को दुरुस्त किया, बल्कि न्यायिक कर्मचारियों की कमी को दूर करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया। न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों की मदद के लिए उन्होंने नियमों की पुस्तिका का भी प्रकाशन करवाया। 13 अगस्त 2014 को वह सुप्रीम कोर्ट में जज बनीं। जस्टिस भानुमति के अलावा सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी दो अन्य महिला जज हैं।

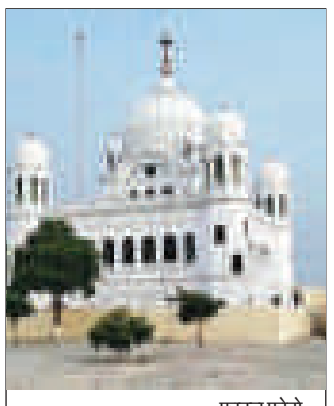
फाइल फोटो

पैसेंजर टर्मिनल की लेन में नहीं जा पाएंगे श्रद्धालु

महिंदर सिंह अर्लीभन्न, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)

भारत-पाक के बीच डेरा बाबा नानक में बनाए गए कॉरिडोर के रास्ते सीमा पर जाकर दूरबीन से श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने वाले श्रद्धालु अब पैसेंजर टर्मिनल की लेन में नहीं जा पाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कॉरिडोर के बीच में 10 से 12 फीट ऊंची लोहे की जाली लगा दी गई है। टर्मिनल के करीब आधा किलोमीटर पीछे चेक पोस्ट तक यह व्यवस्था बना दी गई है।

चेकपोस्ट से दर्शन स्थली की ओर जाने वाले श्रद्धालु सर्विस लेन से भेजे जाएंगे। पहले सभी श्रद्धालु टर्मिनल के बाहर तक घूम सकते थे। श्रद्धालु परमजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, जसविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, बलविंदर सिंह और बख्शीश सिंह का कहना है कि पहले जो श्रद्धालु श्री करतारपुर साहिब से आते थे उनसे अन्य लोग बात कर लेते थे, लेकिन अब बीच में लोहे की जाली लगा दी गई है। पहले ही चेक पोस्ट से लेकर टर्मिनल में प्रवेश द्वार तक कड़ी सुरक्षा की गई थी, लेकिन अब बीच में एक और दीवार बना दी गई है।

पाक ने भेजी 650 श्रद्धालुओं की सूची, दर्शन करने गए 554: कॉरिडोर के रास्ते रविवार को 554 श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन किए। पाकिस्तान ने 650 श्रद्धालुओं की सूची भेजी थी जिनमें से 96 श्रद्धालु नहीं गए। नौ दिन में 3388 भारतीय श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब के खुले दर्शन कर चुके हैं। रविवार को जाने वाले श्रद्धालुओं में डेरा बाबा नानक के एसएमओ ओम प्रकाश, जगदेव सिंह, हरमन सिंह, जसबीर सिंह, रमन कुमार, तरलोक सिंह, बलविंदर सिंह, सतनाम सिंह, डॉक्टर रजनी, सरबजीत सिंह, कुलविंदर पाल, हरविंदर कौर और मनदीप सिंह भी शामिल थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें वहां गुरुद्वारा साहिब में कुआं साहिब, दीवान हॉल आदि दिखाए गए।

न्यूज गैलरी

1.52 करोड़ चोरी में महिला समेत नौ को जेल

प्रयागराज : सिविल लाइंस में रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी एटीएम कैश वैन से 1.52 करोड़ चोरी के मामले में महिला समेत नौ लोगों को रविवार दोपहर जेल भेज दिया गया। घटना तीन अक्टूबर को हुई थी। शाम पांच बजे कैश वैन रेलवे स्टेशन के सिविल लाइंस साइड स्थित एसबीआइ एसटीएम के सामने पहुंची थी। इकलौते गार्ड के साथ कैश वैन को दोनों कस्टोडियन थैले में 18 लाख रुपये लेकर एटीएम में लोड करने चले गए थे। उसी बीच शातिर गिरोह ने वैन से बक्सा निकाल लिया, जिसमें 1.52 करोड़ रुपये थे। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने बदमाशों की पहचान की थी। इस मामले में पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लेकर पर्दाफाश किया। कोर्ट में पेशी के बाद मजिस्ट्रेट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपित तमिलनाडु में त्रिचिरापल्ली के मनिकन्दम भुलई पट्टी गांव का मुकेश कुमार, प्रेम कोइरी, उसका भाई राजा कोइरी, जैक मुदलियार, गोकुल, कुमारन, साहुल हमीद, सुब्रमण्यम है जबकि महिला मीना सेलवी पश्चिम बंगाल में हुगली की रहने वाली है। (जासं)

सीतामढ़ी से जयपुर जा रही बस पलटी, पांच की मौत

कुशीनगर : हेतिमपुर मुजहना टोल प्लाजा के पास रविवार रात बिहार के सीतामढ़ी से राजस्थान के जयपुर जा रही बस पलटने से पांच यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन यात्री घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 80 यात्री सवार थे। जयपुर निवासी मोनू (30) ठेकेदार बिहार के मजदूरों को बस से लेकर जयपुर जा रहा था। रात नौ बजे के करीब बस टोल प्लाजा के निकट पहुंचने पर चालक नियंत्रण खो बैठा और बस फोरलेन से नीचे खेत में पलट गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को हाटा और कसया के अस्पतालों में पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने पांच को मृत घोषित कर दिया। समाचार लिखे जाने तक तीन मृतकों की पहचान राकेश, गुड्डू और धीरज के रूप में हुई है। तीनों महराजगंज के रहने वाले हैं। (जासं)

पैर फिसलने से साध्वी उमा भारती चोटिल

ऋषिकेश : गंगा की अविरलता और स्वच्छता को लेकर गोमुख से गंगासागर तक पैदल यात्रा पर निकली पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ब्रह्मपुरी आश्रम के कक्ष में फिसलने से घायल हो गई। उनकी एड़ी में चोट आई है। चिकित्सकों ने उन्हें एम्स में उपचार के साथ आराम की सलाह दी है। (जासं)

बस में कांस्टेबल की लगी आंख एके 47, चार मैगजीन चोरी

जागरण संवाददाता, खन्ना (लुधियाना)

▸ पंजाब का मामला, कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज, गिरफ्तार

पटियाला के बहादुरगढ़ में तैनात एक कांस्टेबल की बस में सफर के दौरान एक एके-47 असाल्ट्स, 100 कारतूस, चार मैगजीन और वर्दी चोरी हो गई। वारदात उस समय हुई जब कांस्टेबल को बस में नींद आ गई थी। पुलिस ने कांस्टेबल तस्वीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, पुलिस का शक तस्वीर सिंह के अलावा उसके साथ बस में बैठी एक महिला पर भी है, जिसके बारे में तस्वीर सिंह को अंदेशा है कि उसी ने हथियार चुराए हैं। पूरे राज्य के थानों से श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को मनाने के लिए पुलिस मुलाजिमों की सुल्तानपुर लोधी में ड्यूटियां लगाई गई थीं। तस्वीर सिंह भी ड्यूटी पर गया था। ड्यूटी के बाद अन्य मुलाजिम वापस आ गए, लेकिन तस्वीर सिंह अपना हथियार साथ लेकर जिला बटाला में अपने घर चला गया था। रविवार को वह बटाला से जालंधर और लुधियाना होते हुए पटियाला जा रहा था। खन्ना पहुंचने पर उसे इस बात का अहसास हुआ कि उसका बैग गायब है। बैग में उसका हथियार, कारतूस, मैगजीन और वर्दी थी। घबराहट में वह खन्ना ही उतर गया। उसने घटना की सूचना अपने हेडक्वार्टर के साथ सिटी वन पुलिस को दी। इसके बाद पहले पुलिस ने हथियारों की तलाश की, फिर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मामला दर्ज कर तस्वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ के दौरान उसने बताया कि लुधियाना के बाद बस में उसके बगल में महिला बैठी थी। उसे उस पर शक है।

शुरुआती जांच में दिख रही लापरवाही : एसएसपी

खन्ना के एसएसपी गुरशरणदीप सिंह ग्रेवाल ने कहा कि शुरुआती जांच में कांस्टेबल तस्वीर सिंह की लापरवाही सामने आई है। सारे मामले की जानकारी पटियाला पुलिस समेत उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। तस्वीर के बयान के आधार पर इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही हैं। पूरी जांच के बाद ही कुछ सामने आ पाएगा।

ज्वेलर से बन गए गोसेवक...

देश में गो तस्करों की मॉब लिंचिंग को लेकर खूब सवाल उठे, लेकिन गोसेवा की हकीकत जाननी है तो मिलिए तेलंगाना के 80 वर्षीय गोसेवक धर्मराज रांका से। अपना ज्वेलर का चलता हुआ व्यवसाय छोड़कर धर्मराज ने गायों की सेवा और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हैदराबाद स्थित तीन एकड़ में फैले सत्यम, शिवम सुंदरम गऊ निवास में 5,300 गाय हैं। इनमें अधिकांश ऐसी गाय हैं, जिन्हें बूचड़खानों से बचाया गया। धर्मराज प्रतिवर्ष नवंबर माह में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन करते हैं। इसमें देशभर से हजारों लोग सम्मलित होने पहुंचते हैं। एएनआइ

मध्य प्रदेश में दुर्घटना, एक ही परिवार के पांच लोगों की जान गई

नईदुनिया, बड़वानी (मप्र) : मध्य प्रदेश के बड़वानी में अंजड़ से करीब आठ किमी दूर ग्राम मंडवाड़ा के समीप रविवार सुबह पोकलेन मशीन ले जा रहे ट्रॉले और कार की भीषण टक्कर हो गई। इसके बाद ट्रॉला कार पर चढ़ गया। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, वहीं चार वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना इतनी जबर्दस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

जानकारी के अनुसार अंजड़ के राजपुर रोड निवासी परिवार कार (एमपी 09-सीबी 2111) से खरगोन जिले के ग्राम छोटी कसरावद शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। कार में दो महिला, दो पुरुष और दो बच्चे शामिल थे। ग्राम मंडवाड़ा के समीप कार की सामने से आ रहे ट्रॉले (जीजे 18-एटी 8494) से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में अकील (32) पिता सदिर मिर्जा, पत्नी कौशर मिर्जा (30) व पुत्री माहेरा (दो) सहित मुबारिक (46) पिता बाबू शेख व पत्नी सुल्ताना (40) दोनों निवासी छोटी कसरावद, हाल मुकाम, अंजड़ की मृत्यु हो गई। अक ल की चार वर्षीय बेटी साफीया गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया।

चिन्मयानंद की सीजेएम कोर्ट में आज होगी पेशी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

चिन्मयानंद प्रकरण में सोमवार से कोर्ट ट्रायल शुरू होगा। छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में चिन्मयानंद को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया जाएगा। चिन्मयानंद को 20 सितंबर को विशेष जांच दल (एसआइटी) ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब तक न्यायिक हिरासत में होने के कारण चिन्मयानंद की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हो रही थी। बीते दिनों चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब इस मुकदमे पर सुनवाई शुरू होगी, जिस कारण उनको सोमवार को तारीख पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

उधर, चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को फैसला आ सकता है। वहीं छात्रा की जमानत याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होना तय है। अन्य तीनों युवकों की ओर से अभी कोई याचिका दायर नहीं की गई है। चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग की आरोपित छात्रा, उसके दोस्त संजय सिंह, विक्रम सिंह, सचिन सेंगर भी जेल में बंद हैं।

उन लोगों की पेशी मंगलवार को कोर्ट में होगी। इस तारीख पर ब्लैकमेल के आरोपित जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डीपी सिंह और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री अजीत सिंह भी इस दिन कोर्ट में पेश हो सकते हैं। दोनों के नाम एसआइटी ने चार्जशीट में शामिल किए हैं, लेकिन जमानतीय धाराएं होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गई थी।

चश्मा बरामदगी न होने पर उठ सकते हैं सवाल

चिन्मयानंद प्रकरण में एसआइटी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मगर, वह चश्मा नहीं तलाश सकी जिस पर लगे कैमरे से चिन्मयानंद के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए थे। भले ही एसआइटी ने जांच में चश्मे की कोई खास उपयोगिता न बताई हो, लेकिन वकील इसको लेकर एसआइटी पर भी सवाल उठा सकते हैं।

दिल्ली-नैनीताल हाईवे पर 18 और 19 की रात बंद रहेगा यातायात

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : दिल्ली-नैनीताल हाईवे पर रुद्रपुर और बिलासपुर के मध्य रेलवे फाटक की मरम्मत और टीटीएम (टाइट टैंपिंग मशीन) का पैकिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते 18 और 19 नवंबर की रात बिलासपुर-रुद्रपुर के बीच मार्ग पर वाहनों का यातायात बंद रहेगा। इस मार्ग पर दिल्ली के लिए ज्यादातर आवागमन होता है। छतरपुर और पंतनगर रेलवे स्टेशन के बीच मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को भी दिल्ली-नैनीताल हाईवे 14 घंटे बंद रहा था। अब 18 और 19 नवंबर की रात को बिलासपुर और रुद्रपुर रेलवे स्टेशनों के बीच ग्राम इंदरपुर स्थित रेलवे फाटक संख्या 89 रेलवे लाइन की मरम्मत होगी। साथ ही, ओवरहालिंग और टीटीएम की पैकिंग का काम होना है। इसके लिए रेलवे ने संबंधित मार्ग पर वाहनों को रात में बंद करने के लिए जिला प्रशासन को पत्राचार किया है। इसमें 18 और 19 नवंबर की रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रुद्रपुर और बिलासपुर मार्ग पर वाहनों का आवागमन रोकने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा है। संभावना जताई जा रही है कि उक्त मार्ग बंद रहने से दिल्ली, मुरादाबाद को आने-जाने वाले वाहन वाया काशीपुर होकर निकाले जाएंगे।

दो राज्यों में इनामी दस्यु सुंदरी साधना पटेल गिरफ्तार

नईदुनिया, सतना

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे दस्यु प्रभावित क्षेत्र से दुर्दांत डकैत बबुली और लवलेश का सफाया करने के बाद पुलिस ने शनिवार को तराई क्षेत्र में सक्रिय अंतरराज्यीय डकैत गिरोह की सरगना साधना पटेल (21) को गिरफ्तार कर लिया है। उससे असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। साधना पर दोनों राज्यों की पुलिस ने 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने बताया कि सतना पुलिस साधना पटेल गिरोह पर नजर रख रही थी। जानकारी मिली कि वह अपने साथियों के साथ मझगवां थाने के कड़ियन मोड़ के जंगल के पास है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

आपराधिक पृष्ठभूमि: साधना पटेल उर्फ बेलनी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रामपुर पालदेव गांव की रहने वाली है। उसकी बुआ के कुख्यात डकैत चुन्नी लाल पटेल से घनिष्ठ संबंध थे। साधना नवल धोबी गिरोह की सक्रिय सदस्य बनी, लेकिन गिरोह के कई सदस्य पुलिस गिरफ्त में आ गए तो खुद का गिरोह बना लिया। वह अपहरण, ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने के साथ राहगीरों से लूटपाट करने लगी। उसके खिलाफ सतना के नयागांव, मझगवां और बरौंधा थानों में पांच मामले दर्ज हैं।

समर्पण नहीं, गिरफ्तार किया: उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले से साधना के आत्मसमर्पण करने की चर्चा थी। लेकिन सतना के एसपी रियाज इकबाल ने कहा कि सतना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस हमारे साथ नहीं थी।

दस्यु सुंदरी साधना पटेल। जागरण

आयोजन

मेले में खाने-पीने की कई चीजें सैलानियों को कर रहीं आकर्षित, दूर-दराज से आ रहे हैं लोग

लिट्टी-चोखा के साथ लीजिए सोनपुर मेला का आनंद

जागरण संवाददाता, हाजीपुर

आस्था एवं परंपरा के विविध रंगों में रंगे हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला में भारतीय संस्कृति के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। मेले में लजीज व्यंजन की मिठास घुली हुई है।

लिट्टी-चोखा व कई जायकेदार व्यंजन मेले में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं। गुड़ की जलेबी, पापड़ी मिठाई जैसे व्यंजन सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे। आम दिनों में गुड़ की जलेबी बमुश्किल मिलती है लेकिन हरिहरक्षेत्र मेला के दौरान इसकी जमकर बिक्री हो रही है। मेला क्षेत्र के नखास, गज-ग्राह चौक, हरिहरनाथ मंदिर रोड, चिड़िया बाजार, गाय बाजार आदि में गुड़ की जलेबी की दर्जनों दुकानें सजीं हैं। मेले में चटपटे अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अचार की कई दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां आम, नींबू, मिक्सड, मिर्च व अन्य फ्लेवर के अचार की खूब बिक्री हो रही है। मेला क्षेत्र के चिड़िया बाजार रोड में पापड़ी मिठाई व खजूर की आधा दर्जन से अधिक दुकानें हैं।

सोनपुर मेले में लिट्टी-चोखा की दुकान पर अपनी बारी का इंतजार करते लोग। जागरण

अपराध निरोध प्रदर्शनी का डीजीपी ने किया उद्घाटन: पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने रविवार को हरिहरक्षेत्र मेला में अपराध निरोध अनुसंधान विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद डीजीपी ने मंडप में पुलिस तथा अन्य विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। यहां एसटीएफ के कमांडो दस्ते के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है।

निरंजनी अखाड़ा में महंत ने गोली मारकर दी जान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▸ रविवार सुबह अपने कक्ष में लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी के पास मारी गोली

दारागंज में गंगा तट पर स्थित पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में महंत आशीष गिरि (45) ने रविवार सुबह गोली मारकर अपनी जान दे दी। पुलिस अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और छानबीन की।

वह मूलरूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। करीब आठ साल से दारागंज में पंचायती अखाड़ा श्रीनिरंजनी में थे। इन दिनों वह अखाड़ा के सचिव भी थे। वह अखाड़ा भवन में प्रथम तल स्थित कक्ष में रहते थे। रविवार सुबह नौ बजे उन्हें मठ बाघंबरी गद्दी जाना था। वहीं जलपान करना था। कुछ पदाधिकारी वहां पहुंच भी चुके थे। अखाड़ा का लेखा-जोखा संभालने वाले कमलेश द्विवेदी के मुताबिक, महंत को सुबह आठ बजे कमरे में चाय दी गई। उन्होंने कहा था कि कुछ देर बाद वह नीचे आ रहे हैं। जब देर तक वह नहीं उतरे तो एक साधु उन्हें बुलाने पहुंचा तो वह कमरे में फर्श पर बिछे अपने बिस्तर पर पड़े थे। सिर से खून बह रहा था। पास में पिस्टल पड़ी थी। साधु ने शोर मचाया तो अखाड़ा में मौजूद अन्य साधु पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी पहुंची।

महंत की दाहिनी कनपटी के पास गोली लगी थी। पुलिस को कमरे में बड़ी मात्रा में दवाएं और मेडिकल जांच रिपोर्ट मिलीं। साधुओं ने बताया कि महंत आशीष गिरि काफी समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीने पहले देहरादून के अस्पताल में भर्ती भी रहे। एक-दो बार बोले भी थे कि बीमारी ने जीना मुश्किल कर दिया है। एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव ने कहा कि मेडिकल जांच रिपोर्ट व अखाड़ा पदाधिकारियों के बयान से साफ हुआ है कि महंत ने बीमारी की वजह से गोली मारकर जान दी है। इससे इतर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को लीवर और किडनी सामान्य मिली।

12 घुसपैठिए व एक सोना तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता : दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के बीएसएफ के जवानों ने शनिवार को सीमावर्ती जिला उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद के विभिन्न स्थानों से अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले 12 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और नादिया की सीमा क्षेत्रों से विभिन्न माध्यमों से बांग्लादेश को तस्करी किए जा रहे 28 मवेशी और 499 बोतल फेंसिडिल को भी जब्त किया गया है।

बीओपी गोबर्धा,153 बटालियन बीएसएफ (थाना स्वरूप नगर के अंतर्गत), दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्र से चार बांग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक को,153 बटालियन बीएसएफ के बीओपी घोजाडांगा (थाना बशीरहाट के अंतर्गत) से दो बांग्लादेशी नागरिकों को, 112 बटालियन बीएसएफ के बीओपी तराली (थाना स्वरूप नगर के अंतर्गत) से एक बांग्लादेशी नागरिक को और 64 बटालियन बीएसएफ के बीओपी डोबारपारा (थाना गायघाटा के अंतर्गत) से एक बांग्लादेशी नागरिक को उस वक्त गिरफ्तार किया।

1200 सरकारी स्कूलों में उत्तराखंड में वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। पहले चरण में 500 स्कूलों से शुरुआत होगी। इसमें सेंट्रलाइज्ड स्टूडियो के माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षा 6-12 तक के विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 18 नवंबर 2019

जम्मू में आइईडी धमाका, जवान शहीद

नापाक हरकत ▸ प्लांवाला सेक्टर में गश्त के दौरान हुआ हादसा, दो अन्य जवान घायल

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू जिले के सीमावर्ती अखनूर के प्लांवाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब रविवार दोपहर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) धमाके में सेना का एक जवान शहीद और दो अन्य घायल हो गए। विस्फोट उस समय हुआ जब सेना के कुछ जवान वाहन से अग्रिम चौकी की ओर बढ़ रहे थे कि जोरदार धमाका हुआ। एक जवान की हालत गंभीर बताई जाती है।

आशंका जताई जा रही है कि आइईडी विस्फोट में पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। इस क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान सेना लगातार कोशिशें कर रही है। आतंकी रात के अंधेरे में फेंसिंग के पास पहुंचने की फिराक में रहते हैं। रविवार को नियंत्रण रेखा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मुहिम के तहत सैन्य जवान में जवान गश्त कर रहे थे। वाहन का टायर आइईडी पर पड़ते ही जोरदार धमाका हुआ। इसमें तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत अन्य जवान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायल जवानों को अखनूर अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद सेना ने तीनों को ऊधमपुर के कमान अस्पताल में एयर लिफ्ट कर दिया। घायल हवलदार संतोष कुमार निवासी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के तहसील बाह के पुरा बदोरिया शहीद हो गए। अन्य घायल जवानों की पहचान नायक गेमरा राम व नायक कृष्ण लाल के रूप में हुई है। धमाके के बाद क्षेत्र में प्लांवाला क्षेत्र में दशहत का माहौल बन गया।

▸ उप्र के रहने वाले थे शहीद जवान संतोष कुमार, एलओसी के पास हुई घटना, पाक सेना का हाथ होने की आशंका

आतंकी कई बार कर चुके घुसपैठ की कोशिशें

अखनूर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कई बार पाकिस्तान की बार्डर एक्शन टीमें भी इस इलाके में खूनखराबा करने की साजिशें रच चुकी हैं। ऐसे हालात में गत माह अखनूर के केरी बट्टल में घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में ललयाली इलाके में सेना के तीन जवान घायल हो गए। कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने फिर से इस सेक्टर में गोलियां दाग कर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी।

सेना कर रही आइईडी धमाके की जांच : पीआरओ: धमाके से उपजे हालात में सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेन्द्र आनंद ने जागरण को बताया कि आइईडी धमाका संदिग्ध हालात में हुआ व इसमें एक सैनिक शहीद और दो घायल हो गए। नियंत्रण रेखा के करीब हुए इस आइईडी घमाके की जांच की जा रही है। पुलिस के डीएसपी अजय शर्मा ने बताया कि यह आइईडी ब्लास्ट किन हालात में हुआ, यह पता लगाने की कार्रवाई जारी है।

पुंछ के जंगल में दिखे संदिग्ध, तलाशी अभियान

जागरण संवाददाता, पुंछ: पुंछ जिला के सुरनकोट स्थित सांगला के जंगल में कुछ संदिग्ध लोगों के देखे जाने की सूचना पर सुरक्षाबलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं। देर रात गए तक तलाशी अभियान में किसी के पकड़े जाने की सूचना नहीं है।

जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर को सुरक्षाबलों को सूचना दी गई कि सुरनकोट के सांगला जंगल में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। यह सीमा पार से घुसपैठ करके आए हुए आतंकी भी हो सकते हैं।

इससे सुरक्षाबलों के जवान सतर्क हो गए और सांगला जंगल को घेर कर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों के जवानों को कोई सफलता नहीं मिली है। सेना व पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं।

जम्मू में आतंकियों ने ट्रक जलाया

राज्य ब्यूरो, जम्मू : कश्मीर में धीरे-धीरे सुधर रहे हालात से आतंकी और अलगाववादी बौखला गए हैं। इसी के चलते आतंकियों ने शनिवार रात को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में एक ट्रक जला दिया। श्रीनगर नंबर का यह ट्रक त्राल के गांव अमीराबाद में सड़क किनारे खड़ा था। रात को अचानक उसमें आग लग गई। पुलिस के अनुसार ट्रक के ऊपर घास लदी हुई थी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ट्रक में शार्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी, लेकिन अब प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ट्रक आतंकियों ने जलाया है।

उल्लेखनीय है कि आतंकी घाटी में अपने फरमानों की नाफरमनी होते देख ट्रकों और उनके चालक-परिचालकों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने कश्मीर में अब तक करीब पांच ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है, जबकि चार ट्रक चालकों-परिचालकों की भी हत्या की है। पुलिस ने ट्रक चालकों को सुरक्षित जगहों पर पर ही जाने की सलाह दी है। शनिवार रात को जब ट्रक जलाने की घटना हुई, उस समय ट्रक में कोई भी नहीं था। पुलिस ने रविवार की सुबह आग लगने की घटना वाले स्थल के आसपास तलाशी अभियान भी चलाया लेकिन कोई नहीं मिला। पुलिस इस मामले में शामिल आतंकियों की धर पकड़ के लिए जुटी हुई है।

स्पीकर का कार्यकाल खत्म होने से खफा हैं निर्मल सिंह

राज्य ब्यूरो, जम्मू: डॉ. निर्मल सिंह के विधानसभा स्पीकर के पद का कार्यकाल रविवार को समाप्त कर दिया गया है। कानून विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन निर्मल सिंह ने प्रशासन के इस फैसले पर ऐतराज जताया। उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए प्रशासनिक फैसला करार दिया। डॉ. निर्मल सिंह ने जागरण से बातचीत में कहा कि वह इस मुद्दे पर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। यह मामला देश के संविधान की गरिमा और विधायिका की स्वतंत्रता का है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

बता दें कि मौजूदा हालात में जम्मू कश्मीर के स्पीकर पद को लेकर प्रशासन की ओर से किया फैसला अस्पष्ट है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पुनगर्ठन के फैसले के प्रभावी होने के दिन श्रीनगर में 31 अक्टूबर को डॉ. निर्मल सिंह को उप राज्यपाल जीसी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में स्पीकर बुलाया था। इसके बाद शीतकालीन राजधानी जम्मू में 4 नवंबर को दरबार खुलने के दिन डॉ. निर्मल ने विधानसभा में कामकाज का जायजा लेने के लिए बैठक भी की थी।

अब अचानक प्रशासन की ओर से 31 अक्टूबर के प्रभाव से उनका कार्यकाल समाप्त करने का फैसला किया है। 10 मई 2018 को जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 57 के तहत डॉ. निर्मल को विधानसभा का स्पीकर बनाया था। इससे पहले वह पूर्व उपमुख्यमंत्री थे। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद डॉ. निर्मल के स्पीकर पद पर बने रहने पर असंमजस बरकरार था।

2020 में उपलब्ध होगा जीका वायरस का टीका

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

▸ भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का दावा, अंतिम दौर में परीक्षण

दुनिया में अभी तक जीका वायरस से बचाने का टीका या सीधा इलाज नहीं है। मगर, जल्द ही जीका वायरस को लेकर चिंता खत्म होने वाली है। वर्षों से शोध कर रही हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड अगले साल (2020) यह टीका लांच कर देगी और यह बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। यहां होटल रॉयल रेजीडेंसी में चल रहे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अधिवेशन 'यूपी पेडिकॉन 2019' में रविवार को जीका वायरस समेत कई वैक्सीन को प्रमोट करने आई भारत बायोटेक की टीम ने यह जानकारी दी। टीम का नेतृत्व कर रहे एरिया बिजनेस मैनेजर मोहम्मद आरिफ ने दैनिक जागरण को बताया कि भारत बायोटेक ने देश को अनेक गंभीर बीमारियों की वैक्सीन दी हैं। करीब पांच साल पहले सबसे पहला थायराइड का टीका (ह्ल4श्चड्ढड्ड-ह्ल1ष्) भी हमने ही लांच किया। एक ग्लोबल लॉबी इसे पूरी दुनिया में स्पांसर कर रही है। एक टीके से जिंदगी भर के लिए थायराइड जैसे बीमारी से बचाव हो जाता है। इसी तरह रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी, आदि के टीके भी भारत बायोटेक ने बनाए।

जल्द होगा पेटेंट: उन्होंने दावा किया कि अब जीका वायरस से बचाव का टीका भी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। वायरस पर शोध व परीक्षण के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। भारत सरकार के निर्देशन में जल्द ही टीका पेटेंट होगा। 2020 में इसे लांच करने की तैयारी है। जीका वायरस का पहला टीका 'मेक इन इंडिया' होगा।

ये है जीका वायरस

जीका वायरस एडिज, एजिप्टी व अन्य मच्छरों के काटने से फैलने वाला संक्रमण है। इसका वायरस वीनस फ्लेविवायरस व फैमिली फ्लेविविरिडी के तहत आता है। इसकी शुरुआत लैटिन अमेरिकी देशों से हुई है, जो अब भारत भी पहुंच चुका है। इससे संक्रमित गर्भवती से पैदा बच्चा आकार में छोटा व अविकसित दिमाग के साथ होता है। यह शरीर के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है।

उत्तर प्रदेश में भले ही जीका वायरस ने दस्तक न दी हो, मगर यह तेजी से फैल रहा है। भारत बायोटेक टीका लांच कर रहा है। टीका लांच होने से वायरस से बचाव तो होगा ही, दूनिया में भारत का नाम भी होगा।
-डॉ. प्रदीप बंसल, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ।

वैलेट पार्किंग से वाहन चोरी होने पर होटल की जिम्मेदारी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि कोई भी होटल अपने कर्मचारियों के हाथों या वैलेट पार्किंग में खड़े किए गए वाहन की चोरी पर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। वह 'ओनर्स रिस्क' का क्लाज लगाकर मुआवजा देने से नहीं बच सकते हैं।

सर्वोच्च अदालत का कहना है कि होटल पर वैलेट पार्किंग में अन्य पार्किंग सुविधाओं के विपरीत वाहन के मालिक को खुद पार्किंग की जगह नहीं ढूंढनी पड़ती है। और नाही ही उसे खुद जाकर वाहन को सही तरह से खड़ा करना होता है। बल्कि वापसी में वाहन की पर्ची या टोकन दिखाने पर होटल स्टाफ खुद ही उनकी गाड़ी ड्राइव करके उसके पास लाता है। इसलिए वैलेट पार्किंग वाले ग्राहक का वाहन चोरी होने पर होटल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है।

सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि ऐसे में किसी का वाहन चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की सूरत में होटल की जिम्मेदारी है कि वह साबित करे कि उसके पार्किंग परिसर से वाहन चोरी या क्षतिग्रस्त होने में उसकी गलती कैसे नहीं है। ऐसे मामले में सीधे तौर पर होटल की जिम्मेदारी होती है। चूंकि इसमें वाहन मालिक सुरक्षा के भरोसे के साथ अपना वाहन होटल कर्मचारी को सौंपता है। और उसकी पर्ची या टोकन उस करार का सुबूत होता है।

जस्टिस एमएम शांतनागौदर और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा कि होटल का मालिक इस करार की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। किसी भी परिस्थिति में अपनी या अपने कर्मचारी की लापरवाही से अपने ग्राहक के वाहन को क्षति पहुंचने पर वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। खंडपीठ ने कहा कि जहां आम प्रावधान लागू होते हैं या किसी छूट का क्लॉज भी होता है, वहां भी प्रथम दृष्टया होटल की जिम्मेदारी बनती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उपभोक्ता अदालत के मुआवजा देने के फैसले के खिलाफ होटल की अपील को खारिज करते हुए सुनाया है। हाल ही में जब पीड़ित ने अपनी गाड़ी एक पांच सितारा होटल की वैलेट पार्किंग में खड़ी करा के होटल के अंदर गया। वापसी में जब उसने पर्ची दिखा कर जब अपनी गाड़ी लाने को कहा था होटल स्टॉफ ने बताया कि उसकी गाड़ी पहले ही कोई तीन लड़के ड्राइव करके ले जा चुके हैं। यह तीन लड़के एक अलग कार से होटल आए थे। जब वाहन मालिक ने बीमा की रकम मांगी तो होटल ने पार्किंग कूपन पर लिखे 'ओनर्स रिस्क' का क्लॉज दिखा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की।

तृप्ति देसाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी

▸ प्रथम पेज का शेष

तिरुअनंतपुरम, एएनआइ : केरल की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अंजना ने रविवार को महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह सबरीमाला मंदिर आती हैं तो कल्पना नहीं कर सकती यहां क्या हो सकता है। देसाई ने कहा है कि वह 20 नवंबर को सबरीमाला मंदिर जाएंगी, भले ही उन्हें सुरक्षा मिले या ना मिले। अंजना ने कहा कि देसाई आती हैं तो हम सब उनका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारी परंपराओं के विरोधी हैं। वे सबरीमाला को तीर्थस्थान रहने देने की जगह कमाई का अड्डा बनाना चाहते हैं।

कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा : खुशबू

चेन्नई, एएनआइ : कांग्रेस नेता खुशबू ने रविवार को कहा कि हम सभी को सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। खुशबू ने कहा, 'हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना होगा। संविधान पीठ ने मामले को सात जजों की पीठ में भेज दिया है। हमें अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा।'कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें सोचना होगा, हड़बड़ी नहीं करनी होगी। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह वर्षों से चली आ रही आस्था और विश्वास का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ किसी को उसके अधिकारों से भी वंचित नहीं किया जा सकता है।

सबरीमाला में रविवार को भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालुओं के उत्साह में भारी बारिश के बावजूद कोई कमी नही आई। प्रेट्र

मेघालय में 117 साल पुराना चर्च और घर खाक, दंपती की जान गई

शिलांग, प्रेट्र : मेघालय की राजधानी शिलांग में रविवार तड़के लगी भीषण आग से 117 साल पुराना चर्च व पड़ोस का घर खाक हो गए। इस अग्निकांड में दम घुटने से एक वृद्ध दंपती की मौत हो गई। आसपास के कई अन्य घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने अग्निकांड में मारे गए लोगों और चर्च ऑफ गॉड फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

पूर्वी खासी जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आग लगने की घटना सुबह करीब चार बजे हुई। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि क्वालापट्टी इलाके में स्थित चर्च में इलेक्ट्रिक वायरिंग समेत बड़े पैमाने पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। चर्च सघन आबादी वाले इलाके के बीच में स्थित है और इसके आसपास कई घर हैं। सघन आबादी व सकरी गलियों के कारण दमकल वाहनों को भी वहां तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। अपने घर में आग लगने के बाद दंपती उसमें रखे कीमती सामान निकालने के लिए घुसा था। इस दौरान दोनों की दम घुटने से मौत हो गई।

शिलांग में रविवार तड़के 117 साल पुराने चर्च में लगी भीषण आग। प्रेट्र

आइएएनएस के मुताबिक चर्च की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। लकड़ी से बना 95 साल का यह चर्च राज्य के सबसे पुराने चर्चों में से एक था। चर्च के सीनियर पास्टर रेव. ओएल स्नैतंग ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प जताया है।

30 साधु-संतों ने मांगी बदरीनाथ में तप की अनुमति

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: कपाट बंद होने के बाद बदरीनाथ धाम में पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है। आसपास के गांव भी पूरी तरह खाली हो जाते हैं। तब यहां सुरक्षाकर्मी एवं सेना के जवानों के सिवा और कोई नजर नहीं आता। लेकिन, ऐसी स्थिति में भी प्रशासन की अनुमति से कई साधु-संत पूरे शीतकाल यहां रहकर तप करते हैं। इस बार भी 30 से अधिक साधु-संतों ने शीतकाल के दौरान बदरीनाथ धाम में रहने की अनुमति मांगी है। हालांकि, अभी जांच प्रक्रिया के चलते किसी को अनुमति नहीं मिली है। बीते वर्ष आठ साधुओं को बदरीनाथ में रहने की अनुमति मिली थी।

भू-वैकुंठ बदरीनाथ धाम को तप के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 'स्कंद पुराण' के केदारखंड में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने नर-नारायण के अवतार में यहां तप कर सहस्रबाहु दैत्य का भी वध किया था। आज भी कपाट बंद होने के बाद जब पूरा बद्रिकाश्रम क्षेत्र बर्फ के आगोश में समा जाता है, तब प्रशासन की अनुमति से कई साधु-संत यहां तप करते हैं। क्योंकि, इस अवधि में हनुमानचट्टी से आगे आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है।

शीतकाल के लिए बदरीनाथ धाम के भी कपाट बंद, चारधाम यात्रा का समापन

संवाद सूत्र, बदरीनाथ (चमोली)

गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद शीतकाल के लिए बदरीनाथ धाम के भी कपाट बंद कर दिए गए। इसी के साथ चार धाम यात्रा का भी समापन हो गया। करीब नौ हजार से ज्यादा श्रद्धालु इस खास पल के साक्षी बने। भगवान बदरी नारायण की चल विग्रह उत्सव डोली सोमवार को अपने शीतकालीन पूजा स्थल योगध्यान बदरी मंदिर के लिए रवाना होगी।

51 कुंतल गेंदे के फूलों से सजे बदरीनाथ धाम में तड़के भगवान बदरी-विशाल की नित्य पूजा के साथ ही अभिषेक व महाभिषेक किया। इसके बाद राजभोग व बालभोग लगाया गया। दोपहर तक आम श्रद्धालु भगवान नारायण के दर्शन करते रहे। दोपहर बाद इस वर्ष की अंतिम सायंकालीन पूजाएं शुरू हुईं। धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने भगवान का फूलों का श्रृंगार उतारने के बाद उनके शरीर पर घृत कंबल ओढ़ाई।

सीजन में रिकॉर्ड 12 लाख 40 हजार भक्तों ने किए दर्शन: इस साल बदरीनाथ धाम में रिकॉर्ड 12 लाख 40 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले साल यह आंकड़ा दस लाख 58 हजार 490 था।

भविष्य बदरी धाम के कपाट भी हुए बंद: बदरीनाथ धाम के साथ ही सुभाई गांव स्थित भविष्य बदरी धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। इस मौके पर वेदपाठी, हक-हकूकधारी व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। परंपरा के अनुसार जोशीमठ-मलारी हाईवे पर जोशीमठ से 17 किमी दूर स्थित भविष्य बदरी मंदिर के कपाट भी बदरीनाथ धाम के साथ ही खोले और बंद किए जाते हैं।

बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दौरान रविवार को करीब नौ हजार से ज्यादा श्रद्धालु इस खास पल के साक्षी बने। बदरीनाथ धाम में दर्शनों को लगी श्रद्धालुओं की भीड़। जागरण

संटूर होटल से एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट किए 34 सियासी बंदी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▸ होटल में नहीं थे ठंड से बचाव के पुख्ता प्रबंध, अनुच्छेद-370 हटाने के पहले से हिरासत में हैं नेता

कश्मीर में ठंड बढ़ते ही होटल संटूर में हिरासत में रखे गए 34 राजनीतिक बंदियों को एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि होटल में भारी बर्फबारी के चलते ठंड से बचाव के सही प्रबंध नहीं थे। बता दें कि प्रशासन ने सभी बंदियों को अनुच्छेद-370 हटाने से पहले ही हिरासत में लेकर होटल में रखा था।

श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के कारण नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस के नेताओं के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी सेहत खराब होने की शिकायत कर रहे थे। इनकी सुरक्षा में शामिल सुरक्षाबलों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था। इसके चलते करीब 15 दिन से सभी को यहां से शिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी। प्रशासन ने श्रीनगर शहर के मौलाना आजाद स्टेडियम में स्थित एमएलए होस्टल में इन्हें रखने के लिए जरूरी काम किए हैं। इसे अब वैकल्पिक जेल का दर्जा दिया गया है। रविवार को इसमें सभी को शिफ्ट कर दिया गया। इन राजनीतिक बंदियों में पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन, नेशनल कांफ्रेंस के अली मुहम्मद सागर, पीडीपी के नईम अख्तर, पूर्व आइएएस शाह फैसल शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को शुक्रवार को टूरिस्ट हट से सरकारी आवास में शिफ्ट किया गया था।

तीन करोड़ का बिल सौंपा

संटूर होटल ने 34 राजनीतिक बंदियों को सौ दिन से अधिक तक रखने पर गृह विभाग को तीन करोड़ का बिल सौंपा है। यह होटल इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। उसने यह बिल गृह विभाग को भेजा है। हालांकि होटल द्वारा सौंपे गए बिल पर प्रशासन सहमत नहीं है। उनका कहना है कि होटल को जेल में बदला गया है और सरकारी रेट पर बिल दिया जाएगा। सरकार एक दिन ठहरने का मात्र आठ सौ ही देती है लेकिन होटल प्रबंधन ने एक दिन ठहरने के पांच हजार रुपये मांगे हैं।

बदलती तस्वीर

घाटी में सर्दी का मौसम शुरू होते ही बाजारों में बढ़ी रौनक, श्रीनगर के टीआरसी चौक, जहांगीर चौक, लाल चौक पर लगे स्टाल

कश्मीर के संडे बाजार में खूब बिके गर्म कपड़े

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे हुए सौ दिन से अधिक हो गए हैं। अब कश्मीर में हालात लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। लोग घरों से निकल कर बाजारों का रुख करने लगे हैं। सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने से रौनक बढ़ गई है।

रविवार को श्रीनगर के संडे बाजार में आलम कुछ ऐसा ही था। बाजार में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमडी हुई थी। किसी को अलगाववादियों और आतंकवादियों की धमकियों की कोई चिंता नहीं थी। सभी बेखौफ होकर बाजार में खरीदारी कर रहे थे। श्रीनगर शहर के टीआरसी चौक, जहांगीर चौक, लाल चौक व शहर के अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में रेहड़ी-फडी वालों ने स्टाल लगाए। ज्यादातर स्टाल पर सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़े रखे हुए थे। रेहड़ी-फड़ी का बाजार दोपहर बाद तक सजा रहा, जहां से लोगों ने सर्दियों के लिए गर्म कपड़े सहित अन्य आवश्यक सामान की खरीदारी की।

रविवार को छुट्टी होने के कारण सड़कों पर बड़ी संख्या में निजी वाहन दौड़ते हुए नजर आए। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा के साथ अन्य वाहनों की भी खूब आवाजाही रही। इसके अलावा अंतरराज्यीय कैब का भी संचालन हुआ। उधर, मगर प्रशासन ने किसी भी तरह की संभावित घटना को देखते हुए पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों और पुलिस के जवान तैनात रहे। कश्मीर घाटी में रविवार को हालात पूरी तरह शांत और सामान्य रहे।

पिछले कुछ दिनों से घाटी के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश व बर्फबारी हो रही है। इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। श्रीनगर के चौक-चौराहों पर रविवार को संडे मार्केट में गर्म कपड़ों की खूब बिक्री हुई। कमरान रशीद बट

उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पूर्व कश्मीर में लैंडलाइन फोन और मोबाइल फोन की कॉलिंग सहित इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था, लेकिन हालात में बेहतरी के बाद लैंडलाइन फोन और पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा को बहाल कर दिया था। हालांकि कश्मीर में प्री-पेड मोबाइल फोन और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरे जम्मू कश्मीर में एहतियातन बंद रखा हुआ है।

कश्मीर में बनिहाल तक बहाल हुई रेल सेवा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कश्मीर में बनिहाल-श्रीनगर-बारामुला रेलवे सेक्शन के बीच आखिर तीन महीने के बाद रेल सेवा बहाल हो गई। शनिवार को दो और रविवार को एक सफल ट्रायल रन के बाद रेल सेवा शुरू हो गई। यह रेल सेवा तीन अगस्त को राज्य प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बनिहाल-बारामुला रेल सेवा को बंद कर दी थी। बता दें कि बारामुला और श्रीनगर के बीच यह सेवा बीते मंगलवार से ही बहाल कर दी गई थी।

डिवीजनल ट्रैफिक मैनेजर कश्मीर विपिन पुरोहित ने बताया कि बनिहाल-श्रीनगर रेलवे सेक्शन पर शनिवार को दो बार और रविवार को भी एक ट्रायल रन किया। तीनों ने ट्रायल रन सफल रहे। इसके बाद से रविवार दोपहर 12:40 मिनट पर ट्रेन बारामुला से बनिहाल के लिए शुरू कर दी गई। ट्रेन सफलतापूर्वक बनिहाल में पहुंची गई। उन्होंने बताया कि सोमवार से सुबह दस बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक दो बार रेल सेवा चलाए जाएगी।

विपिन पुरोहित ने कहा कि सोमवार से पहले की तरह रेलगाड़ी चलेगी। श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन पर 106 दिन से रेल सेवा बंद थी। अब इसके चलने से बनिहाल से श्रीनगर जाने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। इसमें जहां किराया कम हैं, वहीं समय की भी बचत होती है। यही नहीं बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवाहर सुरंग के बंद होने से आम लोगों को जम्मू से कश्मीर पहुंचने में काफी मुश्किल होती है, उससे से भी बचा जा सकेगा।

उन्होंने पूरे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर दक्षिण कश्मीर में जिला पुलवामा के काकपोरा, अवंतीपोर और कुलगाम में काजीगुंड में विशेष प्रबंध किए हैं। ट्रैक पर जीआरपी, सीआरपीएफ और सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं।

कश्मीर में बनिहाल-श्रीनगर-बारामूला रेलवे सेक्शन के बीच तीन माह बाद रेल सेवा पूरी तरह बहाल हो गई। श्रीनगर स्टेशन पर रविवार को उमड़ी यात्रियों की भीड़। प्रेट्र

2.75 लाख घन मीटर भूभाग में बनने वाला राम मंदिर दो मंजिल का होगा। इसकी लंबाई 270 मीटर, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट होगी। 330 बीम और 212 खंभों वाले मंदिर में पांच दरवाजे होंगे और इसका निर्माण पांच हिस्सों- गर्भगृह, कौली, रंग मंडप, नृत्य मंडप और सिंह द्वार में किया जाना है।

कम ही सफल होती हैं पुनर्विचार याचिकाएं

अयोध्या विवाद ▶ याचिका में मुख्य फैसले के बदलने या फिर से उसके संशोधित होने की गुंजाइश है कम

सुनवाई के लिए संविधान पीठ में एक नया जज किया जाएगा शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सर्वसम्मति से दिए गए फैसले से कुछ मुस्लिम पक्षकार संतुष्ट नहीं हैं और वे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के जो नियम और प्रक्रिया तय है, उसमें पुनर्विचार याचिका में मुख्य फैसले के बदलने या संशोधित होने की बहुत कम गुंजाइश होती है। ज्यादातर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हो जाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और उस पर सुनवाई की प्रक्रिया तय है। किसी भी फैसले पर आपत्ति या कानूनी खामी होने पर पक्षकारों को फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का अधिकार है। अयोध्या मामले में कुछ मुस्लिम पक्षकारों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की है। पक्षकारों को हमेशा से ही फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का अधिकार रहता है। हालांकि इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पक्षकार

सुप्रीम कोर्ट फाइल

नहीं है। मुख्य मामले में बोर्ड की ओर से कोई अपील नहीं थी। लेकिन अयोध्या का यह मुकदमा प्रतिनिधि सूट है। ऐसे में बोर्ड फैसले का असर पूरे मुस्लिम समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ बता कर कोर्ट जा सकता है। यह कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस हद तक उसकी पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करता है।

पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की तय प्रक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर तभी पुनर्विचार करता है जबकि फैसले में सीधे तौर पर सामने कोई खामी नजर आ रही हो। इसके अलावा पुनर्विचार याचिका पर वही न्यायाधीश विचार करते हैं जिन्होंने फैसला सुनाया होता है। इस मामले में फैसला सुनाने वाले एक न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई सेवानिवृत हो गए हैं। ऐसे में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पीठ में जस्टिस गोगोई की जगह किसी नए न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा ताकि पांच न्यायाधीशों का कोरम पूरा हो। इसके अलावा पुनर्विचार याचिका पर वही पीठ चैम्बर में सर्कुलेशन के जरिए विचार करती है जिसने मुख्य फैसला दिया होता है। वहां वकीलों की बहस और दलीलें नहीं होतीं। पीठ के सामने सिर्फ मामले से जुड़े दस्तावेज और रिकार्ड होते हैं। अगर कोर्ट पुनर्विचार याचिका में उठाए गए मुद्दों से संतुष्ट होता है और उस पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत समझता है, तब मामले को खुली अदालत में लगाने का आदेश पारित किया जाता है, लेकिन ऐसा विरले ही मामलों में होता है। पुनर्विचार याचिका में नए तथ्य नहीं उठाए जा सकते सिर्फ फैसले की ऐसी कानूनी खामी उजागर करनी होती है जो साफ तौर पर सामने नजर आ रही हो। इन तकनीकियों के कारण बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं में सुनवाई करते हुए अपने पूर्व आदेश को पलटता या बदलता है।

ट्रस्ट में भूमिका जानने के लिए पीएम से मिलेगा निर्मोही अखाड़ा

माला दीक्षित, नई दिल्ली।

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नया ट्रस्ट गठित कर मंदिर निर्माण के लिए सारी जमीन उसे सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद नये ट्रस्ट के गठन को लेकर चर्चा तेज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार को साफ निर्देश दिया गया है कि गठित किये जाने वाले नये ट्रस्ट में वह निर्मोही अखाड़ा को शामिल करेगी। ऐसे में निर्मोही अखाड़ा ने ट्रस्ट में अपनी भूमिका जानने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का फैसला किया है।

निर्मोही अखाड़ा ने रविवार को अयोध्या में बैठक की और इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार किया गया। बैठक में सरपंच रामचंद्रा आचार्य सहित सभी 13 पंचों ने भाग लिया। निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा कहते हैं कि बैठक में फैसला लिया गया कि नये ट्रस्ट में अपनी स्पष्ट भूमिका जानने के लिए प्रधानमंत्री से मिला जाएगा। पंच जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ट्रस्ट में उनकी क्या भूमिका तय कर रही है। इसके लिए इसी सप्ताह निर्मोही अखाड़ा प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेगा। चोपड़ा का कहना है कि वैसे तो निर्मोही अखाड़ा फैसले से खुश है क्योंकि उसने 150 साल तक जिस मंदिर के निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी उसके बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन फिर भी अखाड़ा के संत इस बात से निराश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस आधार उनके शेबियत (सेवापूजा) के अधिकार को खारिज कर दिया जबकि कोर्ट फैसले में निर्मोही अखाड़ा की उस जगह पर ऐतिहासिक मौजूदगी मान रहा है। अखाड़ा सरपंच राजा रामचंद्रा आचार्य का कहना है कि फैसले का अध्ययन किया जा रहा है प्रधानमंत्री से मिलने बाद और ट्रस्ट में भूमिका का पता चलने के बाद ही निर्मोही अखाड़ा इस मामले में आगे की रणनीति तय करेगा। जब से फैसला आया है ट्रस्ट में शामिल होने और उसमें भूमिका को लेकर संत समाज में चर्चा और विचार विमर्श तेज है। कई ओर से सरकार को सुझाव और विचार दिये जा रहे हैं। लेकिन निर्मोही अखाड़ा के बारे में फैसले में ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। निर्मोही अखाड़ा का हमेशा से राम जन्मभूमि में सेवा व पूजा प्रबंधन का दावा रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट मे भी इसी दावे और अधिकार का मुकदमा दाखिल किया था हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा समय बाधित बता कर खारिज कर दिया है। मुकदमा खारिज किये जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा की राम जन्मभूमि पर ऐतिहासिक मौजूदगी को देखते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वह ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को भी शामिल करे।

धर्माचार्यों ने जताया मुस्लिमों पर भरोसा

रघुवरशरण, अयोध्या

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड रामजन्मभूमि मामले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बोर्ड की यह पहल शीर्ष संतों को निराश करने वाली है। रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं मणिरामदासजी की छावनी के महंत नृत्यगोपालदास ने कहा कि यह निराशाजनक है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने की बात करता रहा है। अब निर्णय आने के बाद पुनर्विचार याचिका की बात कर अपनी ही बात से मुकर रहा है।

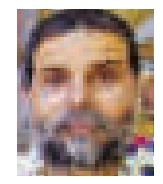

यह जिद स्वयं उनके लिए ही ठीक नहीं है। वे मुस्लिमों के बीच ही अलग-थलग पड़ जाएंगे।

-महंत बिंदुगाद्याचार्य देवेंद्र प्रसादाचार्य, आचार्य पीठ दशरथमहल बड़ा स्थान

विवाद की दुकान चलाने वाले मुट्ठीभर लोगों को छोड़कर देश के मुस्लिमों पर पूरा भरोसा है।

-महंत जन्मेजयशरण, रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष

पर्सनल ला बोर्ड का रुख मुस्लिमों की ही भावना के खिलाफ है। नौ दिन के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि आम मुस्लिमों ने फैसला स्वीकार किया है।

-शरद शर्मा, विहिप प्रवक्ता

यह विवाद की दुकानदारी जिंदा रखने की महज जिद है पर देश का हिंदू हो या मुस्लिम, अब उसे आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता।

-महंत रामदास, नाका हनुमानगढ़ी

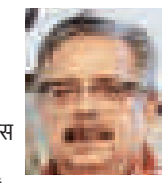

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सदियों पुराने विवाद का सम्माजनक समाधान निकला है। समझदारी इस फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़ने में है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि निर्णय देने वाली पीठ के सभी पांच जजों ने एक मत से फैसला दिया है।

- बिमलेंद्रमोहन मिश्र, राजा अयोध्या

यह एक प्रकार से अनर्थ है और सौहार्द की भावना के प्रतिकूल है।

-त्रिलोकीनाथ पांडेय, कोर्ट में रामलला के सखा

मुस्लिमों के नेतृत्व का दावा करने वालों के पास बहुसंख्यक हिंदुओं से रिश्तों को मजबूत करने का शानदार मौका था पर अब वे अवसर खोते प्रतीत हो रहे हैं।

-राजकुमारदास, शीर्ष पीठ रामवल्लभाकुंज के अधिकारी

मुस्लिमों के नेतृत्व का दावा ऐसे लोग कर रहे हैं, जिनमें नेतृत्व का रंचमात्र गुण नहीं है। **-महंत दिनेंद्रदास, निर्मोही अखाड़ा**

जस्टिस नजीर व उनके परिवार को मिलेगी जेड श्रेणी की सुरक्षा

नई दिल्ली, एएनआइ : अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों की ओर से जस्टिस नजीर को जान का खतरा बताए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और स्थानीय पुलिस को उनको सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

सरकार ने खतरे को देखते हुए सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस को तुरंत जस्टिस नजीर और उनके परिवार को कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इसके तहत जस्टिस नजीर को बेंगलुरु, मंगलुरु और कर्नाटक में कहीं जाने पर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इसी तरह की सुरक्षा उनके परिवार को बेंगलुरु और मंगलुरु में दी जाएगी। अयोध्या मामले से पहले जस्टिस नजीर 2017 में तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के भी सदस्य थे। जेड श्रेणी में अर्धसैनिक बल और पुलिस के 22 जवान किसी व्यक्ति की सुरक्षा में तैनात रहते हैं।

प्रस्तावित डिजाइन के लिए राम मंदिर को और 33 एकड़ जमीन की दरकार

नई दिल्ली, एएनआइ : अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगले साल अप्रैल में शुरू होगा और वर्ष 2022 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि प्रस्तावित डिजाइन के लिए अभी और 33 एकड़ जमीन की दरकार बताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए और अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल 67 एकड़ भूमि उपलब्ध है। लेकिन इस काम के लिए कुल 100 एकड़ जमीन की जरूरत है। लिहाजा और 33 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी।

सूत्र का कहना है कि जहां तक मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन का सवाल है, उसके लिए जमीन इस मंदिर परिसर में देना संभव नहीं। चूंकि मंदिर के लिए पहले ही 33 एकड़ जमीन कम पड़ रही है। मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन राज्य सरकार कहीं और देगी। मस्जिद बनाने के लिए प्रस्तावित पांच एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होगा। मस्जिद के लिए भूमि आवंटन का काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना है।

सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर राम मंदिर निर्माण के लिए भी ट्रस्ट बनाएगी। लेकिन इसमें 14-17 सदस्य हो सकते हैं। जबकि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में सिर्फ छह सदस्य हैं। नया ट्रस्ट बनाए जाने के बजाय पुराने राम जन्मभूमि न्यास में ही नए लोगों को शामिल करने के विकल्प पर भी चर्चा हो रही है।

मंदिर ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल को भी शामिल किया जाएगा। ट्रस्ट में कौन-कौन शामिल होगा इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। नया ट्रस्ट केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन पंजीकृत होगा। इस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार फिलहाल राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के पास है।

अयोध्या का मास्टर प्लान हो रहा तैयार : केंद्र सरकार अयोध्या के 388 वर्ग किलोमीटर के मास्टर प्लान को भी तैयार कर रही है। हनुमान गढ़ी को केंद्र बनाकर अयोध्या को फिर से डिजाइन करने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। अयोध्या को स्मार्ट सिटी की सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

40 फीसद काम पूरा : मुख्य आर्किटेक्ट

अहमदाबाद, एएनआइ : राम मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने कहा है कि आज की तारीख में राम मंदिर का 40 फीसद काम पूरा किया जा चुका है। लेकिन मंदिर परिसर के लिए और जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। मंदिर के निर्माण के लिए निर्धारित जमीन पर्याप्त होगी लेकिन मंदिर परिसर के निर्माण के लिए हमें और जमीन चाहिए। राम मंदिर का डिजाइन करीब तीस साल पहले तैयार करने वाले आर्किटेक्ट सोमपुरा ने रविवार को बताया कि फिलहाल मंदिर परिसर में भोजन के लिए एक हॉल, एक भोगशाला, पुजारियों के आवास, भक्तों को ठहराने के स्थान की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन मंदिर के टाउनशिप में अस्पतालों और होटलों के निर्माण की भी आवश्यकता है। ताकि यहां देश भर से ही नहीं, बल्कि विदेशी लोग भी आएं।

मंदिर में 250 स्तंभ, हरेक में राम की 16 प्रतिमाएं होंगी : उन्होंने बताया कि मंदिर में करीब 250 स्तंभ होंगे। प्रत्येक स्तंभ में राम की करीब 16 प्रतिमाएं होंगी। गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली रामलला की प्रतिमा करीब सात फीट लंबी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रस्तावित डिजाइन में तभी कोई बदलाव किया जाएगा, अगर वह शास्त्र सम्मत होगा।

कानून की ढाल और धर्म-शास्त्र का हथियार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सत्तर साल तक न्यायालय में चले मुकदमे में निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष को कानूनी दांवपेंच पर ही एतबार था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने की बात दोहराई जाती रही। मगर, फैसला रामलला के पक्ष में जाते ही मुस्लिम पक्ष ने यू-टर्न ले लिया है। पुनर्विचार याचिका के लिए कानूनी बिंदु तो वही चुने हैं, जिन पर लंबी जिरह हो चुकी है। साथ ही इसके सहारे अब मुस्लिम पक्ष ने धर्म-शास्त्र और शरीयत के आधार पर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी की है।

नौ नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजधानी में जो बैठक की, उसमें सबसे पहले कोर्ट के फैसले के बिंदुओं पर ही मंथन हुआ। तीन घंटे तक वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम के साथ मौलाना और मुस्लिम नेता ऐसे बिंदु छांटने में जुटे रहे, जिनके जरिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुचित करार दिया जा सके और पुनर्विचार याचिका दायर की जा सके। यहीं से एक तर्क यह निकाला गया है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात में बलपूर्वक रामचंद्र जी की मूर्ति तथा अन्य मूर्तियां रखा जाना अवैधानिक था। इस प्रकार अवैधानिक रूप से रखी गई मूर्तियों को देवता कैसे मान लिया गया। बोर्ड का तर्क है कि हिंदू धर्म-शास्त्र के अनुसार भी यह मूर्तियां देवता नहीं हो सकतीं। बोर्ड ने इस तथ्य को भी उठाया है कि बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे की भूमि को जन्मस्थान के रूप में पूजा किया जाना साबित नहीं है। अतः जन्मस्थान को देवता नहीं माना जा सकता। साथ ही तर्क दिया है कि बाबरी मस्जिद में 1857 से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया है। फिर मस्जिद की जमीन किस आधार पर रामलला को दे दी गई। इसी तरह पांच एकड़ भूमि लेने से इन्कार करने के लिए भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत को आधार बनाया है। कहा है कि शरीयत मस्जिद के बदले कुछ भी लेने की इजाजत नहीं देती है।

इस कानूनी तर्क पर भी जोर

संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते समय न्यायमूर्ति ने इस बात पर विचार नहीं किया कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 104-ए तथा 51(1) के अंतर्गत मस्जिद की जमीन के एक्सचेंज या ट्रांसफर को पूर्णतया बाधित किया गया है तो अनुच्छेद 142 के तहत मस्जिद की जमीन के बदले में दूसरी जमीन कैसे दी जा सकती है।

नींव में अशर्फियां मिलीं तो मंदिर को नाम मिला अशर्फीभवन

रघुवरशरण, अयोध्या : फैसला आने के बाद रामनगरी में यदि रामलला के भव्यतम मंदिर की प्रतीक्षा शुरू हो गई है तो उन मंदिरों की मौजूदगी मौजूं बन पड़ी है, जो रामजन्मभूमि के अलावा भी आस्था के केंद्र हैं। ऐसे मंदिरों में अशर्फीभवन अहम है। 80 वर्ष पूर्व वासंतिक नवरात्र की पावन बेला में स्थापित अशर्फी भवन प्रमुख उपासना केंद्र के साथ ही चमत्कारिक अतीत के लिए जाना जाता है। वह रामानुज संप्रदाय के समर्पित संत स्वामी मधुसूदनाचार्य थे जिन्होंने पूरे श्रम और यत्न से एकत्रित राशि देकर रामनगरी में लक्ष्मी-नारायण मंदिर के लिए भूमि क्रय की। निर्माण शुरू होने से पहले एक वास्तुविद ने बताया कि जहां निर्माण होना है, उस भूमि के नीचे हड्डियां और कंकाल हैं।

मंदिर स्थापना से जुड़ा स्वप्न खटाई में पड़ता देख व्यग्र मधुसूदनाचार्य गुरु गोपालाचार्य के दरबार में पहुंचे। गुरु ने शिष्य को आश्वस्त किया, तुम जैसा संत जहां चरण रखेगा, वहां हड्डी भी सोना बन जाएगी। गुरु के आश्वस्त करने पर मधुसूदनाचार्य ने मंदिर के लिए नींव की खोदाई शुरू कराई। इस दौरान मजदूरों को अशर्फी का घड़ा मिला। श्रमिक चुपके से उसे अपने घर ले गए पर चैन से नहीं रह सके। हार कर वे अशर्फी का घड़ा लेकर वापस पहुंचे। मधुसूदनाचार्य तो इतने से ही आह्लादित थे कि जिस भूमि में हड्डियां और कंकाल मिलने की आशंका थी, उससे गुरु के आशीर्वाद के अनुरूप अशर्फियां मिलीं। उन्होंने मंदिर निर्माण तो अपने कोष से जारी रखा और जो अशर्फियां मिलीं, उससे कई दिनों तक तीर्थों में भंडारा कराया। अशर्फियां तो भंडारे में प्रयुक्त हो गईं पर इस संयोग को आराध्य कृपा मान मधुसूदनाचार्य ने लक्ष्मी-नारायण मंदिर को अशर्फीभवन नाम दिया। आज अशर्फीभवन गोसेवा, संत सेवा, संस्कृत पाठशाला, धार्मिक-आध्यात्मिक गतिविधियों एवं संस्कार केंद्र के रूप में प्रवाहमान है।

दुनियाभर में बने आकर्षण का पर्याय : अशर्फीभवन के वर्तमान महंत जगदगुरु स्वामी श्रीधराचार्य इस विरासत को आचार्य और आराध्य की प्रत्यक्ष कृपा का परिचायक बताते हैं। प्रतिवर्ष वासंतिक नवरात्र में लक्ष्मी-नारायण के प्राकट्योत्सव के साथ विरासत के प्रति अनुराग पूरी भव्यता से परिलक्षित होता है।

कोएना का ओवैसी पर प्रहार, कहा-मुझे 40 हजार मंदिर वापस चाहिए

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बॉलीवुड अभिनेत्री कोएना मित्रा ने एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा शेयर एक आर्टिकल 'मुझे अपनी मस्जिद वापस चाहिए' पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि 'मुझे हमारे 40 हजार मंदिर वापस चाहिए।' इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी को इडियट तक कह डाला। दरअसल, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादित ट्वीट किया था। वहीं, दूसरी ओर बिग बॉस सीजन 13 से बाहर होने के बाद कोएना मित्रा लगातार चर्चा में बनी हुईं हैं। उन्होंने बिग बॉस में अपनी जिंदगी और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी कई खुलासे किए। इसी बीच अयोध्या फैसले पर ओवैसी ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि 'मुझे अपनी मस्जिद वापस चाहिए'। इस पर कोएना ने लिखा कि 'मुझे हमारे 40 हजार मंदिर वापस चाहिए।'

अयोध्या मामला बेहतरीन फैसले का उत्कृष्ट उदाहरण : जस्टिस शाह

अहमदाबाद, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि अयोध्या मामले में फैसला उच्च गुणवत्ता के फैसलों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस फैसले को मूर्तरूप देने में किए गए अथक परिश्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

'न्यायिक देरी और न्यायिक सुनवाई में असमर्थता' विषय पर निरमा यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए रविवार को जस्टिस शाह ने कहा कि जजों को खुद को किसी मामले से तब तक अलग नहीं करना चाहिए जब तक कि उस मुकदमे में उनके आर्थिक हित न जुड़े हों। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी परेशानी बड़ी तादाद में लंबित मामले और मुकदमों में असामान्य रूप से देरी है। इसके बावजूद उच्च श्रेणी के फैसले दिए गए हैं। इसका ताजा उदाहरण राम जन्मभूमि (अयोध्या) का फैसला है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह (अयोध्या) फैसला देने में कितना परिश्रम किया है। जनहित के मामले को 40 दिनों तक

जस्टिस एमआर शाह। फाइल

सुनना और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच संतुलन कायम रखते हुए फैसला करना और उसे सुनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामले में न्याय हो।

उल्लेखनीय है कि रविवार को सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने अयोध्या में विवादित स्थल पर एक सरकारी ट्रस्ट के जरिए राम मंदिर के निर्माण का फैसला विगत नौ नवंबर को दिया है।

रामलला के 'टाट से ठाठ तक' पहुंचने का खड़े-खड़े कर रहे इंतजार

आशीष कुलश्रेष्ठ, आगरा

अयोध्या में रामलला का मंदिर बने। लाखों-करोड़ों देशवासियों का यह सपना रहा है, लेकिन चरणदास उर्फ खड़ेश्वरी बाबा ने रामलला को टाट से ठाठ तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, वह वास्तव में चौंकाने वाला है। आठ साल से वह दिनरात खड़े रहकर मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद उन्हें संकल्प पूरा होने उम्मीद है, लेकिन मंदिर निर्माण होने तक वह अपने प्रण पर अडिग हैं।

आगरा के बटेश्वर में चल रहे वार्षिक कार्तिक मेले में चरणदास उर्फ खड़ेश्वरी बाबा को देखने-सुनने वालों की भीड़ जुटी रही है। दरअसल, वह अपने गुरु की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आठ वर्ष से खड़े रहने से उनके पांव फूल गए हैं, लेकिन संकल्प इतना कठोर कि वह मानने को तैयार ही नहीं हैं। कहते हैं, अब तभी बैठेंगे जब प्रतिज्ञा पूरी होगी।

गुरुजी जहां खड़े हो जाएं, फर्श भीग जाता था

पागलदास बाबा खड़े-खड़े ही ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन वचन नहीं त्यागा। चरणदास उर्फ खड़ेश्वरी बाबा कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि गुरुजी के पांव दरकने लगे। उनमें से खून और मवाद इस कदर बहता था कि जहां खड़े हो जाएं, जमीन का फर्श कुछ ही देर में भीग जाता था।

खड़ेश्वरी बाबा बताते हैं कि 1999 में फीरोजाबाद के कन्हैयानगर आश्रम के उनके गुरु महंत पागलदास बाबा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राममंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, वह जमीन पर खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। उन्होंने खड़े रहकर घोर तपस्या की और जीवन काट दिया। 20 दिसंबर, 2011 को बाबा पागल दास ने शरीर त्याग दिया। गुरुजी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं

आगरा : अपने गुरु पागलदास का संकल्प राममंदिर निर्माण को पूरा करने के लिए आठ वर्ष से खड़े चरणदास उर्फ खड़ेश्वरी बाबा। जागरण

हुई तो उन्होंने उनका प्रण पूरा करने की ठानी। 2011 से आज तक वह भी खड़े होकर ही सारे कार्य संपन्न करते हैं। झूले के सहारे झपकी लेकर समय व्यतीत कर रहे हैं। वह कहते हैं कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नई उमंग आई है, लेकिन प्रण तभी पूरा होगा, जब रामलला तिरपाल से हटकर भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे।

होगी खोज

तीन खदानों में हीरा होने की हो चुकी है पुष्टि, एनएमडीसी और सीएमडीसी मिलकर करेंगे तलाश

छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी हीरा उत्खनन की उम्मीद

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में अब तक तीन खदानों में हीरा होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन से अधिक खदानों में हीरा होने की उम्मीद की जा रही है। यहां अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान 1990 में पहली बार हीरा उत्खन्न की पहल हुई थी। निजी कंपनी को यह काम सौंपा गया था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की अनदेखी के कारण मामला 29 वर्ष से अटका हुआ है। मौजूदा सरकार की पहल से फिर से हीरा उत्खनन की उम्मीद बढ़ गई है।

सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के साथ मिलकर राज्य में नई हीरा खदानों की तलाश करने का फैसला किया है। एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) के साथ मिलकर महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में हीरा की तलाश करेगा।

छत्तीसगढ़ में अब तक यहां मिले हीरा होने के प्रमाण: गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरा खनिज की मातृशिला किंबरलाइट के छह पाइप बेहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली, कोसमबुड़ा और बेहराडीह टेंपल क्षेत्र में अंकित किए गए हैं। इसमें बेहराडही, बेहराडीह टेंपल और पायलीखंड क्षेत्र में किंबरलाइट पाइप में हीरे की उपस्थिति प्रमाणित हो चुकी है। निजी क्षेत्र में स्वीकृत खनिज रियायतों के फलस्वरूप महासमुंद और रायगढ़ जिले में भी हीरे मातृशिला किंबरलाइट के संकेत मिले हैं।

विवादों में पहला टेंडर: 1990 में पायलीखंड, बेहराडीह, जांगड़ा ,कोदोमाली और आसपास किंबरलाइट पाइप मिले, जिनमें हीरे मिलते हैं। तब तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने 4600 वर्ग किलोमीटर में एक निजी कंपनी को पीएल लाइसेंस जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहां की तत्कालीन सरकार शर्तों के उल्लंघन के कारण पीएल निरस्त कर दिया गया। 2008 में हाई कोर्ट के बाद यह मामला खान मंत्रालय के ट्रिब्यूनल में रिवीजन के लिए चला गया।

यहां भी तलाशी जाएगी संभावना

हीरा ब्लाक	शमिल जिले	क्षेत्र वर्ग किमी
आइबी मैनी	जिला जशपुर, रायगढ़, सरगुजा	4980
सारंगढ़	रायगढ़, जांजगीर, महासमुंद, बलौदाबाजार	4855
पिथौरा	गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार	4930
बेहराडीह	गरियाबंद, धमतरी	4600
कंकेर-केशकाल	कांकेर, बालोद, धमतरी, कोंडागांव	4680
नारायणपुर, लांजोर	कांकेर, कोंडगांव, नारायणपुर	4680
छोडोंगर	बस्तर, कोंडागांव	4380
तोकापाल	बस्तर दंतेवाड़ा	4505

टैक्स फ्री राज्य की हुई थी कल्पना

हीरा खदानों के दम पर ही छत्तीसगढ़ को टैक्स फ्री राज्य बनाने की कल्पना की गई थी। राज्य में अजीत जोगी के नेतृत्व में बनी पहली सरकार के दौरान यह बात बार- बार कही गई। इस बीच राज्य सरकार का वार्षिक बजट सात हजार करोड़ से बढ़कर एक लाख करोड़ के पार पहुंच गया है।

पंजाब में नशा करते एएसआइ व हेडकांस्टेबल का वीडियो वायरल, सस्पेंड

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन: डोप टेस्ट में तरनतारन के कई पुलिस मुलाजिमों के फेल होने के बाद इसमें एक और दाग जुड़ गया है। थाना पट्टी में तैनात एएसआइ और हेडकांस्टेबल का हेरोइन पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर एसएसपी ध्रुव दहिया ने दोनों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं। तीन दिन पहले जिला पुलिस के दो दर्जन मुलाजिमों के डोप टेस्ट हुए थे। इसमें कई फेल हो गए थे। इस पर डीएसपी ने रिपोर्ट बनाकर शुक्रवार को एसएसपी को सौंपी थी। रविवार को एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें थाना पट्टी में तैनात एएसआइ दर्शन सिंह हेडकांस्टेबल टहल सिंह के साथ कमरे में बैठकर हेरोइन के कश लगाते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। डोप टेस्ट में फेल होने वाले पुलिस कर्मियों की सूची में एएसआइ दर्शन सिंह और हेडकांस्टेबल टहल सिंह का नाम भी शामिल है। इस पर एसएसपी ध्रुव दहिया ने दोनों को सस्पेंड कर दिया।

पीएमसी बैंक घोटाले में पूर्व भाजपा विधायक के बेटे के घर की तलाशी

मुंबई, प्रेट्र : पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमस

दैनिक जागरण

जीवन ताउम्र चलने वाली पाठशाला के समान है

कलह का रास्ता

इस पर हैरानी नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या फैसले को नामंजूर करते हुए उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया। इसके आसार तभी उभर आए थे जब अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसले आने के बाद से ही कुछ मुस्लिम नेता अपने पुराने रवैये का परित्याग करते दिखने लगे थे। जो मुस्लिम नेता पहले यह कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा वह उन्हें स्वीकार होगा वे बाद में उसे अस्वीकार करने के लिए तरह-तरह के बहाने गढ़ने लगे। किसी को फैसला आस्था के आधार पर होते हुए दिखा तो किसी ने उसमें विरोधाभास खोजना शुरू कर दिया। शायद यह माहौल इसीलिए बनाया गया ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अयोध्या फैसला अस्वीकार करने के लिए आसानी से तैयार किया जा सके। निःसंदेह किसी भी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर किया जाना एक अधिकार है। यदि अयोध्या मामले के पक्षकार इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक तो प्रमुख पक्षकार इकबाल अंसारी फैसले को चुनौती देने की जरूरत नहीं समझ रहे और दूसरे, जो लोग उनसे अलग रास्ता पकड़ रहे हैं वे यह भली-भांति जान रहे हैं कि अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि अयोध्या मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना फैसला सर्वसम्मति से सुनाया। आखिर यह जानते हुए भी अयोध्या फैसले को चुनौती देने का क्या मतलब कि इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है? यह केवल समय की बर्बादी ही नहीं, बल्कि कलह के रास्ते पर जानबूझकर चलने की कोशिश भी है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर हठधर्मी दिखाने पर तुल गया है, इसका पता उसके नेताओं के इस बयान से चलता है कि शरई कानून के मुताबिक मस्जिद की जमीन किसी और को नहीं दी जा सकती। वे अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेने से भी इन्कार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अयोध्या में तो पहले से ही 27 मस्जिदें हैं। क्या इसका यह मतलब नहीं कि वे बाबर के नाम पर बनाई गई मस्जिद को हासिल करने की ललक दिखा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हिंदू ढांचे पर बनी बाबरी मस्जिद इन 27 मस्जिदों से अलग और विशिष्ट कैसे थी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिद पूरी करने या फिर खुद को पीड़ित दिखाने के लिए अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र है, लेकिन वह याद रखे तो बेहतर कि भारतीय मुस्लिम समाज को आक्रमणकारी बाबर से जोड़ना उसका अपमान करना है।

टैब पर सवाल

झारखंड सरकार द्वारा शिक्षकों को दिए गए टैब विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक बंद रहेंगे। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शिक्षकों को फिलहाल टैब को नहीं खोलने तथा बायोमिट्रिक उपस्थिति इससे नहीं बनाने का आदेश दिया गया है। शिक्षक लगभग दो माह अपने मोबाइल से बायोमिट्रिक उपस्थिति बनाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? दरअसल राज्य सरकार द्वारा हजारों शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टैब के खुलने पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो प्रसारित होता है, जिसमें मुख्यमंत्री डिजिटल इंडिया को लेकर एक संदेश देते नजर आते हैं। इस तरह का वीडियो प्रसारित होना आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है। टैब में मुख्यमंत्री का संदेश आना कोई गलत नहीं है, लेकिन यह सवाल लाजिमी है कि इस वीडियो को कुछ समय के लिए क्यों नहीं हटाया जा सका? यदि समय पर कुछ दिनों के लिए वीडियो हटा लिए जाते तो टैब के इस्तेमाल नहीं करने का आदेश देना नहीं पड़ता। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय भी लगभग दो माह टैब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। उस समय शिक्षकों ने मैनुअल हाजिरी बनाई थी। टैब के संचालन के लिए लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों को तो उसी समय सचेत होकर समय पर यह काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही होना था। इधर शिक्षक निजी मोबाइल से बायोमिट्रिक उपस्थिति बनाने का विरोध कर रहे हैं। वे इसे निजता का उल्लंघन बताते हैं। हालांकि शिक्षकों को मोबाइल रिचार्ज के लिए प्रतिमाह 300 रुपये विद्यालय विकास अनुदान से देने पर सहमति दी गई है। प्रति विद्यालय किसी एक शिक्षक को यह राशि दी जाएगी, जिसके मोबाइल से उस विद्यालय के सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति बनाएंगे। इसका भी विरोध हो रहा है। जो भी हो, अब जरूरत इस बात की है कि शिक्षक दो माह तक मोबाइल से ही बायोमिट्रिक उपस्थिति बनाएं। पदाधिकारियों को भी भविष्य में इस तरह की लापरवाही से बचने का प्रयास करना चाहिए। उनका यह व्यवहार लचर कार्यप्रणाली का एक बड़ा उदाहरण है।

> लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया, अब फिर दो माह तक शिक्षकों के टैब इस्तेमाल करने पर लगी रोक

संवैधानिक मर्यादा के साथ होगा मंदिर निर्माण

रविशंकर प्रसाद

> अयोध्या विवाद लंबे अर्से से कायम था। इसमें आस्था और भावनाओं का टकराव था। इसका न्यायिक मर्यादा के साथ हल सभी के लिए हर्ष एवं संतोष का विषय है

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि स्थल रामलला विराजमान को सौंपने का फैसला किया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मंदिर निर्माण के लिए तीन महीनों के भीतर एक न्यास बनाए। इसी न्यास को भारत सरकार वह 2.77 एकड़ जमीन भी सौंपेगी जिस पर फिलहाल रिसीवर के रूप में उसका नियंत्रण है। न्यास ही मंदिर निर्माण की पूरी व्यवस्था करेगा। यदि इसके लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता हुई तो वह भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसे उस भूमि से दिया जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने भू अर्जन के जरिये अपने नियंत्रण में लिया है। फैसले में मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। अयोध्या की सीमा में यह जमीन भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

गरिमा और नैतिक आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन के प्रमुख तत्व हैं। राम कथा हजारों वर्षों से आम भारतीयों की प्रेरणा है। राम भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक विरासत के प्रमुख अंग हैं। इस लिहाज से अदालत का सर्वानुमति से आया फैसला देश की संवैधानिक मर्यादा का अप्रतिम उदाहरण है। राम मंदिर भारत की न्यायिक और संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप बनने जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष मुझे भी रामलला विराजमान और हिंदू पक्ष की पैरवी का अवसर मिला।

सुप्रीम कोर्ट को मुख्य रूप से चार मामलों में फैसला सुनाना था। पहला मामला रामलला के भक्त गोपाल विशारद से जुड़ा था। दूसरा निर्मोही अखाड़े का। तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड का। और चौथा रामलला विराजमान का जिसमें मांग थी कि विवादित जमीन का मालिकाना हक घोषित किया जाए और उनके भक्तों को पूजा का अधिकार मिले। इसमें अदालत ने निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली। 2003 में अदालत ने निर्देश दिया कि विवादित स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा खोदाई की जाएगी। इससे हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्ष आशंकित थे कि इसका क्या नतीजा निकले। बहरहाल आदेश में अदालत ने यह भी तय किया कि उत्खनन में दो तिहाई मजदूर हिंदू और एक तिहाई मजदूर मुसलमान होंगे। उत्खनन के बाद एएसआइ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विवादित ढांचे के नीचे दसवीं शताब्दी से निर्माण की प्रक्रिया के संकेत मिले हैं। इसमें कमल का चिन्ह, गोल आकार की मूर्ति जिसमें प्रणाला भी था, जैसे कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले जो उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इसके मुताबिक विवादित बाबरी मस्जिद पुराने अवशेष की दीवारों पर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में इसका संज्ञान लिया। उसने माना कि जहां से पुरातात्विक अवशेष मिले वहीं विवादित मस्जिद के आधारभूत स्तंभ हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि खोदाई में मिली वस्तुएं हिंदू धार्मिक भावनाओं की प्रतीक हैं।

अब दूसरे पहलू पर दृष्टि डालते हैं। 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने से जुड़े मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इसमें साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यदि ढांचा नहीं गिरता तो क्या अदालत खोदाई के आदेश देती। तब क्या जमीन के भीतर दफन भारत की सैकड़ों वर्ष पुरानी शाश्वत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा सामने आ पाती।

इस मामले में हजारों पन्नों के सुबूत उपलब्ध हैं। दस्तावेजी साक्ष्य भी थे। दोनों पक्षों की ओर से गवाहियां भी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया। इसमें कई विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत का उल्लेख बहुत आवश्यक है। जोसफ ट्राइफेनथेलर एक जेसुएट मिशनरी थे। उन्होंने 1740 ई. में भारत की यात्रा की। वह अयोध्या भी गए। इस पड़ाव को उन्होंने अपने वृतांत में 'अजुध्या' कहा। उनके अनुसार अयोध्या पवित्र नगरी है जहां एक वेदी है। वहां बेशचन (विष्णु) राम के रूप में पैदा हुआ थे। एएसआइ के महानिदेशक रहे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1862 की अपनी रिपोर्ट में अजुध्या को राम का जन्म स्थान बताया। फैजाबाद के आयुक्त और सेटलमेंट अधिकारी पी कनिंघम ने 1870 की रिपोर्ट में यह कहा, 'अयोध्या का हिंदुओं के लिए वही महत्व है जो महत्व मुसलमानों के लिए मक्का का है।' इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि राम जन्मस्थान पर प्रार्थना करते हुए उनके भक्तों ने सैकड़ों वर्षों तक विशेष धार्मिक संतोष प्राप्त किया। अदालत के अनुसार उक्त स्थान पर एक इस्लामिक ढांचे का निर्माण भी भक्तों के इस विश्वास को नहीं हिला पाया कि यह भगवान राम का जन्मस्थान नहीं है।

अदालत के अनुसार मुस्लिम पक्ष द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि 1857 के पहले विवादित भूमि पर उनका एकाधिकार या नियंत्रण था। ऐसा भी कोई सुबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद उन्होंने वहां सवा तीन सौ साल तक नमाज अदा की। अदालत ने यह भी पाया कि मुस्लिम गवाहों ने भी स्वीकार किया कि ढांचे के ऊपर वराह, जय विजय और गरुड़ आदि धार्मिक चिन्ह थे। उसके अनुसार ये आस्था और विश्वास का संकेत नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से होने वाली पूजा को भी स्पष्ट करता है।

यह विवाद लंबे अर्से से कायम था। इसमें आस्था और भावनाओं का टकराव था। कई बार हिंसा भी हुई। मगर सत्य में इतनी शक्ति होती है कि वह उजागर होता ही है, भले ही इसमें कुछ समय लगे। यह सच न्यायिक मर्यादा के जरिये सामने आया। यह हर्ष एवं संतोष का विषय है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष अभिनंदन भी आवश्यक है। उनकी अपील ने देश में शांति, सद्भाव और भाईचारा बनाने में बहुत मदद की। यह एक नए आशावान, ऊर्जावान और भाईचारे की भावना से प्रेरित भारत के उदय का समय है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भारत की समावेशी और आत्मसात करने वाली परंपरा का उल्लेख किया है जो धर्म पूजा और उपासना पद्धति को भी संस्कृति, समाज के युगानुकूल ढलने की प्रेरणा देती है। इस्लाम सहित कोई भी धर्म या पूजा पद्धति इसका अपवाद नहीं है, बल्कि यह भारतीय परंपराओं की विशेषता भी है जो किसी धर्म को कमजोर नहीं करती। संभवतः यह कबीर, रहीम और रसखान की विरासत की विजय है। न यह किसी की हार है और न किसी की जीत है, बल्कि यह भारत की विजय है।

(लेखक केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला और हिंदू पक्ष के वकील भी रह चुके हैं)

response@jagran.com

संस्कृत की महत्ता समझने का समय

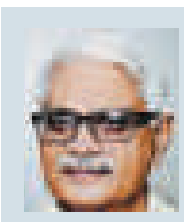

गिरीश्वर मिश्र

> भौतिकता पर केंद्रित पश्चिमी सभ्यता मनुष्य के अस्तित्व को ही प्रश्नांकित कर रही है। अब संस्कृत ही सही विकल्प है

बीते दिनों नई दिल्ली में विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कई देशों ने शिरकत की। ऐसे में संस्कृत की प्रासंगिकता पर नए सिरे से विचार की दरकार लगती है। आज वैश्वीकरण के प्रभाव में जिस वेग से पश्चिमी जीवन शैली और सांस्कृतिक मूल्य चारों ओर छाते जा रहे हैं उसकी विसंगतियों को लेकर अनेक देशों के विचारक विकल्पों की तलाश में हैं। इस दौर में भारतीय सभ्यता का विशेष महत्व आंका जा रहा है जो मनुष्य की जगह समग्र सृष्टि को ध्यान में रखकर उसके विभिन्न तत्वों की परस्पर-निर्भरता पर बल देती है। इस प्रकार के चिंतन में संस्कृत भाषा और साहित्य के विभिन्न पक्षों के अध्ययन की प्रमुख भूमिका है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें इस तथ्य को भी याद रखना चाहिए कि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय मानस की मुक्ति की संभावना और रचनात्मकता का दमन किया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय प्रतिभा ने अपनी रंगत और चरित्र ही खो दिया। पश्चिम की नकल के चलते हमारी अमूल्य विरासत आज विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए भारतीय विचारों और ज्ञान-परंपराओं का विनष्ट होना पश्चिमी दुनिया समेत संपूर्ण विश्व की भी अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है जिसमें संस्कृत एक अहम कड़ी होगी।

संस्कृत की परंपराएं मात्र मनुष्य ही नहीं, बल्कि जीवन और प्राणिमात्र के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। भिन्न-भिन्न देश काल में बहुलता के साथ पनपा यह ज्ञान जीवन-शैली, कलाओं, शिलालेखों, अनुष्ठानों, काव्य और आस्थाओं आदि रूपों में अभिव्यक्त होता रहा है। इनके बारे में रोचक तथ्य यह है कि इनमें किसी एक के वर्चस्व की जगह अनेकता या बहुलता का महत्व प्रकट होता है। इनका एक प्रमुख संदेश यह भी है कि मनुष्य प्रकृति का ही एक अंश है न कि उसका नियंता। आज जीवों का विलोप, जलवायु-परिवर्तन, सामूहिक विद्वेष, नरसंहार और प्रकृति का दोहन संस्कृत की मैत्री, सह-अस्तित्व और सहकार वाली जीवन शैली के विरुद्ध है। वाचिक परंपरा जो समुदायों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही थी, वह अब वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में तिरोहित होती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, पुरखों के प्रति ममत्व, अगली पीढ़ी के प्रति दायित्व और आध्यात्मिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं। आज जैविक और सांस्कृतिक रूपों की विविधता नष्ट हो रही है। प्रकृति के साथ अटूट रिश्ता और टिकाऊ अर्थव्यवस्था आज भौतिकता और उपयोगितावाद की भेंट चढ़ रही हैं। प्रकृति को पवित्र न मानकर उसका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। विकसित देशों में, जहां का मानव विकास सूचकांक ऊंचा है वहां उत्पादन और उपभोग का स्तर भी स्वाभाविक रूप से उतना ही ऊंचा है। वहां छोटी सी जनसंख्या द्वारा अधिकांश संसाधनों का उपयोग किया जाता है। दुनिया पर एकछत्र अधिकार जमाने की अवधारणा के चलते धरती को खंगालना, मानवता का मानकीकरण, हिंसा, युद्ध, सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता मूलतः निरपेक्ष पश्चिमी विचारों की देन हैं।

वैदिक काल से ही यह स्वीकृत है कि इस धरती पर भिन्न-भिन्न भाषाओं और धर्मों के लोग रहते हैं। एक सत्य का अनेक ढंग से वर्णन किया जाता है। साथ ही इसमें मन, हृदय और कर्म की एकता पर भी बल दिया गया, ताकि सबके बीच सहृदयता बनी रहे। जीवों की परस्पर-निर्भरता तथा समस्त ब्रह्मांड की संबद्धता का भाव निरंतर उपस्थित है। इस परंपरा में अंतः सांस्कृतिक संवाद का भी अवसर बना, जिसका आधार मूलतः नैतिक आचरण था। करुणा, मध्यम मार्ग, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, भक्ति, धर्म, अहिंसा, दान, परोपकार, आत्मसंयम तथा संस्कार जैसी अवधारणाओं के साथ समाज के संचालन की व्यवस्था की गई थी। संस्कृति द्वारा प्रकृति के परिष्कार द्वारा मनुष्य की सहभागिता द्वारा संतुलन की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस दृष्टि में बहुसांस्कृतिक समाज के लिए एक आधार-दृष्टि मिलती है जिसमें पारस्परिक भरण-पोषण तथा साझेदारी, आदर की प्रमुखता है। ऐसी समावेशी और मानवीय दृष्टि के साथ संस्कृत की ज्ञान परंपरा लोभ और हिंसा का विकल्प देती है। इसके अंतर्गत टिकाऊ विकास के लिए जरूरी व्यापक पारिस्थितिक नजरिये के साथ प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया गया है। नदी, नगरी और पर्वतों को पवित्र तीर्थ की महत्ता देकर उनका संरक्षण और परम तत्व की उपस्थिति से अनुप्राणित स्वीकार कर शरीर, विश्व और विश्वात्मा का संबंध स्थापित किया गया। वेद, पुराण, काव्य, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र, योग, शिल्प, वृक्षायुर्वेद, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, दर्शन आदि के सुदृढ़ अध्ययन की परिपाटी स्थापित हुई। ये सभी सार्वभौम मानवीय सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। इनमें लोक-कल्याण के लिए मानक कर्तव्य के भाव को प्रमुखता दी गई। इन सबमें शास्त्र और प्रयोग को परस्पर संबद्ध रखते हुए वस्तुवादी और उपयोगितावाद से बचने का यत्न किया। इस परंपरा का विस्तार कभी सुदूर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व तथा मध्य एशिया तक ब्राह्मण गुरुओं, सम्राट अशोक के दूतों, बौद्ध और जैन भिक्षुओं द्वारा किया गया।

आज पश्चिमी सभ्यता में गहरी त्रासदी देखी जा सकती है जो मनुष्य के अस्तित्व को ही प्रश्नांकित कर रही है। आधुनिकता और विकास के तर्क की सीमाएं दिख रही हैं। विकासवाद वाली आधुनिकता को विकास का चरम मानना भ्रामक और प्रगति भी एक मिथक लगने लगा है। सामाजिक विकासवाद को मानें तो भविष्य में विश्व नष्ट हो जाएगा। सुख की उपयोगितावादी विचारधारा नाकाफी है, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक पूरकता का रिश्ता ही जीवन को संभव बनाता है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन होना चाहिए। तभी लोक-संग्रह या जन-कल्याण का लक्ष्य पाया जा सकेगा। ऐसे में विस्मृत होती संस्कृत ज्ञान की समृद्ध परंपरा को रचनात्मकता और सुधार के साथ पुनर्जीवित और स्थापित करना एक मानवीय आवश्यकता है। इसके लिए खुले मन से संस्कृत ज्ञान परंपरा के संरक्षण, अनुकूलन और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना होगा।

(लेखक शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता की चाह

आजकल हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन सफलता उससे भी तेज गति से पलायन कर रही है। कुछ लोग शीघ्र से शीघ्र सफलता अर्जित करने के लिए शॉर्टकट की राह भी चुनने में देर नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप उनके हाथों नाकामयाबी ही आ रही है। आखिर सफलता का रहस्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना और सफलता को भलीभांति समझे बिना उसे पाने की हर कोशिश व्यर्थ ही है। कुछ लोग सफलता का सही अर्थ समझे बिना ही व्यर्थ की होड़ में लगे रहते हैं। वे समझते हैं कि सफलता कोई पड़ाव है। असल में सफलता कोई पड़ाव न होकर निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है।

सफलता को पाने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। मेहनत और सफलता का रिश्ता चोली दामन का कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सफलता का सुनहरा सपना देखने वालों को अपनी योग्यता पर भरोसा होना चाहिए। जब योग्यता आ जाती है तो सफलता की राह बेहद ही आसान हो जाती है। सफलता जैसे शब्द के हर व्यक्ति की नजर में अलग-अलग मायने हो सकते हैं। एक छात्र के लिए नौकरी और अधिक धन की प्राप्ति सफलता का एक पहलू हो सकता है। भले ही मायने ढेरों हों पर सभी के लिए सफलता तक पहुंचने का एक ही विकल्प है-धैर्य और परिश्रम, लेकिन आज के युग में सबसे बड़ी कमी है तो धैर्य की। त्वरित परिणाम की चाह में हम अक्सर बेकाबू होकर गलत राह की ओर अग्रसर होकर सफलता के सन्निकट होने के बावजूद दूर हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी आने लगता है जब हम किंकर्तव्यविमूढ़ की दशा में पहुंच जाते हैं। फिर जिंदगी में तनाव और आक्रोश का अनायास ही प्रवेश होना लगता है।

अतः कहा भी गया है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले, न किसी को मिला है और न मिलेगा। असफलता के बाद भी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

देवेंद्रराज

सिलिकोसिस नीति से जगी उम्मीदें

सुधीर कुमार

> सिलिकोसिस के खतरे वाले उद्योगों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर निम्न आय वर्ग से संबंधित होते हैं

गत दिनों राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस बीमारी से जूझ रहे मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए अपने राज्य में सिलिकोसिस नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत रोगियों की पहचान, उनके पुनर्वास तथा रोकथाम के भी प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद सिलिका के कणों के बीच सांस लेने को विवश हजारों मजदूरों ने राहत की सांस ली है। सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों को अब 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, जबकि 4 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह नीति जारी करने वाला हरियाणा के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य बन गया है।

सिलिकोसिस मुख्यतः फेफड़ों से जुड़ी एक लाइलाज बीमारी है। यह रोग सिलिका मिश्रित धूल के संपर्क के कारण होता है। सिलिका या सिलिकन डाईऑक्साइड पत्थर, बालू, ईंट, ग्रेनाइट, कांच और सीमेंट के महीन कणों में मौजूद होती है। यह मुख्यतः खनन, क्रशर, निर्माण एवं ढुलाई कार्य, मिट्टी के बर्तन और स्लेट-पेंसिल आदि बनाने वाले उद्योगों में उत्सर्जित होती है। जो मजदूर इन उद्योगों में काम करते हैं, वे कालांतर में इस बीमारी के शिकार बन जाते हैं। दरअसल एक नियमित प्रक्रिया के तहत श्वसन के जरिये सीलिका के कण मजदूरों के फेफड़ों में जमा होते जाते हैं और फेफड़ों की दीवारों पर धीरे-धीरे जम कर एक मोटी परत बना लेते हैं। इससे फेफड़े खराब होने लगते हैं और एक दिन पीड़ित व्यक्ति की सांस लेने की क्षमता ही छिन जाती है! एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10 लाख से अधिक श्रमिकों पर सिलिकोसिस का खतरा है। इसकी भयावहता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी पहचान होने के बाद मरीजों को जो प्रमाणपत्र मिलता है, उसे वे अपना 'डेथ वारंट' या 'डेथ सर्टिफिकेट' बताते हैं।

इस बीमारी का एकमात्र इलाज इससे बचाव ही है। सिलिकोसिस के खतरे वाले उद्योगों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर निम्न आय वर्ग से संबंधित होते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते। वहीं कई बार कारखानों के मालिक और ठेकेदार भी मजदूरों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नजर नहीं आते हैं। 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस बीमारी के प्रति जनजागृति और बचाव कार्यक्रम शुरू किया था और 2030 तक इस बीमारी को पूरी दुनिया से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य बनाया था। भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मजदूरों के ऊपर सिलिकोसिस का खतरा सर्वाधिक है।

1948 के फैक्ट्री अधिनियम में श्रमिकों के लिए हवादार वातावरण, धूलकण से बचने के उपाय तथा बुनियादी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का नियम तो बनाया गया है। निर्माण एवं खनन कंपनियों को चाहिए कि वे अपने मजदूरों के लिए मास्क और विशेष सुरक्षित पोशाक तथा नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

सामूहिक नाकामी का सबब

प्रदूषण नियंत्रण पर निराशाजनक रवैया शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने ठीक ही कहा है कि केंद्र और राज्यों को यह समझने की सख्त जरूरत है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उनकी ओर से बहुत कुछ किया जाना शेष है। मेरा मानना है कि जलवायु में जीवन-यापन के लिए मुख्य दो अवयव जल और वायु हैं। दुख की बात यह है कि ये जल और वायु, दोनों ही आज जीवन को जीने देने के बजाय शनैः शनैः मारने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति विगत कई वर्षों से नवंबर महीने में दिल्ली में सभी देखते हैं। इसमें जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक संसाधन का कोई दोष नहीं है। शायद पूरा समाज और उसमें रहने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। पराली, पंजाब-हरियाणा के किसान, धुआं, स्मॉग आदि की गूंज कुछ दिन सुनाई पड़ती है और धीरे-धीरे दिसंबर के बाद सन्नाटा हो जाता है। सवाल है कि इस समस्या का निदान कैसे होगा? इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। 135 करोड़ जनता अपनी भावी पीढ़ी के अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी आमदनी में से कुछ उपकर जल और वायु की रक्षा के लिए सरकार के मांगने या लगाने से पहले खुद ही देने का प्रस्ताव कर दे, ताकि सरकार कोई व्यवस्था कर सके या ढांचा खड़ा कर सके। यह भारत की परंपरा में एक नवाचार होगा। यह तो देर-सवेर करना ही होगा। हम यह जितना जल्दी करेंगे उतना ही जीवन बचा पाएंगे। हम सभी धरती पर पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं तो कुछ तो समुचित किराया दें। अब बात बहुत हो चुकी, समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए कारगर काम शुरू होगा तभी प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी।

प्रो. मान सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

कांग्रेस की विफल नीति

दैनिक जागरण के 14 नवंबर के अंक में संपादकीय, झूठ की राजनीति बेनकाब, में सही लिखा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया तो स्पष्ट है कि यह अभियान सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए चलाया गया। निःसंदेह ऐसा ही हुआ है। असल में कांग्रेस भी येन केन प्राकरेण सत्ता की चौखट तक पहुंचना चाहती थी। इसी वजह से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चोर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आम चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जमकर राफेल मुद्दे का दोहन किया, लेकिन वह अपने ही बयानों में फंसते गए। कभी राफेल की कीमत 540 करोड़ बताई तो कहीं 524 करोड़ बता दी और अंत में 700 करोड़ बता दी। कभी कहते मोदी ने तीस हजार करोड़ अंबानी की जेब में डाल दिए। ऐसे बयानों का जनता पर कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस राफेल मुद्दे को बोफोर्स का रंग देना चाहती थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए था कि राफेल सौदे पर कीचड़ उछालने से बोफोर्स के दाग नहीं धुल सकते। उच्चतम न्यायालय ने अब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

याद किए जाएंगे गोगोई

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर, 2019 को रिटायर हो गए। उन्होंने कोर्ट में अपने आखिरी दिन के कामकाज को संभालने से पहले अपनी पत्नी के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर एक उच्च आदर्श स्थापित किया है। उन्हें मात्र 13 माह के कार्यकाल में कई एतिहासिक फैसले सुनाने का गौरव प्राप्त हुआ। एक राजनीतिक परिवार से होते हुए भी उन्होंने अपने काम में कभी इसका असर नहीं आने दिया। ऐसे उच्च आदर्श व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को आज की राजनीति में होना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र को स्वच्छ बनाया जा सके।

बदरी प्रसाद भागवत, किशनगंज

हर व्यक्ति सहयोग करे

दिल्ली के दम घोंटू प्रदूषण में लोग सांस लेने को विवश हैं। ऑड-इवेन भी प्रदूषण को रोकने में बहुत कारगर नजर नहीं आया। लोगों को चाहिए कि वे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के प्रयास पर ही निर्भर न रहें। खुद भी जो हो सके प्रयास करें। वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। खुले में कूड़ा न जलाएं। सरकार तो अपने स्तर पर योजनाएं बनाकर काम करेगी ही। अगर हर नागरिक अपना कर्तव्य समझकर इसमें सहयोग करे तो इस पर काबू पाने में सहूलियत होगी।

anandchetri621@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक

31 फीसद का नुकसान हुआ है अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के कारण। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह बात कही गई है।

आजकल

जलवायु आपातकाल के पैदा होते हालात

मनीषा सिंह
स्वतंत्र पत्रकार

हाल ही में जर्नल-बायोसाइंस द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि पिछले 40 वर्षों में ग्रीनहाउस गैसों के अबाध उत्सर्जन और आबादी बढ़ने के साथ-साथ पृथ्वी के संसाधनों के अतिशय दोहन, जंगलों के कटने की रफ्तार बढ़ने, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और मौसम के पैटर्न में बदलाव से हालात जलवायु आपातकाल वाले हो गए हैं। इससे निपटने के उपायों को युद्धस्तर पर लागू नहीं किया गया तो हमारी सांसों और रगों में घुलते प्रदूषण के जहर को बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा

इस दुनिया को यूं तो बदलना ही था। जैसी धरती हमें सदियों पहले मिली थी, उसका चेहरा हमेशा ठीक वैसा ही तो नहीं रह सकता था, क्योंकि विकास की कीमत हमारे इसी पर्यावरण को अदा करनी थी, लेकिन यह धरती और इसका पूरा माहौल औद्योगिक क्रांति के डेढ़ सौ बरस में ही इतना ज्यादा बदल गया है कि वैसा कुछ पृथ्वी पर जीवन के विकास के हजारों साल लंबे इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसकी एक गवाही 40 साल पहले जेनेवा में आयोजित हुए पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (क्लाइमेट कांफ्रेंस) से मिलती है, जिसमें जुटे विज्ञानियों ने प्रदूषण के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई थी। इधर कुछ वैसी ही चिंता दुनिया भर के 11,258 वैज्ञानिकों ने यह कहते हुए प्रकट की है कि अगर जल्द ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई गई तो इंसानों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जलवायु आपातकाल (क्लाइमेट इमरजेंसी) का वक्त आ पहुंचा है।

हाल ही में जर्नल-बायोसाइंस द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत समेत दुनिया के 153 देशों के 11,258 वैज्ञानिकों ने एक स्वर में कहा है कि पिछले 40 वर्षों में ग्रीनहाउस गैसों के अबाध उत्सर्जन और आबादी बढ़ने के साथ-साथ पृथ्वी के संसाधनों के अतिशय दोहन, जंगलों के कटने की रफ्तार बढ़ने, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और मौसम के पैटर्न में बदलाव से हालात सच में क्लाइमेट इमरजेंसी वाले हो गए हैं। दुनिया के कुछ देशों ने तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने की पहल भी कर दी है, जैसे इसी साल मई में आयरलैंड की संसद ने जलवायु आपातकाल घोषित किया था। आयरलैंड से पहले यह कदम ब्रिटेन ने उठाया था, जो एक मई, 2019 को ऐसा आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। वहां यह कदम लंदन में एक आंदोलन के बाद उठाया गया था। इस आंदोलन का मकसद 2025 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा शून्य पर लाने और जैवविविधता के नुकसान को पूरी तरह खत्म करना है। सवाल है कि आखिर इस किस्म के आपातकाल को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ रही है?

इसके पीछे कुछ कारण तो बिल्कुल साफ हैं। प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जैसी चीजें एक समस्या हैं, पर ये असल में इंसान की उस प्रवृत्ति की देन हैं, जिसमें उसने इस जीवनदायिनी धरती से सिर्फ लेना सीखा है, उसे लौटाना नहीं। यही वजह है कि पृथ्वी की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। हम भले ही विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस जैसे आयोजन कर लें, पर सच्चाई यह है कि इसकी परवाह कोई नहीं कर रहा है कि पृथ्वी का इतने तरीकों से और इतनी अधिक बेदर्दी से दोहन हो रहा है कि धरती हर पल कराह रही है। पृथ्वी के वायुमंडल में पहले से ज्यादा जहरीली गैसें और गर्मी घुल गई है। इस गर्मी के चलते गंगोत्री और अंटार्कटिका-आर्कटिक जैसे ग्लेशियर तेजी से पिछलने लगे हैं। इन वजहों से पृथ्वी के जीवन में रंग घोलने वाली तितलियों, मधुमक्खियों, मेंढक एवं मछलियों, चिड़ियों, दुर्लभ सरीसृपों और विभिन्न जीव-जंतुओं की सैकड़ों किस्में हमेशा के लिए विलुप्त हो गई हैं। जंगल खत्म हो रहे हैं, पानी का अकाल पड़ रहा है। मरुस्थलों के फैलाव की रफ्तार में तेजी आ रही है, कार्बन डाईऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। अब तो नदियों के ही अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है।

हालांकि इसमें संदेह नहीं है कि बीते 40-50 वर्षों की अवधि में दुनिया में पृथ्वी की सेहत यानी पर्यावरण संबंधी मामलों को लेकर लोगों में जागरूकता आई है और उनकी जानकारी का स्तर बढ़ा है, लेकिन ऐसी जागरूकता किस काम की, जो पृथ्वी के संसाधनों के बुरी तरह से हो रहे दोहन पर कोई लगाम न लगाए। समस्या संसाधनों के दोहन को लेकर इंसान के बढ़ते लालच की है। असल में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहा है, लेकिन उसकी भरपाई का जरा सा प्रयास नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण इकाई (यूनेप) ने आकलन किया है कि धरती के संसाधनों के दोहन की रफ्तार प्राकृतिक रूप से होने वाली भरपाई के मुकाबले 40 प्रतिशत तक ज्यादा है। यानी मनुष्य एक साल में जितने प्राकृतिक संसाधनों-हवा, पानी, तेल, खनिज आदि का इस्तेमाल करता है, उतने संसाधनों की क्षतिपूर्ति में पृथ्वी को न्यूनतम डेढ़ साल लग जाता है। धीरे-धीरे भरपाई के मुकाबले दोहन का प्रतिशत बढ़ता भी जा रहा है। दावा है कि इसकी भरपाई अब तभी हो सकती है जब इंसानों के रहने के लिए डेढ़ पृथ्वियां मिल जाएं। चूंकि हम अपने इस ग्रह का विस्तार नहीं कर सकते, इसलिए स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक यह आह्वान करते रहे हैं कि अब इंसानों को अपने रहने के लिए किसी और ग्रह का इंतजाम कर लेना चाहिए। चूंकि दूसरे ग्रह पर जा बसना अभी की सूरतों में किसी भी तरह मुमकिन नहीं लगता, इसलिए कोशिश यही है कि इसी पृथ्वी को रहने लायक बनाया जाए, जिसका एक रास्ता जलवायु परिवर्तन थामने की कोशिशों के तहत की जाने वाली संधियां हैं, पर इसमें बड़ी बाधा यह है कि बड़े देश ही इन संधियों को बेजा बताकर इनमें शामिल नहीं होने या किसी बहाने इनसे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। जैसे इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2015 के पेरिस समझौते से बाहर निकलने का एलान किया है।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के 21वें जलवायु सम्मेलन के तहत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती और पर्यावरण सुधार के वास्ते किए जाने वाले खर्च को लेकर 195 देशों ने एक समझौता किया था। सीरिया और निकारागुआ को छोड़कर अन्य सभी देशों ने ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करते हुए दुनिया में बढ़ रहे तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) को रोकने पर यह सहमति जताई थी कि 2020 में लागू किए जाने के बाद वैश्विक तापमान को दो डिग्री सेल्सियस घटाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन थामने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता के रूप में 100 अरब डॉलर हर साल दिए जाएंगे और इस राशि को आने वाले वर्षों में बढ़ाया जाएगा।

इतना तय है कि ग्लोबल वार्मिंग और इस कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या ने पृथ्वी पर निवास योग्य स्थितियों में बड़ा बदलाव कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर देश के बड़े शहरों में इधर जो वायु प्रदूषण छाया रहा है, उससे हालात की गंभीरता का अंदाजा हमें अपने देश में भी हो रहा है। इसलिए यह बात कोई भी कह सकता है कि दुनिया के हालात इस समय क्लाइमेट इमरजेंसी वाले ही हैं और इससे निपटने के उपायों को युद्धस्तर पर लागू नहीं किया गया तो हमारी सांसों और रग-रग में घुलते प्रदूषण के जहर को बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरह पृथ्वी को खोखला करने वाली दोहन की नीतियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हवा-पानी से लेकर हर चीज का ऐसा अकाल पैदा हो जाएगा कि इंसान चाहकर भी जीवन के लिए जरूरी संसाधन नहीं जुटा सकेगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों, इसके लिए जरूरी है कि क्लाइमेट इमरजेंसी को एक वास्तविकता माना जाए और इससे बचने-निपटने के असरदार उपाय लागू किए जाएं।

गरीबी बढ़ा रहा जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन का एक सीधा असर देशों की अमीरी-गरीब पर भी पड़ता है। इसका शायद ही पहले कोई अंदाजा लगाता रहा हो, पर अब यह साबित हो रहा है कि असल में बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम अमीरों को और धनी, जबकि गरीबों और ज्यादा मुफलिसी की हालत में पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के कारण 31 फीसद का नुकसान हुआ है। यह अध्ययन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग का नकारात्मक असर नहीं होता तो भारतीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती। दूसरे कई देशों की अर्थव्यवस्था भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुई है। जैसे कि इससे सूडान को 36 फीसद, नाइजीरिया को 29, इंडोनेशिया को 27 और ब्राजील को 25 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1961 से 2010 के बीच विभिन्न देशों के बीच पैदा हुई कुल आर्थिक असमानता के एक चौथाई हिस्से की वजह मानव गतिविधियों से हो रही ग्लोबल वार्मिंग ही है। अध्ययन में इस बात को पहला आधार बनाया गया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से किस देश का तापमान कितना बढ़ा? इसके पश्चात यह आकलन किया गया कि अगर ऐसा न होता तो उस देश का आर्थिक उत्पादन कितना होता? इस तरह पिछले 50 वर्षों में 165 देशों के बढ़ते तापमान और जीडीपी के रिश्तों का हिसाब लगाया गया।

इस अध्ययन की सबसे रोचक बात यह रही है कि जिन विकसित ठंडे देशों का इस दौरान तापमान बढ़ा, उन्हें तो ग्लोबल वार्मिंग से लाभ ही हुआ है। जैसे कि नॉर्वे, जिसने इन 50 वर्षों में क्लाइमेट चेंज के विपरीत हालात में तेज विकास किया। जबकि भारत जैसे गर्म देश में न सिर्फ जैव विविधता इस दौरान खतरे में पड़ी, बल्कि साफ हवा-पानी का भी संकट बढ़ा, जिसकी चोट अंततः अर्थव्यवस्था पर पड़ी।

नौकरियों पर भी लगा रहा ग्रहण

जलवायु में हो रहा बदलाव सिर्फ प्राकृतिक नुकसान की वजह नहीं बन रहा है, बल्कि जिन कई और तरीकों से वह किसी इलाके या देश को क्षति पहुंचा रहा है, उनमें एक नौकरियों का संकट पैदा करना भी है। नौकरियां किस तरह क्लाइमेट चेंज की भेंट चढ़ रही हैं, इसका एक खाका संयुक्त राष्ट्र ने इसी वर्ष यानी 2019 में खींचा है, जिसके मुताबिक भारत में बढ़ता तापमान 2030 तक करीब 3 .4 करोड़ नौकरियां लील जाएगा। दुनिया भर में मजदूरों की जिंदगी पर क्लाइमेट चेंज का असर मापने के लिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले वक्त में बढ़ती गर्मी के कारण मजदूरों के लिए दिन में काम करना मुश्किल होता जाएगा, जिससे उनके काम के घंटे कम हो जाएंगे। काम के घंटे कम होने का प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी मजदूरी पर पड़ेगा, जिससे या तो उनकी आय बेहद कम हो जाएगी या फिर वे नौकरी छोड़कर जीवन-यापन के लिए आय के दूसरे स्रोतों पर निर्भर हो जाएंगे।

भारत जैसे देश में जहां 90 फीसद से ज्यादा मजदूर खेती और भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन अंततः उनकी नौकरियों पर ग्रहण लगाने वाला साबित हो सकता है। वैसे तो यह रिपोर्ट आशंका जताती है कि क्लाइमेट चेंज से तापमान बढ़ने पर पूरी दुनिया में काम करने के घंटों में 2 .2 फीसद की कमी आएगी, पर इसका सबसे बुरा असर भारत जैसे देशों पर ही पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1995 में भारत में काम के घंटों में 4 .3 फीसद की कमी आई थी, जिसका असर मजदूरी कम होने के रूप में पड़ा, पर अब 2030 तक यह आंकड़ा 5 .8 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इधर जिस प्रकार से दिल्ली-एनसीआर में 40 फीसद से ज्यादा लोगों ने यहां के गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर छोटे शहरों की ओर पलायन की बात कही है, इसका साफ संकेत है कि इससे ढांचा आदि क्षेत्रों की नौकरियों पर संकट आएगा।

खरी-खरी

अमीर की गोभी, गरीब की गोभी

शशांक भारतीय

एक बहुत बड़ा जलसा था। उसमें हर क्षेत्र के बड़े सितारे शामिल हुए। हजारों लोग सितारों को देखने, सुनने और मदहोश होने आए थे। शिविर बाहर की गहमागहमी से महफूज, शांत और अंदर से भव्य था। वहां आराम और खानपान की बढ़िया व्यवस्था थी। एक फिल्मी सितारा अभी-अभी शिविर में आया था। पसीना पोंछते हुए उसने कहा-बाहर लोग पागलों जैसे टूट पड़ते हैं। दूसरा सितारा जो किसी छोटी उल्का को ऑटोग्राफ दे रहा था, बोला-जब कोई अपरिचित बहुत घनिष्ठ होकर तस्वीर खिंचवाता है, तब मैं कैमरे की तरफ देखता ही नहीं, इधर-उधर देखता हूं। पहला सितारा चहका, वाह! ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने। छोड़िए, ये डिश ट्राई कीजिए, गोभी बहुत बढ़िया है, उसने कहा। सितारे ने माना कि गोभी वाकई अच्छी थी। ऐसा कहकर वह न्यूज एंकर की तरफ बढ़ गया। एंकर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी दिनभर चीखना है, आइये कुछ साथ में खाते हैं। एंकर ने वेटर से कहा कि गोभी वाली डिश की एक-एक सर्विंग और दे।

वहां हिंदी का एक लेखक और एक कवि भी था। वे एक-दूसरे को नहीं जानते थे। उन दोनों को कोई नहीं जानता था। लेखक ने कहा, आइये जलपान करते हैं। चर्चा की मद्धम उत्तेजना के बीच उन्होंने दोहराया कि गोभी बहुत अच्छी थी। वहीं किनारे एक गुरुजी बैठे थे, जो वेदों का ज्ञान अंग्रेजी में देते थे। कठिन समाधि से उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ था कि पैसा अमेरिका में है। वे सोफे पर पूरे कॉस्टयूम में बैठे थे। उनके पीआर ने उन्हें खाद्य पदार्थों का भोग लगाने को कहा। गुरुजी ने गोभी का भोग दो बार लगाया। तभी वहां एक राजनेता का प्रवेश हुआ। उसे देखते ही सितारों ने रीढ़ की हड्डी में झुकाव महसूस किया। वे झुके ही झुके नेता की तरफ खिंचने लगे। राजनेता कभी फूहड़ गाने एवं उत्तेजक वीडियो बनाया करता था। उसे अहसास हुआ कि वह फूहड़ बातें भी करे तो राजनीति में जा सकता है और वह मंत्री हो गया। एंकर ने कहा, छोड़िये वो सब, ये ट्राई कीजिए, गोभी अच्छी है।

जलसे की चकाचौंध से बहुत दूर, किसी गांव में खपरैल घर की देहरी पर एक अस्थि पंजर झूल रहा था। बाहर मूसलधार बारिश से बहकर आती सर्द हवा उसे कंपकपा रही थी। पत्नी ने पूछा, इतनी रात गए वहां बाहर क्यूं खड़े हो? उसने कहा, प्रकृति का कोप बेमौसम टूटा है, इस बार गोभी अच्छी नहीं होगी।

ट्वीट-ट्वीट

अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका पर यही कहूंगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम के एनजीओ की राय देश के सारे मुसलमानों की राय कदापि नहीं हो सकती।समीर अब्बास@TheSamirAbbas

भारतीय मुसलमानों के लिए वक्त आ गया है कि वे खुद को खिलजी, बाबर और औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक खलनायकों के साथ जोड़कर देखना बंद करें। कुछ ऐसे ही अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी, औपनिवेशिक शासकों और उस भयावह उत्पीड़न के महिमामंडन को बंद करना चाहिए जो उन्होंने किया।
डॉ. डेविड फ्राउली@davidfrawleyved

एनएसएसओ सर्वे में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि उनमें हर बार कम से कम उपभोग को शामिल किया जाता है। मगर यह पहली बार हुआ कि उपभोग में कमी आई है। ऐसे में रिपोर्ट को जारी करके उस पर विद्वानों को विचार क्यों नहीं करने दिया जाता? इससे पहले बेरोजगारी के आंकड़े रोकना भी अच्छा कदम नहीं था।
सुनील जैन@thesuniljain

उत्तर प्रदेश डायरी

आम मुसलमानों की सुनें उनके स्वयंभू लीडर

सद्गुरु शरण
स्थानीय संपादक, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से उपजा आनंद दोनों पक्षों, यानी हिंदुओं और मुस्लिमों के दिल में बस गया है। राजधानी में सचिवालय से लेकर गांवों में खेत-खलिहान तक एक नया सपना पुष्ट हो रहा है कि भव्यतम राम मंदिर और वैसी ही मस्जिद बनने के बाद रामनगरी किस तरह न सिर्फ दोनों धर्मों की महान तीर्थस्थली बन जाएगी, बल्कि दुनिया में हिंदू-मुस्लिम सद्भाव की नई धरती के रूप में भी पहचानी जाएगी।

दरअसल अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दो बातें उल्लेखनीय रहीं जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। पहली यह कि संविधान पीठ के सभी सदस्यों ने एकराय होकर यह फैसला दिया। इससे देश की न्यायप्रणाली का पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि फैसले को इस विवाद के दो अहम पक्षकारों मोहम्मद इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत देशभर में बेहद खुशी के साथ स्वीकार किया गया। यह प्रतिक्रिया देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चरित्र के अनुरूप थी। सबको आशंका थी कि जिस पक्ष के खिलाफ फैसला आएगा, वह इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। अयोध्या समेत देशभर ने इस फैसले को जिस तरह स्वीकार किया, उससे दुनिया के देश हिंदुस्तान के असली चरित्र से वाकिफ हुए, यद्यपि पाकिस्तान और उसकी परस्ती में यहां पल रहे कुछ स्थानीय संगठनों के दिल बुरी तरह टूट गए। फैसला आते ही जाहिर तौर पर मुसलमानों के ऐसे स्वयंभू ठेकेदार संगठनों के चेहरे उतर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके चार दशक से जमे-जमाए कारोबार को इस तरह ठप कर देगा और उनकी सदाबहार दुकानों पर ताले पड़ जाएंगे। मंदिर-मस्जिद के नाम पर जो दुकानें पिछले चार दशक से गुलजार थीं, उन्हें ये ठेकेदार ऐसे कैसे बंद हो जाने दें? जनभावना के ज्वार से सहमकर ये संगठन

दो-चार दिन चुप रहे या धीमी स्वर में बोलते रहे, फिर हिम्मत जुटाकर पुनर्विचार याचिका का शिगूफा छोड़ दिया। मुख्य मुस्लिम पक्षकार मोहम्मद इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तुरंत ही पुनर्विचार याचिका के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। आम मुस्लिमों, यहां तक कि अयोध्या के मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया, पर सबकी राय अनसुनी करके ये स्वयंभू संगठन और उनके ठेकेदार पदाधिकारी पुनर्विचार याचिका पर अड़े हुए हैं। यह गौरतलब है कि पुनर्विचार याचिका की तरफदारी कर रहे लोगों में अयोध्या या यूपी का एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो मुसलमानों का सचमुच प्रतिनिधित्व करता हो। आम मुसलमान के मन की बात इकबाल अंसारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या, यूपी, देश और मुसलमानों को आगे ले जाने वाला है। सबको इसे स्वीकार करना चाहिए। बहरहाल मुसलमानों के ठेकेदारों को चिंता है कि आम मुसलमान इस तरह सोचने लगे तो उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? मुसलमानों के इन जबरिया ठेकेदारों के भविष्य का फैसला कौन करेगा? मुसलमानों को यह देखना चाहिए कि उनकी वास्तविक नुमाइंदगी इकबाल अंसारी जैसे सच्चे और समझदार लोग करें या मुसलमानों के नाम पर दशकों से मलाई उड़ा रहे उनके स्वयंभू ठेकेदार। इनकी ऐसी कारगुजारियों से लगता है कि इन्होंने मुसलमानों को चैन से न रहने देने का प्रण कर रखा है ताकि इनका अपना चैन कायम रहे। काश! मुसलमानों के इन जबरिया हमदर्दों ने एक बार आम मुसलमानों की भी राय जान ली होती। मुसलमान देश की तरह तरक्की चाहते हैं। यह पुनर्विचार की जिद किसके लिए?

भगवा खेमा भी बेचैन : ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सिर्फ मुस्लिम पक्ष के संगठनों में बेचैनी है। अयोध्या के कुछ साधु भी रामलला का प्रसाद पाने को व्यग्र हैं। एक ऑडियो वायरल है जिसमें दो भगवा वस्त्रधारी संत श्रीराम जन्मभूमि न्याय और राम मंदिर ट्रस्ट पर कब्जा करने के लिए श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन की मुख्यधारा से जुड़े रहे एक बड़े संत के गोलोकवास का गुणा-भाग करते सुनाई देते हैं। ये साधु-संत खुद को उन राम का अनुयायी बताते हैं जिन्होंने अपना राजतिलक ठुकराकर चौदह साल वनों में काटे और तरह-तरह के कष्ट सहकर धरती को राक्षसों से मुक्त कराया। ऐसे राम के मंदिर पर कब्जा करने के लिए कुछ साधु घटिया स्तर पर उतर चुके हैं।

योगी जी हैं तो मुमकिन है : सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का सपना साकार होने की राह प्रशस्त कर दिए जाने के बाद अयोध्या अपना रंग-रूप आधुनिक एवं सुविधाजनक करने के नए सपने में डूब गई है। बहरहाल इस सपने की पूर्ति के लिए उसकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी है। योगी का अयोध्या-प्रेम जगजाहिर है। उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में प्रतिवर्ष दीपोत्सव के अलावा कई विकास कार्य भी हुए हैं। इस कड़ी में गुप्तारघाट से लेकर नयाघाट तक करीब 10 किमी देश का सबसे लंबा नदीघाट निर्माणाधीन है, पर अयोध्या ऐसे विकास की ख्वाहिशमंद है जो देश के सबसे बड़े तीर्थस्थल एवं भव्यतम मंदिर की कल्पना से मेल खाता हो। अयोध्यावासी मानते हैं कि योगी जी हैं तो यह भी मुमकिन है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या स्मॉग टावर लगाने से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी?

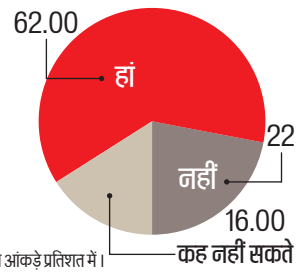

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कुछ दलों द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध उचित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मौलाना करने लगे फिर से वही सवाल,
मिला फैसला किंतु है वही सूरतेहाल।
वही सूरतेहाल पुरानी है बीमारी,
करते पुनर्विचार याचिका की तैयारी!
उन्हें नहीं मंजूर सुलझता ताना-बाना,
हैं फिर से तैयार उलझने को मौलाना।
- ओमप्रकाश तिवारी

अयोध्या फैसला

अयोध्या और भाजपा

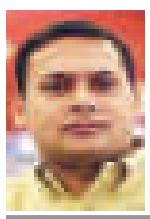

अमित मालवीय
राष्ट्रीय प्रमुख, आइटी सेल, भाजपा

उच्चतम न्यायालय का फैसला राष्ट्रीयता के प्रतीकों के प्रति सम्मान और हमारी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का हमेशा बोध कराता रहेगा

नौ नवंबर, 2019 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय के बाद श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। साथ ही भाजपा शासित केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी सुनिश्चित करके दिखा दिया कि भारत में अब नफरत एवं हिंसा के लिए जगह नहीं है। निर्णय को लेकर एक विशेष वर्ग जरूर कुछ आशंकाएं जता रहा था, लेकिन देशभर में एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि देश में प्रेम, सद्भाव एवं सौहार्द का एक नया अध्याय लिखा जाए जो फलीभूत भी हुआ है।

मेरा मानना है कि यह निर्णय भले ही सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार एवं भाजपा द्वारा सुख-शांति एवं सौहार्द के लिए किए गए प्रयास सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के मंत्र को ही प्रतिष्ठित करने वाले हैं। भाजपा ने हमेशा से श्रीराम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, लेकिन यह कभी नहीं चाहा कि देश में सौहार्द का माहौल बिगड़े। भाजपा ने देश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, वैभव और सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। यह देश की सांस्कृतिक धरोहर में भाजपा की अटूट प्रतिबद्धता ही थी कि श्रीराम मंदिर के मामले में भी देश में जब सभी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थीं, भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने प्रस्ताव में शामिल किया था। जून, 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बुलाई गई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में श्रीराम मंदिर निर्माण पर प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र की प्रस्तावना में संकल्प रखा कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर श्रीराम मंदिर का निर्माण होना चाहिए।

संत समाज एवं विभिन्न संगठन जब राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, तब अटल जी और लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भाजपा ने ही यह एलान किया था कि राम मंदिर बनकर रहेगा। भाजपा का यह संकल्प हरिद्वार में आयोजित हुई साधु-संतों की बैठक में और सशक्त हो गया जब निर्णय किया गया कि 30 अक्टूबर, 1990 को श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए कारसेवा शुरू की जाएगी। भाजपा ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दे दिया। उसके बाद 25 सितंबर, 1990 को तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू करके भाजपा की राम के प्रति प्रतिबद्धता को दुनिया के समक्ष मजबूती से स्थापित कर दिया। मोदी जी उस यात्रा में आडवाणी जी के साथ एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता की तरह डटे रहे और इससे अद्भुद संयोग क्या होगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं।

उस राम रथ यात्रा से नाखुश केंद्र की तब की कांग्रेस सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया था। बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक-एक करके भाजपा के शीर्ष नेताओं एवं हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद यात्रा जारी रही। कार सेवा अयोध्या पहुंची तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की तब की सपा सरकार ने भी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। लाखों कारसेवकों को गिरफ्तार किया गया। 72 घंटे के भीतर दो बार गोलियां चलवाकर करीब 50 कारसेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद रामभक्त अयोध्या पहुंचे, जन्मभूमि से कुछ दूरी पर ध्वज फहराया गया और 10 नवंबर को शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हुआ। इसके बाद 29 नवंबर, 1992 को आडवाणी जी समेत प्रमुख भाजपा नेताओं ने कारसेवा का आह्वान किया।

जब यह प्रतीत होने लगा कि श्रीराम जन्मभूमि के लिए हो रहे संघर्ष पर एक पुख्ता दस्तावेज की जरूरत है तो 1993 में भाजपा ने अयोध्या एवं श्रीराम मंदिर आंदोलन पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया और श्रीराम को एकात्मता एवं एकता की प्रतिमूर्त के रूप में वर्णित करते हुए प्रस्तावना में सरकार के शासन को रामराज जैसा होने की अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर स्पष्ट कर दी। 1996 और 1998 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

2004 और 2009 के दृष्टि पत्र में भाजपा ने फिर श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान 2010 में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। हालांकि वह जनांकाक्षाओं के अनुकूल नहीं था। सभी पक्ष फैसले से असंतुष्ट थे और सुप्रीम कोर्ट चले गए। कई विशेषज्ञों ने घोषणा की कि इस मामले का हल कभी नहीं निकलेगा, लेकिन वे शायद यह नहीं जानते थे कि 2014 से भारतीय राजनीति में एक नया कालखंड शुरू होने वाला है। जनभावनाओं के अनुरूप भाजपा ने चुनाव के घोषणापत्र में संकल्प दोहराते हुए कहा, 'संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं के तहत अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किया जाएगा।' भाजपा की प्रचंड विजय हुई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई में तेजी आए, इसके लिए भी ठोस प्रयास शुरू हुए।

15 साल बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अगस्त, 2017 में सरकार के आग्रह पर उच्चतम न्यायालय ने मामले पर ध्यान देना शुरू किया। न्यायालय ने कहा कि मामले से संबंधित हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं फ्रेंच भाषाओं के दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनु

8.5 प्रतिशत भारत की जीडीपी का हर साल वायु प्रदूषण के कारण नुकसान हो जाता है। यह कहना है विश्व बैंक का। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का अनुमान है कि अगर प्रदूषण में कमी की जाए तो 300 से 400 अरब डॉलर की वार्षिक बचत होगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 18 नवंबर 2019

डाटागीरी

राजनीति को कॅरियर के तौर पर नहीं देखतीं अधिकतर महिलाएं

भारतीय राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की बात जब आती है तो आंकड़े बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी का औसत सिर्फ 12 फीसद है। हालांकि, महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं का कहना है कि सक्रिय राजनीति में भागीदारी पर उन्हें कई तरह की बाधाओं से गुजरना पड़ता है। इस वजह से वह इसे कॅरियर के रूप में नहीं देखतीं।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति और उनकी धारणाओं के बारे में लोकनीति-सीएसडीएस और कोनराड एडनॉयर स्टिफ्टिंग की ओर से गत दिवस एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में महिलाओं और राजनीति को कई नजरियों से देखा गया है। यह रिपोर्ट देशभर की महिलाओं के बीच एक सर्वेक्षण पर आधारित है, इसमें राजनीति में भागीदारी और प्रतिनिधित्व करने के विभिन्न आयामों पर महिलाओं की धारणा के बारे में पता लगाया गया है।

रिपोर्ट में सामने आया है कि सामाजिक-आर्थिक वर्ग भी चुनावी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को निर्धारित करता है। उच्च सामाजिक और आर्थिक वर्ग की महिलाएं निम्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग की तुलना में चुनावी राजनीति में अधिक सक्रिय पाई गईं। अध्ययन में पाया गया कि मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में पिछले कुछ वर्षों में तेजी देखी गई है। यद्यपि महिला उम्मीदवारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, फिर भी एक व्यापक अंतर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजनीति में अपना कॅरियर बनाने के लिए केवल एक चौथाई महिलाएं ही उत्सुक होती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इसे अपने कॅरियर के रूप में चुनेंगी तो 61 फीसद ने इन्कार कर दिया, जबकि केवल 28 फीसद महिलाओं ने ही सहमति जताई। 12 फीसद महिलाएं ऐसी थीं, जिन्होंने अपनी राय व्यक्त नहीं की। एक प्रश्न पूछे जाने पर कि यदि एक महिला और पुरुष समान रूप से अच्छे उम्मीदवार हैं तो लगभग 44 फीसद महिलाओं ने सहमति जताई कि पार्टियां हमेशा टिकट देते समय पुरुष उम्मीदवार पसंद करती हैं। केवल 15 फीसद महिलाओं ने इस पर असहमति जताई और 12 फीसद ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहीं, 29 फीसद की राय मिली-जुली रही। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस बात से सहमत हैं कि 'एक पुरुष के खिलाफ महिला के जीतने की संभावना कम होती है, इसलिए महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए।' इस कथन पर प्रत्येक पांच में से दो महिलाएं असहमत थीं।

राजनीति में महिलाओं के जाने में आने वाली बाधाओं के बारे में पूछे जाने पर एक तिहाई महिलाओं ने तो कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महिलाओं ने बताया कि समाज का पितृसत्तात्मक मानदंड सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी बड़ी बाधा घरेलू जिम्मेदारियां और तीसरी बाधा व्यक्तिगत कारण थे।

चुनावी भागीदारी का स्तर

जाति समाज	बिल्कुल नहीं	कुछ हद तक सक्रिय	पूरी तरह से सक्रिय
सवर्ण	78	15	7
ओबीसी	75	18	7
एससी	81	14	5
एसटी	81	15	5
मुस्लिम	70	22	8
अन्य	81	12	6
(आंकड़े प्रतिशत में)			
आर्थिक वर्ग			
कमजोर	83	13	4
निम्न	78	16	6
मध्यम	74	19	7
उच्च आय	78	14	9

प्रतीकात्मक

सवाल : राजनीति को कितनी महिलाएं कॅरियर के तौर पर चुनना चाहती हैं?

सहमत	28 प्रतिशत
असहमत	61 प्रतिशत
कोई राय नहीं	12 प्रतिशत
महिलाओं को राजनीति में जाने से रोकने वाली बाधाएं	
पितृसत्तात्मक संरचना	22 प्रतिशत
घरेलू जिम्मेदारियां	13 प्रतिशत
व्यक्तिगत बाधाएं	12 प्रतिशत
सांस्कृतिक मानदंड	7 प्रतिशत
आर्थिक बाधाएं	6 प्रतिशत
राजनीति की गलत छवि	3 प्रतिशत

इंदौर से शुरू हुए शॉप किराना स्टार्टअप ने चार साल में ली 225 गुना बढ़त

जागरण विशेष ▶ कुछ ही महीने पहले किसान किराना नाम से ब्रांड की हुई शुरुआत

कम दाम और अच्छी गुणवत्ता का सामान उपलब्ध कराना है लक्ष्य

गजेंद्र विश्वकर्मा, इंदौर

इंदौर से संचालित होने वाला शॉप किराना स्टार्टअप धूम मचा रहा है। इसकी शुरुआत तीन दोस्तों दीपक धनोतिया, तनुतेजस सारस्वत और सुमित घोरावत ने 2015 में की थी। पहले ही साल में स्टार्टअप का टर्नओवर करीब दो करोड़ रुपये था। इस स्टार्टअप की सफलता को देखते हुए अमेरिका की बैटर कैपिटल, जापान की इन्क्यूबेट फंड और नौकरी डॉट कॉम ने 14 करोड़ की फंडिंग की है। इसके अलावा अन्य कंपनियों से स्टार्टअप को करोड़ों रुपये की फंडिंग के ऑफर हैं।

इंदौर के बाद जयपुर, सूरत, वडोदरा और अन्य शहरों में भी शॉप किराना की शुरुआत हो चुकी है। इनका दावा है कि 2019 में शॉप किराना का टर्नओवर करीब 450 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से स्टार्टअप चार साल में 225 गुना बढ़त ले चुका है। स्टार्टअप को कुछ ही महीने पहले फोर्ब्स इंडिया मैग्जीन ने सर्वे के जरिये टॉप बेबीकॉर्न कंपनियों में शामिल किया। देश की 500 कंपनियों के बीच इस स्टार्टअप ने पहला स्थान बनाया था। फोर्ब्स इंडिया के कवर पेज पर स्टार्टअप जगह बना चुका है।

स्टार्टअप 'शॉप किराना' की टीम। नईदुनिया

90 शहरों में जगह बनाएंगे शॉप किराना के फाउंडर : तनुतेजस सारस्वत का कहना है कि इस समय आठ शहरों में किराना का सामान सेल कर रहे हैं। इंदौर हमारा मुख्यालय है और यहां अन्य सभी ब्रांड के मुकाबले सबसे ज्यादा सामान हम सेल कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगले साल देश के 90 शहरों में जाएंगे। वर्क कल्चर को लेकर उनका कहना है कि हम कर्मचारियों को परिवार जैसा माहौल देते हैं। उनकी परेशानियों को हम अपनी व्यक्तिगत परेशानी मानते हैं। ऑफिस में हर दूसरे दिन छोटे-छोटे अचीवमेंट पर केक काटे जाते हैं। कर्मचारी खुद अपने टारगेट फिक्स करते हैं और जिस तरह के माहौल में उन्हें काम करना पसंद होता है, वैसा करने की छूट देते हैं। तनुतेजस का कहना है कि हमारे पास अब कुल 700 कर्मचारी हैं। इसमें कई बड़े शहरों के अनुभवी लोगों को भी जोड़ा गया है।

किसान किराना भी आठ शहरों में शुरू

शॉप किराना स्टार्टअप के तहत जनवरी 2019 में किसान किराना की भी शुरुआत की गई है। इंदौर के बाद इसे भी देश के आठ शहरों में शुरू किया जा चुका है। फाउंडर का कहना है कि पहले हम दूसरे ब्रांड से अनाज, मसाले और अन्य सामग्री खरीदते थे, लेकिन अब किसानों को जोड़ा गया है। किसान किराना में कुछ ही महीने में हमने एक करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

योग से टूटेंगी मजहब की दीवारें

जागरण संवाददाता, देहरादून: महर्षि कण्व की तपोस्थली एवं चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम में योग के माध्यम से धार्मिक सौहार्द की एक नई इबारत लिखी जाने वाली है। कण्वाश्रम में आगामी 20 नवंबर से मुस्लिम समुदाय के लिए पांच-दिवसीय योग शिविर आयोजित किया जाना है। शिविर में मुस्लिम समुदाय के लोग योगासन के साथ नमाज तो अदा करेंगे ही, यज्ञ और हवन में भी शामिल होंगे।

उत्तराखंड में कोटद्वार से 13 किमी दूर कण्वाश्रम में वैदिक आश्रम गुरुकुल की ओर से विश्वस्तरीय मुस्लिम योग शिविर का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस शिविर का उद्घाटन करेंगे। शिविर में क्षेत्रीय विधायक एवं वन मंत्री हरक सिंह रावत, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज, महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी, माता मंगला देवी, भोले जी महाराज आदि भी हिस्सा लेंगे।

रविवार को लैंसडौन चौक स्थित एक रेस्तरां में वैदिक आश्रम गुरुकुल के कुलपति योगीराज डॉ. विश्वपाल जयंत ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। बताया कि शिविर में देश-विदेश के 500 मुस्लिम महिलाएं एवं पुरुष शामिल होंगे। 20 से 24 नवंबर तक चलने वाले शिविर में योग, हवन, यज्ञ, पूजा, ध्यान व प्रवचन के साथ ही नमाज भी अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि योग एवं ध्यान के माध्यम से मनुष्य कई रोगों से मुक्ति पा सकता है। यह स्वस्थ रहने का सबसे आसान एवं बेहतर तरीका है।

आइसक्रीम स्टिक से ऐसा पुल बनाया जो उठा सकता है इंसान का वजन

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। यह कहावत इंजीनियरिंग के उन दो विद्यार्थियों पर सटीक बैठती है, जिन्होंने आइसक्रीम स्टिक से ऐसा पुल बनाया है जो एक आदमी का वजन आसानी से उठा सकता है। कई प्रयास के बाद उन्होंने यूनीफॉर्मली बेयरिंग लोड (यूवीएल) कांसेप्ट पर पुल बनाया जो उम्मीदों पर खरा उतरा।

महज 239 ग्राम के पुल ने 52.5 किलो वजन उठाकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) की 'ब्रिज क्रांति' प्रतियोगिता में जीत दर्ज कराई है। जोनल विजेता रहे इस पुल को कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआइटी) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष के छात्र सौरभ सिंह व वैष्णवी मिश्रा ने बनाया। वैष्णवी ने बताया कि आने वाला समय कम सामग्री से बनने वाले पुलों का है। इसी कांसेप्ट पर यह पुल तैयार किया गया है। इसमें तराजू लटकाकर 52.2 किलो का वजन रखा गया। पुल ने इस वजन को न केवल संभाला, बल्कि वह टस से मस भी नहीं हुआ। मैकेनिज्म यह है कि पुल पर वजन रखते ही भार अलग-अलग हिस्से में बंट जाता है।

वैष्णवी मिश्रा और सौरभ सिंह आइसक्रीम स्टिक से बनाए पुल को दिखाते हुए। जागरण

कम लागत में बन सकते हैं बड़े पुल : छात्र सौरभ सिंह ने बताया कि पुल के ऊपर गोलाकार बेस उसे संतुलित रखने के साथ वजन को बांट देता है। यूवीएल कांसेप्ट पर हल्के वजन के ऐसे बड़े पुल तैयार किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि कम सामग्री व कम लागत में ऐसे पुल बनाए जाने पर काम शुरू हो चुका है। अब वह एकेटीयू की ओर से 23 नवंबर को होने वाली राज्यस्तरीय ब्रिज क्रांति प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

पेड़-पौधों और परिंदों का भी दम घोंट रहा प्रदूषण

महेश कुमार वैद्य, रेवाड़ी

पर्यावरण

- उम्र घटा रही है जहरीली हवा, बिगड़ रहा है पारिस्थितिकीय संतुलन
- रुक रही है पौधों की बढ़त, विचलित हो रहे हैं परिंदे
- एनसीआर में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में लाखों की कमी

वायु प्रदूषण सिर्फ मानव स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं है बल्कि पेड़-पौधे व पशु-पक्षियों पर भी इसकी मार पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जहरीली हवा न केवल पशु-पक्षियों की उम्र घटा रही है, बल्कि पेड़-पौधों को भी बीमार बना रही है। इन दिनों पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र व हरियाणा के अधिकांश शहरों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है, जिसके चलते पेड़-पौधे और पशु-पक्षियों पर भी भारी संकट आ चुका है। इससे एक ओर जहां पौधों की बढ़त रुक रही है, वहीं परिंदे विचलित हो रहे हैं। एनसीआर में आने वाले लाखों प्रवासी पक्षी इस बार दूरी बना चुके हैं। इन तमाम बदलावों से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ रहा है।

प्रदूषण के पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों पर पड़ने वाले असर को लेकर वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिकों, वन्य जीव विशेषज्ञों, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करनाल में काम कर चुके वैज्ञानिकों व पशु चिकित्सकों से बात की गई तो सभी का कहना था कि समय रहते नहीं चेते तो नुकसान की भरपाई मुश्किल हो जाएगी। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. नसीब सिंह के अनुसार, मनुष्य की तरह पशुओं पर भी प्रदूषण की मार पड़ रही है। आंकड़ों के साथ यह कहना तो मुश्किल है कि हिमाचल में रह रही गाय की तुलना में यहां की गाय का दूध कितना कम हुआ, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि पशुओं और परिंदों पर प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही बाधित : वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक व एग्रीकल्चर कालेज बावल के पूर्व प्राचार्य डॉ. अशोक यादव का कहना है कि निलंबित सूक्ष्म कण पार्टिकुलेट मैटर-10, नाइट्रस एवं सल्फर डाइआक्साइड का स्तर बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। इसे फोटो सिंथेटिक कहते हैं। इससे पौधे सही ढंग से भोजन नहीं बना पाते। हालांकि कुछ पौधे प्रदूषण के प्रति सहनशील भी हैं, परंतु इनकी संख्या कम है। अधिकांश पौधों पर प्रदूषित हवा का बुरा असर हो रहा है। पत्तियों पर जमने वाले प्रदूषित कण स्टोमेटाज (पत्तियों पर बने सूक्ष्म छिद्र) को अवरुद्ध करते हैं, जिससे पौधे खुद की खुराक तैयार नहीं कर पाते। पशुओं के मामले में भी ऐसा ही है।

प्रतीकात्मक

प्रदूषण के कारण इस बार दिल्ली एनसीआर में प्रवासी पक्षियों की संख्या काफी कम हो चुकी है। भिंडावास, सुल्तानपुर व मसानी बैराज में आने वाले हजारों परिंदे इस बार दूर रहे हैं। प्रदूषण से निश्चित रूप से जल, जंगल और जमीन प्रभावित हो रही है, जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ रहा है। सड़क किनारे व खुले में लगे पौधों को देखकर प्रदूषण के असर को समझा जा सकता है।

-सुंदरलाल सांभरिया, जिला वन अधिकारी

पेड़-पौधों को सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने में आ रही बाधा : क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल में वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक डॉ. जोगेंद्र सिंह के मुताबिक, हम जानते हैं कि पौधे भी सांस लेते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। प्रदूषित हवा उनके जीवन में जहर घोल रही है। यह सर्वविदित है कि पेड़-पौधे क्लोरोफिल (पर्णहरित) के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके भोजन तैयार करते हैं। प्रदूषित माहौल में पेड़-पौधों को न तो सही ढंग से धूप मिल रही है और न ही पत्तियों पर धूलकण जमे होने के कारण न ही भोजन बनाने की क्रिया सही रूप में हो पाती है।

कॉर्बेट से लेकर बर्फीले मुक्तेश्वर तक किंग कोबरा की मौजूदगी

गोविंद बिष्ट, हल्द्वानी

- गर्म व ठंडे दोनों इलाकों में बनाते हैं प्रवास
- वन अनुसंधान केंद्र किंग कोबरा की मौजूदगी व संरक्षण के लिए रिसर्च में जुटा

सांप सामने देखते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। बात अगर किंग कोबरा की हो तो डर और बढ़ जाता है। उत्तर भारत में नैनीताल जिले में सबसे अधिक मौजूदगी के बावजूद आज तक किंग कोबरा ने एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि यह उन जहरीले सांपों को खुराक बनाता है जो आबादी में घुसकर लोगों की जान लेते हैं। इसलिए इनकी मौजूदगी और संरक्षण पर वन महकमा विस्तृत रिसर्च कर रहा है। समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तेश्वर से लेकर मैदान में कॉर्बेट नेशनल पार्क तक में इनके घोंसले मिले हैं।

उत्तराखंड में सांपों की कई प्रजातियां मिलती हैं। इनमें सबसे जहरीला किंग कोबरा है। चीन सीमा से लगे मुनस्यारी और पिथौरागढ़ में भी इसकी मौजूदगी मिली है, लेकिन नैनीताल जिले में संख्या ज्यादा है। इस वजह से वन अनुसंधान केंद्र शोध में जुटा है। वन विभाग इसे पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा मानता है क्योंकि 12 फीट लंबा कोबरा ज्यादातर सांपों को ही अपना निवाला बनाता है। वाइपर, करैत जैसे सांप आबादी में दस्तक देकर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। यही सांप किंग कोबरा का मुख्य आहार है। अपवाद स्वरूप यह गौह (लीजर्ड) भी खाता है। किंग कोबरा कहां-कहां अपना प्रवास बनाता है, उसे किन चीजों से खतरा है और संरक्षण को क्या नीति बनाई जाए, इन तीन अहम बिंदुओं को शोध में शामिल किया गया है। इसे चीड़ या बांस दोनों में से कौन सा जंगल ज्यादा पंसद है, इसका भी पता लगाया जा रहा है।

किंग कोबरा का मुख्य आहार सांप है। नैनीताल में इनके कभी इंसानों को डसने का मामला सामने नहीं आया। इनके व्यवहार, आवास, खाद्य शृंखला आदि पर रिसर्च चल रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का यह अहम हिस्सा है।

- संजीव चतुर्वेदी, वन संरक्षक (अनुसंधान) उत्तराखंड

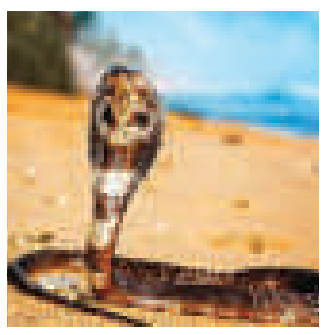

किंग कोबरा फाइल

उत्तर भारत में नैनीताल में ज्यादा किंग कोबरा

किंग कोबरा मप्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी पाया जाता है। उत्तराखंड में प्रारंभिक सर्वे के दौरान इस बात के प्रमाण मिले हैं कि नैनीताल जनपद में इनकी संख्या इन पांच राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। शोध पूरा होने पर सही आंकड़ा सामने आ जाएगा। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट वाले इलाकों के अलावा उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी किंग कोबरा अच्छी संख्या में है।

मई-जून में घोंसलों पर खतरा : फरवरी से उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही हरियाली पर खतरा बढ़ जाता है। मई और जून में सबसे ज्यादा जंगल सुलगते हैं। जंगलों में घोंसला बनाने वाला किंग कोबरा इस दौरान सबसे ज्यादा खतरे में रहता है। संरक्षण में वनाग्नि बड़ी बाधा है।

छह से आठ हफ्ते अंडे सेती है मादा : किंग कोबरा सांपों की एक मात्र प्रजाति है जो घोंसला बनाकर रहता है। अंडा देने के छह से आठ सप्ताह तक मादा कोबरा उन पर बैठ जाती है। यह घोंसला पिरूल या घास-फूस से बना गुंबदनुमा आकार का होता है।

पुरुषों से अधिक महिलाएं आर्थराइटिस की शिकार

पुनीत शर्मा, रोहतक

- पीजीआइ रोहतक में आने वाले आर्थो के 20 फीसद मरीजों में मिले बीमारी के लक्षण
- गठिया वाय के कारण 45 वर्ष से कम आयु में ही बढ़ी जोड़ों के दर्द की समस्या

हरियाणा में करीब 20 फीसद लोगों को आर्थराइटिस के लक्षणों के चलते जोड़ों के दर्द से जूझना पड़ रहा है। पीजीआइ रोहतक के आर्थो विभाग में आने वाले मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह बीमारी अधिक पाई गई। पुरुषों की तुलना में 10 फीसद अधिक महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित पाई गईं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के मुताबिक आर्थराइटिस की समस्या मुख्यतः एक्सीडेंट, मोटापे, गठिया बाय, अधिक कमजोर होने या फिर बढ़ती उम्र के कारण होता है। महिलाओं का वजन पुरुषों की तुलना में अधिक और खानपान ठीक न होने के कारण वह इस बीमारी की चपेट में अधिक आती हैं।

हरियाणा के 50 फीसद लोगों को जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द से जूझना पड़ रहा है। इनमें से 20 फीसद लोग ऐसे हैं, जिन्हें केवल घुटने, कोहनी समेत अन्य जोड़ों के दर्द से जूझना पड़ रहा है। इस बीमारी के कारण 10 फीसद पुरुषों और 20 फीसद महिलाओं के जोड़ समय से पहले खराब होने लगते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अनियमित दिनचर्या ओर पौष्टिक आहार के कम सेवन के चलते लोग इस बीमारी से अधिक ग्रसित हो रहे हैं।

पीजीआइ में आने वाले करीब 20 फीसद लोगों को आर्थो आर्थराइटिस बीमारी पाई गई है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इससे अधिक ग्रसित हैं। लोगों को कोई भी परेशानी होते ही उसका इलाज शुरू कराना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन व्यायाम और सही खान से बीमारी से निजात मिल सकती है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी हड्डियों के दर्द से निजात पाई जा सकती है।

- डॉ. राजेश रोहिल्ला, सीनियर प्रोफेसर आर्थो विभाग, पीजीआइएमएस

प्रतीकात्मक

यह हैं उपचार : जोड़ों के दर्द में पौष्टिक आहार का सेवन, धूप सेवन, हल्की मालिश तथा भौतिक चिकित्सा आवश्यक है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के मुताबिक, आर्थराइटिस के तीन प्रकार माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होते हैं। माइल्ड आर्थराइटिस (शुरुआती दर्द) में मरीज को दर्द निवारक गोलियां देने के साथ उसे व्यायाम करने तथा हड्डियों के बीच मौजूद फर्टिलेज में सुधार की दवाइयां दी जाती हैं। मॉडरेट आर्थराइटिस में हायलूरौनिक एसिड इंजेक्शन जोड़ों में इंजेक्शन के माध्यम से डालते हुए उपचार किया जाता है। अंतिम चरण सीवियर मुख्यत: 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को होती है। ऐसे लोगों को अधिक परेशानी होने की दशा में उनके जोड़ों को ऑपरेशन के माध्यम से बदला जाता है।

चलने-फिरने में होने लगती है परेशानी : आर्थराइटिस का सबसे आम प्रकार है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका असर जोड़ों, विशेष रूप से कूल्हे, घुटने, गर्दन, पीठ के नीचले हिस्से, हाथों और पैरों पर पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर कार्टिलेज ज्वाइंट में होता है। कार्टिलेज हड्डियों की सतह पर मौजूद सॉफ्ट टिश्यू है, जो आर्थराइटिस के कारण पतला और खुरदरा होने लगता है। इससे हड्डियों के सिरे पर मौजूद कुशन कम होने लगते हैं और हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं। आर्थराइटिस के लक्षण इसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। इसमें दर्द, अकड़न, ऐंठन, सूजन, हिलने-डुलने या चलने-फिरने में परेशानी होने लगती है।

ये हैं लक्षण

जोड़ों में दर्द या नरमी, चलते समय, कुर्सी से उठते समय, लिखते समय, टाइप करते समय, किसी वस्तु को पकड़ते समय, सब्जियां काटते समय अधिक दर्द होना। साथ ही यदि आपको जोड़ों में सूजन, अकड़न, लाल हो जाने, जोड़ों के लचीलेपन में कमी, जोड़ों के आस-पास गर्माहट महसूस होना, चलने पर जोड़ों से आवाज आना आदि की समस्या है तो आपको तुरंत विशेष चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए।

प्रकाश की मदद से उपकरण बताएगा भूकंप में कितनी टिकेगी इमारत

बरमेश्वर, सिंदरी

प्रतिभा

- इमरान का इनोवेटिव आइडिया बीआइटी के टेक-फेस्ट संधान में चुना गया
- निर्माण के दौरान दीवार बनाने में हुई खामियों को पकड़कर कराएगा दुरुस्त

प्रकाश का एक खास गुण है कि वह सीधी रेखा में ही चलता है। उसकी राह में कोई वस्तु रख दी जाए तो वह उसे रोशन कर देता है। उससे आगे नहीं बढ़ता। प्रकाश के इस गुण के आधार पर झारखंड के सिंदरी के अभियंत्रण संस्थान बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग के बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र इमरान नजीर खास उपकरण तैयार कर रहे हैं। इमरान के मुताबिक, भूकंप से भवनों की सुरक्षा के लिए के लिए वॉल ई-रेक्टीफाइड उपकरण मददगार साबित होगा। यह उपकरण निर्माण के अंतिम चरण में है। इसका प्रदर्शन वह बीआइटी मॉडल क्लब के प्रतिष्ठित वार्षिक टेक-फेस्ट 'संधान' में करेंगे। यह उपकरण भवन की दीवार बनने के दौरान हुई खामियों की तुरंत जानकारी दे देगा। उसे अभियंता दूर कर सकते हैं।

इमरान ने बताया कि अक्सर भवन बनाने में अकुशल मजदूर कई गलतियां कर जाते हैं। ऐसी दीवारें बना देते हैं जो बिल्कुल सीधी न होकर कहीं-कहीं हल्की टेढ़ी हो जाती हैं। दो ईंटों के बीच अधिक जगह छोड़ देते हैं। भूकंप या भूस्खलन के दौरान यह दीवारें हल्के से कंपन में ही गिर जाती हैं। पुल और बड़े भवन बनाने में करोड़ों की रकम खर्च होती है, जो ऐसी खामियों के कारण पानी में चली जाती है। इस समस्या का निदान खोजने में प्रकाश के गुण का प्रयोग उपकरण में किया है। इमरान के मुताबिक, उन्होंने यह आइडिया टेकी ऑफ द इयर प्रतियोगिता में दिया था। वहां उसे चयनित कर लिया गया। अब संधान में उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। उपकरण के सहारे मजबूत दीवार का निर्माण संभव हो सकेगा। अभियंता कोई गलती करेगा तो उसकी पहचान करेगा।

छात्र इमरान जागरण

दीवार निर्माण के दौरान ऐसे काम करेगा उपकरण : दीवारों को बनाने के दौरान वह जरा सी भी टेढ़ी हुईं तो उपकरण से निकल रही लेजर लाइट उसे पकड़ लेगी। यह हर ईंट पर नजर रखेगी, जहां भी दीवार बनने में खामी हुई है, वहां वह लाइट रुक जाएगी। उससे आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बाद इंजीनियर गलती को दुरुस्त कर लेंगे। दीवार बनाने में हुई खामी की जानकारी उपकरण में लगे एलसीडी डिस्प्ले में दिख जाएगी।

प्रॉक्सी लेजर लाइट का उपकरण में हुआ प्रयोग : इमरान ने बताया कि उन्होंने अपने उपकरण में प्रॉक्सी लेजर लाइट, एलसीडी डिस्प्ले, आर्डरुइनो (सर्किट बोर्ड), नौ वोल्ट की बैट्री व सेंसर का प्रयोग किया है। उपकरण बनाने में 600 रुपये की लागत आई है। उपकरण दीवार बनने के दौरान ईंट के .01 डिग्री कोण के भी विचलन तक को पकड़ लेगा।

1 नाराज

लेखक : राहत इंदौरी
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस

राहत इंदौरी रंगों और रेखाओं के फनकार हैं। इस संग्रह में पाठकों का उनकी इस कला से परिचय होता है। राजनीतिक-सामाजिक विसंगतियों और कशमकश पर उनका तंज पाठकों को सोचने पर विवश करता है। संग्रह में ऐसी शायरी की बहुतायत है।

2 कुछ इश्क किया, कुछ काम किया

लेखक : पीयूष मिश्रा
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन

इस संग्रह की कविताओं में पीयूष मिश्रा ने अपने सपनों, आकांक्षाओं, सफलता, असफलता और क्षोभ को वाणी दी है। अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले पीयूष की कविताएं भी पाठकों को अलग तरह का स्वाद देती है।

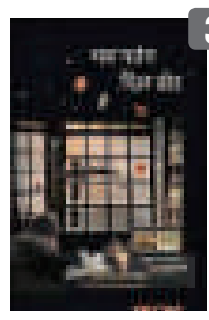

3 मन पतंग दिल डोर

लेखक : पारितोष त्रिपाठी
प्रकाशक : हिंद युग्म ब्लू

लेखक पारितोष त्रिपाठी का मानना है कि मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता। इस पुस्तक में उन्होंने यौवन के मधुर अहसासों को शब्दों में उतारने की कोशिश है। प्रेम की रुमानियत व पवित्रता के अहसास से सराबोर हैं ये कविताएं।

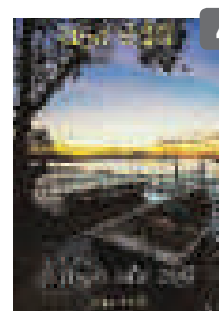

4 दो कदम और सही

लेखक : राहत इंदौरी
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस

राजनीति और इश्क को अपनी शायरी का हिस्सा बनाने वाले राहत इंदौरी के इस संग्रह में जीवन और जगत के अलग-अलग पहलुओं को समेटा गया है। साथ ही बेबाकी से अपनी बात कहने की उनकी ताकत का अंदाजा भी होता है।

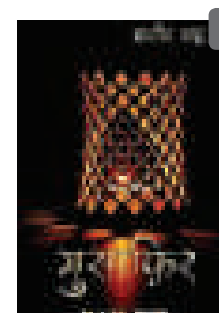

5 मुसाफिर

लेखक : बशीर बद्र
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस

गजलों की दुनिया में बशीर बद्र की आवाज अलग से पहचानी जा सकती है। पुस्तक में संकलित इनकी शायरी में जज्बे और अहसास इस तरह घुल जाते हैं जिससे पाठकों को अलग ही तरह का आस्वाद मिलता है।

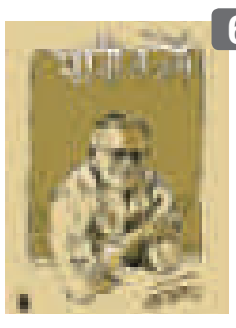

6 पाजी नज्में

लेखक : गुलजार
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन

गुलजार की इन नज्मों में सीधे तौर पर तो सवाल नहीं हैं, लेकिन इनमें पाठकों को कवि की प्रश्नाकुलता दिखती है। इन नज्मों में गुस्सा भी है, हल्का तंज भी है। मंदिरों में तेल चढ़ाने को लेकर वह भक्तों पर तंज करते हैं।

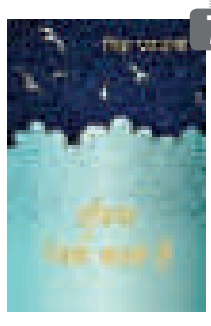

7 दुनिया जिसे कहती है

लेखक : निदा फाजली
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग

इस संग्रह में निदा फाजली की मशहूर गजलों को रखा गया है। इसमें कई गजलें ऐसी हैं, जिनके बारे में इससे पहले पाठकों को जानकारी नहीं थी। इस संग्रह को निदा की शायरी के प्रतिनिधि संकलन के तौर पर भी देखा जा सकता है।

8 मुनव्वरनामा, चुनिंदा गजलें, नज्में और अशआर

लेखक : मुनव्वर राना
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस

मुनव्वर राना हमारे दौर के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित शायरों में हैं। यह उनकी चुनिंदा रचनाओं का संकलन है। इसमें इंसानी जज्बातों को बेहद सादगी और खूबसूरती के साथ गजल बनाकर पेश किया है।

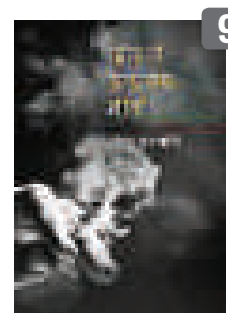

9 पाल ले इक रोग नादां

लेखक : गौतम राजऋषि
प्रकाशक : हिंद युग्म

हाल में जिन लेखकों ने अपनी रचनाओं से हिंदी जगत को चौंकाया है, उनमें गौतम का नाम प्रमुख है। अपनी गजलों में उन्होंने जिस तरह के बिंब प्रयोग में लाए हैं, वो रोचक हैं। जैसे-चांद सिगरेट पीता या धूप शॉवर में नहा रही होती।

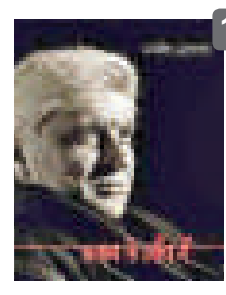

10 ख्वाब के गांव में

लेखक : जावेद अख्तर
प्रकाशक : मंजुल पब्लिशिंग हाउस

जावेद अख्तर के बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी की आपाधापी को फिल्म के सीन की तरह देखते और फिर उसे शब्दों में पिरो कर पेश करते हैं। इस किताब में गहराई से महसूस की गई उनकी अभिव्यक्तियां हैं।

कल पढ़ें अनुवाद श्रेणी में बेस्ट 10 किताबें

मप्र की अल्का बनीं मिसेज इंडिया की फर्स्ट रनरअप

नईदुनिया, रीवा : अहमदाबाद में शनिवार की रात बीपीआर द्वारा आयोजित मिसेज इंडिया खिताब में मध्य प्रदेश के रीवा की बेटी अल्का कुलचंदानी ने फर्स्ट रनरअप का खिताब अपने नाम किया। मिसेज इंडिया बनने के लिए देशभर से सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इनमें 70 महिलाओं का चयन किया गया। पहले ही दौर में रीवा की अल्का ने टॉप टेन में अपना स्थान बना लिया था।

एक वर्ष से कर रही थीं तैयारी : अल्का कुलचंदानी इस मुकाम को पाने के लिए पिछले एक वर्ष से तैयारी कर रही थीं। वह अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में लेक्चरर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं।

बहन लता ने बनाया था विश्व रिकार्ड : अल्का का परिवार हुनर में किसी से भी कम नहीं है। अल्का की बड़ी बहन लता टंडन ने 87 घंटे तक कुकिंग करके सबसे लंबे समय तक खाना बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

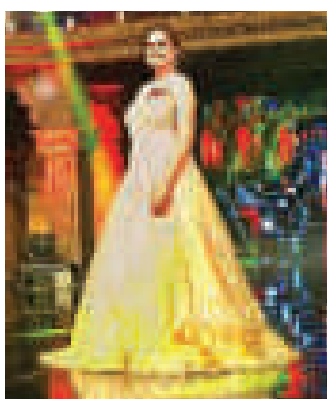

अहमदाबाद में प्रतियोगिता के दौरान अल्का कुलचंदानी। (सौजन्य अल्का के परिजन)

पराली से तैयार किए डिस्पोजेबल बर्तन

तलाशी राह ▸ सूखी पराली की लुग्दी से तैयार किया फार्मूला, बढ़ेगी किसानों की आय

इंदौर के दंपती को कृषि बिजनेस इंक्यूबेटर में मिला स्थान

दीपक शुक्ला, रायपुर

'आम के आम गुठलियों के दाम' और वह भी उस पराली के लिए जो पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का प्रमुख कारण बनी हुई है। अब यही पराली किसानों के लिए आय का साधन बनेगी। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर में इंदौर के युवा दंपती प्रदीप पाण्डेय और पूजा पाण्डेय ने पराली से डिस्पोजबल बर्तन तैयार किया है। साथ ही, एग्रो स्टार्टअप भी शुरू किया है और किसानों को इसे लघु उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मालूम हो कि फसलीय अवशेष विशेषकर पराली का निस्तारण बड़ी समस्या बनी हुई है। कुछ जगहों पर किसान इसे जला देते हैं, जो प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहा है। प्रदीप पाण्डेय बताते हैं कि ऐसे में हमने प्लास्टिक से तैयार डिस्पोजेबल को चुनौती मानते हुए पराली से डिस्पोजेबल बर्तन तैयार किया है। यह स्वतः गल जाएगा और इससे खाद भी बनाई जा सकती है।

पर्यावरण संरक्षण

ऐसे होता है तैयार : प्रदीप ने बताया कि पराली को पानी में डुबो कर एक से दो दिन रखने के बाद उसकी लुग्दी तैयार की जाती है। लुग्दी से आसानी से डिस्पोजेबल बर्तन तैयार किया जा सकता है। इसके लिए अलग से मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। कागज के डिस्पोजेबल बनाने वाली मशीन से ही यह बन सकता है। इससे कप, गिलास, थाली, प्लेट, कटोरी भी बनाई गई है।

पैरा (धान की भूसी) से तैयार किया गया डिस्पोजल। नईदुनिया

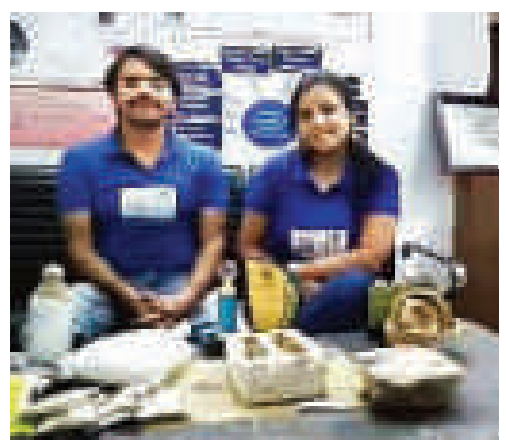

डिस्पोजेबल बर्तन तैयार करने वाले प्रदीप व पूजा पाण्डेय। नईदुनिया

नालियां नहीं होंगी जाम : प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल कप, प्लेट आदि के कारण नालियां जाम हो जाती थीं, लेकिन पराली से तैयार ये सामान नालियों को साफ करने का काम करेंगे। ये डिस्पोजेबल बर्तन नाली में जाते ही लुग्दी बन जाते हैं और उसमें मौजूद गंदगी को अपने साथ लपेट लेते हैं। जब उसे बाहर निकालते हैं तो नाली पूरी तरह से साफ हो जाती है। प्रदीप कहते हैं कि अगर तालाब की सफाई करनी है तो उपयोग किए जा चुके पराली के डिस्पोजेबल बर्तन को उसमें फेंक दें। 12 घंटे के बाद निकालने से तालाब पूरी तरह से साफ हो जाएगा।

> प्रदीप और पूजा ने पराली से डिस्पोजेबल बनाने का नवाचार किया है। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर में उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अब इसे बड़े रूप में तैयार करने की योजना है।
> **-डॉ. हुलास पाठक, सीईओ रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर**

तैयार हो जाएगी जैविक खाद : पराली के डिस्पोजेबल से खाद भी तैयार की जा सकती है। अगर इसके साथ गोबर को मिला दिया जाए तो 10 से 15 दिन में खाद बन जाती है।

दिल्ली के लिए फायदेमंद : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की समस्या से परेशान है। वहां से सटे हरियाणा और पंजाब के इलाकों में किसान फसल काटने के बाद पराली खेतों में जला देते हैं, जो प्रदूषण का बड़ा कारण माना जा रहा है। वहां भी यह फार्मूला काम आ सकता है।

आप भी जुड़ें

अपने आस-पास के ऐसे ही किसी अभिनव, प्रेरक व सार्थक प्रयास की जानकारी आप भी हमें दे सकते हैं, जो व्यक्ति, देश व समाज को नवप्रेरणा से भर सकती हो। संक्षिप्त विवरण response.story@jagran.com पर भेजें।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

इंटरनेशनल माउंटेन डे के पोस्टर पर उत्तराखंड का छलिया नृत्य

गणेश पांडे, हल्द्वानी

इस वर्ष 11 दिसंबर को होने वाले इंटरनेशनल माउंटेन डे के पोस्टर पर उत्तराखंड के छलिया नृत्य को जगह मिली है। छलिया नृत्य को शौर्य व पराक्रम का प्रतीक माना गया है। पोस्टर इंग्लिश, चायनीज, फ्रेंच समेत विश्व की छह भाषाओं में जारी हुआ है। हाथों में तलवार-ढाल लिए महिला छलिया कलाकारों की फोटो को नैनीताल निवासी अमित साह ने क्लिक किया है।

पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने 2003 में इंटरनेशनल माउंटेन डे की शुरुआत की। तब से 11 दिसंबर को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। पर्वत दिवस मनाने का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालना व अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्र के प्रति दायित्वों के लिए जागरूक करना है। इस बार की थीम 'माउंटेन मैटर ऑफ यूथ' है। युवा कल का भविष्य हैं, इसलिए पहाड़ एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से बचने के उद्देश्य से युवाओं को जागरूक करने के लिए यह थीम दी गई है।

नैनीताल निवासी अमित साह ने बताया कि महिला छलियारों की तस्वीर को उन्होंने बागेश्वर के लीती में 2017 में हुए पर्वत दिवस पर खींचा था। उन्होंने बताया कि छलिया नृत्य शौर्य, पराक्रम के साथ हिमालय के समान अदम्य साहस का प्रतीक है।

ये है छलिया नृत्य : छलिया नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में प्रचलित लोकनृत्य है। यह एक तलवार नृत्य है, जो मुख्य रूप से शादी-बारातों में या दूसरे शुभ अवसरों पर किया जाता है। छलिया नृत्य की शुरुआत खस राजाओं के समय की मानी जाती है। चंद राजाओं के आगमन के बाद यह नृत्य क्षत्रियों की पहचान बन गया।

अगले महीने 11 दिसंबर को होने वाले इंटरनेशनल माउंटेन डे के पोस्टर पर उत्तराखंड के छलिया नृत्य को मिला स्थान। जागरण

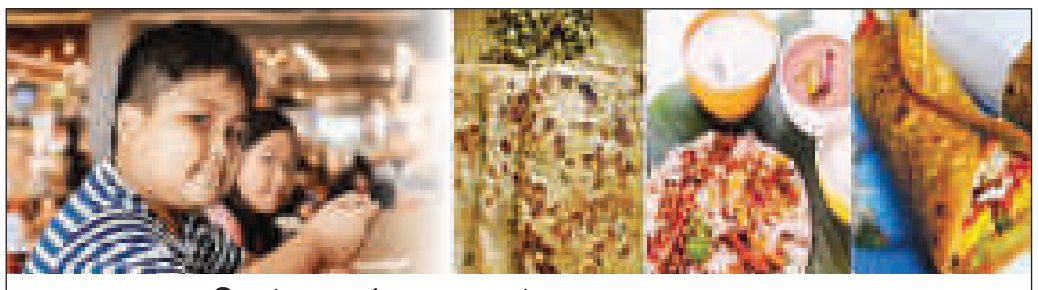

उत्पम, काठी रोल और दाल के पराठे खाने से स्वस्थ रहेंगे बच्चे

बच्चों के समुचित विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने अनोखी पहल की है। उसने पोषण युक्त खाद्य पर किताब जारी की है। फ्रॉम उत्पम टू स्प्राउटेड दाल पराठा नामक यह किताब बताती है कि 20 रुपये से कम लागत में तैयार पौष्टिक भोजन से बच्चों में खून की कमी, कम वजन और मोटापे जैसी समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण बना आधार

यह किताब राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-18 के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें पाया गया कि भारत में पांच साल से कम आयु वाले 35 फीसद बच्चों की उनकी उम्र के हिसाब से कम लंबाई है। 17 फीसद बच्चों की लंबाई के मुकाबले कम वजन है। 33 फीसद बच्चे उम्र और लंबाई के मुकाबले कम वजनी हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि एनीमिया (खून की कमी) से 40 फीसद किशोर लड़कियां और 18 फीसद किशोर लड़के प्रभावित हैं। वहीं स्कूली बच्चों और किशोरों में मोटापा बढ़ने से उनमें मधुमेह (10 फीसद) जैसे गैर-संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है।

> किताब का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि कौन सा भोजन कितना पौष्टिक है। किसी व्यक्ति के जीवन में दो चरण होते हैं जब उनके लिए पोषण बेहद महत्वपूर्ण होता है। पहले चरण में बच्चों को पोषण की जरूरत शुरुआत के 1000वें दिन तक होती है। यह वह समय होता है जब हम मां को पोषण के बारे में सिखा सकते हैं। दूसरा जब वे किशोरावस्था में होते हैं तब उन्हें शिक्षकों के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। पौष्टिक भोजन का ज्ञान स्कूलों में लाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए
> **- हेनरिटा एच फोर-** यूनिसेफ प्रमुख

कई व्यंजनों को किया गया सूचीबद्ध

28 पेज की इस किताब में कई भोज्य पदार्थों का उल्लेख है। प्रत्येक की तैयारी की लागत भी बताई गई है। कम वजन की समस्या से निपटने के लिए आलू भरे पराठे, पनीर काठी रोल और साबूदाना कटलेट की विधियां दी गई हैं। वहीं मोटापा दूर करने के लिए अंकुरित दाल के पराठे, पोहा और सब्जियों वाले उपमा को खाने के सुझाव हैं। इस किताब में सभी व्यंजनों की कैलोरी मात्रा के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर ,आयरन, विटामिन सी और कैल्शियम की मात्रा की भी पूरी जानकारी दी गई है।

29 साल पुराने हाथियों के कॉरिडोर को मिलकर संवारेंगे भारत-नेपाल

जागरण संवाददाता, लखीमपुर

▸ दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में बनी सहमति

▸ 50 से 60 किलोमीटर लंबा है यह प्राकृतिक कॉरिडोर

शुक्लाफाटा नेशनल पार्क से लखीमपुर के मैलानी, महेशपुर रेंज तक 29 साल पुराने हाथियों के कॉरिडोर को भारत-नेपाल मिलकर संवारेंगे। करीब 50-60 किमी लंबे इस प्राकृतिक कॉरिडोर को हाथियों के लिए मुफीद बनाया जाएगा। कॉरिडोर के निकट आबादी बसने और खेती करने पर रोक लगेगी। वन्यजीवों की सुरक्षा एवं उनके संरक्षण के लिए दोनों देशों के रेंजस्तर के अधिकारियों की बैठक जल्द कराई जाएगी।

गत दिनों नेपाल के शुक्लाफाटा से मैलानी और महेशपुर रेंज तक हाथियों के पहुंचने से भारत-नेपाल के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। शनिवार को नेपाल से आए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और भारत की ओर से दुधवा व बफरजोन के अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई। अफसरों ने बताया कि 1990 में नेपाल से हाथियों का एक झुंड मैलानी के जंगलों तक आया था। तब से शुक्लाफाटा से हाथियों के समूह का आना-जाना बना हुआ है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हाथियों की मेमोरी बहुत तेज होती है। वे रास्ते नहीं भूलते। हाल ही में शुक्लाफाटा से 25 हाथियों का झुंड यहां आया था। करीब 22 दिनों के बाद नेपाल लौट गया था। ऐसे में अगर हाथियों के कॉरिडोर क्षेत्र में खेती होगी या आबादी बसेगी तो हाथी लोगों को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। तब इस परिस्थिति का सामना करना काफी मुश्किल होगा।

> शुक्लाफाटा से मैलानी के बीच हाथियों का पुराना कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर को कवर रखने की जरूरत है। दोनों देशों में कॉरिडोर को संवारने पर सहमति बनी है।
> **- डॉ. अनिल पटेल, डीडी बफरजोन**

कॉरिडोर के निकट आबादी बसने और खेती करने पर लगेगी रोक। प्रतीकात्मक

कॉरिडोर संवारने और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर भारत-नेपाल के बीच अब उच्चस्तरीय बैठक होगी। सबसे पहले कंचनपुर के डीएफओ और दुधवा के अधिकारी हाथियों के मुद्दे पर रणनीति तैयार करेंगे। इसके बाद प्रदेश और नेपाली अधिकारियों के बीच बैठक में शिकार, तस्करी व शिकारी गिरोहों के संबंध में बैठक होगी।

मानव और वन्यजीव संघर्ष थामने को अब आरआरटी

केदार दत्त, देहरादून : राजाजी टाइगर रिजर्व और इसके नजदीकी पांच वन प्रभागों में चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुके मानव-वन्यजीव संघर्ष को थामने को सरकार अब सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में राजाजी के अलावा देहरादून, हरिद्वार, लैंसडौन, टिहरी और पौड़ी वन प्रभागों में रैपिड रिस्पांस टीमें (आरआरटी) तैनात की जा रही हैं। ये टीमें अपने-अपने प्रभागों से लगे आबादी वाले इलाकों में वन्यजीवों की सक्रियता अथवा कोई घटना होने पर त्वरित कार्रवाई करेंगी।

राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे हरिद्वार समेत अन्य क्षेत्रों में हाथियों के आतंक ने नींद उड़ाई हुई है। हरिद्वार के पिंजनहेड़ी में हाल में हाथी ने दो लोगों को मार डाला था। इससे पहले भी हरिद्वार में वन्यजीवों के हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी ही स्थिति हरिद्वार, देहरादून, लैंसडौन, टिहरी व पौड़ी वन प्रभागों की भी है। कहीं हाथी तो कहीं गुलदार समेत दूसरे वन्यजीवों ने नाक में दम किया हुआ है। वन्यजीवों के आक्रामक व्यवहार और इनकी आबादी वाले क्षेत्रों में धमक ने वन महकमे से लेकर शासन व सरकार की पेशानी पर बल डाले हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता तो हरिद्वार को लेकर है, जहां 2021 में महाकुंभ का आयोजन होना है। यदि हाथी समेत दूसरे वन्यजीवों की हरिद्वार क्षेत्र में आवाजाही पर अंकुश नहीं लगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

अब इस समस्या के निदान को गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। वन सीमा पर मजबूत सोलर पावर फैंसिंग, वन्यजीवरोधी दीवार जैसे कदम उठाने के साथ ही राजाजी रिजर्व व उसके आसपास के पांच वन प्रभागों में रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात की जा रही हैं। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव भरतरी के अनुसार राजाजी रिजर्व व टिहरी में यह टीमें गठित हैं, जबकि पौड़ी, देहरादून, लैंसडौन व हरिद्वार प्रभागों में नए सिरे से इनके गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वह बताते हैं कि यह टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगी और कहीं भी आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की सक्रियता अथवा कोई घटना होने पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बताया कि इन विभागीय टीमों को इसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। जर्मन एजेंसी जीआइजेड के सहयोग से इन्हें मानव-वन्यजीव संघर्ष थामने से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

रखी बात

महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के पड़पौत्र फिलिक्स पैडल भारत में कर रहे आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए काम, बोले- जंगल से दूर होने की वजह से पनपा आदिवासियों में कुपोषण

'अंग्रेजों ने बिगाड़ी आदिवासियों की संस्कृति'

सौरभ खंडेलवाल, भोपाल

मानव विकास का क्रम समझाने वाले महान वैज्ञानिकों में से एक चार्ल्स डार्विन के पड़पौत्र फिलिक्स पैडल भारत में पिछले 40 साल से आदिवासियों की संस्कृति और उनकी भाषा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आदिवासी भाषाओं पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने भोपाल आए पैडल ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से कहा कि ब्रिटिश राज ने भारत में आदिवासियों की संस्कृति बिगाड़ने की शुरुआत की थी और यह सिलसिला आज भी चला आ रहा है। लंदन में जन्मे फिलिक्स ने कहा, 'मेरी नजर में ब्रिटिश सरकार की प्रशासन और पुलिस व्यवस्था सबसे खराब व्यवस्थाओं में से एक है और आदिवासियों का सामाजिक ताना-बाना सबसे बढ़िया व्यवस्था है।'

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच फैले कुपोषण की बड़ी वजह यही है कि ब्रिटिश राज के दौरान ही आदिवासियों को जंगल से हटाने की साजिश शुरू हो गई थी। पैडल ने दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमफिल और लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। वह ओडिशा में नियमगिरी जंगलों और वहां रह रहे आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं। पैडल ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग बनाकर आदिवासियों को जंगल से दूर किया। आजाद भारत में भी तथाकथित मुख्यधारा में लाने के नाम पर उनसे वनाधिकार छीने गए।

आदिवासी ही बचा सकते हैं जंगल : पैडल का कहना है कि भारत में हजारों सालों से जंगलों की रक्षा आदिवासी करते आए हैं, इसलिए जंगलों को उन्हें ही सौंपा जाना चाहिए। वे ही इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी रखते हैं और इस काम में दक्ष हैं। हम लोकतंत्र उन पर थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि आदिवासी ही सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत और आदिवासियों की संस्कृति एक ही संदेश देती है।'

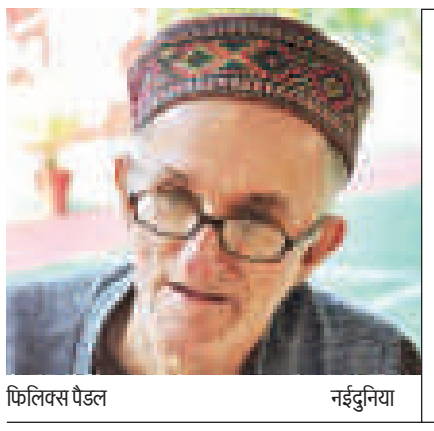

फिलिक्स पैडल नईदुनिया

स्कूलों में पढ़ाई जाएं आदिवासी भाषाएं

पैडल ने कहा कि आदिवासी समुदाय के बच्चों पर स्कूल में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था थोपी जा रही है। पूरे भारत में करीब एक हजार तरह की आदिवासी भाषाएं हैं। इन्हें क्षेत्र के हिसाब से स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि इन समुदायों के बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। मध्य प्रदेश में इसे लागू किया जाना चाहिए। प्रदेश के कई इलाकों में रहने वाले पारधी समुदाय को आदिवासी दर्जा दिया जाए।

मशीन का इस्तेमाल कर बनाया जाएगा 'बांग्लार रसगोल्ला'

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कोलकाता के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक जादवपुर विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग राज्य सरकार के साथ मिलकर 'बांग्लार रसगोल्ला' के भंडारण और उपयोग की अवधि बढ़ाने पर काम कर रहा है। दो वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए बंगाल के रसगुल्ले को जीआइ का टैग मिला था। इस संबंध में खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया कि अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) विभाग परिरक्षकों की किस्म पर काम कर रहा है ताकि बंगाल के रसगुल्ले के भंडारण एवं उपयोग की अवधि को बढ़ाया जा सके। प्रोफेसर ने यह भी बताया कि विवि का आर एंड डी विभाग एक निश्चित समय, छह महीने तक रसगुल्ले के भंडारण और उपयोग की अवधि बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए काम कर रहा है। फिलहाल इस प्रक्रिया का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं हो पाया है। प्रोफेसर ने बताया कि आने वाले समय में मशीनों के इस्तेमाल से मिठाई का निर्माण किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार का पशु संसाधन विकास विभाग यह बेहतर तरीके से बता सकता है कि बाजार में कब और कैसे यह मिठाई उपलब्ध होगी।

बंगाल के रसगुल्ले फाइल

इस बारे में राज्य के पशुपालन मंत्री स्वपन देवनाथ ने कहा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जादवपुर विवि के विशेषज्ञों द्वारा तैयार तय मानदंडों के आधार पर राज्य एक संयंत्र में स्वचालित मशीनों की सहायता से रसगुल्ला निर्माण करेगा एवं 'मदर डेयरी' ब्रांड के तहत उत्पाद की बिक्री शुरू करेगा।

खाद कंपनियां रिलायंस से गैस नहीं खरीद रहीं

नई दिल्ली : केजी-डी6 बेसिन से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) से गैस खरीदने के मामले में एस्सार स्टील और अडानी ग्रुप जैसी निजी कंपनियों के अलावा सरकारी क्षेत्र की गेल प्रमुख रही है। दिलचस्प यह है कि देश की प्रमुख सरकारी खाद कंपनियां इन बोलियों से बाहर रही हैं। ये खाद कंपनियां महंगी आयातित एलएनजी से काम चला रही हैं, जबकि आरआइएल से गैस खरीदने पर उनके 800 करोड़ रुपये बच सकते थे। (प्रेट्र)

बिजली वितरण कंपनियों की हालत चिंताजनक है। इन्हें किसी भी सूरत में परिचालन योग्य बनया जाना चाहिए।

— एन. चंद्रशेखरन
चेयरमैन, टाटा संस

जलवायु में जहर घोल रहे घटिया कीटनाशक

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

खाद्य सुरक्षा को महफूज बनाने वाले कीटनाशक हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने के बावजूद हमारी चुनौतियां बहुत बढ़ गई है। दरअसल जागरूकता के अभाव में प्रतिबंधित और घटिया कीटनाशकों का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसके उत्पादन, वितरण, बिक्री और प्रयोग के लिए बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन नहीं होने से मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। ऐसे प्रतिबंधित कीटनाशकों का आयात भी हो रहा है, जो जलवायु और लोगों के जीवन में जहर घोल रहे हैं।

इन कीटनाशकों से कृषि क्षेत्र की फसल श्रृंखला दूषित हो रही है। खेती के बुनियादी ढांचे मिट्टी, बीज और पानी में रोजाना जहर घुल रहा है। कीटनाशकों के ताबड़तोड़ प्रयोग से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव सबसे पहले खत्म होते हैं। फसल की बोआई और कटाई ही नहीं, अब तो भंडारण तक में इन कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन किस फसल में किस रोग के लिए कितना, कब, कैसे और कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, इसकी जानकारी का अभाव है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. आरबी सिंह का कहना है कि किसानों में जागरूकता का अभाव और जानकारी देने वाली प्रसार प्रणाली के खत्म होने का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है।

डॉक्टर सिंह ने कहा, 'कीटनाशकों के प्रयोग के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे है। लेकिन इसके गलत प्रयोग के चलते हालात बहुत खराब हैं, जिस पर बिना किसी देरी के रोक लगनी चाहिए।' इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक डॉ. मंगला राय कहते हैं, 'भारत में प्रति हेक्टेयर 500 ग्राम कीटनाशक छिड़का जाता है, जबकि जापान में यह 15 किलोग्राम तक है। लेकिन भारत में कौन सा कीटनाशक प्रयोग हो रहा है, यह देखने वाला कोई नहीं है।'

कीटनाशकों को लेकर बनाए गए नियम-कानून लागू करने वाली एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाने में हैं। लिहाजा बाजार में 40-50 प्रतिशत नकली कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहे हैं। सिंह ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि कीटनाशकों के उत्पादक, वितरक, खुदरा व्यापारियों और किसानों के बीच कोई तालमेल नहीं है। खुदरा व्यापारी जो उत्पाद बेचना चाहता है, किसानों को बेहिचक बेच देता है। आमतौर पर देश में कीटनाशकों के मॉलिक्यूल का ही आयात किया जाता है, जिसका फॉर्मूलेशन (अंतिम उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया) घरेलू कंपनियां करती हैं। इस दिशा में शोध नहीं हो रहा है। इसके अन्य देशों में प्रतिबंधित कीटनाशकों का भी भारत में खुलकर प्रयोग हो रहा है। प्रो. टीवीएस राजपूत का कहना है, 'पेस्टिसाइड्स (कीटनाशकों) का उत्पादन और वितरण प्राइवेट सेक्टर के पास है। कीटनाशकों के बेहिसाब प्रयोग से मिट्टी में विषाक्तता बढ़ रही है। मिट्टी के सूक्ष्म जीव मरते जा रहे हैं। उचित गाइडलाइन नहीं होने से मिट्टी की हालत और बिगड़ रही है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर सख्ती से अमल की जरूरत है, जो नहीं हो पा रही है। खेत की घास खत्म करने से लेकर फल तोड़ने अथवा हार्वेस्टिंग तक इन कीटनाशकों का प्रयोग हर स्तर पर हो रहा है, जिसके बारे में उचित जानकारी न होने से किसान भी मुश्किल में हैं।

कम कीटनाशकों के उपयोग के बावजूद भारत में फसल श्रृंखला दूषित हो रही है। प्रतीकात्मक

मात्र नौ फीसद रकबा में कीटनाशक

भारत में कीटनाशकों के बहुत अधिक प्रयोग को लेकर बनी हुई धारणा वास्तविकता के आसपास नहीं है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कृषि योग्य कुल भूमि में से केवल नौ फीसद (1.67 करोड़ हेक्टेयर) में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें भी सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाला राज्य जम्मू-कश्मीर है, जहां प्रति हेक्टेयर खेती में 2.33 किलोग्राम का उपयोग हो रहा है। पंजाब दूसरे स्थान पर है, जहां प्रति हेक्टेयर 1.38 किलोग्राम कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा में कीटनाशकों का प्रयोग 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

स्टार्ट-अप्स को नियम पालन में लगेंगे सिर्फ एक घंटे

- स्टार्ट-अप इंडिया विजन 2024 के तहत डीपीआइआइटी ने किया प्रस्ताव
- कंपनियों को हर महीने विभिन्न तरह के फॉर्म भरने में लगने वाला समय घटेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार स्टार्ट-अप कंपनियों को नियम पालन में लगने वाला समय घटाने के प्रति गंभीर है। अगर सब तय योजना के अनुरूप रहा, तो जल्द स्टार्ट-अप कंपनियों को हर महीना नियम पालन में महज एक घंटे का वक्त देना पड़ेगा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने जिस स्टार्ट-अप इंडिया विजन 2024 की योजना तैयार की है, उसके बहुत से प्रस्तावों में एक यह भी है कि उभरती स्टार्ट-अप कंपनियों को नियम-कानून के पालन में लगने वाला वक्त घटाया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी स्टार्ट-अप कंपनी से एक महीने की उतनी ही जानकारी मांगी जाएगी, जितनी वे एक घंटे में भर सकें।

विभाग के विजन दस्तावेज के मुताबिक अन्य प्रस्तावों में कर्ज मुहैया कराने का प्रावधान भी है। इसके अलावा विभाग इन कंपनियों के लिए 500 नए इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स (जहां छोटी स्टार्ट-अप कंपनियों को बड़ा बनने के गुर सिखाए जाते हैं और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं) और शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका और नगर निगम) में इनोवेशन जोन स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है। विभाग ने यह विजन दस्तावेज विभिन्न मंत्रालयों के पास भेजा है और उस पर उनके राय मांगे हैं। एक अधिकारी का कहना था कि वर्तमान में स्टार्ट-अप कंपनियों को जीएसटी फाइलिंग, टैक्स रिटर्न और इस तरह के कई अनुपालनों में हर महीने लंबा वक्त देना पड़ता है। इनमें इन कंपनियों को खर्च भी ज्यादा होता है। प्रस्ताव में स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए देश में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी आयोजित करना शामिल है।

स्टार्ट-अप इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का एक प्रमुख कदम है। इसे जनवरी, 2016 में लांच किया गया था। इसका मकसद देश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम तैयार करना है। इससे देश में विकास को गति मिलेगी और रोजगार में खासा इजाफा होगा। विभाग ने अब तक 24,000 स्टार्ट-अप कंपनियों को मान्यता दी है। मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप कंपनियों को सरकार एंजल टैक्स समेत कई अन्य मदों में छूट भी दे रही है।

न्यूज गैलरी

दिल्ली में कारोबार शुरू करना हुआ आसान

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि अब घरेलू कंपनियों को दिल्ली में उत्पादन कार्य शुरू करने के लिए प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग से एनओसी नहीं लेना पड़ेगा। जावडेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यापार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इससे तीन लाख उद्योगों को लाभ मिल सकेगा। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को नियमों के अनुपालन में लगने वाला समय घटाने की दिशा में काम कर रही है। (एएनआइ)

एमएसएमई का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार बना रही नीति

नागपुर : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार एमएसएमई सेक्टर का निर्यात बढ़ाने के लिए दो नीतियों पर काम कर रही है। इसके लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर देश के विकास में 29 परसेंट का योगदान देता है और निर्यात में इस सेक्टर का योगदान 48 परसेंट है। इसके अलावा यह सेक्टर 11-12 करोड़ नौकरियां भी दे रहा है। (प्रेट्र)

कश्मीर में सेब खरीदने की योजना विफल

नई दिल्ली : ऑल इंडिया किसान संघर्ष कॉर्डिनेशन कमेटी (एआइकेएससीसी) ने कहा है कि कश्मीर में नैफेड के माध्यम से सेब खरीदने का सरकारी प्रयास बुरी तरह से विफल साबित हुआ है। इस किसान संगठन के मुताबिक 11 करोड़ बॉक्स में से अभी तक सिर्फ 1.36 लाख बॉक्स ही खरीदे गए हैं। यह लक्ष्य का सिर्फ 0.01 परसेंट है। इससे पता चलता है कि सेब खरीद की योजना विफल रही है। (प्रेट्र)

आरकॉम की संपत्तियों की खरीद प्रक्रिया से हटी एयरटेल

नई दिल्ली : भारती एयरटेल ने आरकॉम की संपत्ति खरीदने के लिए लगाई गई बोली से पीछे हटने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि आरकॉम के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने बोली लगाने की अवधि बढ़ा दी है, जो बेहद अनुचित और पक्षपातपूर्ण है। आरकॉम की सीओसी ने रिलायंस जियो के अनुरोध पर बोली की अवधि बढ़ाई थी। एयरटेल के निदेशक (वित्त) हरजीत कोहली ने इस बारे में आरकॉम की सीओसी को पत्र लिखा है। कंपनी ने कहा है कि एयरटेल ने बोली अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था, तो सीओसी ने ठुकरा दिया। लेकिन एक अन्य बोलीकर्ता के आग्रह पर अवधि बढ़ा दी गई है। कंपनी का कहना है कि उसका आग्रह ठुकराने और एक अन्य संभावित बोलीकर्ता का वही आग्रह स्वीकार करने का मतलब यह है कि प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी। (प्रेट्र)

भारत में तेज आर्थिक विकास की क्षमता : गेट्स

उम्मीद ▶ कहा- अगले एक दशक में भारत की इकोनॉमी करेगी तेज गति से विकास, आधार सिस्टम बेहद कारगर

कहा - लोग गरीबी से उबरेंगे, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में करेगी बड़ा निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेर बिल गेट्स को यकीन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पास बेहद तेज गति से विकास करने की पूरी क्षमता है। उनके मुताबिक अगले एक दशक में भारत की विकास गति इतनी तेज होगी कि लोग गरीबी से उबर सकेंगे और सरकार स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं में बड़ा निवेश कर सकेगी। उन्होंने आधार कार्ड जैसे पहचान तंत्र विकसित करने और फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार की प्रशंसा भी की।

भारत को लेकर गेट्स का यह भरोसा ऐसे वक्त में सामने आया है, जब एशिया की इस तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की विकास दर गिर रही है। जानकारों को ऐसी आशंका है कि देश की इकोनॉमी पर यह दबाव लंबे वक्त तक रह सकता है। भारत में अपने फाउंडेशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए तीन दिवसीय दौरे पर आए गेट्स ने कहा, 'निकट भविष्य के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगले एक दशक के बारे में मेरा मानना है कि बेहद तेज विकास की पूरी क्षमता है। यह ऐसा विकास होगा जो लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगा और सरकार को स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं में निवेश के रास्ते खोलेगा।' उन्होंने कहा कि हर किसी को उम्मीद है कि भारत सचमुच तेज विकास दर हासिल करेगा। इसकी वजह यह है कि भारत के पास इसकी भरपूर क्षमता है।

बिल गेट्स ने अमेजन इंक के प्रमुख जेफ बेजोस को पछाड़ते हुए पिछले सप्ताह शुक्रवार को दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेर का रुतबा वापस हासिल कर लिया था। अमेजन इंक को हुए जबर्दस्त तिमाही नुकसान के बाद बेजोस की संपत्ति घटकर 108.7 अरब डॉलर (करीब 7.61 लाख करोड़ रुपये) रह गई। वहीं, गेट्स की संपत्ति इस वक्त 110 अरब डॉलर (करीब 7.70 लाख करोड़ रुपये) है। वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से कई देशों में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए अब तक 35 अरब डॉलर (करीब 2.4 लाख करोड़ रुपये) दान कर चुके हैं।

आधार सिस्टम की तारीफ करते हुए गेट्स का कहना था कि उनका फाउंडेशन जहां कहीं भी कार्यरत है, उनमें भारत इनोवेटर और फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराने वाले प्रमुख क्षेत्रों में एक है। भारत ने जिस तरह से आधार सिस्टम विकसित किया है और यहां यूपीआइ सिस्टम जिस प्रकार से अपनाया जा रहा है, वह वाकई रोचक है। इस तरह के कार्यों में सीखने लायक बहुत कुछ है। गेट्स ने कहा, 'हम नंदन नीलेकणि (आधार योजना को कार्यरूप देने वाले, इन्फोसिस के सह-संस्थापक) जैसे लोगों से गठजोड़ कर यह समझना चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम से हासिल सीखों का अन्य देशों में किस तरह उपयोग किया जा सकता है।'

पटना में रविवार को स्वास्थ्य एवं पोषण एजेंडे पर आयोजित परिचर्चा में शामिल होने आए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स को सम्मानित करते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जागरण

नीतीश कुमार से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, पटना

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक विमर्श में हिस्सा लिया। बिहार में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्वास्थ्य व विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सामुदायिक स्तर पर जन व्यवहार परिवर्तन, पोषण, स्वास्थ्य व कृषि क्षेत्रों में अभिनव प्रयास को बढ़ाने में फांउडेशन की सहभागिता प्रशंसनीय है। इस बात पर सहमति बनी कि राज्य में कालाजार, लिंफेटिक फाइलेरिया समेत टीबी जैसे संक्रामक रोगों के उन्मूलन में तेजी लायी जाएगी।

बिल गेट्स ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार ने गरीबी और बीमारी के खिलाफ अत्यधिक प्रगति हासिल की है। बिहार में अब जन्म लेने वाले शिशु में अपने पांचवें जन्मदिन तक पहुंचने की संभावना दो दशक पहले की तुलना में दोगुने से अधिक है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों।

बीएसएनएल के 23 जोन घाटे में, सिर्फ चार को हुआ फायदा

प्रमोद यादव, प्रयागराज : संचार क्षेत्र की सरकारी कंपनी बीएसएनएल की कमाई का ग्राफ गिर रहा है। अक्टूबर माह में पिछले साल की तुलना में यूपी ईस्ट जोन की कमाई 317 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में 22.25 फीसद कम है। सबसे ज्यादा घाटा हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और अंडमान निकोबार जोन फायदे में है।

कुछ वर्षों से बीएसएनएल के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। घाटा कम करने के लिए कंपनी पिछले दिनों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लाई है। करीब 75,000 कर्मचारियों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि तीन दिसंबर रखी गई है। बीएसएनल की दूसरी तिमाही की कमाई के आंकड़े भी निराशाजनक हैं। इसके मुताबिक देश के 27 में सिर्फ चार जोन में ही कंपनी फायदे में रही है। घाटे वाले जोन में सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है। वहां पर कमाई 39.82 फीसद कम हुई। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जोन-2 में कमाई 30.85 फीसद, कर्नाटक में 30.85 फीसद और असम में 29.99 फीसद घटी है। चेन्नई (27.88 फीसद), केरल (24.85 फीसद), महाराष्ट्र (24.05 फीसद), जम्मू (22.41 फीसद), पूर्वी यूपी (22.25 फीसद), गुजरात (15.79 फीसद), छत्तीसगढ़ (10.16 फीसद) और आंध्र प्रदेश में (6.55 फीसद) में भी कंपनी की कमाई घटी है।

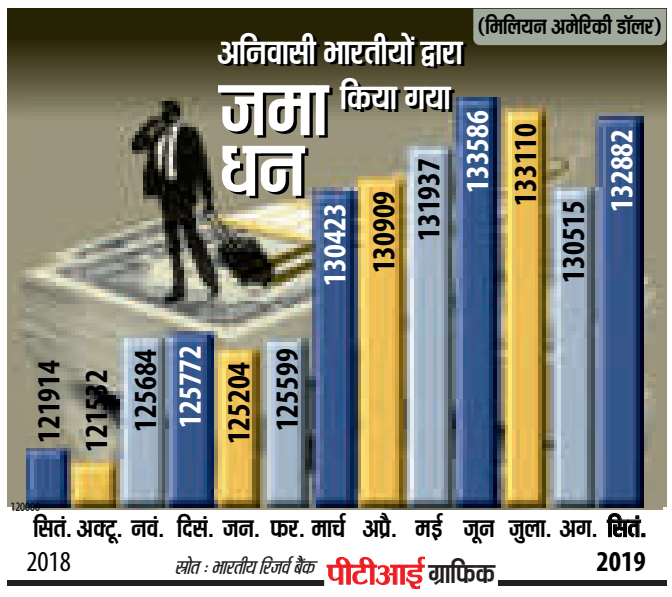

कुछ सेक्टरों से नए एनपीए सामने आने की आशंका

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- इसी हफ्ते वित्त मंत्री सीतारमण करेंगी बैंक प्रमुखों से विमर्श
- टेलीकॉम और पावर सेक्टर को लेकर सरकारी बैंकों में चिंता बढ़ी
- वोडाफोन में बैंकिंग सेक्टर का एक लाख करोड़ रुपये फंसा
- पावर सेक्टर में 1.75 लाख करोड़ रुपये का बैंकिंग कर्ज फंसा

प्रतीकात्मक

एस्सार स्टील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक तरफ जहां बैंकों को एनपीए के मोर्चे पर कुछ राहत दी है वहीं कुछ अन्य सेक्टर से परेशान करने वाली खबरें भी आ रही हैं। परेशानी भरी खबरें खासतौर पर दूरसंचार और बिजली सेक्टरों से हैं। देश की तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की खराब माली हालत से बैंकिंग सेक्टर की सांसें अटकी हैं, वही दर्जनों ताप बिजली संयंत्रों के बंद होने के खतरे से नई समस्या पैदा होती दिखने लगी है। यही वजह है कि अगले हफ्ते जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आरबीआइ के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी तो उसमें नए सेक्टर से एनपीए के खतरे से निपटने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि नए सेक्टर से एनपीए बनने का खतरा तब आया है जब आरबीआइ गवर्नर ने एनपीए के मोर्चे पर हालात के सुधरने की बात कही है। शनिवार को अहमदाबाद विश्वविद्यालय में पहले वार्षिक आर्थिक कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सात वर्षों बाद पहली बार एनपीए का स्तर घटता दिख रहा है। मार्च, 2019 में घरेलू बैंकिंग सेक्टर में परिसंपत्तियों के कवरेज का अनुपात 48.3 फीसद से बढ़कर 60.5 फीसद हो गया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो भी 14.3 फीसद पर पहुंच गया है, जो निर्धारित मानदंड से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक व ढांचागत परियोजनाओं को समय पर मंजूरी नहीं मिलने से सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्या गंभी हुई है। इसके साथ ही इन बैंकों में गवर्नेंस की समस्या और बैंकों पर ज्यादा से ज्यादा समाजिक उत्तरदायी योजनाओं को डालने की रणनीति भी इनकी बुरी हालत की जिम्मेदार रहीं।

देश के दो बड़े बैंकों के अधिकारियों ने दैनिक जागरण को बताया कि वित्त मंत्रालय के साथ पिछले महीने हुई बैठक में भी कुछ नए सेक्टर से फंसे कर्जे की स्थिति पर चर्चा हुई थी। लेकिन उस बैठक के बाद बिजली सेक्टर की स्थिति और खराब होने की खबरें भी आ चुकी हैं और वोडाफोन व आरकॉम जैसी दूरसंचार कंपनियों के भारी घाटे से भी हालात खराब होने के संकेत मिले हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि उसके प्रमुख ने भारत से बोरिया-बिस्तर समेटने तक का संकेत दे दिया। हालांकि कंपनी प्रमुख के बयान पर सरकार के एतराज के बाद वोडाफोन ने माफी मांगते हुए कहा कि वह भारत में निवेश बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वोडाफोन में देश के सरकारी व निजी बैंकों के करीब एक लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में है। इसी तरह से देश की ताप बिजली कंपनियों में अभी भारतीय बैंकों का करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है। दर्जनों थर्मल पावर प्लांट में क्षमता का महज 40-50 फीसद तक बिजली उत्पादन हो रहा है। इन प्लांटों की दर्जनों इकाइयों को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के आंकड़ों को देखें तो अधिकांश बैंकों में एनपीए का स्तर (कुल अग्रिम के मुकाबले फंसे कर्जे का अनुपात) पहले से कम हुआ है, लेकिन नए एनपीए बनने का सिलसिला भी बना हुआ है। सिर्फ सरकारी क्षेत्र के पांच सबसे बड़े बैंकों को देखे तो अप्रैल से सितंबर, 2019 के दौरान इनके खाते में 63,259 करोड़ रुपये का नया एनपीए जुटा है।

रॉयल्टी भुगतान पर लग सकती है पाबंदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के एवज में रॉयल्टी भुगतान पर पाबंदी लगाने पर फिर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि डीपीआइआइटी इस बारे में जल्द एक प्रस्ताव वितरित करने वाला है। विभाग के मुताबिक टेक्नोलॉजी के एवज में रॉयल्टी भुगतान के मद में विदेशी कंपनियों के खाते में देश से मोटी रकम का भुगतान किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर किसी भारतीय कंपनी के माध्यम से विदेशी कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी हस्तांतरण का करार हुआ हो, तो ऐसे मामलों में रॉयल्टी भुगतान की सीमा तय की जा सकती है।

निगाहें

तिमाही नतीजों का दौर लगभग खत्म, बड़े आर्थिक आंकड़े बाजार के पक्ष में नहीं, भारत-अमेरिका कारोबारी समझौते पर निवेशकों की रहेगी पैनी नजर, चीन के ब्याज दर आंकड़ों और ट्रेड वार पर अमेरिका के रुख का भी दिखेगा असर

संकेतों के अभाव में शेयर बाजार का दायरा रहेगा सीमित

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले सप्ताह मुश्किल से सकारात्मक स्तर पर बंद होने में कामयाब बीएसई सेंसेक्स के लिए सामने अगले कुछ कारोबारी सत्रों के लिए कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। एनएसई निफ्टी को तो पिछले शुक्रवार को कारोबार बंद होते वक्त साप्ताहिक गिरावट का सामना करना पड़ा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि घरेलू शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते रहेंगे। विदेशी बाजारों के चुनिंदा घटनाक्रमों को बिना शक घरेलू शेयर बाजारों पर असर दिखेगा। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसके घटनाक्रमों से शेयर बाजार तात्कालिक तौर पर प्रभावित हो सकते हैं।

सैमको सिक्युरिटीज एंड स्टॉकनोट के फाउंडर व सीईओ जिमीत मोदी का मानना है कि तिमाही नतीजों का दौर लगभग खत्म हो चुका है, लिहाजा शेयर बाजार कुछ सत्रों में विदेशी कारकों से ही प्रभावित होंगे। इनमें अमेरिका-भारत कारोबारी समझौता प्रमुख है। बाजार में सकारात्मक संकेतों का अभाव दिख रहा है, लिहाजा सेंसेक्स और निफ्टी एक सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आएंगे।

एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम के घरेलू शेयर बाजारों को प्रभावित करने के लिए कई सीमापार घटनाक्रम इस सप्ताह हैं। हमें चीन में ब्याज दर का आंकड़ा देखना है और अमेरिका से भी कई वित्तीय आंकड़े आने हैं। हांगकांग के हालात बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका और चीन किसी कारोबारी समझौते पर सहमत हो गए, तो घरेलू शेयर बाजार निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर की राय भी नदीम और मोदी से अलग नहीं है। नायर मानते हैं कि अमेरिका और चीन में चल रहा ट्रेड वार अब अंजाम की ओर पहुंचता नजर आ रहा है। दुनिया की इन दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सुलह के प्रारंभिक संकेत दिखने लगे हैं और इसका दुनियाभर के बाजारों पर सकारात्मक असर दिखा है। नायर के मुताबिक घरेलू मोर्चे पर बड़े आर्थिक आंकड़े निवेशकों के लिए उत्साहजनक नहीं हैं। हालांकि पिछले कुछ समय के दौरान सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे में यकीन है कि अपनी अगली समीक्षा बैठक में भी आरबीआइ महंगाई दर के बारे में सोचने के बजाय विकास दर को गति देने पर विचार करेगा।

छह कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2.4 लाख करोड़ रुपये बढ़ा

नई दिल्ली : पिछले सप्ताह के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से छह कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 2.40 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल), एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) शामिल हैं।

हालांकि हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड (एचयूएल), इन्फोसिस, आइटीसी और एचडीएफसी के बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई। पूंजीकरण में बढ़ोतरी के मामले में पिछले सप्ताह टीसीएस 1,93,666.73 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे रही। इस बढ़ोतरी के साथ सप्ताह के आखिर में टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 8,16,068.63 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। आरआइएल का बाजार पूंजीकरण 15,182.29 करोड़ रुपये बढ़कर 9,31,412.63 करोड़ रुपये हो गया। एचडीएफसी के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 12,917.96 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब यह बैंक 6,99,704.93 करोड़ रुपये पूंजीकरण के साथ सोमवार को बीएसई में कारोबार के लिए उतरेगा। गौरतलब है कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले सप्ताह सात लाख करोड़ रुपये बाजार पूंजीकरण का भी आंकड़ा पार किया था। इससे पहले सिर्फ आरआइएल और टीसीएस इस आंकड़े को पार कर सकी हैं।

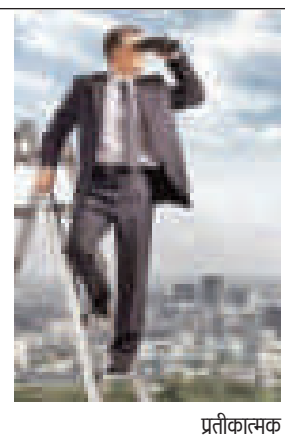

प्रतीकात्मक

एफपीआइ ने लगाए 19,203 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने नवंबर में अब तक घरेलू शेयर बाजारों में 19,203 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1-15 नवंबर के दौरान एफपीआइ ने इक्विटी मार्केट में 14,435.6 करोड़ रुपये और डेट मार्केट में 4,767.18 करोड़ रुपये का निवेश किया। इससे पहले अक्टूबर में एफपीआइ डेट और इक्विटी बाजारों में 16,464.6 करोड़ रुपये और सितंबर में 6,557.8 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

90 प्रतिशत देशों की जीडीपी से बड़ी कंपनी सऊदी अरैमको

रियाद (सऊदी अरब), एएफपी : सऊदी अरब ने सरकार नियंत्रित एनर्जी कंपनी सऊदी अरैमको का मूल्य 1.71 लाख करोड़ डॉलर (120 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) बताया है। अरैमको का यह मूल्य 90 प्रतिशत से ज्यादा देशों की जीडीपी से ज्यादा है। हालांकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने कंपनी का मूल्य दो लाख करोड़ डॉलर (140 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) लगाया था।

कंपनी का यह मूल्यांकन उसके आइपीओ के तहत हुआ है। कंपनी ने डेढ़ प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 25 अरब डॉलर (करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये) जुटाने का लक्ष्य रखा है। अरैमको पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आइपीओ लाना चाह रही थी। इसके तहत करीब दो प्रतिशत शेयर सऊदी अरब के तादाउल शेयर बाजार और तीन प्रतिशत शेयर विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराए जाने थे। लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्धता का इरादा फिलहाल टाल रही है।

7 लोगों की मौत हो गई बांग्लादेश के चटगांव शहर में रविवार सुबह गैस पाइप लाइन में धमाका होने से। पुलिस के अनुसार, इस धमाके से पांच मंजिला घर की बाहरी दीवार छह गई और रास्ते से गुजर रहे लोग भी उसकी चपेट में आ गए।

हांगकांग की अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था को कर रही डावांडोल

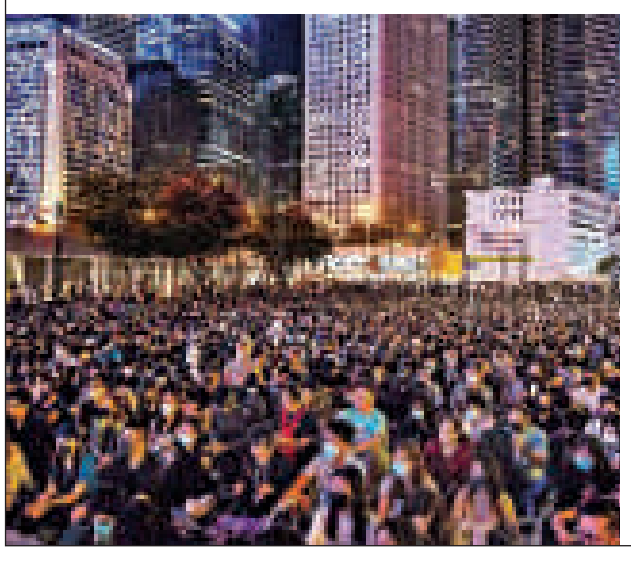

हांगकांग में पांच महीने पहले शांतिपूर्ण सामूहिक मार्च के रूप में जो आंदोलन शुरू हुआ था, वर्तमान में वह शहर के सबसे बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया है। सरकार और चीन की नीतियों को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन से बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है। वैश्विक वित्तीय केंद्र होने के नाते हांगकांग में जारी अस्थिरता का असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ना शुरू हो गया है। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां और ब्रांड हांगकांग से बाहर निकलने और अपनी शाखाओं को कहीं और स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं। निवेश कमजोर होने लगा है। पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है।

अर्थव्यवस्था को नुकसान

पांच महीने की हिंसा और उपद्रव ने शहर की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से अक्टूबर में हांगकांग मंदी की गिरफ्त में फंस गया है।

पर्यटकों का आना हुआ कम

खुदरा व्यापार और शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं, और छोटे व्यवसायों को बंद करने को मजबूर हैं। इस साल मई में पर्यटकों की 59 लाख संख्या सितंबर में कम होकर 31 लाख रह गई।

जून में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से अबतक पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट (संख्या लाख में)

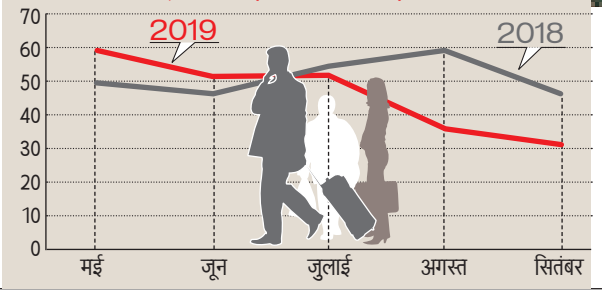

होगा बुरा हाल

हांगकांग एक वैश्विक वित्तीय केंद्र है, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था पर जरा सी भी चोट दुनिया भर में व्यापार को प्रभावित करती है। कई आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अशांति जारी रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हांगकांग से बाहर निकलने और अपनी शाखाओं को कहीं और स्थानांतरित कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चीन ने अपनी सेना शहर में तैनात की तो इस तरह की कार्रवाई हांगकांग के लिए विनाशकारी हो सकती है। शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा। इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बड़े पैमाने पर शहर से पलायन शुरू हो जाएगा और अन्य देशों में हांगकांग से आने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी। 1997 की विरासत के रूप में कई हांगकांग वासियों के पास विदेशी पासपोर्ट है और उनके लिए विदेश जाना आसान है।

संकट में कई अंतरराष्ट्रीय कंपनी

कई ब्रांड और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां चीन समर्थक और चीन विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच फंस गई हैं। जो ब्रांड और कंपनियां प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूति रखती हैं, उनका सामना चीनी उपद्रव और वित्तीय गतिरोध से होता है और जो चीन के प्रति सहानुभूति रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रदर्शनकारियों का समाना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एनबीए टीम के महाप्रबंधक ने विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में ट्वीट किया तो चीन के दबाव के चलते एनबीए को माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद महाप्रबंधक ने फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। इससे चीन भड़क गया और उसने एनबीए से अपनी साझेदारी तोड़ ली। मूल्यवान चीनी साझेदारी खो दी। ले ब्रॉन जेम्स और ओनील जैसे बास्केटबॉल सितारों ने भी इस मुद्दे पर बात की। वैन, नाइके, वर्साचे, कोच और गिवेंची जैसे ब्रांड भी चीन या प्रदर्शनकारियों के टार्गेट में हैं।

भविष्य की राह: प्रदर्शनकारियों और सरकार दोनों ही फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे है। ऐसे में यह कहना कठिन है कि संघर्ष कब या कैसे समाप्त हो सकता है।

हांगकांग में विश्वविद्यालय के भीतर से पुलिस पर बरसे तीर

बढ़ा बवाल ▶ पांच विश्वविद्यालय परिसरों पर छात्रों का कब्जा

पुलिस ने प्रदर्शकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले और नीले रंग का तरल पदार्थ

हांगकांग, रायटर: एक दिन की शांति के बाद हांगकांग में रविवार को फिर हिंसा भड़क उठी। काऊलून प्रायद्वीप में अवरोधों से घिरे हांगकांग पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय से पुलिस पर तीरों और पेट्रोल बमों से हमला हुआ। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर बने मोर्चों की आड़ लेकर और भवन की छतों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने जवाब में आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और नीले रंग का तरल पदार्थ छोड़ा। करीब छह महीने के आंदोलन में पुलिस पर पहली बार तीरों से हमला हुआ है। आंदोलनकारियों ने इसकी तैयारी कई दिनों से कर रखी थी। हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर है, इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

नाथन रोड पर हुई टकराव की घटना में भी पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुछ और स्थानों पर पुलिस और आंदोलनकारियों की भिड़ंत की खबर है। पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय से शनिवार-रविवार की पूरी रात पुलिस पर हमले हुए। तीन के साथ ही गुलेल से फेंके गए पत्थरों के टुकड़े भी पुलिसकर्मियों को लगे। जवाब में पुलिस ने परिसर के भीतर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने कहा है कि दंगाई लगातार पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला कर रहे हैं। उनकी बनाई गुलेलों से पत्थर 40 मीटर की दूरी तक आकर गिर रहे हैं।

पुलिस ने कहा है कि विश्वविद्यालय परिसर से हो रहे ये हमले तनाव को बढ़ा रहे हैं। जबकि विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद सिविल इंजीनियरिंग के छात्र जोरिस (23) के अनुसार आंदोलनकारी आत्मरक्षा में तीर चला रहे हैं। छात्रों के खिलाफ पुलिस की हिंसा हद पार कर गई है। हम पुलिस को जवाब देना जारी रखेंगे, भले ही जेल जाना पड़े। हम सब हांगकांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। महानगर के पांच विश्वविद्यालयों के परिसरों को आंदोलनकारियों ने कब्जे में ले रखा है। साथ ही क्रॉस हार्बर टनल को भी बंद कर रखा है। यह इलाके में आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। रविवार को देर शाम भी टकराव जारी होने की खबर है। माना जा रहा है कि रात में यह टकराव और बढ़ेगा।

हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। रायटर

सड़कों पर उतर आई थी सेना : बता दें कि हांगकांग में हफ्ते भर से चल हिंसा के दौर से निपटने के लिए चीन ने बीते शनिवार को सेना सड़कों पर उतर गई थी। संगीनों के साए में टी शर्ट और हाफ पैंट पहने सैनिकों ने नागरिकों की मदद से रास्ता रोकने के लिए लगाए गए अवरोधकों को हटाया। यह कार्य सबसे पहले हांगकांग स्थित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अड्डे के नजदीक से शुरू हुआ था। हांगकांग में करीब छह महीने से चल रहे हिंसक आंदोलन में पहली बार चीन ने सेना को सड़कों पर उतारा। इससे पहले 1997 में हांगकांग के ब्रिटेन से चीन को हस्तांतरण के समय चीनी सेना सड़कों पर दिखाई दी थी। इसके बाद 2018 में आए तूफान में पीड़ितों की मदद के लिए सैनिक अड्डे से बाहर आए थे। शनिवार को इन सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक भी घरों से निकलकर सड़कों से अवरोधकों को हटाने के कार्य में लगे।

चीन समर्थकों ने निकाला था जुलूस : सेना सड़क पर उतरी तो हांगकांग में चीन समर्थकों ने भी सड़क पर आकर लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ जुलूस निकाला था। सामान्य दिनों में इनका आंदोलनकारियों से टकराव हो जाता था, लेकिन आंदोलनकारियों की गैरमौजूदगी में सरकार समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला।

राजपक्षे की नीतियों पर होगी भारत की नजर

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

▶ बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने चीन को श्रीलंका में जड़ें जमाने दी थी

श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे पर भारत की पैनी नजर रहेगी। आतंकी संगठन लिट्टे के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान वह रक्षा सचिव थे और उन पर निर्दोष तमिल आबादी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन के काफी आरोप लगे थे। इसके अलावा नेपाल के बाद श्रीलंका इस क्षेत्र का दूसरा देश है, जहां हुए चुनाव में किसी ऐसे व्यक्ति या पार्टी की जीत हुई है, जिसकी छवि भारत समर्थक की नहीं रही है। नेपाल में भारत विरोधी छवि वाले केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते सामान्य गति से ही आगे बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत पहले ही यह निर्णय कर चुका है कि वह पड़ोसी देशों में होने वाले चुनाव में पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगा और जो भी सरकार आएगी उसके साथ काम करेगा। अब वे दिन गए जब कोई देश किसी देश की राजनीति को बदल सकता था। आखिरकार भारत भी एक साथ रूस और अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान, इजरायल व फलस्तीन के साथ सामंजस्य बनाए हुए है। ऐसे में श्रीलंका में जो भी सरकार बनेगी, भारत उसके साथ द्विपक्षीय सहयोगात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा।

विदेश मंत्रालय के इस सकारात्मक नजरिये के बावजूद भारत राजपक्षे की भावी नीतियों पर करीबी नजर रखेगा। इसकी वजह यह है कि श्रीलंका की नीतियां सीधे तौर पर भारत की अंदरूनी राजनीति, सुरक्षा और बाह्य सामरिक हितों को प्रभावित करती हैं। कुछ महीने पहले ही हिंद महासागर के एक अन्य देश मालदीव से चीन के हितों का खुल कर समर्थन करने वाली सरकार के बाहर होने से भारत ने राहत की सांस ली थी। प्रसिद्ध रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक, श्रीलंका में चीन के एक बड़े समर्थक का चुनाव जीतना अमेरिका के नेतृत्व में 'एक मुक्त व खुला हिंद-प्रशांत क्षेत्र' बनाने की कोशिश को धक्का है। लेकिन भारत की चिंता सिर्फ बाहरी सामरिक हितों से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि घरेलू राजनीति से भी जुड़ी हुई है। राजपक्षे की छवि तमिल विरोधी की है। तमिल बहुल इलाके में उन्हें सिर्फ 15 फीसद वोट मिलने से साफ है कि इस अल्पसंख्यक समुदाय के मन में उनके लिए काफी संदेह है। राजपक्षे के चुनाव प्रचार में खुल कर बहुसंख्यक सिंहली आबादी के हितों की बात कही गई। पूर्व में भी जब महिंदा राजपक्षे की सरकार थी तो वहां तमिलों से जुड़े मुद्दे भारतीय राजनीति में भी असर दिखाते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में श्रीलंका में तमिलों की स्थिति एक प्रमुख मुद्दा होता है।

दो वजहों से राजपक्षे को लेकर भारत रहेगा सतर्क

1. अगर चीन का करेंगे समर्थन तो भारत के हित होंगे प्रभावित
2. तमिलों को लेकर उनकी नीति भारत की अंदरूनी राजनीति पर डालेगी असर

सिंहली बहुल इलाकों में एकतरफा जीत

प्रथम पृष्ठ से आगे

10 वर्षों तक श्रीलंका के रक्षा मंत्री रहे गोतबाया ने सिंहली बहुल देश के दक्षिणी इलाकों में एकतरफा जीत दर्ज की। लेकिन अल्पसंख्यक तमिल और मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तमिलों की बहुलता वाले उत्तरी प्रांत के सभी पांच जिलों जाफना, किलिनोच्ची, मुल्लातिवु, वावुनिया और मन्नार में गोतबाया को हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम बहुल पूर्वी प्रांत के तीन जिलों त्रिंकोमाली, बट्टीकलोआ और अंपारा में भी यही स्थिति रही। पूर्वी प्रांत में ही ईस्टर बम धमाकों के संदिग्धों का घर है। इस साल अप्रैल में हुए इन आत्मघाती विस्फोटों में 250 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

कोलंबो में अपने आवास पर श्रीलंका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर समर्थकों का अभिवादन करते गोतबाया राजपक्षे। एएफपी

गोतबाया राजपक्षे का भारत से पुराना नाता

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए पूर्व सैन्य अफसर गोतबाया राजपक्षे का भारत से पुराना नाता रहा है। उन्होंने 1980 में असम में उग्रवाद निरोधी अभ्यास में हिस्सा लिया था और 1983 में मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। बतौर रक्षा मंत्री वह 2012 और 2013 में भारत की यात्रा पर भी आए थे। गोतबाया का जन्म 20 जून, 1949 को मतारा जिले के पलटूवा में हुआ था। नौ भाई-बहनों में पांचवें नंबर के गोतबाया श्रीलंका के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता डीके राजपक्षे प्रतिष्ठित राजनेता होने के साथ ही श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। गोतबाया 1971 में बतौर कैडेट अफसर सीलोन आर्मी में शामिल हुए थे। 1991 में उन्हें सर जॉन कोटेवाला डिफेंस अकादमी का डिप्टी कमांडेंट नियुक्त किया गया। इस पद पर वह अपनी सेवानिवृत्ति (1992) तक रहे। बीस वर्षों की सैन्य सेवा के दौरान उन्हें श्रीलंका के तीन राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने, रणसिंघे प्रेमदासा और डीबी विजेतुंगा से वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए। सेना से रिटायर होने के बाद 1992 में गोतबाया ने कोलंबो विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी में परास्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह कोलंबो स्थित एक आइटी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हो गए। यहां कुछ दिन काम करने के बाद वह 1998 में अमेरिका चले गए और लॉस एंजिलिस के लोयोला लॉ स्कूल में काम करने लगे। 2005 में वह अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति चुनाव में मदद करने के लिहाज से श्रीलंका लौट आए। बड़े भाई के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद गोतबाया को नवंबर, 2005 में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने ही 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के खिलाफ चले सैन्य अभियान का सफल नेतृत्व किया था।

केंटुकी के बाद लुसियाना में भी जीते डेमोक्रेट प्रत्याशी

वाशिंगटन, एएफपी : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए अमेरिका के लुसियाना प्रांत के मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉन बेल एडवर्ड्स को एक बार फिर अपना गवर्नर चुना है। एडवर्ड्स को 51.3 प्रतिशत मत मिले हैं जबकि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी एडी रिस्पोंस को 48.7 प्रतिशत मत मिले हैं। एडी की हार तब हुई जब खुद ट्रंप तीन बार उनके लिए प्रचार के वास्ते गए। लुसियाना में रिपब्लिकन पार्टी की हार को ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले लुसियाना की यह हार ट्रंप के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को इस प्रांत से बढ़त मिली थी। जबकि केंटुकी में पिछले सप्ताह रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर मैट बेविन की हार हुई थी। कांटे की टक्कर में उन्हें डेमोक्रेट प्रत्याशी एंडी बेशेर ने हराया था। इससे ट्रंप के अपनी स्टार पावर के दावे को धक्का लगा है जिसके बल पर वह अमेरिका के हर चुनाव में जीत का दम भर रहे थे।

ट्रंप ने कराया सालाना मेडिकल चेकअप

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यहां वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में अपना सालाना मेडिकल चेकअप कराया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने बताया कि राष्ट्रपति स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। लेकिन ट्रंप के चेकअप और टेस्ट रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।

ट्रंप की इस अप्रत्याशित और अनिर्धारित मेडिकल सेंटर यात्रा के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की झड़ी लग गई। ग्रिशम ने कहा, साल 2020 के बेहद व्यस्त होने की संभावना के बीच राष्ट्रपति ने सप्ताहांत का लाभ वाल्टर रीड में सालाना स्वास्थ्य चेकअप के जरिए उठाया। इस दौरान राष्ट्रपति ने मेडिकल स्टाफ घायल सैनिकों की देखभाल के लिए धन्यवाद दिया।

एमक्यूएम नेता ने पीएम मोदी से मांगी शरण

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन में निर्वासित जीवन बिता रहे पाकिस्तानी नेता और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में शरण देने की मांग की है। एमक्यूएम नेता ने कहा कि पीएम मोदी मेरे साथियों सहित मुझे भारत में शरण दें, यदि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आर्थिक रूप से हमारी मदद करें।

जियो न्यूज के मुताबिक, ब्रिटेन के अभियोजन विभाग ने वर्ष 2016 में अपने पाकिस्तानी समर्थकों को ब्रिटेन से भड़काऊ भाषण देने के मामले में हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अगले साल जून में इस मामले की सुनवाई होगी। अब वकील इस बात का आकलन करने में जुटे हैं कि कहीं अल्ताफ ने प्रधानमंत्री मोदी से शरण की गुहार लगाकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया है। एमक्यूएम नेता ने कहा, यदि प्रधानमंत्री मोदी इजाजत देते हैं तो मैं अपने साथियों के साथ भारत आने के लिए तैयार हूं। मेरे दादा-दादी और हजारों रिश्तेदारों को भारत में ही दफनाया गया है।

एफएटीएफ कार्य योजना लागू करने में पाकिस्तान को मदद की पेशकश

इस्लामाबाद, प्रेट्र : आतंकवादियों के समर्थन के आरोपों और वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को यूरोपीय संघ (ईयू) ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की कार्य योजना लागू करने के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराने की पेशकश की है। पाकिस्तान ने एफएटीएफ कार्य योजना को लागू करने में ईयू की तकनीकी मदद की पेशकश का स्वागत किया है। पाकिस्तान अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक, ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ और पाकिस्तान के संयुक्त आयोग के 10वें सत्र के समापन के बाद जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में इस तरह की मदद की पेशकश की गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों ही पक्षों ने पाकिस्तान द्वारा एफएटीएफ की कार्य योजनाओं को लागू करने के महत्व पर जोर दिया।

बता दें कि वैश्विक आतंकी वित्तीय लेन-देन पर नजर रखने वाले एफएटीएफ ने पिछले महीने ही पाकिस्तान को 'ग्रे सूची यानी निगरानी सूची' में अगले साल फरवरी तक के लिए डाला है। दरअसल आतंकी गतिविधियों के लिए धनशोधन और धन मुहैया कराने के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं किए जाने पर एफएटीएफ ने यह कदम उठाया। गौरतलब है कि पाकिस्तान को पिछले साल जून में एफएटीएफ ने 'निगरानी सूची' में डाला था और इस संबंध में एक कार्य योजना भी सौंपी थी जिसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करना था। इस कार्य योजना को पूरा नहीं करने पर पाकिस्तान को 'काली सूची' में डाले जाने की संभावना थी, लेकिन उसे फरवरी तक का समय मिल गया।

इमरान खान। फाइल

उइगरों के खिलाफ चीन की बर्बरता का दस्तावेज लीक

हांगकांग : चीन में उईगर मुस्लिमों के खिलाफ सरकारी बर्बरता के बारे में अभी तक खबरें ही आ रही थीं। लेकिन पहली चीन के अत्याचार के दस्तावेज दुनिया के सामने आए हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स को हाथ लगे इस दस्तावेज ने चीन की कलई खोल कर रख दी है। इससे पता चलता है कि चीन ने दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए नजरबंदी शिविरों को प्रशिक्षण केंद्र का नाम दे रखा है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शिंजियांग की प्रांतीय सरकार को उईगर, कजाख और अन्य अल्पसंख्यकों को नजरबंदी शिविरों में रखने के लिए दिए गए निर्देश इसमें दर्ज हैं।

स्थानीय अधिकारियों को स्कूल की छुट्टी पर घरों को आने वाले छात्रों को चुप रखने के निर्देश दिए गए हैं। घरवालों और रिश्तेदारों के बारे में पूछने पर छात्रों को धमकाकर चुप रखने को कहा गया है। कहा गया है कि छात्र अगर दबाव बनाते हैं तो उन्हें बताया जाए कि उनके व्यवहार से उनके माता-पिता की हिरासत की अवधि बढ़ सकती है।

शिंजियांग प्रांत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से लगती है। अनुमान के मुताबिक यहां 10 लाख से ज्यादा उईगर मुस्लिमों को तीन साल से अधिक समय से नजरबंदी शिविरों में रखा गया है।

2009 से शुरू हुआ दमन का सिलसिला : शिंजियांग प्रांत की राजधानी उरूम्की में 2009 में एक साथ कई क्षेत्रों में नस्लीय दंगे भड़क गए थे। साथ ही सरकार और चीन विरोधी हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। उसके बाद ही चीन ने उईगर मुस्लिमों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई शुरू की थी। 2014 में यहां बाजार में हुए हमले में 39 लोग मारे गए थे।

लीक पेपर में शी के गुप्त भाषण भी शामिल : 403 पेज के लीक दस्तावेज में राष्ट्रपति शी चिनफिंग के अधिकारियों के सामने दिए गए गुप्त भाषण ही 200 पेज में दर्ज हैं। इसके अलावा 150 पेज में उईगर मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी निर्देश हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स से

10 लाख से ज्यादा उईगर मुस्लिमों को तीन साल से अधिक समय से नजरबंदी शिविरों में रखा गया है।

- चीन ने नजरबंदी शिविरों को प्रशिक्षण केंद्र का नाम दे रखा है
- छुट्टी में घर आने वाले उईगर मुस्लिम छात्रों पर भी रखी जाती है नजर

दाढ़ी रखने, अरबी पढ़ने पर रोक

शिंजियांग प्रांत में उईगर मुस्लिमों के लंबी दाढ़ी रखने और अरबी पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। मस्जिदों के बाहर वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। सिगरेट और शराब पीने पर भी पाबंदी है।

कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने दिए दस्तावेज

चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक सदस्य ने अखबार को ये पेपर मुहैया कराए हैं। तीन दशक में शायद यह पहली बार है कि इस तरह के दस्तावेज किसी अखबार को हाथ लगे हैं। अपना नाम गुप्त रखते हुए सदस्य ने उम्मीद जताई कि उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज के चलते चिनफिंग समेत कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेता बड़े पैमाने पर हिरासत के दोष से बच नहीं पाएंगे।

अन्य हिस्सों में भी इस्लाम पर पाबंदी की योजना

लीक दस्तावेज से पता चलता है कि चीन देश के अन्य हिस्सों में भी इस्लाम पर पाबंदी लगाने की योजना बना रहा है। लीक सामग्री से यह भी पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में असंतोष भी बढ़ रहा है।

अहम वार्ता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष से की मुलाकात, दोनों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर हुई खास चर्चा

भारत और अमेरिका की 'टू प्लस टू' की तैयारी जोरों पर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच होने वाली दूसरी टू प्लस टू वार्ता की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इस क्रम में बैंकॉक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उनके अमेरिकी समकक्ष एमटी एस्पर के साथ हुई मुलाकात काफी अहम रही। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच आगामी वार्ता में उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर खास तौर पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय और बाद में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं उससे साफ है कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम रणनीतिक गठबंधन पर काम चल रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वर्ष 2017 में हुई पहली मुलाकात में टू प्लस टू वार्ता की सहमति बनी थी। इसमें दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री शामिल होंते हैं। अभी तक इसकी सिर्फ एक बैठक हुई है। दूसरी बैठक अगले महीने के अंत तक होने वाली है। सितंबर, 2019 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा के दौरान इससे जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई थी।

माना जा रहा है कि आगामी बैठक में रक्षा व सुरक्षा साझेदारी से जुड़ी कुछ अहम घोषणाएं होंगी जो दोनों देशों की रणनीतिक सहयोग की दिशा तय करेंगी। पिछली बैठक में दोनों देशों ने कहा था कि वे रक्षा उपकरणों को भारत में बनाने और उनके निर्यात को लेकर खास उपाय करने वाले हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले एक वर्ष के दौरान इस बारे में जो वार्ताएं हुई हैं उससे जुड़ी घोषणा आगामी टू प्लस टू में होंगी।

बहरहाल, बैंकॉक में आसियान-प्लस के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर राजनाथ सिंह और एस्पर की बैठक से यह बात साफ हो गई है कि भारत व अमेरिका के बीच होने वाले रक्षा सहयोग का केंद्र मुख्य तौर पर हिद-प्रशांत क्षेत्र ही रहेगा। भारत ने कहा है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान भारत की रणनीति के केंद्र में है। जबकि अमेरिका ने कहा है कि इस क्षेत्र में भारत के साथ उसके सुरक्षा संबंधों के केंद्र में आसियान है। इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की अपार संभावनाओं का जिक्र दोनों नेताओं ने किया है।

बैंकाक में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को सम्मेलन से इतर अमेरिका के अपने समकक्ष मार्क एस्पर से मुलाकात की। एएफपी

राजनाथ सिंह की कई देशों के रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता

बैंकॉक, प्रेट्र : थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बातचीत में रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग और संबंधों को और मजबूती देने पर जोर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान और उसके आठ सहयोगी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने बैंकॉक गए हैं। यह बैठक सोमवार को होगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक जापान के रक्षा मंत्री टैरो कोनो, ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनोल्ड और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री रोन मार्क के साथ बैठकों में राजनाथ सिंह ने इन देशों के साथ भारत के संपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा की। साथ ही नए रक्षा क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा भी की। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री रायसीना संवाद में शामिल होने अगले साल भारत आ सकती हैं। 5बयान के मुताबिक जापान के विदेश मंत्री कोनो के साथ राजनाथ सिंह की यह पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच इस महीने के आखिर में नई दिल्ली में टू प्लस टू की बैठक भी निर्धारित है।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल। फाइल फोटो, प्रेट्र

शमी-मयंक ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग

आइसीसी टेस्ट रैंकिंग ▶ गेंदबाजों की सूची में सातवें स्थान पर पहुंचे शमी, विराट कोहली नंबर दो बल्लेबाज

बल्लेबाजों की सूची में अग्रवाल 11वें पायदान पर काबिज

दुबई, प्रेट्र : बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर में पहले टेस्ट में भारत की पारी और 130 रन की जीत में अहम योगदान देने के बाद तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी और सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने रविवार को जारी हुई ताजा आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया।

शमी ने पहले टेस्ट की पहली पारी पारी में 27 रन देकर तीन विकेट और दूसरी पारी में 31 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए थे। अपने इस प्रदर्शन की बदौलत उन्हें आठ स्थान का फायदा हुआ और वह सातवें पायदान पर पहुंच गए। अब उनके 790 रेटिंग अंक हो गए हैं जो किसी भारतीय तेज गेंदबाज के लिए टेस्ट में तीसरे सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक हैं। इस मामले में सिर्फ कपिल देव (877) और जसप्रीत बुमराह (832) ही उनसे आगे हैं।

भारतीय की एकमात्र पारी में 243 रन की दोहरी शतकीय पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच बनने वाले मयंक हालांकि 11वें पायदान पर हैं। 28 साल का यह बल्लेबाज करियर के शुरुआती आठ टेस्ट मैचों में 858 रन बनाने के बाद 691 रेटिंग अंकों पर पहुंच गया है। अपने शुरुआती आठ टेस्ट मैचों में मयंक से ज्यादा रन सिर्फ सात बल्लेबाजों ने बनाए थे, जिनमें डॉन ब्रैडमैन (1210), एवर्टन वीक्स (968), सुनील गावस्कर (938), मार्क टेलर (906), जॉर्ज हेडली (904), फ्रैंक वॉरेल (890) और हरबर्ट सटक्लिफ (872) शामिल हैं।

भारत के चार बल्लेबाज शीर्ष-10 में शामिल हैं, जिनमें कप्तान विराट कोहली दूसरे, चेतेश्वर पुजारा चौथे, अजिंक्य रहाणे पांचवें और रोहित शर्मा 10वें नंबर पर हैं। भारत के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को चार स्थान का फायदा हुआ और वह बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से 35वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और उमेश यादव एक-एक स्थान के फायदे के साथ क्रमश 20वें और 22वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी शीर्ष-10 गेंदबाजों की सूची में है, जबकि ऑलराउंडर की सूची में वह फिर से चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के लिए मुश्फिकुर रहीम ने 43 और 64 रन की पारियां खेलीं, जिसकी बदौलत वह पांच स्थान के फायदे के साथ 30वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि लिटन दास 92वें स्थान से 86वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

गेंदबाजों में तेज गेंदबाज अबू जाएद ने इंदौर में चार विकेट झटके, जिससे उन्हें 18 स्थान का फायदा हुआ और वह सिर्फ छह टेस्ट खेलने के बाद 62वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस बीच भारत ने आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। भारतीय टीम के नाम अब 300 अंक हैं, जबकि श्रीलंका और न्यूजीलैंड 60-60 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं।

शीर्ष पांच बल्लेबाज

बल्लेबाज	देश	अंक
स्टीव स्मिथ	ऑस्ट्रेलिया	937
विराट कोहली	भारत	912
केन विलियमसन	न्यूजीलैंड	878
चेतेश्वर पुजारा	भारत	790
अजिंक्य रहाणे	भारत	759

शीर्ष पांच गेंदबाज

गेंदबाज	देश	अंक
पैट कमिंस	ऑस्ट्रेलिया	908
कैगिसो रबादा	दक्षिण अफ्रीका	839
जेसन होल्डर	वेस्टइंडीज	814
जसप्रीत बुमराह	भारत	802
जेम्स एंडरसन	इंग्लैंड	798

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी। फाइल फोटो, प्रेट्र

आक्रामक बल्लेबाजी से मयंक ने पेश किया वनडे का दावा

नई दिल्ली, प्रेट्र : मयंक अग्रवाल की टेस्ट मैचों में आक्रामक बल्लेबाजी से उनके लिए सीमित ओवरों की टीम में चयन के दरवाजे खुल सकते हैं और यह सलामी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने होने वाली सीरीज के लिए टीम में जगह बना सकता है। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में अगर उप कप्तान रोहित शर्मा को अगले साल के शुरू में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे से पहले विश्राम दिया जाता है तो फिर अग्रवाल अच्छे विकल्प हो सकते हैं। रोहित पिछले कुछ समय से लगातार खेल रहे हैं। हालांकि उन्हें वेस्टइंडीज में खेले गए दो टेस्ट मैचों में मौका नहीं मिला था, लेकिन वह टीम में शामिल थे।

भारतीय उप कप्तान न्यूजीलैंड दौरे के लिए तीनों प्रारूपों में टीम का अहम हिस्सा होंगे। इस दौरे में भारत को पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों के मैचों में अग्रवाल एक विकल्प हो सकते हैं, जिन्होंने लिस्ट-ए में अब तक 50 से अधिक औसत और 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और 13 शतक ठोके हैं। शिखर धवन की लंबे समय से चली आ रही खराब फॉर्म तथा केएल राहुल के अलावा एक अन्य विकल्प तैयार रखने की जरूरत के चलते भी अग्रवाल के पक्ष में मामला बन सकता है। अग्रवाल को विश्व कप के दौरान आखिरी मैचों के लिए चोटिल विजय शंकर की जगह टीम में लिया गया था। उन्हें टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इससे यह संकेत मिले कि कर्नाटक का यह बल्लेबाज अपने आक्रामक खेल के कारण सीमित ओवरों की योजना में शामिल है।

जानकारों का मानना है कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अग्रवाल लंबी अवधि का विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे धवन तब टीम में न हों। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट विश्लेषक दीप दासगुप्ता को अग्रवाल को छोटे प्रारूप में आजमाने में कुछ गलत नजर नहीं आता और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज इसके लिए उचित मंच हो सकता है। दासगुप्ता ने कहा कि यह अच्छा होगा अगर भारतीय टीम प्रबंधन के दिमाग में सलामी बल्लेबाज के विकल्प के तौर पर मयंक का नाम है। वह सफेद गेंद के नैसर्गिक खिलाड़ी हैं।

डे-नाइट टेस्ट के लिए ईडन गार्डेंस की पिच तैयार

कोलकाता, आइएएनएस : भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डेंस मैदान पर 22 नवंबर से खेलेगी। यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच होगा, जो देश में पहली बार डे-नाइट प्रारूप में खेला जाएगा। ईडन गार्डेंस स्टेडियम के क्यूरेटर सुजान मुखर्जी का मानना है कि यह मैदान भारत और बांग्लादेश के बीच डे-नाइट टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है।

मुखर्जी को विश्वास है कि इस मैदान में दोनों टीमों के बीच एक अच्छा मैच होगा और दर्शकों को एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट देखने को मिलेगा। मुखर्जी ने कहा कि पिछले सप्ताह हुई बारिश ने कुछ हद तक इसे खराब किया था, लेकिन शुक्र है कि हमारे पास पर्याप्त समय था। अब चीजें (मौसम) सामान्य हैं। पिच अच्छी स्थिति में है। यह तैयार है और पिछले कुछ वर्षों से ऐसा ही है। ईडन गार्डेंस क्रिकेट की एक अच्छी पिच मुहैया कराएगा और मैं इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।

यह पूछे जाने पर कि आपने गुलाबी गेंद का मैदान पर परीक्षण किया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब तक ऐसा नहीं किया है। अगले कुछ दिनों में मैं इसे जरूर करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर पिच का व्यवहार वैसा ही होगा, जैसा कि अन्य टेस्ट मैचों में होता है।

कोहली, रोहित व तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने नहीं किया अभ्यास

इंदौर, प्रेट्र : कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा मुहम्मद शमी, इशांत शर्मा और उमेश यादव की तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने रविवार को यहां अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया, जबकि टीम के अन्य सदस्यों ने होलकर स्टेडियम में दूधिया रोशनी में अभ्यास किया। कोलकाता में पहले डे-नाइट टेस्ट की तैयारियों के लिए भारतीय टीम दूधिया रोशनी में अभ्यास कर रही है। तेज गेंदबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ यहां पहले टेस्ट में 14 विकेट चटकाए थे, जिसके बाद उन्हें ब्रेक दिया गया।

भारत और बांग्लादेश गुलाबी गेंद से अपना पहला टेस्ट कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डेंस में 22 से 26 नवंबर तक खेलेंगे। पहले टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने भी अभ्यास किया। चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने अभ्यास किया, जबकि रिषभ पंत, हनुमा विहारी, शुभमन गिल और कुलदीप यादव ने भी पसीना बहाया।

खिलाड़ियों के अभ्यास के दौरान मुख्य कोच रवि शास्त्री, बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर और क्षेत्ररक्षण कोच आर श्रीधर भी स्टेडियम में मौजूद रहे। पहला टेस्ट तीन दिन के भीतर ही जीतने के बाद भारत ने दो दिन यहीं दूधिया रोशनी में अभ्यास करने का फैसला किया, जिससे कि अंधेरा घिरने के समय गुलाबी गेंद से खेलने की चुनौती का अभ्यास किया जा सके। बांग्लादेश की टीम भी यहीं रुकी हुई है और दूधिया रोशनी में अभ्यास कर रही है। दोनों टीमें 19 नवंबर को कोलकाता के लिए रवाना होंगी और ईडन गार्डेंस में दो दिन अभ्यास करेंगी। इसके बाद 22 नवंबर से डे-नाइट टेस्ट खेला जाएगा।

गुलाबी गेंद से भारतीय तेज गेंदबाजों को मिलेगी मदद : अमीनुल

कोलकाता, प्रेट्र : बांग्लादेश के पूर्व कप्तान अमीनुल इस्लाम भारत के मौजूदा तेज गेंदबाजों से काफी प्रभावित हैं और उन्हें लगता है कि मेजबान टीम को शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले डे-नाइट टेस्ट में गुलाबी गेंद से फायदा होगा। बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाले अमीनुल ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की तुलना 1970 और 1980 के समय के वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से की।

अमीनुल ने कहा कि जिस तरह से हमने शमी, इशांत और उमेश की तेज गेंदबाजी में विविधता देखी है उससे उन्हें गुलाबी गेंद से काफी फायदा मिलेगा। आप जहां भी खेलते हैं, आपको शाम को वहां अतिरिक्त हवा का साथ मिलता है। भारत इसका भरपूर फायदा उठाएगा। बांग्लादेश के पदार्पण टेस्ट (साल 2000) में भारत के खिलाफ 145 रन की पारी खेलने वाले 51 साल के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि इससे पहले हमने अनिल कुंबले की अगुआई वाली भारत की स्पिन गेंदबाजी को देखा है लेकिन अब समय तेज गेंदबाजों का है। यह भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव है। उनके पास सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण है, यह वैसा ही है जैसे एक जमाने में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज पूरी दुनिया में हावी थे। उन्होंने कहा कि आम तौर पर दुनिया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का अनुसरण करती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम निरंतर रही है। वे प्रेरणास्रोत हो सकते हैं। उन्होंने शीर्ष स्तर पर इसे साबित किया है।

अमीनुल ने कहा कि ईडन गार्डेंस में खेल जाने वाला डे-नाइट मैच क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय सा होगा जब लगभग 70 हजार दर्शक भारत में पहली बार डे-नाइट का टेस्ट देखेंगे। दोनों टीमों को मेरी शुभकामनाएं। अमीनुल ने कहा कि दादा (गांगुली) ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं वहां आने की सोच रहा हूं। यह मेरे यहां के कार्यक्रम पर निर्भर करेगा।

डे-नाइट टेस्ट के शुभंकर 'पिंकू-टिंकू' का अनावरण

कोलकाता, प्रेट्र : भारत के पहले डे-नाइट टेस्ट की उलटी गिनती शुरू हो गई है और रविवार को यहां बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस मैच के आधिकारिक शुभंकर 'पिंकू-टिंकू' को अनावरण किया। गांगुली ने ईडन गार्डेंस पर मैच की टिकट और शुभंकर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। ईडन गार्डेंस पर इस मौके पर एक विशाल गुलाबी गुब्बारा भी उड़ाया गया जो भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक टेस्ट के अंत तक आसमान में लहराता दिखेता। शहर के महत्वपूर्ण स्थलों शहीद मीनार, सबसे ऊंची इमारत '42' और कोलकाता नगर निगम के कुछ पार्क भी गुलाबी लाइटों से जगमगाएंगे। हुगली नदी में जगमगाती गुलाबी गेंद वाली नाव को भी देखा गया। यह मैच के दिन 22 नवंबर तक प्रत्येक शाम ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु के बीच चलेगी। टाटा स्टील बिल्डिंग की 20 नवंबर से 'थ्री डी मैपिंग' की जाएगी, जबकि मिएजर्स क्लब पहले ही रात में गुलाबी रंग में जगमगा रहा है और अन्य कुछ इमारतों के भी ऐसा करने की उम्मीद है।

भारत के गैर अनुबंधित खिलाड़ियों को बीपीएल में लेना चाहता है बांग्लादेश

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) अपने नए सिरे से तैयार किए गए घरेलू टी-20 लीग के स्तर को बढ़ाने के लिए गैर अनुबंधित भारतीय खिलाड़ियों को भविष्य में इस टूर्नामेंट से जोड़ना चाहता है। मैच फिक्सिंग और कुछ विदेशी खिलाड़ियों के भुगतान में देरी से 2011 में शुरू किए गए बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) की छवि धूमिल हुई थी जिसके बाद देश के क्रिकेट बोर्ड ने इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे 'बंगबंधु बीपीएल' का नया नाम दिया।

बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन ने शनिवार की रात यहां पत्रकारों से कहा कि हमने उन भारतीय खिलाड़ियों को लाने का प्रस्ताव रखा है जो उनके बोर्ड (बीसीसीआइ) से अनुबंधित नहीं हैं। वे सैद्धांतिक तौर पर खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि हम इस बीपीएल में उन्हें ले पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा होगा। बीसीसीआइ अपने क्रिकेटरों को विदेशी टी-20 लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी सभी तरह की क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विदेशी लीग में खेले हैं जिनमें ग्लोबल टी-20 कनाडा भी शामिल है।

रसेल पर नकेल कसने से हारी नॉर्दर्न वारियर्स

विशाल श्रेष्ठ, अबू धाबी

टी-10 लीग

विस्फोटक पारियों के लिए मशहूर कैरेबियाई किंग आंद्रे रसेल पर टीम अबू धाबी के गेंदबाजों ने इस तरह नकेल कसी कि नॉर्दर्न वारियर्स को 24 घंटे के अंदर दूसरी हार का सामना करना पड़ा। रोहन मुस्तफा, रिचर्ड ग्लीसन, बेन लाफलिन और हैरी गर्ने की कसावट भरी गेंदबाजी के आगे रसेल धीमे पड़ गए और यही उनकी टीम को ले डूबा। रसेल गेंदबाजी में भी महंगे साबित हुए और दो ओवर के अपने कोटे में उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 27 रन लुटा दिए। रविवार को शेख जाएद स्टेडियम में गत बार की विजेता को टीम अबू धाबी ने छह विकेट से हरा दिया। इससे पहले शनिवार को कलंदर्स ने भी नॉर्दर्न वारियर्स को 66 रन से करारी मात दी थी। नॉर्दर्न वारियर्स उस मैच में महज 46 रन पर ढेर हो गई थी। टूर्नामेंट के पहले मैच में शानदार अर्धशतक से शुरुआत करने वाले रसेल उस मैच में सिर्फ एक रन बना पाए थे।

टीम अबू धाबी के खिलाफ नॉर्दर्न वारियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान डैरेन सैमी (17) के रूप में सिर्फ एक विकेट खोने के बावजूद नॉर्दर्न वारियर्स बोर्ड पर रन नहीं जुटा पाई। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार रसेल अंत तक क्रीज पर थे। रसेल ने 27 गेंद खेलकर 37 रन बनाए, जिसे टी-20 में भी धीमा स्ट्राइक रेट माना जाता है। रसेल की पारी में सिर्फ तीन चौके और एक छक्का शामिल रहा। टीम अबू धाबी के गेंदबाजों भले ज्यादा विकेट न ले सके, लेकिन उन्होंने विरोधी टीम के बल्लेबाजों पर लगाम कसे रखी। नौ विकेट हाथ में होने के बावजूद नॉर्दर्न वारियर्स 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई।

संयम का मोल जानते हैं युवा बल्लेबाज मयंक

वीवीएस लक्ष्मण
वेरी-वेरी स्पेशल

एक मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने मेहमान टीम पूरी तरह से नौसिखिया नजर आई। उनमें अनुभव की कमी थी और उनके विशेषज्ञों की पोल भी खुल गई।

भारत के तेज गेंदबाजों इशांत शर्मा, उमेश यादव और मुहम्मद शमी ने अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही रविचंद्रन अश्विन ने भी एक सामान्य सी पिच पर काफी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन सभी का ध्यान पहले टेस्ट में एक युवा ने खींचा, जो पिछले 11 महीनों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार अपनी छाप छोड़ रहा है। यह सोचते हुए भी अजीब लगता है कि सिर्फ दो वर्ष पहले मयंक अग्रवाल कर्नाटक की रणजी टीम में भी अपने स्थान को लेकर सुनिश्चित नहीं थे। लय से भटके मयंक भटक रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी मानसिकता, तकनीक में बदलाव किया। इसका नतीजा यह रहा कि उन्होंने एक महीने के अंदर ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक हजार से ज्यादा रन बना दिए।

नवंबर 2017 से अग्रवाल अपनी काबिलियत पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक, दक्षिण क्षेत्र और भारत-ए के लिए ढेरों रन बनाए। इससे उनके लिए भारतीय टीम में खेलने के दरवाजे खुल गए। उन्होंने पिछले दिसंबर जिस तरह की क्षमता बांग्लादेश की टीम ने टी-20 सीरीज में दिखाई, वह टेस्ट सीरीज में दूर तक भी नहीं थी। यही वजह है कि बांग्लादेशी टीम तीन दिन के अंदर ही पहला टेस्ट हार गई। टीम में स्थान बनाया और सलामी बल्लेबाज के तौर पर उभरते चले गए। अग्रवाल ना सिर्फ शतक, बल्कि शतक को दोहरे और दोहरे शतक को तिहरे शतक में बदलने की काबिलियत रखते हैं। जो भी उन्होंने अपने बुरे दिनों या घरेलू क्रिकेट में सीखा, वह उनके अब काम आ रहा है। पिछले चार टेस्ट में दो बार उन्होंने शतक को दोहरे शतक में तब्दील किया। टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए काफी लंबा इंतजार करने की वजह से वह जानते हैं कि संयम का क्या मोल है। यह उनकी बल्लेबाजी में भी साफ नजर आता है और वह एक अच्छे ढंग से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं।

एक फ्रंट फुट बल्लेबाज जो हमेशा कवर डाइव पसंद करता है, वह अब अपनी बल्लेबाजी के अन्य हिस्सों में भी सुधार कर रहा है। खास तौर से छोटी गेंद के खिलाफ। एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर उनका स्पिन पर संतुलन कमाल का है। उनका फुटवर्क सकारात्मक है। वह ना सिर्फ कदम निकालकर चौका लगाते हैं, बल्कि क्रीज में घुसकर दोनों ओर स्क्वॉयर में भी खेलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन, उनकी परिपक्वता का नमूना यही है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वह घरेलू स्तर के तौर पर ही अपने रनों की गति बढ़ाए हैं।

मैं दूसरे टेस्ट का इंतजार नहीं कर सकता, जब भारतीय टीम पहले डे-नाइट टेस्ट में खेलकर इतिहास रचेगी और एक अंजान रास्ते का सफर रोमांचक होगा। तो क्यों नहीं कुछ अलग होना चाहिए?

नजरिया

पूर्व पाकिस्तानी लेग स्पिनर ने कहा कि दोनों मुल्कों के लिए जरूरी है कि वे एक-दूसरे के साथ खेलें

अब भारत-पाक सीरीज का भी खुले रास्ता : मुश्ताक अहमद

विशाल श्रेष्ठ, अबू धाबी

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद चाहते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर की तरह भारत-पाक द्विपक्षीय क्रिकेट का भी रास्ता खुले। टी-10 लीग में डेक्कन ग्लैडिएटर्स के कोच मुश्ताक ने खास बातचीत में कहा, 'जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर खुल गया है, उसी तरह भारत-पाक के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट भी बहाल होना चाहिए। इसमें दोनों मुल्कों का फायदा है। करतारपुर कॉरिडोर खुलना दोनों तरफ की सरकारों के लिए बहुत अच्छा और सकारात्मक संकेत है। इस तरह की पहल से चीजें खुलेंगी।'

मुश्ताक मानते हैं कि भारत-पाक के रिश्तों को सामान्य करने में क्रिकेट बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा, 'ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते और सरकारें सख्त रवैया अपनाती हैं तो क्रिकेट ही उन्हें इकट्ठा करती है। यह खेल प्यार और खुशी लेकर आता है, इसलिए दोनों मुल्कों के लिए जरूरी है कि वे एक-दूसरे के साथ खेलें। भारत-पाक के मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धी होते हैं। ये एशेज से भी बढ़कर होते हैं। दोनों मुल्कों के लोग भी अपने नायकों को खेलते देखना चाहते हैं। जब हम आपस में क्रिकेट खेलेंगे तो चीजें आसान होने लगेंगी। दोनों देशों के राजनेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी स्थिति सहज करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही इस बारे में बातचीत करने के लिए फोन भी किया था। टेबल पर बैठकर तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। जो भी मसले हैं, वे बातचीत से हल किए जाने चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी दूर होगी। इसके साथ ही दुनिया का यह हिस्सा भी मजबूत होगा, जिसमें ये दोनों देश स्थित हैं।'

विराट की बल्लेबाजी कविता जैसी : 49 साल के मुश्ताक ने कहा कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की बल्लेबाजी कविता जैसी है, जिसे देखने में काफी मजा आता है। विराट के आंकड़े उनके लिए बोलते हैं। विराट और पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम की हो रही तुलना पर मुश्ताक के कहा कि दोनों जबरदस्त खिलाड़ी हैं और इस समय दुनिया के सर्वोत्तम बल्लेबाजों में शुमार हैं। वे युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। टेस्ट में 185 और वनडे में 161 विकेट लेने वाले मुश्ताक ने भारत-पाक क्रिकेट की परस्पर तुलना पर कहा कि भारतीय क्रिकेट स्थापित हो गया है, जबकि पाक क्रिकेट नए दौर की तरफ बढ़ रहा है। पाक क्रिकेट बोर्ड के प्रबंधन में बदलाव किया गया है। पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक को मुख्य चयनकर्ता और पाक टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। चीजें बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। पाकिस्तान के पास प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की कमी नहीं है, बस उन्हें स्थापित होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।

वेस्टइंडीज टीम की स्पिन गेंदबाजी के कोच मुश्ताक मानते हैं कि स्पिनरों को नई गेंदें विकसित करते रहना चाहिए, वरना उनका एक समय श्रीलंका के रहस्यमय गेंदबाज रहे अजंता मेंडिस जैसा हाल हो सकता है। मुश्ताक ने कहा, 'शुरू में अजंता को उनकी अबूझ गेंदबाजी के कारण काफी विकेट मिले, लेकिन जैसे ही बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी की शैली को भांप लिया, उनका बुरा हाल हो गया, इसलिए स्पिनरों को नई-नई गेंदें विकसित करती रहनी चाहिए।'

सचिन को दी बधाई

सचिन तेंदुलकर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 30 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई देते हुए मुश्ताक ने कहा, 'सचिन सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इंसान के तौर पर भी रोल मॉडल हैं। उन्होंने इस खेल को काफी साफ-सुथरे तरीके से खेला है और अपने देश की बहुत सेवा की है।'

पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुश्ताक अहमद। फाइल फोटो, प्रेट्र

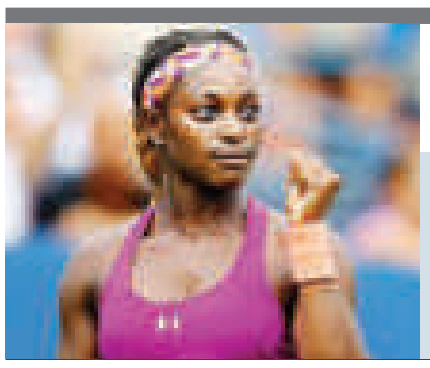

भारतीय तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं।
– डेल स्टेन, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज

ओलंपिक पर अमेरिका की स्टीफंस की निगाहें

मार्लिना डेल रे (कैलिफ), रायटर : अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी स्लोने स्टीफंस ने कहा है कि वह 2019 के अपने निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़कर अपना ध्यान रैंकिंग में सुधार के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने पर है। 2017 की यूएस ओपन चैंपियन स्टीफंस 2018 में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंची थीं, लेकिन इस साल उनका प्रदर्शन खराब रहा और वह 25वें स्थान पर लुढ़क गईं।

नीदरलैंड्स और जर्मनी ने किया क्वालीफाई

यूरो 2020 नीदरलैंड्स ने नॉर्दन आयरलैंड को गोलरहित ड्रॉ पर रोककर हासिल की पात्रता

जर्मनी ने बेलारूस को 4-0 से हराकर हासिल किया यूरो का टिकट

पेरिस, एएफपी : नीदरलैंड्स, जर्मनी और क्रोएशिया जैसी दिग्गज फुटबॉल टीमों ने शनिवार को यूरो 2020 के लिए क्वालीफाई कर लिया। साथ ही ऑस्ट्रिया ने भी अगले साल 12 जून से रोम में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया। 24 टीमों के इस टूर्नामेंट में अब तक 16 टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं। ऐसे में मुख्य क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के जरिये सीधे यूरो 2020 का टिकट हासिल करने के लिए अब केवल चार स्थान खाली रह गए हैं।

ग्रुप-सी से क्वालीफाई करने के लिए नीदरलैंड्स की टीम को एक अंक की जरूरत थी और उसने बेलफास्ट में नॉर्दन आयरलैंड को गोलरहित (0-0) ड्रॉ पर रोककर क्वालीफाई कर लिया। इस मुकाबले में नॉर्दन आयरलैंड के स्टीवन डेविस पेनाल्टी किक को गोल के ऊपर से मार बैठे, जिसने नीदरलैंड्स के लिए क्वालीफाई करने का रास्ता आसान कर दिया। 2014 विश्व कप में तीसरे स्थान के बाद नीदरलैंड्स की टीम पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही है। इसी ग्रुप में जर्मनी ने टोनी क्रूस (55वें व 83वें मिनट) के दो गोल की मदद से बेलारूस को 4-0 से हराकर लगातार 13वीं बार यूरो चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। जर्मन टीम के लिए मैथियास जिंटेर (41वें मिनट) और लियोन गोरेज्का (49वें मिनट) ने भी स्कोर किए। इस दौरान जर्मन कप्तान मैनुअल नॉयर ने एक शानदार बचाव भी किया। ग्रुप-सी में जर्मनी सात मुकाबलों में 18 अंक के साथ शीर्ष पर है।

क्रोएशिया को मिला टिकट : पिछले फीफा विश्व कप की उप विजेता क्रोएशिया की टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्लोवाकिया को 3-1 से हराकर ग्रुप-ई से यूरो चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। स्लोवाकिया के रॉबर्ट बोजेनिक ने 32वें मिनट में गोल करके क्रोएशिया को चौंका दिया, लेकिन दूसरे हाफ में निकोला ब्लासिक (56वें मिनट), ब्रूनो पेत्कोविक (60वें मिनट) और इवान पेरेसिक (74वें मिनट) ने गोल करके क्रोएशिया को शानदार जीत दिलाई। इसी ग्रुप में वेल्स ने अजरबैजान को 2-0 से हराकर अपनी उम्मीदें कायम रखीं। उधर, ग्रुप-जी में नॉर्थ मेसोडोनिया को 2-1 से हराकर ऑस्ट्रिया ने भी यूरो 2020 के लिए क्वालीफाई कर लिया।

हैजार्ड बंधु चमके : ग्रुप-आइ में बेल्जियम ने अपने 100 फीसद जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए रूस को 4-1 से हरा दिया, जहां विजेता टीम की ओर से हैजार्ड बंधुओं ने चमक बिखेरी। पहले ही यूरो कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी बेल्जियम की ओर से ईडन हैजार्ड (33वें व 40वें मिनट) ने दो गोल किए, जबकि उनके भाई थॉर्गन हैजार्ड (19वें मिनट) और लुकाकू (72वें मिनट) ने भी स्कोर किए।

नीदरलैंड्स के क्वालीफाई करने की खुशी में जश्न मनाते विर्गिल वॉन डिज्क। रायटर

रोनाल्डो को नहीं मिलना चाहिए बैलन डि ओर : कैसियास

मैड्रिड, आइएएनएस : स्पेन और रीयल मैड्रिड के पूर्व दिग्गज गोलकीपर आइकर कैसियास का मानना है कि इस साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बैलन डि ओर देना गलत फैसला होगा। कैसियास ने कहा कि विर्गिल वान डिज्क को यूएफा ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना, लियोन मेसी को फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ऐसे में अब अगर रोनाल्डो बैलन डि ओर जीतते हैं तो मुझे लगेगा कि फुटबॉल में हम जिस पैमाने से पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन करते हैं, वह तर्कसंगत नहीं है।

नेगी ने 14 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

मुंबई, प्रेट्र : मेघालय के ऑलराउंडर अभय नेगी ने रविवार को मिजोरम के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने 14 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। यह इस घरेलू टी-20 टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोबिन उथप्पा के नाम था, जिन्होंने 15 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

मुंबई में खेले गए इस मैच में मिजोरम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मेघालय के लिए रवि तेजा ने 31 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने पांच चौके और दो छक्के लगाए। नेगी छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अर्धशतक पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार चार छक्के लगाए। नेगी ने नाबाद 50 रन बनाए। उन्होंने दो चौके भी जड़े।

उनकी पारी की मदद से मेघालय की टीम ने 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए। इसके जवाब में मिजोरम की टीम ने दो विकेट पर 182 रन का स्कोर ही खड़ा किया। तरुवर कोहली ने 59 गेंदों पर 90 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और चार छक्के लगाए। वहीं, केबी पवन ने 46 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने छह चौके और तीन छक्के लगाए। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह के नाम है। युवराज ने पहले टी-20 विश्व कप में 12 गेंदों पर 50 रन पूरे किए थे।

टी-20 टूर्नामेंट

दिल्ली ने सिक्किम को हराया

सूरत, प्रेट्र : कर्ण डागर के चार विकेटों के बाद हितेन दलाल के अर्धशतक के दम पर दिल्ली ने रविवार को यहां सीबी पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-ई मैच में सिक्किम को नौ विकेट से हरा दिया। सिक्किम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 88 रन का स्कोर बनाया। दिल्ली ने नौ ओवर में एक विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।

दिल्ली के लिए हितेन ने 24 गेंदों पर छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 54 रनों की पारी खेली। उनके अलावा शिखर धवन ने 19 और अनुज रावत ने नाबाद 14 रन बनाए। सिक्किम की ओर से यशपाल सिंह को एकमात्र विकेट मिला। इससे पहले दिल्ली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिक्किम को सात विकेट पर 88 रनों पर दिया। सिक्किम की ओर से कप्तान इकबाल अब्दुल्ला ने 45 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 37 रन की सर्वाधिक पारी खेली। उनके अलावा आशीष थापा ने 17, पदम लिंबो ने नाबाद 16 और ईश्वर चौधरी ने नाबाद 13 रन बनाए।

पैटिंसन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया निलंबित

ब्रिसबेन, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने रविवार को निलंबित कर दिया, जिसके कारण वह यहां गाबा में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। विक्टोरिया के लिए खेल रहे पैटिंसन को क्वींसलैंड के खिलाफ शैफील्ड शील्ड के मैच में सीए की आचार संहिता के दूसरे स्तर का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। पिछले 18 महीनों में उन्होंने तीसरी बार आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके कारण उन पर एक मैच का प्रतिबंध लगा। सीए ने कहा कि पैटिंसन ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है। पैटिंसन ने कहा कि मैंने भावनाओं में बहकर गलती कर दी। मुझे समझ आ गया कि मैं गलत हूं और मैंने विपक्षी टीम एवं अंपायर से माफी मांग ली। मैंने गलती की और उसका खामियाजा भुगतने को तैयार हूं।

ज्वेरेव को हराकर फाइनल में पहुंचे थिएम

लंदन, एएफपी : ऑस्ट्रिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थिएम ने मौजूदा चैंपियन एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर एटीपी फाइनल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उनका सामना रोजर फेडरर को हराने वाले स्टेफानोस सितसिपास से होगा।

पांचवीं वरीय थिएम ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में जर्मनी के लंबे कद के खिलाड़ी ज्वेरेव को 7-5, 6-3 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। इससे पहले यूनान के सितसिपास ने फेडरर को 6-3, 6-4 से पराजित किया था। सितसिपास पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। वहीं, थिएम चौथी बार एटीपी फाइनल्स खेल रहे हैं, लेकिन पिछले तीन अवसरों पर वह केवल तीन मैच जीत पाए थे और ग्रुप दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। सेमीफाइनल में थिएम ने पहले सेट के 12वें गेम में ज्वेरेव की सर्विस तोड़ी और फिर दूसरे सेट के छठे गेम में भी उन्होंने जर्मन खिलाड़ी की सर्विस तोड़ी। वहीं, इस दौरान ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी ने अपने सभी चारों ब्रेक प्वाइंट बचाए। जीत के बाद थिएम ने कहा कि यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना सच होने जैसा है। यह टूर्नामेंट साल के सबसे बड़े और खास टूर्नामेंट में से एक है। मुझे फाइनल में खेलना का मौका मिला है।

दूसरी तरफ फेडरर से 17 वर्ष छोटे सितसिपास ने इस 38 वर्षीय दिग्गज की सातवीं बार चैंपियन बनने की उम्मीदों पर पानी फेरा। फेडरर को हराने के बाद सितसिपास ने कहा कि मुझे खुद पर बेहद नाज है। मैंने शानदार खेल दिखाया। मैंने कोर्ट में अपने खेल का आनंद उठाया।

जीत दर्ज करने के बाद जश्न मनाते डोमिनिक थिएम। एपी

मेरा ध्यान सिर्फ रन बनाने पर : शॉ

मुंबई, प्रेट्र : निलंबन की सजा पूरी कर सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में शानदार पारी के साथ वापसी करने वाले मुंबई के युवा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान बल्लेबाजी पर है जिससे कि वह भारतीय टीम में वापसी कर सके। डोपिंग परीक्षण में नाकाम रहने के बाद बीसीसीआइ ने जुलाई में शॉ पर आठ महीने का प्रतिबंध लगाया था जो 16 मार्च 2019 से 15 नवंबर 2019 तक प्रभावी रहा। वापसी के बाद पहले मुकाबाले में 39 गेंद में 63 रन बनाने वाले शॉ ने कहा कि अब मेरा पूरा ध्यान अधिक से रन बनाने और टीम के लिए मैच जीतने पर रहेगा।

शॉ ने आदित्य तारे (48 गेंद में 82 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 13.4 ओवर में 138 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी जिससे मुंबई ने असम को 83 रन से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम में वापसी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान सिर्फ रन बनाने पर रहेगा। इस बारे में सोचना चयनकर्ताओं का काम है। मेरा काम रन बनाना और टीम को जीत दिलाना है। पदार्पण टेस्ट में शतकीय पारी खेलने वाले शॉ के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा शानदार लय में हैं। निलंबन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जाहिर है मैं निराश था। प्रतिबंध के पहले 20-25 दिन मैं काफी परेशान था, मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हुआ। मेरे अभ्यास करने पर 15 सितंबर तक रोक लगी थी, इसलिए मैं लंदन गया और खुद को मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में उनकी काफी मदद की। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। प्रतिबंध के कारण कुछ नहीं कर सकता था। वहां मैंने कई फिटनेस टेस्ट दिए।

विविध

तृणमूल के अत्याचार के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, कोलकाता : भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पर झूठे मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश करने का फिर आरोप लगाया है। वह शनिवार को जगदल विधानसभा क्षेत्र में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने बैरकपुर पुलिस आयुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सिंह ने आरोप लगाया कि इस बैठक के बाद ही तृणमूल के समर्थकों को उनकी खाली जमीन पर हथियार छिपाने का निर्देश दिया गया था ताकि उस बहाने से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके, लेकिन यह साजिश विफल हो गई।

सांसद अर्जुन सिंह के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस, भाजपाइयों ने किया घोला थाने का घेराव

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें झूठे मामले में इसलिए फंसाना चाहती है कि उनका काम आसान हो जाएगा। इस तरह की साजिश रचने के आरोप में भाजपा सांसद ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में वह राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश को लिखित शिकायत करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा अत्याचार किए जाने के आरोप में सोदपुर इलाके में विरोध जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व सांसद अर्जुन सिंह ने किया। उनके नेतृत्व में घोला थाने का घेराव भी किया गया।

जुलूस के दौरान सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर तृणमूल द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर उल्टा पीड़ित भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा तृणमूल की मुहर की तरह काम कर रहे हैं। भाटपाड़ा में शाम को भाजपा ने गणतंत्र बचाओ रैली निकाली। इसका नेतृत्व सांसद अर्जुन सिंह, भाटापाड़ा के विधायक पवन सिंह व भाटपाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन सौरभ सिंह ने किया। यह रैली एंग्लो जूट मिल के समीप से शुरू हुई जो विभिन्न इलाकों से होते हुए कोल डिपो मोड पर संपन्न हुई।

सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। ममता बनर्जी एनआरसी का विरोध कर रही हैं और रोहिंग्या शरणार्थियों को राज्य में जगह दे रही हैं। इसके खिलाफ यह रैली निकाली गई।

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 32 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

प्रवासी भारतीयों को धमकी देकर ठगी करने वाले गिरोह का पश्चिमी जिला पुलिस की साइबर सेल ने पर्दाफाश किया है। मोती नगर में गैरकानूनी तरीके से संचालित हो रहे कॉल सेंटर के माध्यम से कनाडा में कारोबार करने वाले नागरिकों को शिकार बनाते थे। पुलिस ने यहां से 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अब तक 500 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई कनाडा के नागरिक एल्विस हेनरी की शिकायत पर की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के अलावा दूरसंचार विभाग भी इस मामले की तहकीकात कर रहा है। पुलिस फरार कॉल सेंटर संचालक की तलाश कर रही है।

पश्चिमी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त समीर शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में अवैध कॉल सेंटर से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। यह कॉल सेंटर कनाडा के नागरिकों के अलावा प्रवासी भारतीयों को निशाने पर ले रहा है। कॉल सेंटर के काम करने का तरीका बेहद शातिर था। ये लोग अंतरराष्ट्रीय कॉल के लिए अवैध तकनीक का प्रयोग करते थे। इससे दूरसंचार कंपनियों को नुकसान पहुंचाते थे। पुलिस ने दूरसंचार विभाग को जानकारी दी और साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू की। शनिवार रात पुलिस और दूरसंचार विभाग की टीम ने डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र मोती नगर स्थित कॉल सेंटर में छापा मारा। उस समय कॉल सेंटर में तीन फ्लोर मैनेजर सहित 32 लोग काम कर रहे थे। पुलिस ने लोगों से दस्तावेज मांगे और पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि यह फर्जी कॉल सेंटर है। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वे कनाडा पुलिस अधिकारी बनकर वहां के लोगों को फोन करते थे। वे कनाडा मूल के लोगों से कहते थे कि उनका सिन नंबर (कनाडा में कामकाज करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया नौ अंकों का नंबर) आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इस कारण सरकार आपके बैंक खाते में जमा पैसे को जब्त कर सकती है। आरोपित खुद को कनाडा पुलिस का अधिकारी बताते थे और पीड़ितों को जांच का सामना करने की बात कहकर डराते थे। डराने के बाद आरोपित समझौता करने की बात कहकर पीड़ितों को अपने फोन पर कॉल करने को कहते थे। पीड़ित जब आरोपितों को फोन करता था तो वह उन्हें समझौता करने की बात कह उनके खाते में जमा पैसा बिटकॉइन या वॉलेट एप से ले लेते थे।

कर्मियों से कनाडा सरकार के लिए काम करने की कही जाती थी बात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मोतीनगर में फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। शिकार को इन पर शक न हो, इसके लिए ये कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देते थे। इन्हें कनाडा की बोलचाल वाली अंग्रेजी का उच्चारण करना सिखाया जाता था। कॉल सेंटर में नौकरी देने से पहले ये साक्षात्कार भी लेते थे। इस दौरान उन्हें बताया जाता था कि वे कनाडा सरकार की जांच एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप वहां के नागरिकों को फोन करेंगे तो अपनी पहचान कनाडा पुलिस के अधिकारी के तौर पर ही देंगे। कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन मिलता था। किसी को 80 हजार तो किसी को 15 हजार दिया जाता था। जांच में सामने आया है कि कॉल सेंटर में रात के समय ही कॉलिंग की जाती थी। दिन में रात भर चले काम का डाटा तैयार किया जाता था। इसमें ठगी के पैसे की रकम को जोड़ना भी शामिल है।

मामले की जांच कर रहे एसीपी ऑपरेशन उमाशंकर, इंस्पेक्टर अरुण कुमार, एसआइ अमित वर्मा, हेड कांस्टेबल विवेक कुमार की टीम ने आरोपितों से अलग-अलग पूछताछ शुरू की। इसमें सामने आया कि ज्यादा लोग करीब तीन माह पहले नौकरी पर रखे गए हैं। फरार आरोपित राजा, पंकज, सुशील, नवीन और दिव्यम अरोड़ा ने तीन माह पहले कॉल सेंटर शुरू किया था। जिस जगह पर कॉल सेंटर चल रहा था, वह पांच महीने पहले किराये पर ली गई थी। इसके लिए एक फर्जी कंपनी भी बनाई। इस कंपनी की आड़ में ये पांचों दोस्त विदेशियों से ठगी करते थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने अपना प्रोग्राम तैयार कर लिया था, जिसकी मदद से वे दिल्ली में बैठकर लोगों को फोन करते थे और फोन उठाने वाले के मोबाइल पर कनाडा का फोन नंबर दिखाई देता था।

आरोपितों के पास से पुलिस ने 55 कंप्यूटर, 35 मोबाइल, दो इंटरनेट राउटर और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपितों ने कई वॉलेट एप चुने हुए थे। इन्हें वे पीड़ितों से कनाडा सरकार का अधिकारिक वॉलेट एप बताते थे। ये सभी एप गैर कानूनी हैं। आरोपित इन वॉलेट में ही लोगों से पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहते थे। पुलिस इन सभी एप की जानकारी एकत्रित कर रही है।

पंजाब सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश, लगाया जाम

संगरूर के गांव चंगालीवाला में जगमेल सिंह के स्वजनों से मुलाकात करते कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका और पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्ठल। जागरण

जेएनएन, लहरागागा (संगरूर)

दबंगों के अत्याचार से अनुसूचित जाति के युवक जगमेल की मौत का मामला

पंजाब के संगरूर के गांव चंगालीवाला के अनुसूचित जाति के युवक जगमेल सिंह की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर लोगों ने रविवार को लहरा-सुनाम मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया।

रविवार को विधानसभा में नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा व सुनाम से आप विधायक अमन अरोड़ा गांव चंगालीवाला में पीड़ित परिवार से मिले तथा धरने में भी पहुंचे। चीमा ने कहा कि कैप्टन सरकार में जंगलराज है। इसमें पुलिस की नाकामी साफ झलक रही है। गांव में जगमेल सिंह के स्वजनों से कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका और पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्ठल ने भी मुलाकात की। वहीं आक्रोशित लोगों ने कहा कि इस घटना ने अबोहर के भीम टांक हत्याकांड की याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा दे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करे। प्रदर्शनकारियों ने विशेष अदालत गठित कर दोषियों को फांसी देने की भी मांग की।

नायब तहसीलदार हमीर सिंह ने बताया कि एससीएसटी एक्ट के तहत परिवार को 8.25 लाख रुपये मुआवजा व पांच हजार रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। अब तक परिवार ने मुआवजा लेने के लिए कोई अकाउंट नंबर नहीं दिया है। अकाउंट नंबर मिलते ही पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस पर स्वजनों ने कहा कि आठ लाख रुपये देने का प्रावधान तो एससीएसटी एक्ट में है, सरकार क्या कर रही है। दूसरी ओर जगमेल सिंह का रविवार को पीजीआइ में दूसरे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया।

बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा ही नहीं, बार्डर पर भी बरती सख्ती

अनिल बेताब, फरीदाबाद

मां की कोख में भी म्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाती हैं, मगर म्हारी बेटियों को बचाने को लेकर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है। केंद्र के प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीएनडीटी एक्ट) के उल्लंघन के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की टीम दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर नकेल कस रही है।

चार वर्ष में हरियाणा की टीम ने पड़ोसी राज्यों में भ्रूण लिंग जांच के 60 मामलों में कार्रवाई की

हरियाणा में अपने-अपने जिलों में भ्रूण लिंग जांच मामले में सख्ती बरतने के बाद प्रदेश की बेटा-बेटी जन्म दर अनुपात की स्थिति में सुधार आया है। मौजूदा लिंगानुपात 919 है, जबकि चार-पांच वर्ष पहले की बात करें तो यहां लिंगानुपात की स्थिति लगभग 860 थी। अपना घर सुधारने के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने दिल्ली-हरियाणा सीमा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सीमा से सटे शहरों में सख्ती बरतनी शुरू की है। पिछले करीब चार वर्षों के रिकॉर्ड की बात करें तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग जिलों की टीमों ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में जाकर भ्रूण लिंग जांच के 60 मामलों में कार्रवाई की है।

सियासी संरक्षण व बिचौलियों की दखल से पड़ोसी राज्यों में खेल

हरियाणा में सख्ती के चलते दूसरे राज्यों में बिचौलियों की दखल से भ्रूण लिंग जांच का खेल चलता है। अब तक सामने आए मामलों से इस बात की पुष्टि होती है कि राजनीतिक संरक्षण से कई जगह खेल चल रहा है। अलीगढ़ के एक अस्पताल में छापेमारी के यह बात सामने आ चुकी है।

छापेमारी के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों को स्थानीय नेता खड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, अब दो दिन पूर्व बुलंदशहर के गांव दिनोल में जो भ्रूण लिंग जांच गिरोह पकड़ में आया है, इनमें आशा वर्कर की दखल भी सामने आई है। इससे पहले फरवरी 2017 में अलवर में भ्रूण लिंग जांच मामले में एक नर्स को पकड़ा गया था।

जिले के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पीएनडीटी) डॉ. गजराज सिंह कहते हैं कि हरियाणा में पीएनडीटी एक्ट के मामले में बहुत सख्ती है। ऐसे में उनके पास जब यूपी या दिल्ली के किसी शहर में भ्रूण लिंग जांच की शिकायत आती है, तो वहां की टीम के साथ मिलकर छापेमारी की जाती है।

बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने की जरूरत : सतपाल महाराज

जासं, नई दिल्ली : रामलीला मैदान में मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से हंस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सद्भावना सम्मेलन के समापन पर अध्यात्म गुरु सतपाल महाराज ने कहा कि हमें बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार विकसित करने की जरूरत है तभी हम एक स्वस्थ, सुखी व समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को साकार कर सकते हैं।

अध्यात्म गुरु ने लोगों से भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने के साथ ही पुनीत कार्य में सहयोग देने की अपील की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य सड़क एवं परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय उपस्थित थे। मनोज तिवारी ने कहा कि भारत ऋषि-मुनियों का देश रहा है और महाराज जी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी के सद्भावना और राष्ट्रहित में किए जा रहे प्रयास हम सब के लिए अनुकरणीय हैं।

मौसम विशेष

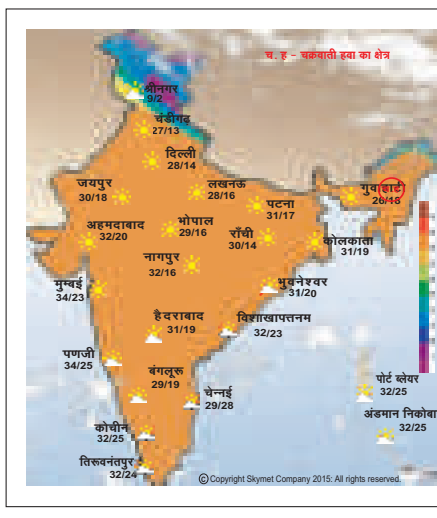

जम्मू-कश्मीर में बदलीयुक्त आसमान के साथ एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा तथा बर्फबारी संभव है। दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होगी। दिल्ली सहित कई भागों में मौसम शुष्क रहेगा। दिन में मध्यम गति की हवाओं के कारण प्रदूषण में सुधार होगा। सुबह व दिन आरामदायक रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/23/व	अहमदाबाद	31/20/आंबा
कोलकाता	30/19/सा	बड़ौदा	32/19/सा
चेन्नई	30/24/व	नागपुर	32/15/व
हैदराबाद	31/19/सा	इन्दौर	29/19/आंबा
बंगलूरू	29/19/आंबा	राँची	28/17/व
त्रिवेन्द्रम	32/24/व	पटना	28/18/आंबा
गुवाहाटी	26/18/सा	जमशेदपुर	27/17/आंबा
गंगटोक	11/00/व	पुणे	29/19/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
सोमवार 18 नवंबर 2019
www.jagran.com

राजस्थान में गुलाबी नगरी जयपुर की हुई स्थापना

1727 में आज ही आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना की थी। 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई रामसिंह प्रथम ने प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था।

पुश बटन डायलिंग पैड वाला टेलीफोन समाने आया

1963 में आज ही अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम्स दुनिया के सामने पहला ऐसा टेलीफोन लेकर आई थी, जिसमें पुश बटन वाला डायलिंग पैड था। इस तरह के टेलीफोन को पहली बार पेंसिलवेनिया शहर में लगाया गया था। उस दौर में डायल वाले टेलीफोन का प्रयोग होता था।

फिल्मों में नए प्रयोग के लिए मशहूर थे वी. शांताराम

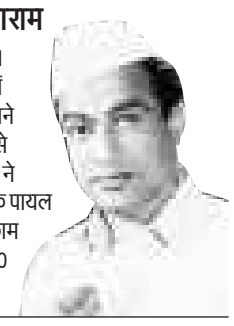

फिल्म निर्माता-निर्देशक वी. शांताराम का जन्म 1901 में आज ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 1921 में सुरेखा हरण नामक मूक फिल्म से बतौर अभिनेता अपने सफर की शुरुआत करने वाले शांताराम बाद में फिल्म निर्देशन से जुड़े। 1927 में नेताजी पालकर बनाकर बतौर निर्देशक शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, अमर भूपाली, झनक-झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ और नवरंग जैसी फिल्मों से अलग मुकाम हासिल किया। 1985 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। 30 अक्टूबर, 1990 को निधन हो गया।

इधर-उधर की

मगरमच्छ को मात देकर रेंजर ने जीती जिंदगी

सिडनी, एजेंसी : मगरमच्छ के चंगुल में आने के बाद बच निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी माना जाता है। हालांकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के वन्यजीव रेंजर क्रेग डिकमैन ने इस मान्यता को गलत ठहरा दिया। रविवार को वे क्रोक कंट्री इलाके में गए। वहां पीछे से एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। नौ फीट का मगरमच्छ उन्हें गहरे पानी की ओर खींच रहा था। डिकमैन ने मगरमच्छ की आंख में अपनी अंगुली से हमला कर दिया। तब तक अंगुली गड़ाए रखी, जब तक कि आंख की हड्डी महसूस न हुई। इस हमले से मगरमच्छ की पकड़ कमजोर हुई और वह उन्हें छोड़कर वापस पानी में चला गया। क्रेग ने बताया कि वे केवल उसका सिर देख पाए। मगरमच्छ ने उनकी जांघ पकड़ रखी थी। वह सिर पर हमला करना चाह रहा था। सकुशल बच निकलने के बाद लोग उनके साहस और सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं।

खतरे में हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के आवास

- इन इलाकों में बढ़ गई है उष्णकटिबंधीय सूक्ष्मजीवों की घुसपैठ
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है प्रभावित

गर्मी बढ़ने से लगातार पिघल रही है ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के आवास खतरे में हैं। हाल ही में प्रकाशित हुए दो अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने बताया है कि इन क्षेत्रों में अब उष्कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले सूक्ष्मजीवों की घुसपैठ बढ़ गई है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है।

सेल नामक जर्नल में प्रकाशित हुए इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने विश्व के महासागरों से 35 हजार से ज्यादा नमूने एकत्र किए। इस अध्ययन में फ्रांस के इंस्टीट्यूट डी बायोलॉजी डी ईकोल नॉर्मल सुपीरिअर (आइबीएएनएस) के शोधकर्ता भी शामिल थे। आइबीएएनएस के क्रिस बॉलर ने कहा, 'अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि पृथ्वी के महासागरों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की विविधता उच्च अक्षांशों (ध्रुवों के पास) पर सबसे कम है और भूमध्य रेखा के आस-पास ज्यादा है।'

दोनों अध्ययनों ने इन सूक्ष्मजीवों की विविधता का आकलन समुद्र से एकत्र किए गए नमूनों में किया, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि इनका समुदाय खुद को कैसे बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल कर लेता है। शोधकर्ताओं ने कहा, ' दो अध्ययनों में से एक प्लैंकटन (प्लवक) नामक सूक्ष्म समुद्री जीवों के समूहों की विविधता पर केंद्रित है और दूसरे में विश्वभर के महासागरों में सूक्ष्मजीवों के जीन की गतिविधि के पैटर्न का आकलन किया।

आइबीएएनएस के शोधकर्ता और 'प्लैंकटन अध्ययन' के सह-लेखक लूसी जिंजर ने कहा, हमारे अध्ययन ने प्लैंकटन पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।' एक बयान में उन्होंने कहा कि प्लैंकटन बैक्टीरिया, आर्किया, जानवरों और पौधों के प्रतिनिधि भी होते हैं। लेकिन इस विविधता के एक बड़े हिस्से को हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते।'

अक्षांशों के विस्तार के साथ कम होती जाती है विविधता : जिंजर ने कहा, ' अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्लैंकटन के समूहों की विविधता अक्षांशों के साथ-साथ कम होती चली जाती है। भूमध्य रेखा पर इनके समूहों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में यह काफी कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण समुद्र का बढ़ता तापमान है। जलवायु परिवर्तन के कारण शीतोष्ण और ध्रुवीय जल में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्लवक मिलने की संभावना अब बढ़ गई है।'

खुद को परितंत्र के लिए अनुकूल बना रहे हैं सूक्ष्म जीव : दूसरे शोध में शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में इनकी कोशिकाएं काम करती हैं। इसमें विश्वभर के महासागरों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के जीनों की गतिविधियों के पैटर्न का अध्ययन किया गया है। स्विटजरलैंड के ईटीएच ज्यूरिख की शोधकर्ता और अध्ययन की वरिष्ठ लेखक शिनिची सुनगावा ने कहा, ' हमारे लिए यह निर्धारित करना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां कौन से सूक्ष्मजीव मौजूद हैं बल्कि यह पता लगाना भी जरूरी है कि वे कौन से सूक्ष्मजीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।' सुनगावा ने कहा कि अध्ययन के दौरान हमने कई ऐसे सूक्ष्मजीव पाए जो पृथ्वी और गर्म क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन अब ठंडे इलाकों में भी रहने लगे हैं। इसका मतलब है कि समुद्र का परितंत्र भी लगातार बदल रहा है और सूक्ष्मजीव खुद को इसके अनुकूल बना रहे हैं।

फेसबुक, ट्विटर को टक्कर देने आया डब्ल्यूटी सोशल

स्पॉटलाइट

- विकीपीडिया के सह-संस्थापक जिम्मी वेल्स ने लांच की नई सोशल मीडिया साइट
- विकीपीडिया की ही तर्ज पर एड-फ्री रहकर डोनेशन से चलेगी यह सोशल साइट

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे विकीपीडिया के बारे में नहीं पता है। किसी भी व्यक्ति या विषय के बारे में एक ही जगह पर सब कुछ जानना हो, तो लोग विकीपीडिया की ओर ही रुख करते हैं। अब विकीपीडिया ने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा है। विकीपीडिया के सह-संस्थापक जिम्मी वेल्स ने डब्ल्यूटी सोशल के नाम से सोशल मीडिया साइट लांच की है।

वेल्स का कहना है कि यह सोशल मीडिया साइट उन खामियों को दूर करेगी, जिन्हें फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट ने नजरअंदाज कर दिया है। वेल्स ने कहा, 'विज्ञापन के जरिये कमाई करने का सोशल मीडिया कंपनियों का कारोबारी मॉडल ही सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रक्रिया में कम गुणवत्ता वाला कंटेंट जीत जाता है।' डब्ल्यूटी सोशल पर भी यूजर्स को अपने आर्टिकल साझा करने का विकल्प मिलेगा, लेकिन इस पर विज्ञापन नहीं होगा।

वेल्स ने इस साइट की शुरुआत विकी ट्रिब्यून के रूप में की थी। यह मुख्य रूप से समाचारों पर केंद्रित प्लेटफॉर्म था, जिसमें कम्युनिटी फैक्ट चेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि विकी ट्रिब्यून साइट लोगों को खास आकर्षित नहीं कर सकी। अब वेल्स ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी की है। इस साइट पर साइन अप करना निशुल्क होगा। हालांकि इसके बाद आपको या तो वेटलिस्ट में रहकर इंतजार करना होगा, डोनेट करना होगा या दोस्तों को इनवाइट करना होगा। फिलहाल महीनेभर में इससे 50,000 लोग जुड़ चुके हैं।

शोध अनुसंधान

उम्र के साथ व्यायाम का स्तर बढ़ाना दिल के लिए फायदेमंद

यह कई शोध में सिद्ध हुआ है कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहना सेहत के लिए फायदेमंद है। हालिया शोध के मुताबिक, बढ़ती उम्र के साथ व्यायाम का स्तर बढ़ाते जाना दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ व्यायाम का स्तर कम करते जाने वालों में दिल और रक्त नलिकाओं से जुड़ी परेशानियों की आशंका 27 फीसद तक बढ़ जाती है। वहीं व्यायाम का स्तर बढ़ा देने वालों में दिल की बीमारियों का खतरा 11 फीसद तक कम हो जाता है। यहां तक कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के शिकार लोगों के मामले में भी व्यायाम के बढ़े हुए स्तर का ऐसा ही असर होता है। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के 11.20 लाख पुरुषों व महिलाओं पर हुए अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष सामने आया है। एएनआइ

दिल के मरीजों की उम्र बढ़ा देता है कुछ समय का उपवास

उपवास से सेहत को होने वाले फायदे कई शोध में सामने आ चुके हैं। हालिया शोध के मुताबिक, नियमित तौर पर कुछ समय का उपवास दिल के मरीजों की उम्र बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों में हार्ट फेल की आशंका भी कम रहती है। शोधकर्ता बेंजामिन हॉन ने कहा, 'नतीजे इस बात का एक और उदाहरण हैं कि किस तरह से नियमित उपवास से सेहत अच्छी होती है और उम्र बढ़ती है।' वैज्ञानिकों ने करीब साढ़े चार साल तक जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर सेहत पर उपवास का असर दिखने के लिए 12 घंटे के उपवास की जरूरत होती है। नियमित तौर पर उपवास करने वालों के लिए यह समय कम भी हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उपवास नहीं करना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी यह सही नहीं है। आइएएनएस

याददाश्त बढ़ाएगी चाय से बनी वाइन

तकनीक ▸ हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर के विज्ञानियों ने तलाशी राह

टी वाइन बनाने में लगता है एक वर्ष का समय, जल्द बाजार में उतारी जाएगी

शारदाआनंद गौतम, पालमपुर

अक्सर उम्र बढ़ने के साथ-साथ भूलने की बीमारी घर कर जाती है, पर अब इसे आप बाय-बाय बोल सकते हैं। यह संभव हुआ है कांगड़ा चाय से बनी टी वाइन से। हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आइएचबीटी) पालमपुर के विज्ञानियों ने कांगड़ा चाय से टी वाइन बनाने की तकनीक तैयार की है। साथ ही संस्थान ने बंगाल की कंपनी कैमेलिया बीवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है।

टी वाइन बनाने में करीब एक वर्ष का समय लगता है और इसे जल्द बाजार में उतारा जाएगा। इस तकनीक से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए संस्थान ने एक हजार लीटर क्षमता वाली मशीनरी अपने पास रखी है।

कांगड़ा चाय से तैयार टी वाइन। जागरण

ऐसे की जाती है तैयार : कांगड़ा चाय को पहले हल्के तौर पर उबाला जाता है और इसके बाद यीस्ट मिलाया जाता है। इस दौरान चाय में अल्कोहल की मात्रा बनती है, जिसे निर्धारित कर मिठास को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद करीब एक साल तक इसे रखा जाता है। इस अवधि में टी वाइन में खुशबू तैयार होती है और इसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक दिन में 120 मिलीलीटर टी वाइन का सेवन किया जा सकता है।

ये हैं खूबियां : टी वाइन हृदयाघात रोकने में भी मददगार होती है। शुगर से पीड़ित लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ठंड से बचाव के लिए भी टी वाइन कारगर रहती है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है उनके लिए यह बड़ी कारगर है।

600 से 700 रुपये है बोतल की कीमत : टी वाइन की अमेरिका में खासी मांग है। टी वाइन की बोतल को तैयार करने में लागत करीब 100 रुपये आती है और बाजार में इसे 600 से 700 रुपये में बेचा जाता है।

यहां होती है कांगड़ा चाय की पैदावार : हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय की पैदावार कांगड़ा, मंडी और चंबा जिलों के कुछ हिस्सों में होती है। सबसे अधिक कांगड़ा चाय धर्मशाला, पालमपुर और बैजनाथ उपमंडलों में होती है। मंडी के जोगेंद्रनगर और चंबा के भटियात उपमंडल में भी बागवान इसे तैयार करते हैं। आइएचबीटी पालमपुर ने कांगड़ा चाय को प्रोमोट करने के लिए वेल्यू एडिशन के बाद विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए हैं।

टी वाइन याददाश्त बढ़ाने के साथ-साथ हृदयाघात रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसे में दवा के तौर पर ली गई टी वाइन हृदय में कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देती है और उसे मूवमेंट में रखती है। टी वाइन में एंटी ऑक्सीडेंट अधिक रहता है और यह नि :संदेह कई रोगों से बचाता है। लिहाजा तीस से साठ एमएल टी वाइन पीने की सलाह दी जाती है।

डॉ. आदर्श भार्गव, हृदय रोग विशेषज्ञ, विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट पालमपुर

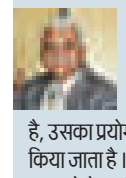

टी वाइन में एंटी ऑक्सीडेंट समेत अल्कोहल होता है और इस कारण यह विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी। कांगड़ा चाय का जो सेकंडरी भाग है, उसका प्रयोग ही टी वाइन तैयार करने में किया जाता है। करीब 10 वर्ष की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है।

-डॉ. संजय कुमार, निदेशक, हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर

इन्फ्लूएंजा वायरस के संक्रमण से बचा सकती है कीटो डाइट

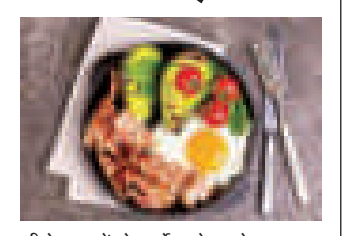

कीटो डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट को अपना कर आजकल लोग खुद को फिट रखते हैं। कीटो डाइट में हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि यदि हम अपने आहार में कीटोजेनिक डाइट को शामिल कर लेते हैं, तो इससे इन्फ्लूएंजा वायरस यानी फ्लू के संक्रमण से बचा जा सकता है। चूहों पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस डाइट को केवल कार्बोहाइड्रेट खाने से बेहतर बताया है।

इस अध्ययन के शोधकर्ताओं में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के शोधार्थी भी शामिल थे। इस टीम के भारतीय मूल के शोधकर्ता दीप दीक्षित ने कहा, 'कीटो डाइट जिसमें मांस, मछली और बिना रेशे वाली सब्जियां शामिल होती हैं, ये फेफड़ों की टी कोशिकाओं के इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) को सक्रिय करती है। साइंस इम्यूनोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि ये कोशिकाएं वायुमार्ग में बगलग का उत्पादन बढ़ा देती हैं, जिसमें फ्लू का वायरस फंस जाता है और फेफड़े संक्रमित होने से बच जाते हैं। इससे पहले शोधकताओं ने यह भी पाया था कि इम्यून सिस्टम के एक्टीवेटर्स, जिसे इन्फ्लेमासम कहा जाता है, हानिकारक इम्यूमन सिस्टम रिस्पांस का कारण बन सकता है। इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि जिन इन्फ्लूएंजा वायरस से संक्रमित चूहों को कीटोजेनिक डाइट दी गई थी, वे सामान्य आहार वाले चूहों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ थे और उनकी जीवित रहने की संभावना भी अन्य से अधिक थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि कीटोजेनिक आहार ने गामा डेल्टा टी कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को बढ़ा दिया था, जिससे चूहों के श्वास नली में बलगम तेजी से बनने लगा और फ्यू का संक्रमण होने से बच गया।

लेगो आकार में बना आवासीय कॉम्प्लेक्स

पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत के कुशान सिटी में लेगो ब्लॉक की तरह बनाया गया आवासीय कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का बेहतरीन नमूना है। यह डिजाइन पर्यटकों को भी काफी आकर्षित कर रही है और यह जगह ट्रेंडी स्पॉट बन गई है। इसमें एक हजार फ्लैट हैं और ऊपर से देखने पर यह कॉम्प्लेक्स बेहद खूबसूरत नजर आता। साभार : सीजीटीएनडॉटकॉम

एयर शो में शामिल हुआ इलेक्ट्रिक विमान

दुबई के प्रसिद्ध एयर शो में शामिल हुआ पहला इलेक्ट्रिक विमान सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र रहा। पर्यावरण के अनुकूल इस विमान को एयर रेस-वन ने तैयार किया है। अपने विमान के साथ कंपनी के सीईओ जेफ जेल्टमैन और उनके सहयोगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी हाल ही में अपने पहले इलेक्ट्रिक विमान एक्स-57 की परीक्षण उड़ान की थी। चीन भी चार सीटर इलेट्रिक विमान का सफल ट्रायल कर चुका है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को देखते हुए इन्हें भविष्य का विमान बताया जा रहा है। एपी

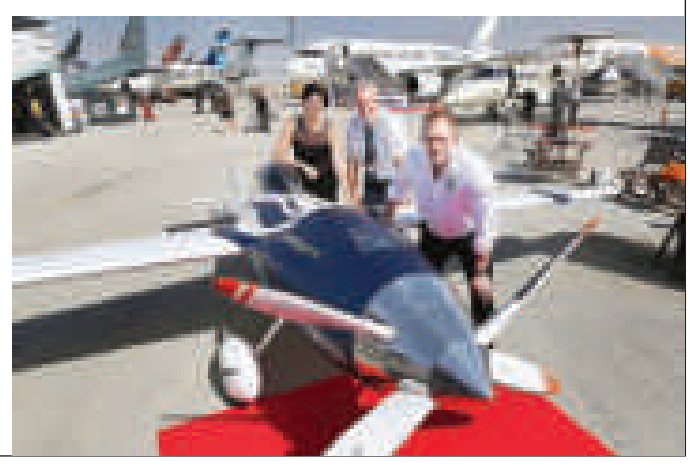

स्क्रीन शॉट

दो घंटे में जेठमलानी का जीवन दिखाना बड़ी चुनौती है : सोहा अली खान

सात सवाल

मां बनने के बाद सोहा अली खान बच्चों से जुड़ी चीजों में खासी दिलचस्पी ले रही हैं। हाल में लॉन्च 'वूट' किड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की ऑडियो स्टोरी 'ए हंड्रेड कार्टलोड्स : कराडी टेल्स' में सोहा ने अपनी आवाज दी है। वह प्रख्यात वकील राम जेठमलानी की बायोपिक बनाने की तैयारी भी कर रही हैं। उनसे बातचीत :

बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म को किस तरह से देखती हैं?

- यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बेटी दो साल की है। यह सही वक्त है उसे स्क्रीन पर एजुकेशनल एंटरटेनमेंट से रूबरू कराने के लिए। इस एप पर कार्टून, ऑडियो किताबें और गेम्स, पजल्स भी हैं। जब वह थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो खेल सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें बीच में विज्ञापन नहीं आते हैं।

आप अपने बचपन में कैसी थीं? आपका एंटरटेनमेंट क्या होता था?

- हम छोटे थे, तो यह सब नहीं था। तब मोबाइल नहीं होता था। पूरे घर में एक लैंडलाइन फोन होता था। टीवी भी एक होता था। ब्लैक ऐंड व्हाइट। टीवी पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स कम थे। हम बाहर ही खेलते थे। किताबें पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते-सुनते, खेलते और गाना गाते थे। आजकल भी यह बहुत जरूरी है, जो बचपन का खूबसूरत हिस्सा है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आपको यह देखना है कि आप उसे बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन के लिए कैसे इस्तेमाल करें।

आपने किताब भी लिखी है... ?

- मुझे किताबें पढ़ने का शौक बचपन से है। पढ़ने से शब्द संग्रह बढ़ता है। एकाग्रता बढ़ती है। बच्चे अपने माता-पिता को जो काम करते हुए देखते हैं, वही खुद भी करते हैं। अगर वे माता-पिता को किताबें पढ़ते हुए देखेंगे, तो वे भी पढ़ेंगे। अगर आप फोन पर रहेंगे, तो वे भी वही करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी नहीं देखे, तो आप उनके सोने के बाद टीवी देखें। हमारे घर पर इनाया के सोने के बाद ही टीवी ऑन होता है।

इनाया का मोबाइल फोन को लेकर क्या रिएक्शन होता है?

- शुरुआत तब हुई थी, जब इनाया खुद फोन पर अपने वीडियोज देखना चाह रही थी। हम उसके फोटो और वीडियोज लेते रहते हैं। वह पूछती है कि आप फोन में क्या कर रहे हो, तो मैं बताती हूं कि आपका वीडियो ले रही हूं। कभी-कभी कहती है-वीडियो दिखाओ। उससे शुरुआत हुई थी। अब दो साल की हो गई है।

बचपन में आप मां (शर्मिला टैगोर) की फिल्में देखती थी, तो कैसा लगता था?

- अम्मा की फिल्मों में बहुत रोना-धोना होता था। कई फिल्मों में वे मर जाती थीं। वह हमें अच्छा नहीं लगता था। 'चुपके-चुपके' जैसी फिल्मों में मां को देखकर अच्छा लगता था। हम उन्हें शूट पर तैयार होकर जाते देखते थे। हमें यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि जो स्क्रीन पर होता है, वह असली नहीं है।

आप राम जेठमलानी की बायोपिक भी बनाने वाली थीं?

- हां, लेकिन वक्त लग रहा है। हमारे पार्टनर रॉनी स्क्रूवाला हैं। राम जेठमलानी ने 95 साल के जीवन में सत्तर साल काम किया है। उनके जीवन में किए हुए कार्यों के साथ न्याय करने के लिए, कैसे दो घंटे की फिल्म बनाएं, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती और स्ट्रगल है।

आप स्क्रीन से दूर हैं?

- एंडोर्समेंट के अलावा मैंने पिछले दो सालों में कुछ नहीं किया है। अब गंभीरता से सोच रही हूं। इनाया स्कूल जाने लगी है। मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूं कि उसे भी साथ ले जा सकूं। ऐसा कुछ मिला है मुझे। जनवरी-फरवरी में एक वेबसीरीज में कुछ करूंगी।

- स्मिता श्रीवास्तव

मेरी पसंद दर्शकों की पसंद से मिलती है : आयुष्मान

आयुष्मान खुराना की नई फिल्म 'बाला' उनकी लगातार सातवीं हिट फिल्म है। आयुष्मान कहते हैं, 'मेरी फिल्मों की सफलता इस बात का सूचक है कि मेरा चयन दर्शकों की पसंद से मिलता है। मैं वे ही फिल्में चुनता हूं, जो दर्शक देखना चाहते हैं।' आयुष्मान कहते हैं, 'मैंने जिस तरह की फिल्मों का चयन किया है, उससे मुझे यह समझने में भी मदद मिली है कि मैं कैसी फिल्मों के साथ जुड़ना चाहता हूं। अक्सर एक्टर सफल होने पर दर्शकों की अपेक्षाओं का दवाब महसूस करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे इससे स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है और रिस्क लेने की हिम्मत होती है।' 'बाला' के बाद आयुष्मान की आने वाली फिल्मों में 'गुलाबो सिताबो' और 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' हैं।

दुआ लिपा को शाह रुख ने सिखाए डांस स्टेप्स

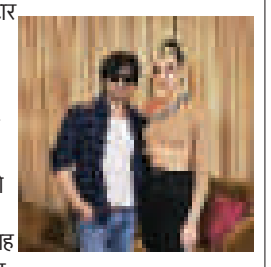

इंटरनेशनल पॉप स्टार केटी पेरी और दुआ लिपा अपने कॉन्सर्ट को लेकर मुंबई में थीं। केटी पेरी करण जौहर की ग्रैंड पार्टी में भी शामिल हुई, तो दुआ शाह रुख के साथ नजर आईं। शाह रुख ने इंस्टाग्राम पर दुआ लिपा के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा-'मेरी तरफ से कॉन्सर्ट के लिए ढेर सारा प्यार। दुआ अगर आप कर सकती हैं तो आप वे स्टेप्स करने की कोशिश कीजिएगा, जो मैंने आपको सिखाए हैं।'

अध्ययन

सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के किया शोध, 24 महीने के चूहे को छह सप्ताह के चूहे में बदलकर किया दावा

उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं गट बैक्टीरिया

सिंगापुर, प्रेट्र : आंतों में रहने वाले सूक्ष्मजीव यानी गट बैक्टीरिया उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। मनुष्यों सहित सभी जीवों के शरीर में असंख्य सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो एक-दूसरे के सहयोग से जीवों के स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखते हैं।

सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एनटीयू) के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने अध्ययन कर यह पता लगाया कि गट बैक्टीरिया पोषण, फिजियोलॉजी (शरीर विज्ञान), मेटाबोलिज्म और हमारे व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एनटीयू के प्रोफेसर स्वेन पेटर्सन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने टीम 24 महीने के चूहों पर गट बैक्टीरिया का प्रत्यारोपण कर उन्हें छह सप्ताह के चूहों में बदल दिया। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि आठ सप्ताह के बाद इन चूहों में शारीरिक वृद्धि होनी शुरू हुई और उनके मस्तिष्क में न्यूरोजेनेसिस यानी न्यूरॉन्स उत्पादन शुरू हुआ।

साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि न्यूरोजेनेसिस की वृद्धि का कारण गट बैक्टीरिया हैं, जो विशिष्ट फैटी एसिड का उत्पादन करते हैं, जिसे ब्यूटायरेट कहा जाता है। ब्यूटायरेट का उत्पादन आंतों के निचले हिस्से में डाइट्री फाइबर के माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के माध्यम से किया जाता है। इससे एफजीएफ-21 नामक एक हार्मोन के उत्पादन बढ़ जाता है, जो शरीर की ऊर्जा और मेटाबॉल्जिम को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'इसका मतलब है कि ब्यूटारेट के उत्पादन बढ़ने से हमें उम्र कम करने में मदद मिल सकती है।'

पेटर्सन ने कहा, 'अध्ययन के दौरान हमने पाया कि एक बड़े चूहे के शरीर से एकत्र किए गए माइक्रोब्स (सूक्ष्मजीवों) में छोटे चूहे की तंत्रिका का विकास करने की क्षमता होती है।' उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक और बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन के निष्कर्ष सामने आने के बाद शायद यह संभव हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति को जवां बनाए रख सकते हैं। हालांकि, इसके लिए अभी कई स्तरों पर अध्ययन की जरूरत है।

प्रतीकात्मक

वाइरस से बैक्टीरिया को मारा

मनुष्य के शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं तो कुछ शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिन्हें बैड बैक्टीरिया कहा जाता है। एक अन्य अध्ययन में इन्हीं जीवाणुओं को मारने के लिए वैज्ञानिकों एक वाइरस की मदद ली और प्रोटीन के जरिये बैड बैक्टीरिया को बदल दिया, जिसके बाद उनकी कार्यप्रणाली भी बदल गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे को दूर करने में मदद मिल सकती है। उनका कहा कि कई बार बीमारियों से बचने के लिए खाई जाने वाली दवाएं असर नहीं करतीं। इसका मुख्य कारण यही होता है कि हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें मारा जाता सकता है।